आरआईएस

वार्षिक रिपोर्ट

2019–20

आरआईएस

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

विषय वस्तु

अध्यक्ष का संदेश v

महानिदेशक की रिपोर्ट vii

अध्याय 1. नीतिगत अनुसंधान 1

अध्याय 2. कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान आरआईएस की सक्रिय भूमिका 37

अध्याय 3. नीतिगत शोध पत्र 41

अध्याय 4. नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ 43

अध्याय 5. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम 91

अध्याय 6. प्रकाशन कार्यक्रम 99

अध्याय 7. आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र 107

अध्याय 8. मानव संसाधन 111

अध्याय 9. वित्तीय विवरण 117

संचालन परिषद

अध्यक्ष

डॉ. मोहन कुमार

पदेन सदस्य

श्री विजय गोखले
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
(28 जनवरी 2020 तक)

श्री हर्षवर्धन श्रिंगला
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
(29 जनवरी, 2020 से)

श्री अतानू चक्रबर्ती
सचिव, आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय
(30 अप्रैल 2020 तक)

श्री तरुण बजाज
सचिव, आर्थिक कार्य
विभाग, वित्त मंत्रालय
(1 मई 2020 से)

प्रोफेसर आशुतोष शर्मा
सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

डॉ. अनूप वाधवन
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग
मंत्रालय

श्री टी. एस. त्रिमूर्ति
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय
(मई 2020 तक)

श्री राहुल छाबड़ा
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय
(जून 2020 से)

अपदेन सदस्य

श्री शेषाद्री चारी
वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक एवं
लेखक

श्री जयंत दासगुप्ता
डब्ल्यूटीओ में भारत के
पूर्व राजदूत

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
अध्यक्षा, एचडीएफसी बैंक,
मुबंई

डॉ शैलेश नायक
निदेशक, नेशनल इंस्टीटयूट
ऑफ एडवांस्ड स्टडीज

सदस्य सचिव (पदेन)

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

अनुसंधान सलाहकार परिषद

अध्यक्ष

श्री एस. टी. देवरे
पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय

सदस्य

प्रोफेसर एन. एस. सिद्धार्थन
मानद प्राध्यापक, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स

प्रोफेसर पुलिन बी. नायक
भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

प्रोफेसर रथिन रॉय
निदेशक, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान

सुश्री सिंधुश्री खुल्लर
भूतपूर्व सीईओ, नीति आयोग

श्री अनुपम रे
सह सचिव (पी पी एण्ड आर)
विदेश मंत्रालय

विशेष आमंत्रित सदस्य

डॉ नागेश कुमार
प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र एस्कैप के दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र एस्कैप–एसएसडब्ल्यूए), नई दिल्ली

सदस्य सचिव

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

राजदूत डॉ मोहन कुमार

अध्यक्ष का संदेश

आरआईएस की यह वार्षिक रिपोर्ट–2019–20 ऐसे समय सामने लाई जा रही है, जब विनाशकारी वैश्विक महामारी कोविड–19 ने हम सभी को जकड़ रखा है और इसने किसी को छोड़ा नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और यहां तक की इस वैश्विक महामारी का राजनीतिक प्रभाव अब भी दिखाई दे रहा है। आरआईएस ने निस्संदेह अपने समान विचारधारा वाली अन्य संस्थाओं के साथ घनिष्ठ सहयोग के साथ इस संभावना को टटोलने का प्रयास किया है कि दक्षिणी विश्व के देश इस अभूतपूर्व संकट से किस तरह निपट सकते हैं। इस संदर्भ में, आरआईएस द्वारा की गईं पहलों को रिपोर्ट के सम्पूर्ण अध्याय में प्रमुखता से रेखांकित किया गया है।

मैं यह देख कर अतीव प्रसन्न हूं कि लॉकडाउन के दौरान भी आरआईएस ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित शोध–अनुसंधान–कार्य के अपने एजेंडे पर परिश्रमपूर्वक काम करता रहा है: इनमें 2022 में भारत की अध्यक्षता में जी–20 देशों का सम्मेलन, सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन की निगरानी (एसडीजी), दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग, विकास, वित्त, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहन, परंपरागत औषधि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा, जेंडर के मसले, जलवायु परिवर्तन और विज्ञान–कूटनीति के नाम लिए जा सकते हैं। आरआईएस की यह रिपोर्ट क्षेत्रीय आर्थिक प्रबंधन को भी अपने अध्ययन में शामिल किया है। इस संदर्भ में आरआईएस कार्यक्रम को इब्सा, ब्रिक्स, बिम्सटेक और आसियान–भारत गठजोड़ सहित विभिन्न समूहों के साथ जोड़ा गया है ताकि इसका आकलन किया जा सके कि इन मंचों पर भारत के हित किस तरह से सध रहे हैं। जैसा कि रिपोर्ट में दर्शाया गया है, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के देश आरआईएस के अनुसंधान एजेंडे में लगातार प्रमुखता से स्थान पाये हुए हैं। सदा की भांति आरआईएस के कार्यक्रमों के विविध आयामों को लेकर नीति संबंधी कुछ संवाद आयोजित किए गए थे, जिनमें काफी संख्या में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने शिरकत की थी। इस संस्था ने बड़ी संख्या में शोध–अनुसंधानों भी प्रकाशित किया है, जिनको नीति–निर्माताओं, शिक्षाविदों और अनुसंधान में लगे लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने की संभावना है। मैं आशा करता हूं कि यह रिपोर्ट शोधार्थियों और निर्णयकर्ताओं दोनों की समान अभिरुचि की होगी।

रिसर्च एजेंडे को सामने लाने के लिए मैं आरआईएस की संचालन परिषद (गवर्निंग काउंसिल) और सामान्य निकाय (जनरल बॉडी) को उनके उत्साह संवर्धन और निर्देशन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को भी इस काम में उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आरआईएस कार्यक्रम को प्रकाश में लाने के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी एवं उनकी टीम को उनके कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि आरआईएस दक्षिणी विश्व के हितों को बढ़ावा देने, दक्षिणीय सहयोग को प्रोत्साहित करने और विकासशील देशों के फायदे के लिए साझा व्यवहारों के अपने बुनियादी लक्ष्यों के प्रति प्रयास करता रहेगा।

मोहन कुमार

महानिदेशक की रिपोर्ट

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

इस साल आरआईएस ने एक बार फिर अपने अनुसंधान के चारों स्तंभों को मजबूती देने तथा अपने दायरे से बाहर की गतिविधियों; जैसे वैश्विक आर्थिक प्रशासन और सहयोग, व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग, कारोबार की सुगमता, संपर्क तथा क्षेत्रीय सहयोग; और सबसे बढ़कर नई प्रौद्योगिकी एवं विकास की थीम को समेटने में सफलतापूर्वक अपना योगदान दिया है। संस्थान की तरफ से किये जाने वाले अकादमिक कार्य और प्रकाशनों को व्यापक रूप से इसकी मुख्य सक्षमता तथा कारोबार, निवेश, वित्त, प्रौद्योगिकी एवं व्यापक विकास के चुनिंदा क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता द्वारा एक आकार दिया जाता है।

हालांकि यह साल कोविड–19 की वैश्विक जकड़न में समाप्त हुआ है और इसने समूची मानव जाति को भयभीत कर दिया है। उस समय, आरआईएस एवं आईटीईसी के तत्वावधान में 'अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों और विकास–नीति' विषय पर 6 मार्च 2020 के कार्यक्रम का समापन होने ही वाला था कि प्रतिभागी सदस्यों में से एक महिला सदस्य के बीमार होने की खबर मिली। इससे हम सभी घबरा गए। उस महिला प्रतिभागी को कोविड–19 के संक्रमण की संदिग्ध मरीज मानते हुए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात थी और हमारे चिकित्सा समुदाय को उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद, कि उस महिला प्रतिभागी का तत्काल उपचार किया गया और उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। इनके साथ ही हम सबों ने चैन की सांस ली। इस प्रकार, वह और आईटीईसी के अन्य प्रतिभागी 9 मार्च 2020 को अपने–अपने घर सुरक्षित विदा हो गए। इसके तुरंत बाद देश में, राज्यों में तथा सभी सेवाओं में लॉकडाउन की घोषणा हुई, जिसने सभी तरह की गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया। आरआईएस स्वयं भी स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व संकट से घिर गया।

संकाय के सदस्यों को घर से कामकाज की एक नयी कार्य–स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि वे वैश्विक स्वास्थ्य–परिणामों तथा आर्थिक मसलों का विश्लेषण करते रहे और उन प्रविधियों को खंगालते रहे, जिससे कि पूरा विश्व क्षेत्रीय, उप–क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय स्तर पर इस वैश्विक महामारी के खतरों को एक साथ चुनौती दे सकें। वे इसके लिए एक व्यवहार्य कार्य–योजना के साथ बाहर आए। इस अवधि में वैश्विक महामारी के विभिन्न आयामों को उद्घाटित करने वाली आरआईएस की डायरी की विशेष मुद्दों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। इसका पहला अंक मार्च में ही तैयार हो गया था और यह अप्रैल 2020 में प्रकाश में आया, जबकि अन्य अंकों को आगामी महीनों में कोविड–19 की चुनौतियों के विशेष आयामों पर संक्षिप्त नीतिगत टिप्पणी के साथ प्रकाश में लाने का विचार किया गया। वार्षिक रिपोर्ट में भी, ''कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान आरआईएस की सक्रिय भूमिका'' (एक्टिव रोल ऑफ आरआईएस ड्यूरिंग कोविड–19 लॉकडाउन) शीर्षक से एक विशेष अध्याय दिया गया है, जिसमें इस दिशा में हमारे द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों का विस्तृत ब्योरा दिया गया है।

संकट की शुरुआत से ही आरआईएस संकाय के सदस्य अपनी व्यक्तिगत विशेषज्ञता के आधार पर काम करते हुए कई मसलों पर नीतिगत रोड मैप को बनाने, टिप्पणियां करने तथा संकट के परिमाण और उनके प्रभावों का अध्ययन करने लगे थे। इस संक्षिप्त नीतिगत टिप्पणी का मकसद बेहतर आर्थिक स्थिति की बहाली के विकल्पों की संभावनाओं को खंगालना, खतरों को कम करना तथा वैश्विक एवं क्षेत्रीय सहयोग की रूपरेखा के बारे में बताना था। तब तक अंतर माइक्रो इकोनॉमी, वैश्विक महामारी पर प्रतिक्रिया, औषधि निर्माण क्षेत्र, बहुपक्षीय व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, परंपरागत

महानिदेशक की रिपोर्ट

औषधि पद्धति, बिम्सटेक में क्षेत्रीय सहयोग, अफ्रीका के लिए समर्थन आदि विषयों पर अध्ययनों का प्रस्ताव किया गया था।

विगत वर्षों में आरआईएस को भारत सरकार के विभिन्न अंगों को नीतिगत अनुसंधान और निवेश के साथ समर्थन करने का गौरव मिलता रहा है। राष्ट्रीय स्तर के विचार–विमर्श एवं कार्यशाला के जरिए सरकार की व्यापक पहुंच (शिक्षाविद् समुदायों और अन्य प्रतिभागियों के साथ) को सुलभ बनाने का अवसर मिलता रहा है। इस साल फिर हमने सरकार के साथ अपनी संलग्नता को और गहन किया है। समावेशी, निरंतरता, आत्मनिर्भर और ज्ञान के सिद्धांतों पर स्थापित "नया भारत" की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ आरआईएस ने विकासशील देशों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों पर अनुसंधान आधारित निवेश, क्षमता निर्माण और जानकारियों को साझा करने के जरिए लगातार उनका समर्थन करता रहा है।

आरआईएस दक्षिणीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्ध है और उसने नये अवधारणात्मक ढांचे, खासकर विकास–प्रभाव के दृष्टिकोण तथा दक्षिणी देशों के संदर्भ में समीचीन प्रभाव आकलन मैट्रिक्स को विकसित करने की दिशा में प्रयास किए है। इस क्षेत्र मे। हमारा प्रयास आरआईएस के तत्वावधान में 'दिल्ली प्रोसेस' के वार्षिक आयोजन द्वारा और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके जरिये हम इन मसलों पर विश्व के चिंतकों से जुड़ते हैं। आरआईएस की 2019 में बीएपीए+40 में भागीदारी और योगदान भावी अनुसंधान कार्यक्रमों को समृद्ध करने की लिहाज से महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे के पृष्ठों पर इस संदर्भ में विस्तृत विवरण दिए गए हैं।

यह साल चुनौतियों से लबरेज था, खासकर थिंक टैंकों के लिए जो बहुपक्षीय और कारोबार से संबंधित संस्थागत ढांचे पर विमर्श करते रहे हैं। अमेरिका और चीन में जारी तनाव, विकास तथा सत्यता के संवादों, एवं भरोसे के अभाव के साथ असंलग्नता और परस्पर बढ़ती दूरी ने हम सबको संकट में डाल दिया है। आरआईएस की तरफ से की गई टिप्पणियों ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। चूंकि इसका उद्भव स्पष्ट है, इसने विकासशील देशों गंभीर असर डाला है। विगत दशकों में कारोबार और तकनीक दक्षिण के उदय के प्रबल कारक रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में लचीलापन और गत्यात्मकता का संचालन करते रहे हैं और समावेशी विकास परिणामो। में सतत सुधार रहे हैं। इस संदर्भ में आरआईएस के प्रभावों के साथ प्रकाशनों की एक सूची भी इस रिपोर्ट में दी गई है।

उभरती चुनौतियों के बरअक्स विश्व की चुप प्रतिक्रियाओं के समक्ष, दक्षिणीय सहयोग के सबक आशा और उम्मीद जगाते हैं। इस प्रक्रिया में आरआईएस ने विश्व स्तर पर अनेक संस्थाओं से संपर्क जोड़ा है। उसने संभावनाओं एव। वायदो। के एक व्यापक दायरे का निदर्शन किया है कि दक्षिण में संस्थाओं में वैश्विक प्रक्रियाओं को एक आकार देने और इस बारे में सूचित करने की जिम्मेदार है। आरआईएस ने एसडीजीसे संबद्ध मुद्दों और जी20, ब्रिक्स, बिम्सटेक, और इनमें कई अनेक वैश्विक समावेशी एवं सतत विकास के लिए सहयोग की अनिवार्यता पर अपना लगातार ध्यान रखने के जरिए, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं पर गहन विमर्श किया है।

वैश्विक मुद्दे और सहयोग ढांचे का विकास

आरआईएस सभी आर्थिक और क्षेत्रवार आयाम पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो 2022 में भारत की जी20 देशों की अध्यक्षता करने के लिहाज से अहम है। विगत 2 सालों में आरआईएस थिंक टैंक20 (टी20) की प्रक्रिया से जुड़ा रहा है और कारोबार एवं निवेश, बहुआयामिता, सतत विकास और वित्त के क्षेत्र में योगदान दे रहा है। जी20 देशों की भारत की अध्यक्षता के मद्देनजर, आरआईएस ने विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के साथ संलग्न रहा है। आरआईएस जी20 खासकर; बी20, एस20, सी20 और डब्ल्यू20 की प्रक्रियाओं से जुड़ा रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और क्षेत्रीय सहयोग के उपक्रमों के साथ आरआईएस ने वित्त, तकनीक, संकेतकों और स्थानीकरण के प्रयास के संदर्भ में एसडीजी के अध्ययन पर अपने को केंद्रित रखा है। किए गए अध्ययन जी20 प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक मुद्दों, तकनीक, व्यापार और व्यापार प्रबंधन, खेती एवं खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ निवेश, आव्रजन, जलवायु परिवर्तन, ढांचागत वित्त, वित्त–प्रौद्योगिकी (फिनटेक), सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं, अवैध वित्त प्रवाहों आदि मुद्दों पर विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में जोर देने के साथ–साथ समझदारी बढ़ाने में योगदान दिया है।

महानिदेशक की रिपोर्ट

आर्थिक सहयोग के उपक्रमों जैसे एससीओ के बारे में भी अध्ययन किया गया है। आरआईएस ने दक्षिणीय और त्रिगुणात्मक सहयोग के बारे में समग्र आंकड़ा जुटाया है। एसडीजी पर अपने अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत आरआईएस ने उत्तर–पूर्व भारत में सतत् विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण पर एक रिपोर्ट पेश की है तथा वित्त मंत्री की घोषणा के मद्देनजर भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज की संभावनाओं पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग में किए गए उपक्रम

द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग मे। आरआईएस की दीर्घकालीन विशेषज्ञता के साथ, इस संस्था ने द्विपक्षीय कारोबार के कई नए अध्ययन किए हैं और इसने क्षेत्रीय सहयोग प्रबंधन तथा एशिया, अफ्रीका एवं लातिनी अमेरिका में एफटीए महादेशीय उद्भव को विश्लेषित किया है। ये अध्ययन दुनिया की बड़ी कारोबारी शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव, बहुपक्षीयता के ध्वस्त होने, डिजिटल कारोबार जैसे नई व्यवस्था के उभरने तथा क्षेत्रीय व्यापार एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला के उद्भव के मद्देनजर महत्वपूर्ण हैं। इन सभी ने वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों की भागीदारी पर गहरा असर डाला है। आगामी विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत कारोबार एवं प्रौद्योगिकी में बढ़ते अंतर्संबंध और विकासशील देशों की सब्सिडियों में बढ़ती दिलचस्पी, विशेष और भिन्न व्यवहार (एसएंडडीटी), क्षेत्रवाद और व्यापार के वैश्विक शासन के ढांचे में सुधार का समग्रता से अध्ययन किया जाएगा। आरआईएस ने भारत के ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के मसले का भी श्रृंखलाबद्ध अध्ययन किया है। वर्गीकृत व्यापार के विस्तार, भारतीय दवा प्रणाली (आईएसएम) की गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण के साथ ही जड़ी–बूटियों के उत्पादन व भारतीय औषधि निर्माण क्षेत्र के बारे में भी अलग से अध्ययन किया गया है। क्षेत्रीय सहयोग के संदर्भ में अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एएफसीएफटीए), ब्रिक्स में व्यापार और निवेश के परस्पर संबंध, व्यापार में स्थानीय मुद्रा के उपयोग की संभावनाएं और बिम्सटेक में वित्तीय प्रौद्योगिकियों की संभावनाओ। का मुख्य रूप से अध्ययन किया गया है। एक स्वतंत्र रिपोर्ट में, इब्सा (आईबीएसए) की समकालीन गत्यात्मकता का एक संयुक्त अध्ययन इब्सा के शोधकर्ताओं और आरआईएस के संकाय के सदस्यों ने किया है।

व्यापार सुगमता, संयोजकता और क्षेत्रीय अखंडता

देशो। के बीच आर्थिक सहयोग सुगमता के मद्देनजर समर्थित कारोबार और निवेश प्रवाहों के लिए कारोबार की सुगमता और संयोजकता महत्वपूर्ण आयाम हैं। व्यापार और उससे संबद्ध संरचना के विकास को क्षेत्रीय अखंडता के उपक्रमों से जोड़ने की आवश्यकता है, जो तत्कालीन तकाजों, राजनीतिक साझेदारी और अपने नागरिकों के प्रति शुभेच्छा से उद्भूत होता है और भूगोल एवं साझा आकांक्षाओं से संपृक्त होता है। इस दिशा में संयोजकता, सीमा संरचना, कस्टम रिफॉर्म्स, आयात–निर्यात प्रक्रियायों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप देना इत्यादि भौतिक संरचना के मुख्य मानक हैं। क्षेत्रीय अखंडता के अनुभवों पर आधारित, खासकर आसियान, आर्थिक गलियारा अथवा ग्रोथ कोरिडोर पर बल देता है,ये क्षेत्रीय सहयोग के सक्षम प्रतिमान हैं। ग्रोथ कोरिडोर बनाने के इस प्रयास में जो प्रतिभागी देशों के बीच सकारात्मकता का माहौल बनाये, इस दृष्टिकोण के मुख्य अवयव हैं: स्थानीय संसाधनों का समतलीकरण, स्थानीय औद्योगिकरणों की सुलभता और निर्यात का संवर्धन। इस दिशा में आर आई एस ने श्रृंखलाबद्ध अध्ययन की शुरुआत की है और, खासकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) और बिम्सटेक मामले में कई उपक्रम किए हैं। यद्यपि एएजीसी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सहयोग को अपने में समाहित करता है, बिम्सटेक के बारे में अध्ययन कारोबार, कनेक्टिविटी, वित्त–प्रौद्योगिकी (फिनटेक) आदि को क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाशील क्षेत्रों के रूप में होता है। अभी हाल ही में, आरआईएस ने अपने अध्ययन में भारत– यूरोपीय यूनियन कनेक्टिविटी और सहयोग की संभावनाओं को समग्रता में देखने का प्रयास किया है।

महानिदेशक की रिपोर्ट

नई प्रौद्योगिकियों और विकास के मुद्दे

आरआईएस ने इस स्तंभ में अपनी विशेषज्ञता के साथ नीति–निर्माण तथा वैश्विक आख्यानों को एक आकार देने अपनी छाप छोड़ी है और अपने मौजूदा अनुसंधान कार्य, उसकी पहुंच एवं क्षमता निर्माण का सफलतापूर्वक काफी विस्तार किया है। इस क्षेत्र में आरआईएस के अनुसंधान कार्यक्रम की आधारशिला, जो विज्ञान–नीति और विज्ञान–कूटनीति दोनों को समाहित करती है, उसकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रक्रियाओं एवं परिणामों मे। उसकी अनोखी पहुंच, समता और समावेशन रही है। इस स्तंभ के अंतर्गत क्षेत्रवार प्राथमिकताएं रही हैं, जिनमें बायोटेक्नोलॉजी, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और भू–आर्थिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, नैनो साइंस भी शामिल हैं। आरआईएस भारत सरकार के वैज्ञानिक मंत्रालयो। और विभागों के साथ गहरे जुड़ाव के साथ काम करता है। इसके साथ ही इस पंक्ति में आने वाले कुछ जरूरी मंत्रालयों और अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय के डिवीजन न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी (नेस्ट) और विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों के अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। हालिया अध्ययनों का अतिरिक्त ध्यान सहयोगी परियोजनाओं; जैसे प्रोडिगीज (उभरती ताकतों और यूरोप में सतत विकास के लिए डिजिटलीकरण के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना), न्यूहोराइज़नजन, उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार (पीआरआई), क्षमता प्रदर्शन आधारित नवाचार परियोजना (रिवार्ड) इत्यादि की तरफ भी दिया गया है।

पहुंच और क्षमता निर्माण

यद्यपि सांस्थानिक उपक्रम जैसे कि आसियान–इंडिया सेंटर, ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर (जीडीसी), फोरम फॉर इंडियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एफआईडीसी), फोरो फॉर साइंस डिप्लोमेसी (एफआईएसडी), ब्लू इकोनामी फोरम (बीईएफ), फोरम फॉर इन इंडियन ट्रेडीशनल मेडिसिन (एफआईटीएम) के साथ आरआईएस अपने कार्यक्रम तथा अपनी पहुंच को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर की जानकारियों के आदान–प्रदान और सभी के फायदों के लिए विकास के अनुभवों को साझा करना है। इसके अलावा, आरआईएस अपने समान प्रयासों के लिए अन्य संस्थाओं से भागीदारी के जरिए अनेक उपक्रम जारी रखे हुए है। इसमें उसने साउथ एशिया सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज (एसएसीपीईएस), ब्रिक्स, अकादमिक फोरम, बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक (बीएनपीटीटी), नेटवर्क ऑफ साउथ थिंक टैंक (नेस्ट) और इब्सा अकैडमी फोरम को शामिल किया है।

इस साल संस्थान ने आईटेक के विज्ञान पर आधारित प्रमुख कार्यक्रमों 'विज्ञान राजनय', 'दक्षिणीय सहयोग से अवगत होने', 'अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति', 'सतत् विकास लक्ष्य', 'व्यापार और निरंतरता', का आयोजन किया। इनके अलावा, नीति संवादों को प्रोत्साहित करने के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और व्यवहारों पर आधारित आरआईएस–एक्ज़िम बैंक समर स्कूल' के चौथे संस्करण का आयोजन भी कई अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ आयोजन किया गया।

हम अपने प्रयासों में व्यापक दूरदर्शिता लाने तथा अनेकानेक चुनौतियां, जो इस समय तथा मध्य अवधि में देश के समक्ष–घरेलू मोर्चे एवं बाहरी मोर्चे पर–मौजूद हैं, उनका अनुसंधान के जरिए हल निकालने तथा अपनी दूरदर्शिता के विस्तार के लिए आरआईएस की संचालन परिषद और रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल (आरएसी) से निरंतर निर्देशित होते रहे हैं। मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर मोहन कुमार को उनके सहयोग–समर्थन और संलग्नता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही, राजदूत सुधीर देवरे और आरएसी के अन्य सदस्यों को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करता हूँ। हम भारत सरकार, विशेष रूप से उसके विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आयुष मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अन्य सहयोगी संगठनों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

आरआईएस के विभिन्न कार्यक्रमों को बहुआयाम देने में कड़ी मेहनत करने के लिए हमारे संकाय के तथा सभी प्रशासनिक विभागों के साथियों को हार्दिक धन्यवाद देना बनता है।

सचिन चतुर्वेदी

अध्याय 1

नीतिगत अनुसंधान

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

क्या जी20 वैश्विक सुधारों के साथ–साथ वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं को भी आवश्यक संबल दे सकता है? आरआईएस ने विकास सहयोग में कटौती और एसडीजी पर विस्तृत खाका पेश किया

व्यापार, निवेश और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस की सुदृढ़ व्ययवस्थाएं होना अत्यंत आवश्यक है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) दरअसल विकास सहयोग के विभिन्न प्रारूपों विशेषकर दक्षिणीय सहयोग और त्रिकोणीय सहयोग हेतु आवश्यक भावी सुधारों की परिकल्पना करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में जी–20 वैश्विक गवर्नेंस की संरचनाओं एवं संस्थानों में सुधारों पर जारी संवाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी–20 के अधिदेश का दायरा और कवरेज पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नियम–कायदे बहाल करने एवं वृहद अर्थव्यवस्था संबंधी नीतिगत सामंजस्य स्थापित करने से लेकर ठोस विकास पहल करने तक के कार्य अब इसके दायरे में आ गए हैं। जी–20 के अधिदेष को व्यापक बनाने के साथ ही वित्तपोषण एवं समन्वय की नई चुनौतियां भी सामने आ गई हैं जिसके लिए निरंतर आगे की कार्यवाही और सावधानीपूर्वक आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में आरआईएस अपनी वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस बुनियाद के एक हिस्से के रूप में जी–20 के घटनाक्रमों पर बड़ी उत्सुकता से करीबी नजर रखता है। चूंकि जी–20 विकसित अर्थव्यवस्थाओं और उभरती एवं विकासषील दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के सृजन और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है, इसलिए जी–20 पर इस कार्यकलाप कार्यक्रम के तहत एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि समावेशी विकास, वित्तीय स्थिरता, बुनियादी ढांचागत विकास, रोजगार सृजन, निवेश संवर्धन, जलवायु परिवर्तन, कर अनुपालन, स्वास्थ्य एवं षिक्षा, खाद्य सुरक्षा, कौशल निर्माण, और सतत विकास जैसे सामूहिक कार्रवाई वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पूरी जानकारी के साथ नीतिगत संवाद संभव हो सके। आरआईएस व्यापार, प्रौद्योगिकी और वित्त पर वैश्विक संस्थागत रूपरेखा को अच्छी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए पिछले दो वर्षों से अनुसंधान अध्ययनों की एक श्रृंखला शुरू करने में काफी बारीकी से संलग्न रहा है जिनमें अल्पकालिक शोध पत्र और पूर्ण शोध लेख दोनों ही शामिल हैं। इस तरह के अध्ययन एसडीजी में उल्लिखित विकास एवं निरंतरता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गहन वैश्विक साझेदारी सृजित करने के साथ–साथ बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग में कमी की पहचान करने के लिए साक्ष्य आधारित विश्लेशण प्रदान करते हैं। अफ्रीका के साथ–साथ पड़ोस में क्षेत्रीय सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है और इसके साथ ही यह दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोग की रूपरेखा में उपर्युक्त कुछ थीम पर जी–20 और संयुक्त राष्ट्र में विचार–विमर्ष में प्रभावकारी योगदान दे रहा है। इस खंड में विभिन्न थीम पर थिंक टैंक 20 (टी20) के नीतिगत सारपत्र के जरिए जी–20 प्रक्रिया के साथ आरआईएस के मौजूदा जुड़ाव, एसडीजी पर आरआईएस के कार्यकलाप कार्यक्रम और दक्षिणीय सहयोग पर आरआईएस के कार्यकलाप कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया है।

जी20 के अधिदेश को व्यापक बनाने के साथ ही वित्तपोषण और समन्वय की नई चुनौतियां भी सामने आ गई हैं। वहीं, अपने वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस स्तंभ के एक हिस्से के रूप में आरआईएस निरंतर जी20 के घटनाक्रमों पर अत्यंत करीबी नजर रखता है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

आरआईएस विशेषकर वर्ष 2022 में भारत द्वारा जी–20 की अध्यक्षता संभाले जाने के मद्देनजर जी–20 के साथ भारत के जुड़ाव की प्राथमिकताओं की पहचान करने में संलग्न रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में आरआईएस के संकाय सदस्यों ने जी–20 के विभिन्न आयामों पर फोकस करने में रुचि दिखाई है।

विगत जी–20 शिखर सम्मेलनों की तरह ही आरआईएस भी सऊदी अरब की वर्तमान जी–20 अध्यक्षता के लिए टी20 को आवश्यक जानकारियां प्रदान करने में जुटा हुआ है। यह अत्यंत संतोष की बात है कि आरआईएस ने टी20 के अलग–अलग कार्यदलों में निम्नलिखित नीतिगत सारपत्रों का योगदान दिया है, और अन्य उभरते बाजारों एवं विकासशील देशों सहित कई वैश्विक मुद्दों पर भारत के हितों और अगुवाई को आगे बढ़ाने में अनुकरणीय नेतृत्व दिखाया है। आरआईएस इसके साथ ही 'आरआईएस जी20 नीतिगत सारपत्र श्रृंखला' के रूप में उनके संशोधित संस्करणों को प्रस्तुत करेगा।

जी–20 का नेतृत्व और संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी रोडमैप के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पर वैश्विक पायलट कार्यक्रम की प्रासंगिकता

प्रौद्योगिकी और जी20 के सामने विकल्प – उभरते एजेंडे पर आरआईएस का रोडमैप

प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ. सब्यसाची साहा

एजेंडा 2030/एसडीजी के एक हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी सुविधा व्यवस्था (टीएफएम) और अन्य समान पहलों जैसे कि यूएनएफसीसीसी के एलडीसी प्रौद्योगिकी बैंक, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र एवं नेटवर्क (सीटीसीएन); राष्ट्रीय क्लीनर उत्पादन केंद्र पहल; हरित उद्योग प्लेटफॉर्म; वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ); और ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) को कई गुना मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी सार्थक प्रभाव अवश्य हो सके। यह वित्तपोशण की समुचित व्यवस्थाओं के बिना नहीं हो सकता है; आकलन की आवश्यकता है, हितधारक की भागीदारी जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मूल्य श्रृंखलाओं के लिए ठोस कार्य करने वाले संबंधित कर्ता या लोग वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं (जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल–संभर के प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि से निपटते हैं) के सृजन एवं प्रसार के लिए दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। विकसित देशों की विषेश भूमिका उपर्युक्त एजेंडे को सुविधाजनक बनाने (उपयुक्त वैश्विक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर एवं अपेक्षित ओडीए प्रतिबद्धताओं को पूरा करके) के संदर्भ में है, जबकि विकासशील देशों को विकास और निरंतरता से जुड़े उपायों में प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोणों के आंतरिकीकरण के लिए व्यापक प्रयास करना चाहिए। भारत जैसे कई विकासशील देशों ने लंबे समय से कायम पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करने के तरीकों पर नीतिगत सबक के साथ बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी आधारित विकास परिवर्तनों का अनुभव पहले से ही कर लिया है।

जी–20 को तीन स्तरों पर एसडीजी रोडमैप हेतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) को बढ़ावा देने के लिए कार्यकलाप एजेंडे का नेतृत्व करना चाहिए:

- पहला, एसडीजी में अंतर के विश्लेषण और एसडीजी रोडमैप हेतु उपयुक्त एसटीआई के सृजन के लिए राष्ट्रीय प्रयास।
- दूसरा, विभिन्न देशों को टीएफएम के संचालन के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस प्रस्ताव तैयार करने; और बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) की वित्तपोशण व्यवस्थाओं सहित सभी अंतरराष्ट्रीय समझौतों में लचीली प्रौद्योगिकी हस्तांतरण धाराओं को शामिल करने में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य एजेंसियों का समर्थन करना चाहिए।
- तीसरा, विभिन्न देशों को क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने, संयुक्त अनुसंधान, और स्वदेशी एसटीआई एवं इसके लिए विकास साझेदारी के समेकित साधनों के संदर्भ में विकास सहयोग के जरिए एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

कुछ विशेष संदर्भों में संसाधनों की भारी कमी को दूर करने के लिए वित्तपोषण के अभिनव साधनों के साथ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाना चाहिए।

वर्ष 2030 तक उपलब्ध सीमित समय को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही वर्ष 2019 में इस नए राजनीतिक घोषणा–पत्र को संबल प्रदान कर दिया है – 'सतत विकास हेतु ठोस कदमों और डिलीवरी वाले दषक के लिए कमर कसना'। इसके अलावा, एसडीजी के लिए एसटीआई को बढ़ावा देने में जी–20 के राजनेताओं द्वारा व्यक्त किए गए सुदृढ़ स्वामित्व के मद्देनजर यह अत्यंत आवश्यक है कि इस अधिदेश को उन सदस्य देशों द्वारा आगे बढ़ाया जाए, जिनका वैश्विक गवर्नेंस की संरचना और एसडीजी रोडमैप हेतु एसटीआई के संचालन के लिए कार्यान्वयन (एसडीजी 17) के साधनों पर व्यापक प्रभाव है। विभिन्न अवसरों और चुनौतियों का विश्लेशण इस संबंध में जी–20 में सामूहिक कदमों के बारे में आवश्यक जानकारियां देगा और इन्हें समुचित स्वरूप प्रदान करेगा।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

व्यापार जी–20 में विकास की गति को तेज करेगा: जीवीसी और प्रौद्योगिकी आधारित व्यापार पर फोकस

क्या विकासशील देश अधिक व्यापार करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में सक्षम हैं? – हां, वे ऐसा करते हैं! जी20 के लिए आरआईएस का एक एजेंडा

प्रोफेसर एस.के. मोहंती

पिछले सात दशकों के वैश्विक अनुभवों से यह संकेत मिलता है कि जीवीसी और प्रौद्योगिकी आधारित सेक्टरों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में वैश्विक व्यापार के बड़े हिस्से को शामिल करने की प्रवृत्ति होती है और वे आर्थिक विकास के पटरी पर आने के साथ–साथ वैश्विक उछाल की अवधि के दौरान भी आकर्शक वृद्धि दर दर्ज कर रहे हैं। जीवीसी और प्रौद्योगिकी आधारित सेक्टरों में व्यापार 21वीं सदी के क्षेत्रीय एकीकरण समझौतों (आरआईए) के साथ तेजी से बढ़ सकता है जो व्यापार में विस्थापन या कमी का मुकाबला करने के लिए उत्पाद के मूल स्थान के सख्त नियमों के साथ व्यापक नियामकीय व्यवस्था से भी लैस हैं। व्यापार अनुकूल माहौल अत्यंत आवष्यक है, ताकि अपेक्षाकृत ज्यादा विघटन तरीके से उत्पादन संबंधी कार्यों को अलग–अलग करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागत कम करना, उत्पादन स्तर बढ़ाना, समस्त भौगोलिक सीमाओं में उत्पादन नेटवर्क को बढ़ाना और स्थानीय फर्मों को निर्धारित अवधि में क्षेत्रीय एमएनसी (बहुराष्ट्रीय कंपनी) बनने के अवसर प्रदान करना है। व्यापार में विस्थापन या कमी का मुकाबला करने के तहत क्षेत्रीय एकीकरण समझौते (आरआईए) कलपुर्जों और उपकरणों (पीएंडसी) के उत्पादन–व्यापार के गठजोड़ को आगे बढ़ाने में एक उपयुक्त नीतिगत रणनीति साबित हो सकते हैं। जीवीसी उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार को नई गति प्रदान करने के लिए कई देषों ने एक साथ रणनीतिक 'औद्योगिक नीतियों' और 'व्यापार नीतियों' को आगे बढ़ाने का सहारा लिया है। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ उपरांत अवधि में क्षेत्रवाद के बढ़ते चलन के साथ–साथ प्रौद्योगिकी आधारित सेक्टरों में व्यापार कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास का वाहक बनता जा रहा है। नई सहस्राब्दी की शुरुआत से ही जी–20 सदस्य देशों का व्यापार विशेषकर मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी गहन निर्यात की अगुवाई में अपेक्षाकृत अधिक प्रौद्योगिकी आधारित होता जा रहा है। प्रौद्योगिकी गहन उत्पाद दरअसल व्यापार की शर्तों को निर्यातक देशों के पक्ष में करने और प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों से मार्जिन का स्तर बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। जीवीसी और प्रौद्योगिकी गहन सेक्टरों के जरिए व्यापार में तेज वृद्धि 'केंद्र–परिधि की परिकल्पना' को तोड़ने में सहायक होगी और इसके साथ ही इससे जी–20 देषों के बीच क्षेत्र के अंदर व्यापार को बढ़ावा मिलने की भी संभावना है। व्यापार के सर्वाधिक गतिशील हिस्से के जरिए इन देशों के बीच व्यापार में तेजी लाने के लिए नीतिगत गुंजाइश करने की जरूरत है। आर्थिक विकास को पटरी पर लाने में आवश्यक सहयोग देने के लिए इस मॉडल को दुनिया के बाकी हिस्सों में भी अमल में लाया जा सकता है।

> **विभिन्न देशों के अनुभवों से यह संकेत मिलता है कि जीवीसी व्यापार समस्त भागीदार देशों को समान अवसर प्रदान करता है जबकि वहां आर्थिक विकास का स्तर एक जैसा नहीं है।**

जी–20 फोरम विश्व अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते संरक्षणवाद के मद्देनजर बहुपक्षीय प्रणाली के कमजोर पड़ने के कारण व्यापार प्रवाह धीरे–धीरे घटता जा रहा है। इस स्थिति में 'क्षेत्रवाद' वैश्विक गवर्नेंस की व्यापक संरचना के तहत तरजीही व्यापार को विकसित होने की नीतिगत गुंजाइश प्रदान करके इस अनचाही स्थिति से बचा सकता है। विभिन्न देशों के अनुभवों से यह संकेत मिलता है कि जीवीसी व्यापार दरअसल उन प्रतिभागी देशों को समान अवसर प्रदान करता है जहां आर्थिक विकास का स्तर एक जैसा नहीं है। जी–20 देशों को निम्न से उच्च प्रौद्योगिकी गहन व्यापार की ओर जाने हेतु प्रेरित करने के लिए सोच–समझकर नीतिगत फोकस करने से इन देशों को 'मध्य आय वर्ग वाले जाल' से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

सतत खाद्य सुरक्षा के लिए ऊर्जा, जल और खाद्य में सामंजस्य

कृषि–खाद्य–जल के पारस्परिक संबंध और जी20 इसमें कैसे मदद कर सकता है?– आरआईएस ने राह दिखाई

डॉ. पी.के. आनंद और श्री कृष्ण कुमार

जी–20 घोषणाओं के वैश्विक विजन से लेकर ओसाका शिखर सम्मेलन, और कृषि मंत्रियों के घोषणा–पत्र, निगाता, 2019 तक के अनुरूप नीतिगत सारपत्र में सतत ऊर्जा एवं जल प्रबंधन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चुनौतियों, प्रस्तावित रणनीतियों एवं कदमों का विश्लेशण किया जाएगा। इसमें सतत और समावेशी तरीके से उभरती एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग और वैश्विक कृषि–खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं के सुदृढ़ीकरण के जरिए जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर निवेश सहित विभिन्न उपायों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत फोकस न केवल कैलोरी की जरूरतों और पोषण के पहलू को पूरा करने पर, बल्कि अधिक वजन/मोटापे की बढ़ती प्रवृत्तियों से निपटने में भी किया जाएगा। इसके तहत आगे चलकर संसाधन के इश्टतम उपयोग, भरण–पोषण, गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों ही पहलुओं पर साझाकरण और इस तरह के तालमेल का उपयोग करने एवं अनुसंधान संस्थानों से बेहतर जुड़ाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को भी कवर किया जाएगा। इसी तरह उपयोग किए जा सकने वाले जल की उपलब्धता के लिए ठोस कदमों को भी कवर किया जाएगा, ताकि यह स्थायी बाधा न बन जाए। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने में विषेशकर महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी के जरिए जी–20 सहयोग को गहरा करने के उपायों, और सतत ऊर्जा, जल एवं कृषि में एसटीआई पहलों को फलीभूत करने की नई प्रवृत्ति को भी उन रणनीतियों में शामिल किया जाएगा जिन्हें बाद में कवर किया जाएगा। आवश्यक अल्पकालिक एवं मध्यमकालिक रणनीतियों पर दिए जा रहे विशेष जोर देने के मद्देनजर नीतिगत सारपत्र में '11 अरब के लिए खाद्य सुरक्षा (एफएस4ग्प्बी)', जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमानित वैश्विक चरम आबादी है, के लिए तैयार रहने के दीर्घकालिक मार्ग या उपाय को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा, चूंकि 'जल–खाद्य–ऊर्जा–जलवायु में सामंजस्य' एक अपेक्षाकृत नई, उभरती और इस तरह से अधूरी रूपरेखा है, इसलिए पूर्ण, प्रासंगिक और विधिवत अलग–अलग किए गए डेटा की उपलब्धता सुनिष्चित करने की आवश्यकता है। इसे ही ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त कार्यप्रणाली अपनाने के लिए पारंपरिक या किसी और माध्यम से डेटा संग्रह एवं प्रसार के वैज्ञानिक तरीकों की ओर बढ़ने का प्रस्ताव किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं पोषण और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता को जी–20 फोरम आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानता है। इसके अलावा, वैश्विक कृषि भूमि के 60 प्रतिशत से भी अधिक हिस्से पर काबिज रहने वाले और कृषि–व्यापार के 80 प्रतिशत हिस्से को संभालने वाले जी–20 देशों के लिए यह अत्यंत प्रासंगिक है। जी–20 ऊर्जा, जल, खाद्य और पोषण सुरक्षा के प्रयासों को नई गति प्रदान करने के लिए कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठकें आयोजित करता है जिसे ध्यान में रखते हुए यह विश्लेशण करना जरूरी है कि ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन इस समस्या को बढ़ा रहा है, नई प्रौद्योगिकियां इसे संभालने के अवसर प्रदान करती हैं।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह को बढ़ावा देना

जी20 में सतत निवेश के लिए नियम बनाना – आरआईएस का नजरिया

श्री ऑगस्टीन पीटर

एफडीआई निश्चित तौर पर निरंतरता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। विकास प्रक्रिया में निरंतरता के उद्देश्य को तेजी से मिल रही मान्यता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि एफडीआई का प्रवाह निरंतरता के उद्देश्यों को पूरा करे, और इसमें एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे। वैसे तो सतत विकास की दृष्टि से कुछ स्तरों की देखरेख में एफडीआई प्रवाह को लाने के लिए कुछ देशों, विशेषकर यूरोपीय संघ द्वारा छिटपुट प्रयास किए गए हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रयास करने और इस तरह के उपायों पर सर्वसम्मति विकसित करने के लिए जी–20 जैसे उपयुक्त फोरम की तत्काल आवष्यकता है। जी–20 देषों द्वारा अन्य बातों के अलावा इन प्रस्तावों पर गौर करने की आवश्यकता है:

(i) सतत निवेश पर मेजबान देश के मानकों को अद्यतन (अपडेट) किया जाना चाहिए क्योंकि आम तौर पर निवेशकों पर घरेलू मानकों से अधिक लागू करना संभव नहीं होता है। हालांकि, घरेलू मानकों के बावजूद एफडीआई के लिए निरंतरता मानकों को भी निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। एफडीआई पर लगाई जा सकने वाली किसी भी व्यापार पाबंदी के लिए निरंतरता उद्देश्य को रियायतों (गैट्स अनुच्छेद ग्प्ट (बी)) के तहत कवर किया जाना चाहिए; (ii) ऐसे नियम जो यह निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं कि क्या कोई आर्थिक गतिविधि टिकाऊ है उसे जी–20 देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए; (iii) विदेशी निवेशकों को उसी हद तक राजकोशीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जिस हद तक उनका निवेश निरंतरता मानकों के अनुरूप हो; (iv) स्वदेष की निवेश संवर्धन एजेंसी (आईपीए) को उन परियोजनाओं के साथ पूरी तरह तैयार रखना होगा जो निरंतरता के अनुरूप हैं; (v) एफडीआई के लिए मेजबान देशों द्वारा सतत ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और मेजबान देशों को टिकाऊ अवसंरचना में एफडीआई को प्राथमिकता देनी चाहिए।

एफडीआई के कुल बाहय प्रवाह में दो तिहाई योगदान जी–20 के सदस्य देशों का है। समूह में प्रमुख गृह देष और मेजबान देश शामिल हैं जिनमें विकसित एवं उभरते दोनों ही राष्ट्र सम्मिलित हैं। हांग्जो में समूह ने वैश्विक निवेश नीति निर्माण के लिए विभिन्न सिद्धांतों को अपनाया। सतत विकास जी–20 का मुख्य लक्ष्य है, और जी–20 अपने कार्यकलाप कार्यक्रम को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि एसडीजी 2030 में निहित है, और जैसा कि विभिन्न शिखर बैठकों में दोहराया गया है। इस प्रकार जी–20 निःसंदेह उस गुणवत्तापूर्ण एफडीआई प्रवाह पर आम सहमति बनाने के लिए उपयुक्त फोरम है जो सतत विकास को सुविधाजनक बनाता है।

जी20 उत्कृष्ट एफडीआई के प्रवाह पर आम सहमति बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त फोरम है जो सतत विकास को सुविधाजनक बनाता है

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

एसडीजी को बढ़ावा देने के लिए जी–20 देशों में प्रवासन से जुड़ी सामान्य लेकिन अलग–अलग रणनीतियां

एक बिल्कुल अलग जन–आवाजाही (पीपुल्स मूवमेंट): प्रवासन और जी20 की राय – आरआईएस द्वारा एक अन्वेषण

प्रोफेसर अमिताभ कुंडू

जी–20 में प्रवासन पर फोकस पहले आंतरिक सुरक्षा और धन प्रेशण (जो हाल के दशकों में उल्लेखनीय कमी के बावजूद 3 प्रतिशत के एसडीजी लक्ष्य के दोगुने से भी अधिक है) को लेकर था जो धीरे–धीरे अब विकास से जुड़े बड़े मुद्दे को लेकर हो गया है। विश्व भर में फैले 260 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से 65 प्रतिशत जी–20 देशों में ही रहते हैं। हाल के दशकों में जी–20 देशों में प्रवासियों की संख्या वृद्धि दर ऊंची होने के बावजूद आबादी में उनकी हिस्सेदारी अब भी काफी कम 3.5 प्रतिशत ही है। रोचक बात यह है कि जी–20 देशों में प्रवासी आबादी की औसत आयु हाल के दशकों में बढ़ गई है एवं इसके आगे और बढ़ने का अनुमान है। अपने परिवारों के बिना ही प्रवासन करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ने के कारण ही यह स्थिति देखने को मिल रही है। स्थानीय आबादी की तुलना में उन्हें ही नौकरी पर रखे जाने की अधिक संभावना होती है। हालांकि, इस वजह से स्थानीय श्रम बाजार में तनाव का माहौल बन जाता है। 26 मिलियन की कुल वैश्विक शरणार्थी आबादी में से 7.3 मिलियन ने जी–20 देशों को ही अपना गंतव्य बनाया है। हालांकि, इनमें से ज्यादातर जी–20 के भीतर या बाहर गरीब देशों में रहते हैं। वर्तमान नीतिगत सारपत्र में आयु एवं महिला–पुरुष सहित विभिन्न श्रेणियों, क्षेत्रों और अन्य सामाजिक–जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत प्रवासन के बदलते रुझानों और स्वरूप के बारे में उल्लेख होगा। इसके अलावा, यह युवा एवं श्रमिक अधिशेष वाली अल्प विकसित जी–20 अर्थव्यवस्थाएं बनाम विकसित एवं उम्रदराज लोगों वाली जी–20 अर्थव्यवस्थाओं में प्रवासन के निहितार्थों का विश्लेशण करेगा, ताकि '2030 एजेंडे' में शामिल करने के लिए वित्तीय बोझ को उचित और न्यायसंगत तरीके से साझा करने से संबंधित सिफारिशें पेश की जा सकें। प्रवासन और विकास नीतियों के बीच सामंजस्य एवं संयोजन वैश्विक स्तर पर अत्यंत कमजोर रहा है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे में निहित 'प्रवासन के लिए विश्वस्तरीय समझौते' में प्रवासन के रुझानों एवं स्वरूप और उनके निहितार्थों का जायजा लेने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। नीतिगत सारपत्र में डेटाबेस की निगरानी सहित इस कार्य को शुरू करने के लिए एक प्रणाली की रूपरेखा पेश की जाएगी।

प्रवासन दरअसल विकास प्रक्रिया की एक निर्धारक विशेषता है, जो एसडीजी को प्राप्त करने की कुंजी है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन गंतव्य देशों में आवश्यक कौशल के अनुरूप उन कामगारों को ढाल कर जनसांख्यिकीय असंतुलन को दूर कर सकता है जो अपने–अपने मूल देशों में सरप्लस में हैं। जी–20 देशों में स्वचालन (ऑटोमेशन) कम कुशल कामगारों की अंतरराष्ट्रीय भर्ती की दीर्घकालिक आवष्यकता को कम कर सकता है, जबकि राष्ट्रीय सीमाओं से परे विभिन्न कार्यों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाला 'डिजिटल श्रम प्रवासन' आगे चलकर वास्तविक प्रवासन को कम कर सकता है। नागरिकता कानूनों पर सख्ती से अमल के जरिए आव्रजन को सीमित करने के लिए बॉयोमीट्रिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है। नीतिगत सारपत्र निर्णय लेने में सुविधा के लिए एक अनुसंधान प्लेटफॉर्म और डेटाबेस की रूपरेखा प्रदान करेगा।

विभिन्न देशों में स्वचालन (ऑटोमेशन) से कम कुशल कामगारों की अंतरराष्ट्रीय भर्ती की दीर्घकालिक आवश्यकता कम हो सकती है, जबकि राष्ट्रीय सीमाओं के पार विभिन्न कार्यों की आउटसोर्सिंग के जरिए डिजिटल ढंग से कामगारों का प्रवासन (माइग्रेशन) होने से वास्तविक प्रवासन कम हो सकता है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

जलवायु परिवर्तन से निपटना और आर्थिक विकास: यूएनएफसीसीसी से परे जाना

जलवायु परिवर्तन और जी20 – आम सहमति को कारगर बनाना : आरआईएस ने विभिन्न विचारधाराओं को आपस में जोड़ा

डॉ. भास्कर बालाकृष्णन

'यूएनएफसीसीसी' के तहत मौजूदा अंतर–सरकारी प्रक्रियाएं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ प्रतीत होती हैं। वहीं, दूसरी ओर समय तेजी से गुजरता जा रहा है। अतः अब ऐसे दृष्टिकोण या उपाय ढूंढे जाने चाहिए जो आवश्यकता से परे हों। इनमें ये शामिल हैं – समान विचारधारा वाले देशों द्वारा अपनी ओर से अपेक्षाकृत अधिक ठोस कदम उठाना और सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी न होने वाली संधि करना जो आपसी सहमति वाले मुद्दों पर एक साथ काम करने देशों के खुले (अबाध–प्रवेश वाले) समूहों पर आधारित हो। विभिन्न देशों के भीतर उप–राष्ट्रीय या राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्राधिकरणों के उत्साहवर्धक कदमों और सिविल सोसायटी के साथ बढ़ते सहयोगात्मक कदमों के सकारात्मक परिणाम विशेषकर उन देशों में देखने को मिल सकते हैं जहां सरकारें इस दिशा में आवश्यक उपाय करने में अनिच्छुक प्रतीत होती हैं। ऐसी कई अच्छी प्रथाएं या तौर–तरीके हैं जिन्हें बेहतर और साझा किया जा सकता है। सिविल सोसायटी की चिंताओं और रचनात्मक कार्यकलापों में अंतर्निहित हताशा को दूर करने के उपाय करने की आवश्यकता है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में कमी के उपाय करने एवं इन्हें अपनाते समय रोजगार और आय सहित आर्थिक विकास एवं प्रगति की जरूरत की अनदेखी कतई नहीं करनी चाहिए। वैज्ञानिक स्तर पर वैश्विक जलवायु मॉडलों पर बहुत अधिक काम किए जाने की आवष्यकता है, ताकि वैश्विक तापमान वितरण और जलवायु से जुड़ी घटनाओं पर ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में हुई वृद्धि के प्रभावों की गणना और भी ज्यादा सटीक तरीके से की जा सके। उदाहरण के लिए, सीओ2 समतुल्य 450 पीपीएमवी और वैश्विक तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि के बीच की कड़ी तो महज एक मोटा अनुमान है और इससे जुड़ी जानकारियों या आकलन को बेहतर करने की आवश्यकता है। बेहतर जलवायु मॉडल दरअसल जलवायु से जुड़ी चरम घटनाओं से निपटने के प्रयासों में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। प्रत्यक्ष वायु अभिग्रहण, सौर फोटोवोल्टिक सेल में सुधार या बेहतरी और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित कार्बन अभिग्रहण एवं संचय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अभी और भी व्यापक अनुसंधान और विकास किए जाने की आवश्यकता है। इनमें से किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने के प्रबल आसार हैं और यह व्यापक बदलाव लाने में सक्षम यानी 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है। हालांकि, इनमें निवेष को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है।

जी–20 का विश्व जीडीपी (सांकेतिक) में 85 प्रतिशत और वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में 81 प्रतिशत योगदान है। वे आर्थिक विकास और समृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के मूल में हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों हेतु अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों में वृद्धि लाने, आर्थिक विकास की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय करने, और जलवायु परिवर्तन के लिए सिविल सोसायटी की सहभागिता पर जी–20 में सहमति है। इस दिशा में अपेक्षित कदमों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों को काफी मजबूती मिलेगी, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक भागीदारी एवं सहयोग करने को प्रोत्साहन मिलेगा।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

फिनटेक क्रांतिः विकासशील देशों में अवसर और जोखिम

फिनटेक ने जी20 में 'वित्त' और 'विकास' एजेंडे को आपस में जोड़ाः विकासशील देशों के लिए विकल्पों पर आरआईएस की राय

डॉ. प्रियदर्शी दाश

पिछले 20 वर्षों से जी–20 अपने सदस्य देशों और विश्व अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के भविष्य को निरंतर बनाए रखने के लिए अनुकूल निरीक्षणात्मक एवं नियामकीय व्यवस्थाओं से युक्त सुदृढ़, लचीला और अनुरूप वित्तीय प्रणालियों को अपनाने की वकालत करता रहा है। जी–20 का एक प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर में उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियों (फिनटेक) सहित वित्तीय सेक्टरों के क्रमिक विकास को बढ़ावा देने के साथ–साथ सुसंगत वैश्विक नियामकीय व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। चूंकि फिनटेक और बीमा प्रौद्योगिकी (इंश्योंरटेक) सेक्टरों के विकास को वित्तीय समावेश, महिला सशक्तिकरण, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को बढ़ावा देने, कौशल विकास जैसे प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से जोड़ा जा सकता है, इसलिए जी–20 को निश्चित तौर पर फिनटेक को एक प्राथमिकता वाले सेक्टर के रूप में देखना चाहिए और संभवतः फिनटेक, विशेषकर उद्योग के आयामों, वित्तीय समावेश और नियामकीय रूपरेखा पर एक टास्क फोर्स एवं कार्यदल के माध्यम से सदस्य देशों व समकक्ष गैर–जी20 विकासशील देशों के बीच आम सहमति बनानी चाहिए। चूंकि साझा थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं की ओर से उत्पन्न बैंकिंग और वित्तीय लेन–देन जोखिमों विशेषकर साइबर जोखिमों का स्वरूप एवं दायरा काफी बढ़ गया है, इसलिए अब विभिन्न देशों के लिए सार्वजनिक नीति से जुड़ी बड़ी चुनौतियां डेटा गोपनीयता की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और एंटी मनी–लॉन्ड्रिंग का अनुपालन एवं आतंकवाद प्रतिबद्धताओं के वित्तपोषण से निपटना हैं। चूंकि फिनटेक एवं इंश्योरटेक सेवाएं आम तौर पर साझा थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं का इस्तेमाल करती हैं और इसमें साइबर स्पेस से जुड़ा व्यापक जोखिम होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी, अवैध वित्तीय प्रवाह और सीमा पार पलायन सहित आर्थिक भगोड़ा संबंधी अपराधों का खतरा बहुत अधिक रहता है। जी–20 को फिनटेक सेक्टर की विकास संभावनाओं को संज्ञान में लेना चाहिए और संदिग्ध एवं अवैध लेन–देन की रोकथाम में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए।

जी–20 वर्ष 2008–09 में वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद समन्वित वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिष्चित करने में स्वयं को मिली शानदार सफलता के लिए जाना जाता है। इसके बाद जी–20 ने दुनिया में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषण की टिकाऊ व्यवस्थांएं करने की वकालत की है। जी–20 ने इसके साथ ही विनिर्माण और सेवाओं से जुड़े विभिन्न आर्थिक प्रभागों या खंडों में तकनीकी नवाचारों की विशेष अहमियत को भी रेखांकित किया है। फिनटेक, जिसमें सूचनाएं एवं वित्त शामिल हैं, दरअसल जी–20 के वित्त और विकास एजेंडे के अनुरूप है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

टिकाऊ और बेहतरीन अवसंरचना के लिए अभिनव वित्तपोषण

अवसंरचना के लिए कम पड़ रही धनराशि को कैसे पूरा करें? आरआईएस ने नवाचार और गुणवत्ता पर फोकस करने की दलील दी!

डॉ. प्रियदर्शी दाश

चूंकि अवसंरचना या बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में निवेश जी–20 और दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक पसंदीदा नीतिगत कदम या उपाय आगे भी बना रहेगा, इसलिए अब सारा जोर अभिनव वित्तपोषण का पता लगाने पर है। बैंक ऋणों और रियायती द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋणों के रूप में पारंपरिक वित्तपोषण दरअसल पूरी तरह से वित्तपोषण के सारे पहलुओं को कवर नहीं कर सकता है। इसके लिए रूढ़िवादी या अपरिवर्तनवादी संस्थागत निवेशकों जैसे बीमा कंपनियों, पेंशन फंडों, इत्यादि और बेकार पड़ी घरेलू बचत के दोहन या उपयोग के संदर्भ में अभिनव उपाय करने होंगे। बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु खुदरा या छोटे निवेशकों को प्रेरित करने के लिए निवेश पर मिलने वाले रिटर्न के बारे में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक होगा। हालांकि, इस तरह के निवेश से जुड़े कथित जोखिम पहले से ही अधिक हैं। पूंजी बाजार के विभिन्न साधन विशेषकर स्थानीय मुद्रा वाले ऊर्जा वित्त बांड, सतत ऊर्जा, सुदृढ़ शहरी परिवहन प्रणालियां, अत्याधुनिक अवसंरचना परिसंपत्तियां, इत्यादि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु उपयुक्त एवं पर्यावरण–अनुकूल उपाय करने के लिए वित्तीय नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करेंगी। गुणवत्तापूर्ण या बेहतरीन और टिकाऊ बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभिनव वित्तपोषण के साधनों में आम तौर पर लैंड वैल्यू कैप्चर, सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जैसे कई प्रपत्र शामिल हो सकते हैं। अप्रयुक्त संसाधनों की पूलिंग करने के साथ–साथ इस तरह के प्रपत्रों की उपयुक्त मार्केटिंग अवसंरचना विकास के पारंपरिक मॉडल से जुड़े प्रतिकूल पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में नई सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, दूरसंचार एवं डिजिटल कनेक्टिविटी परिसंपत्तियों के निर्माण और इन परिसंपत्तियों के रखरखाव के तहत अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन चरणों में निरंतरता, सुदृढ़ता एवं गुणवत्ता आयामों को निश्चित तौर पर ध्यान में रखना चाहिए। जी–20 देशों की सरकारों, फर्मों और सिविल सोसायटी संस्थाओं द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें विकसित की जा रही टिकाऊ अवसंरचना में स्वामित्व लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। किफायती, कम कार्बन–गहन और कम प्रदूषणकारी तकनीकों के प्रचलन को लोकप्रिय बनाकर और लोगों एवं फर्मों के बीच स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन व उपभोग की आदतों को बढ़ावा देकर जी–20 देशों की सरकारें पर्यावरणीय स्थिरता एवं विकास में समानता और अवसंरचना के रखरखाव एवं हस्तांतरण से जुड़ी चिंताओं से निपटने में सक्षम होंगी।

जी–20 दरअसल अवसंरचना के विकास को क्षेत्रीय और वैश्विक प्राथमिकता का क्षेत्र मानता रहा है। वर्ष 2016 में जी–20 की चीनी अध्यक्षता और उसके पश्चात हुए राजनेताओं के शिखर सम्मेलनों के बाद सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्य योजना को अपनाए जाने के साथ ही अवसंरचना का विकास समग्र रूप से पूरी दुनिया के लिए सतत और समावेशी विकास एजेंडे का एक अभिन्न अंग बन गया है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं में जी–20 का योगदान बढ़ाने के लिए नए एवं अभिनव वित्तपोषण और साझेदारियों का पता लगाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, कौशल बढ़ाने एवं उद्यमिता और महिलाओं की भागीदारी पर जी–20 के फोकस के साथ–साथ बेहतरीन एवं अत्याधुनिक बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से आने वाले वर्षों में व्यापक सामाजिक, आर्थिक एवं संबंधित प्रभाव देखने को मिलेंगे। इससे न केवल अवसंरचना के विकास पर जी–20 की मौजूदा पहलों को मजबूती मिलेगी, बल्कि वंचित या पिछड़ रहे क्षेत्रों में विशिष्ट कनेक्टिविटी चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था और विषेशकर डिजिटल प्रौद्योगिकियां जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉक चेन, इत्यादि वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह जी–20 देशों और पूरी दुनिया का संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के जी–20 के आह्वान के साथ पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण तरीके से माकूल साबित होगा।

बैंक ऋणों के रूप में पारंपरिक वित्तपोषण और रियायती द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण दरअसल वित्त पोषण की समूची रेंज को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकते हैं।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में प्रौद्योगिकियों के जरिए तेजी लाना

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज – दोराहे पर जी20 एजेंडाः आरआईएस की दूरगामी राय

प्रोफेसर टी सी जेम्स

स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सा परामर्श, दवाएं, नर्सिंग, नैदानिक सेवाएं व नैदानिक उपकरण, सर्जिकल प्रक्रियाएं एवं सर्जिकल उपकरण और निगरानी शामिल हैं। यह निवारक स्वास्थ्य सेवा जैसे कि टीकों को भी कवर करेगी। बीमारियों के साथ जारी लड़ाई में अनुसंधान एवं विकास और क्लिनिकल परीक्षणों के जरिए नई दवाओं का विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नई तकनीकों जैसे कि जीन थेरेपी एडवांस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) का पता आखिरकार कैसे लगाया जा सकता है। इसमें चिकित्सा देखभाल से संबंधित क्षेत्रों में मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों का आकलन करना भी शामिल होगा। इनमें से कुछ दवाओं एवं उपकरणों के तहत और कुछ सेवा एवं दवा मुहैया कराने के तहत तथा कुछ रोगियों की निगरानी के तहत आएंगे। नए उत्पादों को विकसित करने में जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, दूरसंचार एवं आर्टिफिषियल इंटेलिजेंस का प्रभावकारी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है और उत्पादों एवं सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने पर अच्छी तरह से गौर करना होगा। एक अन्य क्षेत्र जिसमें नई प्रौद्योगिकियां अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं, वह चिकित्सा डेटा का प्रबंधन क्षेत्र है। कई देषों में स्वास्थ्य संबंधी डेटा को पूरी तरह से विश्वसनीय और सुसंगत बनाने के लिए इसमें व्यापक सुधार की आवष्यकता है। डिजिटल और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों से इस पर काफी हद तक असर पड़ने की संभावना है। पिछली प्रौद्योगिकियों से जुड़े अनुभवों से यह पता चला है कि वैसे तो नई प्रौद्योगिकियां महंगी हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ वे सस्ती होती जाती हैं तथा उत्पादों एवं सेवाओं को और भी अधिक किफायती व सुलभ बना देती हैं। इस संबंध में एक प्रमुख चिंता स्थानीय रूप से प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों को जरूरतमंदों को आसानी से हस्तांतरित करने से जुड़ी होगी। नीतिगत सारपत्र में प्रौद्योगिकियों और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सभी की किफायती पहुंच से संबंधित विभिन्न मुद्दों का पता लगाया जाएगा।

कई देशों में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े डेटा को पूरी तरह से विश्वसनीय और सुसंगत बनाने के लिए व्यापक सुधार की आवश्यकता है। डिजिटल और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का इस पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है।

जी–20 देश आम तौर पर आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से विकसित देशों के समूह से वास्ता रखते हैं। एक स्वस्थ वैश्विक आबादी होना विकासशील और विकसित दोनों ही देशों के हित में है। अतः स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दे समूह के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं क्योंकि यह सदस्य देशों में सरकारों, उद्योगों और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों को उभरते परिदृष्य के मद्देनजर अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को नई दिशा प्रदान करने में मदद करेगा। यह स्थिति विशेषकर अनुसंधान एवं विकास और सेवा मुहैया कराने की व्यवस्था के मामले में देखी जा रही है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

ज्वलंत मुद्दा आधारित गठबंधनों और प्रभावकारी क्षेत्रीय एकीकरण के जरिए वैश्विक व्यापार गवर्नेंस में सुधार करना

व्यापार गवर्नेंस में गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता: गठबंधन बनाने पर जी20 के लिए आरआईएस के सुझाव

श्री राजीव खेर, डॉ. सब्यसाची साहा और श्री अरुण एस. नायर

बेवजह देरी के कई प्रकरणों के मद्देनजर वर्तमान वैश्विक गवर्नेंस प्रणाली तकनीकी व्यवधानों सहित विभिन्न संदर्भों में विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझे जाने वाले विशिष्ट प्रस्तावों को तवज्जो देने की दृष्टि से अपर्याप्त है। इसे ध्यान में रखते हुए बहुपक्षीय संगठनों में विकासशील देशों की भागीदारी निरंतर बनाए रखने की दृष्टि से इसके व्यापक निहितार्थ हैं। अतः एक सुधारात्मक उपाय के रूप में प्रभावकारी व्यवस्थाओं, संस्थानों और क्षमताओं के निर्माण के लिए 'वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ)' के ऐसे नए गतिशील और मुद्दे–आधारित गठबंधन तैयार करने की आवश्यकता है जो विकासशील देशों की सौदेबाजी क्षमता को बढ़ा दे, ताकि उनके हितों की रक्षा के साथ–साथ उन्हें बढ़ावा मिल सके। समान विचारधारा वाले अन्य देशों के साथ मिलकर सुदृढ़ गठबंधन बनाने संबंधी हर विकासशील देश की महत्वाकांक्षा तभी परवान चढ़ पाएगी जब उन्हें विशेषकर अपने संबंधित क्षेत्र की आर्थिक प्रगति या समृद्धि में अधिक हिस्सेदारी मिलेगी। अतः क्षेत्रीय एकीकरण इस संबंध में विकासशील देशों की मदद करने का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। हालांकि, प्रभावकारी एवं समावेशी तरीके से क्षेत्रीय एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक गवर्नेंस को एक ऐसे नए संघीय ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित करना अत्यंत आवश्यक है जिसमें बहुपक्षीय/वैश्विक गवर्नेंस संगठनों की क्षेत्रीय शाखाएं शामिल हों और जिन्हें प्रत्येक चिन्हित क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेने एवं लागू करने के अधिकार हों। निर्णय लेने और उसे लागू करने का अधिकार इस तरह से सौंपने से न केवल उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान करने के लिए संबंधित व्यवस्थाओं में वैश्विक नीतिगत समन्वय को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि वैश्विक गवर्नेंस निकायों एवं उनके मानदंडों के लिए हर क्षेत्र और देश से अपेक्षाकृत अधिक सहमति भी प्राप्त होगी। इस उद्देष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए विकासशील देश–आधारित वैश्विक गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ–साथ अंतर–सरकारी निकायों को भी स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि बहुपक्षीय/वैश्विक गवर्नेंस संगठनों को नीतिगत जानकारियां (इनपुट) देने के साथ–साथ विकासशील देशों के पक्ष में जी–20 जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

> **प्रभावकारी व्यवस्थाओं, संस्थानों एवं क्षमताओं के निर्माण के लिए वैश्विक दक्षिण के नए गतिशील और मुद्दा–आधारित गठबंधन तैयार करने की आवश्यकता है**

दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप (समूह), जिसमें विकासशील देशों का भी प्रतिनिधित्व (हालांकि अपर्याप्त) है, होने के नाते जी–20 का वैश्विक नीति निर्माण में व्यापक प्रभाव है। विश्व भर में अब यह माना जाने लगा है कि जलवायु परिवर्तन, टैक्स, स्वास्थ्य, इत्यादि से जुड़ी चुनौतियों, जिन्हें पहले देश–विशेष की जवाबदेही के रूप में देखा जाता था, का समाधान अब केवल समन्वित वैश्विक उपायों के माध्यम से ही किया जा सकता है। हालांकि, बहुपक्षीय/वैश्विक गवर्नेंस प्रणाली को और भी अधिक समावेशी एवं लोकतांत्रिक बनाने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को 'टॉप–डाउन' व्यवस्था, जो सिर्फ शीर्ष पर बैठे अधिकारियों द्वारा नियंत्रित होती है, के बजाय अब प्रभावकारी 'बॉटम–अप' व्यवस्था की ओर उन्मुख करने की आवश्यकता है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

जी–20 में एसडीजी और विकास सहयोग के लिए एक गवर्नेंस संरचना का संस्थागतकरण: एक बहु–केंद्रित दृष्टिकोण

वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं और वैश्विक सार्वजनिक संसाधनों को बनाए रखना – क्या जी20 बहु–केन्द्रीयता का प्रबंधन कर सकता है? आरआईएस ने श्रेणीबद्ध गवर्नेंस से परे जाने के बारे में अपनी राय दी

डॉ. मिलिंदो चक्रबर्ती

प्रस्तावित नीतिगत सारपत्र एक प्रभावकारी संस्थागत संरचना विकसित करने में संलग्न होगा जिसका पालन जी–20 सदस्यों के समूह द्वारा किया जा सकता है। टीकाकरण (जीएवीआई) से जुड़ी चिंताओं से निपटने, वैश्विक शांति हासिल करने (संयुक्त राष्ट्र शांति सेना) और जलवायु परिवर्तन (अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन), तकनीकी सहयोग प्रदान करने (इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक द्वारा रिवर्स लिंकेज के जरिए) के लिए सृजित किए गए प्लेटफॉर्मों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित नीतिगत सारपत्र एक सामान्य संस्थागत संरचना का विकास करेगा जो वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं (जीपीजी) को प्रदान करने एवं जीसी के संरक्षण व सुरक्षा में मदद करने के लिए समस्त विकसित और विकासशील देशों के सरकारी एवं गैर–सरकारी दोनों ही कर्ताओं या निकायों के लिए परिचालन की गुंजाइश कर देती है। अध्ययन में यह तर्क दिया जाएगा कि ये प्रयोग 'बहु–केंद्रित या बहु–ध्रुवीय (पॉलीसेंट्रिक) गवर्नेंस' के आधार पर किए गए हैं। कार्लिसल और ग्रुबी (2017) ने बहु–केंद्रितता (पॉलीसेंट्रिकिटी) के आइडिया का स्पष्ट वर्णन प्रस्तुत किया है। बहु–केंद्रित गवर्नेंस प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें एक संस्थागत संरचना होती है और इसमें 'निर्णय लेने वाले केंद्र एक से अधिक होते हैं जो प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संबंधों में एक–दूसरे को ध्यान में रखते हैं और विवादों को सुलझाने में सक्षम होते हैं।' एसडीजी के परिचालन की बहु–केंद्रित गवर्नेंस व्यवस्था, जो पारंपरिक वर्गीकृत एकल–केंद्रित व्यवस्थाओं से परे है, को एजेंडा 2030 के लिए गवर्नेंस की नई सामान्य स्थिति के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा।

जी–20 दरअसल संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के बाहर विभिन्न देशों का एक ऐसा समूह बनाने का प्रथम प्रयास है जो 'विकासात्मक दर्जा यानी विकसित और विकासशील देषों की सीमाओं से परे है। सामान्य रूप से एजेंडा 2030, और विशेष रूप से विकास सहयोग के संबंध में इसके प्रयासों के संस्थागतकरण की प्रक्रिया के तहत विभिन्न साझेदारों की ताकत और ज्ञान आधारों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि अपेक्षित परिणामों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसे मजबूत बनाया जा सके। नीतिगत सारपत्र जी–20 की इस विशिष्ट क्षमता से जुड़ी वैचारिक और परिचालन समझ में संस्थागत अंतर को कम करने में मदद करेगा कि जी–20 यह सुनिश्चित करने में प्रभावकारी भूमिका निभाता है कि कोई भी पीछे न रह जाए और इस प्रक्रिया में वह जीसी का संरक्षण करते हुए आवश्यक जीपीजी प्रदान करता है। उभर कर सामने आने वाली सामूहिक गवर्नेंस व्यवस्था इसके साथ ही विकास वित्त से जुड़ी चिंताओं के निराकरण में भी प्रभावकारी योगदान देगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सामूहिक रूप से 'जी–20 अर्थव्यवस्थाओं का सकल विश्व उत्पाद (जीडब्ल्यूपी) में लगभग 90 प्रतिशत, विश्व व्यापार में 80 प्रतिशत (यदि यूरोपीय संघ के अंदर होने वाले व्यापार को छोड़ दें तो 75 प्रतिशत), दुनिया की आबादी में दो–तिहाई और विश्व भूमि क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत योगदान है', जी–20 के स्तर पर सृजित गवर्नेंस से जुड़ी इस तरह की संस्थागत संरचना दरअसल 2030 एजेंडा को नई गति देने और प्राप्त करने की दिशा में की जा रही वैश्विक पहलों को कारगर रूप से प्रभावित करेगी।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी–20 पर कार्यकलाप कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय कराधान में दक्षिणीय सहयोग

अवैध वित्तीय प्रवाह पर एजेंडे को आगे बढ़ानाः दक्षिण (विकासशील देशों) में संस्थागत प्रयास और आरआईएस की भूमिका

कर अदायगी से बचना, कर चोरी और कर आधार के क्षरण सहित कराधान के मुद्दे विकासशील देशों के लिए बड़ी नीतिगत चुनौतियां हैं। विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, निश्कर्शण या खनन उद्योगों, बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर चोरी, आधार क्षरण लाभ स्थानांतरण, भगोड़े आर्थिक अपराधियों, ट्रांसफर प्राइसिंग और अवैध वित्तपोषण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कराधान के मुद्दे अत्यंत जटिल हैं जिसके लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर कोई भी वैश्विक निकाय न होने के कारण ये मामले अक्सर निर्णयों को जटिल बना देते हैं क्योंकि विभिन्न कर क्षेत्राधिकार भिन्न–भिन्न राष्ट्रीय नियमों, नियमनों और कानूनी ढांचे के अधीन होते हैं। चूंकि विकासशील देश वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिए कमर कस रहे हैं, इसलिए घरेलू संसाधन जुटाने में दक्षता सुनिश्चित करना और रिसाव (लीकेज) रोकना विभिन्न देशों के लिए प्राथमिकता है। आरआईएस विकास वित्त से जुड़े मुद्दों पर काम करता रहा है। आरआईएस विषेशकर घरेलू संसाधन जुटाने की व्यवस्था को मजबूत बनाने, बाह्य वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने एवं रिसाव (लीकेज) को न्यूनतम करने के लिए संस्थागत संरचना का निर्माण करने और बेशकीमती संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने पर फोकस करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान से जुड़े कुछ उपर्युक्त क्षेत्रों का वर्तमान में अध्ययन किया जा रहा है। इस संबंध में आरआईएस ने जिनेवा स्थित साउथ सेंटर के साथ मिलकर 9–10 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय कर मामलों में दक्षिणीय सहयोग' विषय पर संयुक्त रूप से तीसरे वार्षिक विकासशील देश फोरम का आयोजन किया जिसका उद्देश्य अभिनव समाधानों और देश की तैयारियों के लिए विचार मंथन करना था।

आरआईएस विकास वित्त से जुड़े मुद्दों, विशेषकर, घरेलू संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर फोकस करने, लीकेज को न्यूनतम करने के लिए बाह्य वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने पर काम करता रहा है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

भारत अगला एससीओ शिखर सम्मेलन और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित करेगा। आरआईएस भी एससीओ प्रक्रिया में संलग्न रहा है। संस्थान ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान 'भारत–मध्य एशिया साझेदारीः क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी के लिए आगे बढ़ना' विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की। इसे और मजबूती प्रदान करते हुए आरआईएस आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों के लिए आवश्यक जानकारियां (इनपुट) प्रदान करेगा। आरआईएस ने नई दिल्ली स्थित उजबेकिस्तान दूतावास के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 'उजबेकिस्तान–भारतः रणनीतिक साझेदारी के नए क्षितिज' विशय पर गोलमेज चर्चा आयोजित की।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: अन्य अध्ययन

जी–20 में सेवा व्यापार: ग्रुप के अंदर गतिशीलता और वैश्विक योगदान

डॉ. प्रियदर्शी दाश और सुश्री सभ्या राय

सेवा क्षेत्रों (सर्विस सेक्टर), विशेषकर बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाओं, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रसद (लॉजिस्टिक्स), समुद्री सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में व्यापार से जुड़ी व्यापक अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है। सेवाओं का व्यापार विश्व स्तर पर विकसित हो रहा है और यह माना जाता है कि उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं के व्यापार के विस्तार की व्यापक गुंजाइश है। द्विपक्षीय व्यापार के अलग–अलग डेटा के अभाव एवं विभिन्न देशों की डेटा रिपोर्टिंग में अंतर, सेवाओं के निर्यात और आयात की क्षमता की पूरी समझ का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जाता है। हालांकि, ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्मों जैसे कि अमेजन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इत्यादि द्वारा व्यापार संबंधी व्यवहार में लाए गए बदलाव कई सेवा क्षेत्रों में तेज विकास शुरू होने के बारे में संकेत देते हैं। एक गतिशील अंतरराष्ट्रीय ग्रुप होने के नाते जी–20 सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने और नियंत्रित करने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। जी–20 के राजनेताओं के शिखर सम्मेलन में मुद्दों की कवरेज कोई नाममात्र की नहीं होती है, इससे यह पता चलता है कि सेवाओं के व्यापार को समझने में जानकारियों का व्यापक अंतर होता है। वस्तुओं के विपरीत सेवाओं में व्यापार बाधाएं गुणात्मक होने के साथ–साथ विभिन्न देशों में अलग–अलग होती हैं। इस अध्ययन के तहत जी–20 देशों के भीतर सेवाओं के निर्यात एवं आयात के रुझान, जी–20 में विकासशील देशों के संबंध में उभरते स्वरूप, जी–20 षिखर सम्मेलनों एवं आधिकारिक वार्तालापों में इन रुझानों व स्वरूप के प्रतिबिंब, और वैश्विक सेवाओं के व्यापार के साथ–साथ नियम बनाने के लिए एक बाजार के रूप में जी–20 की भूमिका पर बारीकी से गौर करने के प्रयास किए जाएंगे। सेवाओं के व्यापार में विकसित हो रहे रुझानों, व्यापार बाधाओं और नीतिगत मुद्दों का पता लगाने के अलावा इस अध्ययन में अनुभवजन्य रूप से उस कारक पर गौर किया गया है जो जी–20 देशों के बीच सेवाओं के प्रवाह को निर्धारित करता है।

जी–20 में कृषि – विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य से प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं का आकलन

डॉ. प्रियदर्शी दाश और सुश्री श्रेया कंसल

कृषि जी20 के लिए, विशेषकर जी20–विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। कृषि उत्पादों का व्यापार और संबंधित नीति–निर्माण वैश्विक स्तर पर काफी जटिल रहा है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का कोई भी नया दौर आयोजित नहीं किए जाने के मद्देनजर कृशि व्यापार पर बातचीत के लिए बहुपक्षीय मार्गों का तेजी से पता लगाया जा रहा है। कृषि व्यापार के लिए किसी भी वैश्विक ढांचे या रूपरेखा के अभाव में यही उम्मीद की जा रही है कि जी–20 कृषि व्यापार के मुद्दों को गंभीरता से लेगा। इस प्रेरणा के मद्देनजर यह पेपर इस बात पर गौर करेगा कि क्या जी–20 प्रक्रिया में कृशि को उचित महत्व मिला है। जी–20 के राजनेताओं के शिखर सम्मेलनों और कृषि मंत्रियों के वार्तालापों का गहराई से अध्ययन यह समझने के लिए किया जाता है कि जी–20 ने विगत वर्शों में किन–किन मुद्दों को प्राथमिकता दी है और दुनिया, विशेषकर विकासशील देशों के समक्ष मौजूद समकालीन चुनौतियों के अनुरूप वे कितने सुसंगत हैं।

जी–20 स्वास्थ्य मंत्रियों के प्रस्तावों का मिलान और पिछली जी–20 बैठकों के स्वास्थ्य संबंधी परिणाम

प्रोफेसर टी सी जेम्स

यह अध्ययन नवंबर 2020 में 'चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच पर डब्ल्यूएचओ के वैश्विक सम्मेलन' के आयोजन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ आरआईएस की ज्ञान साझेदारी के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इस अध्ययन के तहत जी–20 फोरम में जी–20 स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं का मिलान और विश्लेषण किया जाएगा।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र और एसडीजी

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ. सब्यसाची साहा, डॉ. पी के आनंद, श्री कृष्ण कुमार और सुश्री प्रतिभा शॉ

एक समग्र प्रतिमान, जो भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के साथ संयोजित होता है, के तहत आठ राज्यों वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास करने में भारत सरकार की गहरी रुचि को ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में एसडीजी के स्थानीयकरण पर काम करने के लिए अपने एसडीजी कार्यकलाप कार्यक्रम के तहत पर्याप्त रूप से फोकस किया है। इस प्रक्रिया में आरआईएस सक्रिय रूप से कई राज्य सरकारों, स्थानीय एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ काम कर रहा है। आरआईएस पूर्वोत्तर राज्यों में एसडीजी की प्रगति पर करीबी नजर रख रहा है और इस संबंध में संस्थागत व्यवस्थाओं को आवश्यक सहयोग दे रहा है। आरआईएस को 24–26 फरवरी, 2020 के दौरान आयोजित 'पूर्वोत्तर राज्यों की साझेदारियों, सहयोग और विकास पर एसडीजी कॉन्क्लेव 2020' के लिए नीति आयोग द्वारा एक ज्ञान साझेदार के रूप में नामित किया गया था। इस अवसर पर आरआईएस को 'पूर्वोत्तर और एसडीजी – साझेदारी, सहयोग और विकास' पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरआईएस रिपोर्ट में निम्नलिखित थीम को रखा गया है: राज्य की पहल और एसडीजी का स्थानीयकरण; आर्थिक समृद्धि और सतत आजीविका के वाहक; जलवायु अनुकूल कृषि और विविधीकरण; पोषण, स्वास्थ्य और खुशहाली; शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता; संचार, कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना विकास; और एसडीजी का वित्तपोषण। रिपोर्ट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु क्रियात्मक कार्यक्रम (एक्शन प्रोग्राम) के लिए विशिष्ट सिफारिशें भी की गई हैं।

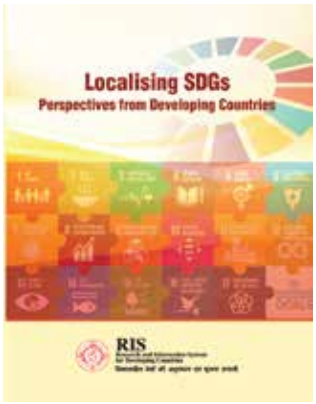

लोकलाइजिंग एसडीजीस पर्सपैक्टिव फ्रोम डेवेलपिंग कन्ट्रीज़

आरआईएस के हालिया प्रकाशन जैसे कि स्प्रिंगर द्वारा एसडीजी पर प्रकाशित पुस्तक और एसडीजी एवं पूर्वोत्तर पर रिपोर्ट इन प्रयासों के ठोस प्रमाण हैं।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

एसडीजी के लिए एसटीआई

राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली और नवीन प्रौद्योगिकी प्रतिमानः आरआईएस ने एसडीजी के लिए एसटीआई में भारत के नेतृत्व को साबित करने का मार्ग प्रशस्त किया

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, डॉ. पी. के. आनंद, श्री कृष्ण कुमार, डॉ. के. रवि श्रीनिवास, डॉ. सब्यसाची साहा और डॉ. कपिल धनराज पाटिल

भारत भी उन अग्रणी देषों में शामिल था, जिन्होंने वर्ष 2015 में एजेंडा 2030 (सतत विकास लक्ष्य–एसडीजी) के हिस्से के रूप में 'प्रौद्योगिकी सुविधा व्यवस्था (टीएफएम)' की शुरुआत करने पर विशेष जोर दिया था। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'एसडीजी रोडमैप के लिए एसटीआई पर वैश्विक पायलट प्रोग्राम' की शुरुआत करने के साथ ही टीएफएम पर विचार–विमर्श एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गया है। वर्ष 2014 से ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एसटीआई, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, आयुश्मान भारत, इत्यादि की सहायता से व्यापक एवं परिवर्तनकारी विकास एजेंडे को साकार करने में मिली महत्वपूर्ण सफलता को ध्यान में रखते हुए भारत अब वैश्विक पायलट प्रोग्राम के लिए स्वेच्छा से पांच पायलट देशों में से एक बन गया है। 'एसडीजी रोडमैप के लिए एसटीआई पर वैश्विक पायलट प्रोग्राम' को जी–20 के राजनेताओं का भी मजबूत और सामूहिक समर्थन प्राप्त हो गया है।

आरआईएस ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार – एसटीआई नीति (जो उभरती एवं नई प्रौद्योगिकियों, नवाचार नीति, प्रणालीगत मुद्दों, आईपीआर, विज्ञान कूटनीति, 'पहुंच, समानता, समावेशन – एईआई', 'वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी – एसएसआर', प्रौद्योगिकी गवर्नेंस मुद्दों, इत्यादि को कवर करती है) के साथ–साथ एसडीजी (जो विशिष्ट एसडीजी के तहत विशयगत मुद्दों, राष्ट्रीय रणनीति, राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं स्थानीयकरण, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं, क्षेत्रीय/दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोग से जुड़े मुद्दों, और संकेतकों को कवर करते हैं) पर भी जो मूल या सर्वाधिक अहम क्षमता हासिल कर रखी है वह एसडीजी के लिए एसटीआई के विभिन्न आयामों पर व्यापक कार्य शुरू करने के अवसर प्रदान कर रही है। एसटीआई की पहचान एसडीजी के कार्यान्वयन के एक प्रमुख साधन के रूप में की गई थी, जिसने सतत, सुदृढ़ और समावेशी विकास के लिए एक मूल्यवान साधन के रूप में बड़ी तेजी से ध्यान आकर्शित किया है। सबसे पहले तो विकास से जुड़े शेष बचे कार्यों को पूरा करने और उसके बाद जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव से लेकर मौजूदा समय में नोवल कोरोना वायरस महामारी के अप्रत्याशित फैलाव से गहराए संकट तक से निपटने में वैश्विक समुदाय ने एसटीआई का सहारा लिया है। कोविड–19 महामारी के कारण लंबे समय से जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को ध्यान में रखते हुए एसडीजी पर अत्यधिक फोकस करने और यहां तक कि संसाधनों को अनुकूलित करने एवं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के एक साधन के रूप में एसटीआई का अधिक से अधिक उपयोग करने की आवष्यकता है। भारत से उभरते साक्ष्य इस संबंध में अत्यंत मजबूत हैं और वे विकास एवं समावेष, आपदा की तैयारी, और निरंतरता के लिए एसटीआई के विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर कई सबक प्रदान करते हैं।

'एसडीजी रोडमैप के लिए एसटीआई पर वैश्विक पायलट कार्यक्रम' में भारत की भागीदारी दरअसल विदेश मंत्रालय और नीति आयोग के साथ निकट सहयोग में भारत की प्रमुख एजेंसी के रूप में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय द्वारा द्वारा संचालित की जा रही है। जापान और यूरोपीय संघ दोनों ने ही इस कार्यक्रम को अपना समर्थन प्रदान किया है। विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियां यूएन–डीईएसए और अन्य निकायों के साथ मिलकर टीएफएम पर इंटर एजेंसी टास्क टीम (आईएटीटी) के हिस्से के रूप में काम करेंगी, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मूल रूप से निर्दिष्ट किया गया था। भारत इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए जापान सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। पीएसए ने इस कवायद या अहम कार्य में आरआईएस को अपने ज्ञान साझेदार के रूप में नामित किया है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

एसडीजी5: महिला–पुरुष भेदभाव को समाप्त करने के तरीके तलाशना – अब भी जारी है

डॉ. बीना पांडे

एसडीजी 5 पर अध्ययन मुख्य रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण एवं रोजगार तक पहुंच को बढ़ावा देने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और महिला–पुरुष भेदभाव को समाप्त करने के लिए गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने पर फोकस करता है। इसके अलावा, भारत में महिला कर्मचारियों की भागीदारी के मौजूदा निम्न स्तर को पलटा जा सकता है, बशर्ते कि अधिक–से–अधिक भारतीय महिलाओं को उद्यमिता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे महिला–पुरुष समानता को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे उनकी खुशहाली पर बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। उस संदर्भ में इस अध्ययन के तहत अन्य लक्ष्यों, विशेषकर गरीबी, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित लक्ष्यों के साथ एसडीजी 5 के अंतर–संयोजन का पता लगाया जाएगा। इसके तहत यह भी पता लगाया जाएगा कि एसडीजी 5 एवं उसके लक्ष्य आखिरकार कैसे संकेतकों में बदल जाएंगे और क्या ये महिलाओं की स्थिति की निगरानी के लिए प्रभावकारी एवं उपयोगी साबित होंगे। अध्ययन के तहत महिलाओं को प्रभावित करने/उनसे संबंधित मौजूदा कानूनों पर भी गौर किया जाएगा, ताकि उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही उभरती जरूरतों पर किए जाने वाले अतिरिक्त विधायी उपायों या संषोधनों पर भी गौर किया जाएगा। अध्ययन के तहत विभिन्न मंत्रालयों, उपक्रमों, स्थानीय निकायों, इत्यादि के बीच प्रभावकारी सामंजस्य सुनिश्चित करने के तरीके का भी पता लगाया जाएगा, ताकि सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा नीतियों की व्यवस्था के जरिए अवैतनिक देखभाल एवं घरेलू कामकाज को पहचानने के साथ–साथ उन्हें विशिष्ट महत्व भी दिया जा सके।

एसडीजी 3 की ओर अग्रसर होना: पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका

प्रोफेसर टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर

अध्ययन में 'स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर सभी की खुशहाली को बढ़ावा देना' नामक सतत विकास लक्ष्य संख्या 3 को प्राप्त करने के प्रयासों के तहत 'पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका' पर गौर करने का प्रस्ताव किया गया है। यह कार्य एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य से किया जाएगा और इसका उद्देश्य आधुनिक स्वास्थ्य सेवा एवं वेलनेस कार्यक्रमों में भारतीय चिकित्सा प्रणालियों की प्रासंगिकता को सामने लाना है। जिन व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा करने का प्रस्ताव है, वे टीएम उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकीकरण, टीएम में नवाचार व बौद्धिक संपदा, सामान्य स्वास्थ्य सेवा में पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पारंपरिक चिकित्सा में स्वास्थ्य कूटनीति से संबंधित मुद्दे हैं। यह अध्ययन अब भी जारी है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी 17) के लिए साझेदारी: वैश्विक साझेदारी, क्षेत्रीय सहयोग, संसाधन जुटाना, स्थानीयकरण और सामाजिक उद्यम

मात्रा से गुणवत्ता की ओर अग्रसर होना: अभिनव वित्तपोषण और एसडीजी के कार्यान्वयन के साधनों पर आरआईएस का एजेंडा

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ. सब्यसाची साहा, सुश्री प्रतिभा शॉ, श्री अरुण एस. नायर

आरआईएस व्यापार, प्रौद्योगिकी और वित्त पर वैश्विक संस्थागत संरचना का वर्णन करने के लिए पिछले दो वर्षों से अनुसंधान अध्ययनों की एक श्रृंखला शुरू करने में बारीकी से जुटा रहा है जिसमें अल्पकालिक शोध पत्र और पूर्ण शोध लेख दोनों ही शामिल हैं। इस तरह के अध्ययन एसडीजी में उल्लिखित विकास और निरंतरता की चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गहरी वैश्विक साझेदारी को सृजित करने के साथ–साथ बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग में कमी की पहचान करने के लिए साक्ष्य आधारित विश्लेषण प्रदान करते हैं। इसके तहत अफ्रीका के साथ–साथ पड़ोस में क्षेत्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही यह उपर्युक्त कुछ थीम पर जी–20 और संयुक्त राश्ट्र में विचार–विमर्श में प्रभावकारी ढंग से योगदान दे रहा है। घरेलू हितधारकों यथा राज्य सरकारों (विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में), सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्र के साथ बड़ी तेजी से गहराते सहयोग से गहन जानकारियां प्राप्त की गई हैं। आरआईएस के हालिया प्रकाशन जैसे कि स्प्रिंगर द्वारा एसडीजी पर प्रकाशित पुस्तक और एसडीजी एवं पूर्वोत्तर पर रिपोर्ट इस तरह के अथक प्रयासों के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

आरआईएस ने हाल ही में विषेशकर परोपकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसायटी संगठनों के साथ साझेदारी में एसडीजी के अभिनव एवं परिणाम आधारित वित्तपोशण पर भी बारीकी से गौर किया है। कई देशों में वित्त पोशण की खाई को पाटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र से पर्याप्त सहायता की आवश्यकता होगी। विकास के लिए वित्त पोषण (एफएफडी) से संबंधित अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (एएएए) में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के वित्त पोषण की रूपरेखा तय की गई है। अदीस अबाबा एक्शन एजेंडे में निजी क्षेत्र, परोपकारी एजेंसियों एवं फाउंडेशनों और व्यापक सिविल सोसायटी से संसाधनों एवं जानकारियों को जुटाने के लिए बहु–हितधारक साझेदारियों को इसके मूल में रखा गया है। सामाजिक उद्यमिता के इस उभरते क्षेत्र में बढ़ती दिलचस्पी दरअसल इसकी अनूठी विशेषता की बदौलत है जिसके तहत सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने और इसके साथ ही एक व्यवहार्य या लाभप्रद वाणिज्यिक मॉडल पर काम करने के लिए निवेश किया जा सकता है। 'सीएसआर' से परे जाकर सामाजिक क्षेत्र हेतु निजी क्षेत्र के वित्तपोषण का इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार ने एक 'सोशल स्टॉक एक्सचेंज' का विचार या आइडिया भी सामने रखा। आरआईएस ने हाल ही में भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सामाजिक उद्यमों और सोशल इनक्यूबेटर की संभावनाओं पर वैश्विक तुलना करते हुए एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज प्रकाशित किया है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

भारतीय परिप्रेक्ष्य में कामकाजी महिलाओं पर कोविड–19 का प्रभाव

डॉ. बीना पांडे

मौजूदा समय में पूरी दुनिया कोविड–19 महामारी के भीषण प्रभावों का सामना कर रही है। इस महामारी के गंभीर दुश्प्रभावों से पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और यहां तक कि बच्चे भी अछूते नहीं हैं। कोई भी प्रामाणिक दवा या टीका (वैक्सीन) उपलब्ध न होने के कारण दुनिया भर में लाखों लोग इस कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं।

इन अप्रत्याशित परिस्थितियों में कोविड–19 का सर्वाधिक खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं को 'घर का काम करने और घर से काम करने' की दोहरी जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं। इसमें महिला रोजगार की वर्तमान स्थिति और अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में उनके योगदान का विश्लेशण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, इसमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए घरेलू कामकाज एवं संगठनात्मक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के संदर्भ में 'घर का काम करने और घर से काम करने' से जुड़ी महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारियों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। इसके साथ ही इस संबंध में सरकार के कदमों या उपायों पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

उद्योग 4.0 से लाभ उठाना: नवाचार, तैनाती, घरेलू विनिर्माण और उच्च प्रौद्योगिकी का व्यापार

स्थानीयकरण सतत् विकास लक्ष्य और उत्तोलन उद्योग

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ. सब्यसाची साहा और सुश्री प्रतिभा शॉ

प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता विश्व स्तर पर एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा और गति पर व्यापक असर डालेगी। वह अत्यंत गहन तकनीकी बदलाव आर्थिक प्रणालियों को संचालित करेगा और भविष्य की अवसंरचना को निर्धारित करेगा जो अब तक अज्ञात है। इस तरह के बदलाव अल्पकाल में विघटनकारी या हानिकारक प्रतीत होते हैं और विकास के एक गैर–रेखीय पथ पर अग्रसर होते हुए नजर आते हैं। निरंतरता और सुदृढ़ता से जुड़ी चिंताओं के साथ–साथ नई आकांक्षाओं से उभरती आवश्यकता प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विघटनकारी बदलावों को और भी अधिक बढ़ावा देगी। 'उद्योग 4.0' का आइडिया तकनीकी बदलाव के इस स्वरूप से शुरू होता है जिसमें हम कंप्यूटिंग और संचार पर आधारित प्रौद्योगिकी की एक नई विशिष्टता को देखते हैं जो सूचनाओं को जोड़ने एवं प्रोसेसिंग करने और अंततः उत्पादन, निर्माण, रसद (लॉजिस्टिक्स), परिवहन और सेवाओं की डिलीवरी से जुड़ी अनगिनत मशीनों को चलाने की प्रमुख जिम्मेदारियों (मनुष्य के स्थान पर) को उठाने की अपनी क्षमता से परिपूर्ण है। विकास के संदर्भ में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने ज्ञान के प्रसार एवं सूचनाओं तक पहुंच; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण; वित्तीय समावेश; गवर्नेंस में पारदर्शिता; और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को काफी बढ़ा दिया है। विकासशील देशों में सरकारें आईसीटी–आधारित गवर्नेंस, आपदा संबंधी सुदृढ़ता और ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित कर रही हैं। भारत को अपनी आईसीटी अवसंरचना, आईसीटी की पैठ, आईसीटी सेवाओं, डिजिटल भुगतान एवं कैशलेस सिस्टम और, आईसीटी–आधारित गवर्नेंस, खरीद एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में विकासशील देशों में अग्रणी के रूप में उद्धृत किया जाता है। एसडीजी पर पुस्तक में एक अध्याय के रूप में प्रकाशित एसडीजी 9 पर एक हालिया शोध लेख में इस दिशा में भारत की कुछ प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। इस क्षेत्र में अब भी बरकरार अनुसंधान मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उद्योग 4.0 के लिए स्वदेशी नवाचार क्षमता और तैयारियों का आकलन करना
- उद्योग 4.0 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रणालियों को डिजाइन करना
- एसडीजी के लिए उद्योग 4.0 से लाभ उठाना – प्रौद्योगिकियों और विकास क्षेत्रों की पहचान करना
- नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत रूपरेखा और एसडीजी की प्राप्ति के लिए इस तरह की तकनीकों का उपयोग करना
- उद्योग 4.0 उपकरणों के संबंध में आत्मनिर्भरता और घरेलू हार्डवेयर (इलेक्ट्रॉनिक्स सहित) विनिर्माण क्षमता
- संबंधित उत्पादों में उच्च–प्रौद्योगिकी के व्यापार का आकलन करना

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: दक्षिणीय सहयोग और वैश्विक सहायता की संरचना

भारत के विकास सहयोग पर आरआईएस का डेटाबेस

विकास सहयोग पर एक डेटाबेस बनाना: आरआईएस का अनूठा एवं अग्रणी प्रयास

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ. सुशील कुमार, और सुश्री अदिति गुप्ता

इस डेटाबेस की मुख्य विषेशता यह है कि यह विकास संविदा के सभी तौर–तरीकों जैसे कि क्षमता निर्माण (विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, मेजबान देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां, थर्ड कंट्री में प्रशिक्षण, स्वयंसेवकों को तैनात करना, व्यवहार्यता अध्ययन करना एवं प्रोटोटाइप का उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र); अनुदान (नकद में अनुदान, वस्तु के रूप में अनुदान, ऋण माफी और मानवीय सहायता); रियायती वित्त (लाइन ऑफ क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट); व्यापार एवं बाजार पहुंच (ड्यूटी मुक्त शुल्क वरीयता योजना, व्यापार सुविधा के लिए अवसंरचना में सुधार, व्यापार संवर्धन एवं व्यापार सहायता सेवाएं, व्यवसाय सुविधा सेवाएं प्रदान करना, नियामकीय क्षमता में सुधार के लिए सहायता, निवेष निधि प्रदान करना और क्षेत्र के भीतर आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करना); और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (तकनीकी सहयोग, संयुक्त वैज्ञानिक एवं अकादमिक अनुसंधान, टर्नकी या तैयारशुदा परियोजनाएं, लाइसेंसिंग पर सब्सिडी या आईपीआर व्यवस्था से छूट, क्षमता निर्माण के घटक के साथ या उसके बिना ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) को कवर करता है। डेटाबेस द्विपक्षीय प्रवाह के साथ–साथ बहुपक्षीय प्रवाह को भी कवर करता है। इसके साथ ही यह भारत के विकास सहयोग मंत्रालय–वार प्रवाह एवं सेक्टर–वार प्रवाह और क्षेत्रीय संस्थानों के साथ भारत के विकास सहयोग को भी कवर करता है। इस डेटाबेस की समयावधि वर्ष 1947 से लेकर आज तक है।

साउथ साउथ आइडियास–साउथ साउथ कोओपरेशन– ए थियोरिटिकल इन्स्टीटयूशनल फ्रेमवर्क

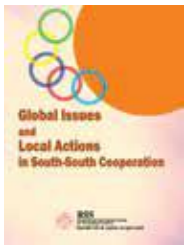

ग्लोबल इशूस एंड लोकल एक्शन्स इन साउथ साउथ कोओपरेशन

दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग पर डेटाबेस

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, प्रोफेसर मिलिंदो चक्रबर्ती, डॉ. सुशील कुमार और सुश्री अदिति गुप्ता

इस डेटाबेस की मुख्य विषेशता यह है कि यह दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग के विभिन्न तौर–तरीकों जैसे कि व्यापार एवं निवेश, ऋणों व रियायती वित्त, अनुदान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं मानवीय सहायता को कवर करता है। इसके अलावा, यह डेटाबेस दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग पर सेक्टर–वार डेटा को भी कवर करता है।

डेटाबेस द्विपक्षीय प्रवाह के साथ–साथ बहुपक्षीय प्रवाह को भी कवर करता है।

यह मंत्रालय–वार और सेक्टर–वार भारत के विकास सहयोग के प्रवाह को भी कवर करता है।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

क्षेत्रीय व्यापार से महाद्वीपीय आर्थिक सहभागिता तकः आरआईएस के अनुसंधान कार्य नीति निर्माण में सटीक विश्लेशणात्मक योगदान देते हैं

व्यापार और निवेश स्तंभ क्षेत्रीय कारोबार प्रबंधन, महाद्वीपीय आर्थिक संबंधों और खास क्षेत्रवार अध्ययनों पर केंद्रित रहे हैं। आरआईएस के वर्क प्रोग्राम भारत के विभिन्न क्षेत्रीय समूहों में विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक हितों मामले को संवेदनशीलता के साथ ग्रहण करता है। यह स्तंभ दक्षिण एशिया, आसियान, अफ्रीका, मध्य एशियाध्एससीओ, ब्रिक्स (ब्रिक्स), इब्सा (इब्सा) और दक्षिणी अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान कार्यक्रमों को समाविष्ट करता है। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौता (एएफसीएफटीए) और मध्य एशिया ध्शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) की हालिया गतिशीलता को देखते हुए आरआईएस ने भारत के इन दो क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के साथ संभावित जुड़ाव को लेकर विशिष्ट विषयगत प्रारंभिक अध्ययन किया है। भारत के दक्षिण एशिया के देशों मुख्यतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और मालदीव के साथ व्यापार और निवेश, विशेषकर सेवा क्षेत्रों में व्यवसाय को लेकर भारत के व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के मामले में फिलहाल चार अध्ययन जारी है। इसके अलावा, दक्षिण एशिया क्षेत्र में मौजूदा गतिरोध की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश और ईरान के साथ संभावित औपचारिक आर्थिक प्रबंधन जैसे पीटीध सीईपीए का गहराई से अध्ययन किए जा रहा है। अनुसंधान अध्ययनों के अलावा इब्सा और ब्रिक्स के लिए फेलोशिप कार्यक्रम युवा अनुसंधानकर्ताओं को भारत एवं इन क्षेत्रीय समूहों के बीच गहरे आर्थिक सहयोग की संभावनाओं के बारे में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करते हैं। वित्तीय क्षेत्र सहयोग के अंतर्गत कुछ अध्ययन तो व्यापार वित्त, स्थानीय मुद्रा का उपयोग, करंसी स्वैप अरेंजमेंट, विनिमय दर प्रबंधन, वित्त–तकनीक, डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी की जांच परख के लिए भी शुरू किए गए हैं।

विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट (डब्ल्यूटीडीआर) 2020

आरआईएस फैकल्टी

आज से चार दशक पहले आरआईएस की स्थापना हुई थी, तब से ही व्यापार और विकास उसके अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। इस प्रयास में, आरआईएस अपनी महत्वाकांक्षी विश्व व्यापार विकास रिपोर्ट (डब्ल्यूटीडीआर) का नियमित अंतराल पर प्रकाशन करता रहा है। इस रिपोर्ट में विश्व व्यापार लैंडस्केप में महत्वपूर्ण विकास, शेयर्सहोल्डर्स को प्रभावित करने वाले मुद्दे, तथा विकासशील देशों के अवसरों और चुनौतियों जैसे विषयों का समावेश किया जाता है। डब्ल्यूटीडीआर–2020 की मुख्य थीम 'व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी' है। इस पर जोर देने की मूल अभिप्रेरणा तकनीक की तेजी से बदलती सीमाओं का व्यापार के तौर–तरीकों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना है। यह भी समझना है कि तुलनात्मक रूप से फायदे, प्रतियोगितात्मकताओं, नियम–आध ाारित व्यापार–क्रम और कारोबार की सुगमता के लिए और क्या–क्या किया जाना चाहिए। रिपोर्ट का दायरा इस तथ्य को सामने लाता है कि व्यापार ने आय की संभावना को विस्तारित किया है, जबकि अवरुद्ध तकनीकी व्यापार क्षमता में अंतराल को बढ़ावा दे सकती है और इस वजह से असमानताओं को भी, अगर व्यापार समान फायदे के लिए न किया जाए। देशों के बीच नियम आधारित कारोबारी प्रणाली को परे रखकर निरंकुश गतिरोधों के जरिए तकनीक जनित अल्पाधिकार वाले व्यापार को बढ़ावा दिया है तथा बड़ी संख्या में कारोबारी राष्ट्रों के बीच प्रतियोगितात्मकताओं के निर्माण को कमजोर करने की तरफ बढ़ती प्रवृत्ति को जाहिर किया है। यद्यपि विकासशील देश अपने व्यापार की तकनीकी तीव्रता बढ़ाने, नियम–कायदों को सद्भाव पूर्ण बनाने, तकनीकी सुस्ती वाली अवैज्ञानिक नियमों की त्रुटियों को दूर करने, पूंजी प्रवाहों को सुनिश्चित करने, डिजिटल कारोबार करने इत्यादि में सक्षम रहे हैंय श्रम बाजार प्रभावों के जरिए, उत्पादन क्षमताओं और मूल्य सृजन का दायरा देशों की भलाई के ऊपर असंगत प्रभाव पड़ता है। विषयगत ध्यान देने के अलावा इस रिपोर्ट में वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, कर और गैर कर अवरोधों, व्यापार सुगमता में प्रगति, विशेष और विभिन्न निरूपण और डब्ल्यूटीओ की कार्यप्रण ाली,तथा बहुपक्षीय व्यापार पद्धति पर भी खंड होंगे।

डब्ल्यूटीडीआर 2020 में व्यापार पर प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों के प्रभाव का आकलन किया गया है, वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार में शैली के अनुरूप रुझानों के बारे में बताया गया है, निर्यात से जुड़ी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर बारीकी से गौर किया गया है, एनटीएम का विश्लेशण किया गया है, और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधारों के बारे में चर्चा की गई है।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंध

प्रो. एस.के. मोहंती

भारत ने अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी है। व्यापार, निवेश, सहायता के प्रवाह और लोगों के पारस्परिक संपर्क या संवाद के क्षेत्र में भारत एवं दक्षिण एशिया के अन्य दिग्गज क्षेत्रीय देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव का दायरा अतीत की तुलना में अब काफी गहरा और व्यापक है। भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंध भारत की हालिया नीति 'हार्ट ऑफ एशिया' की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के ऊर्जा आयात की दृष्टि से भी ईरान विशेष मायने रखता है। भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग उनके द्वारा एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते और समुद्री सहयोग के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बाद से ही शुल्क (टैरिफ) उदारीकरण से काफी परे चला गया है। भारत और मालदीव ने भी एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत एवं अफगानिस्तान ने एक पीटीए और रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसकी बदौलत उनके द्विपक्षीय आर्थिक संबंध काफी मजबूत हो गए हैं।

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित अध्ययन के तहत ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव या संबंधों पर फोकस किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देष्य चुनिंदा दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव के वर्तमान स्तर का आकलन करना और व्यापार एवं निवेश में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना है। अध्ययन के तहत भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता के आधार पर उनके साथ द्विपक्षीय व्यापक साझेदारी समझौते करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। ईएचएस, पीटीए, एफटीए, सीईपीए, इत्यादि के लिए बातचीत की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। विश्लेषण के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार प्रदर्शन, व्यापार संभावनाएं, निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धी क्षमता, दीर्घकालिक आयात हित, टैरिफ, एनटीबी, व्यापार विविधीकरण, तीसरे या अन्य देश से प्रतिस्पर्धा, वरीयता का मार्जिन, एफडीआई, इत्यादि शामिल होंगे। इस तरह की रणनीति दरअसल लक्षित उत्पादों, फोकस सेक्टरों, व्यापार संभावनाओं, निवेश के अवसरों, व्यापार नीति में बदलावों, इत्यादि की दृष्टि से उपर्युक्त दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों में भारत की प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी।

गैर–टैरिफ उपाय: डेटाबेस

व्यापार बाधाओं का मात्रात्मक आकलन: आरआईएस ने अभिनव पद्धति पेश की

प्रो. एस.के. मोहंती

गैर–टैरिफ उपायों (एनटीएम) पर उपलब्ध जानकारियां व्यापक हैं, लेकिन ये सामान्य निर्यातकों और शैक्षणिक अन्वेशण की दृष्टि से अधूरी हैं। एनटीएम पर डेटाबेस दरअसल चुनिंदा कवरेज और विभिन्न देशों में आम प्रारूप न होने के कारण इसके व्यापार प्रभावों के त्वरित आकलन की दृष्टि से अनुरूप नहीं हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा ठोस प्रयास करने के बावजूद एनटीएम डेटा का विश्लेषण काफी बोझिल है और इसमें काफी समय लगता है। प्रक्रिया के लिहाज से एनटीएम की परिभाषा और तादाद को लेकर व्यापक विरोधाभास हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यापार पर एनटीएम–संबंधी परिवर्तनों के प्रभाव के अनुभवजन्य विश्लेषण की गुणवत्ता काफी हद तक व्यक्तिपरक है और डेटा एवं अर्थमितीय तकनीक की पसंद या विकल्प पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चूंकि एनटीएम ही द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के लिए व्यापार नीति के भावी साधन हैं, इसलिए एनटीएम के विभिन्न पहलुओं को किसी ऐसे एकल अध्ययन में सामने लाना अत्यंत जरूरी है जो नीति निर्माताओं, विद्यार्थियों और व्यापार डेटा के सामान्य यूजर के लिए उपयोगी हो। वैसे तो अध्ययन का अधिकांश हिस्सा संबंधित सामग्री के एक गहन सर्वेक्षण को कवर करेगा, लेकिन अध्ययन का उद्देष्य एनटीएम से जुड़े संयुक्त या विवादास्पद शैक्षणिक कथनों के अनावश्यक फैलाव से बचना है। एनटीएम डेटाबेस को विकसित करने का काम इस अवधि में जारी रहा। जब भी जरूरत हो, एनटीएम के व्यापार प्रभावों का अनुभवजन्य आकलन करना अत्यंत सरल हो, यही इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है।

डब्ल्यूटीओ में ई–कॉमर्स के मुद्दे

वैश्विक व्यापार विमर्श में डिजिटल तकनीक ने एक केंद्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। यह भिन्न तरीकों से अभिव्यक्त होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण पर अस्थाई स्थगन का प्रस्ताव और ब्यूनोस आयर्स की डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय बैठक में ई–कॉमर्स पर बहुपक्षीय समूह के गठन के जरिए। हाल ही में, भारत ने तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के लिए एक नियामक और विकासात्मक प्रोफाइल बनाने के लिए ई–कॉमर्स नीति का एक खाका तैयार किया है। डाटा की भूमिका और इससे संबंधित अवसरों एवं चुनौतियां लगातार हमारा ध्यान खींचती है। अतः डिजिटल तकनीकी के क्षेत्र में कई सारे पहलू हैं, जिनकी तरफ नीति बनाने वालों और वैश्विक विशेषज्ञों को ध्यान देना आवश्यक है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर स्थगन, डाटा अवसर और चुनौतियां तथा भारत की ई–कॉमर्स नीति पर बनाए गए मसौदे तथा विकासशील देशों की ई–कॉमर्स में अंतर्निहित अवसरों से पूरा–पूरा फायदा उठाने में पर्याप्त तैयारी का अभाव जैसे मसले शामिल हैं। यह इसी संदर्भ में है कि आरआईएस ने ई–कॉमर्स मसले पर डब्ल्यूटीओ में विचार–विमर्श के लिए एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है.

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

व्यापार वर्गीकरण के विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण और आईएसएम एवं हर्बल उत्पादों के मानकीकरण के लिए कार्यदल

प्रतिस्पर्धी क्षमता, आत्मनिर्भरता और व्यापार – भारतीय फार्मा और पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा रखनाः आरआईएस ने विशेष अनुसंधान कार्यक्रम का शुभारंभ किया

प्रो. एस.के. मोहंती, श्री राजीव खेर, प्रोफेसर टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक, और श्री अपूर्व भटनागर

एफआईटीएम द्वारा आयोजित उद्योग परामर्श के दौरान प्रतिभागियों ने जिन अनेक मुद्दों पर गहन चर्चा की और प्रकाश डाला उनमें 'व्यापार संवर्धन के लिए व्यापार के आंकड़ों का विशेष महत्व' भी शामिल था। मौजूदा समय में उपयुक्त एचएस व्यापार वर्गीकरण के अभाव में पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों के व्यापार की निगरानी सही ढंग से नहीं हो पाती है। विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) द्वारा 6 अंकों वाले एचएस पर वैश्विक व्यापार वर्गीकरण किया जाता है और यह वैश्विक व्यापार की कुल मात्रा के आधार पर समय–समय पर नए एचएस कोड आवंटित करता है। मुख्यतः इस सेक्टर से जुड़े देशों की ओर से दबाव न होने के कारण पारंपरिक दवाओं (टीएम) और औषधीय पौधों (एमपी) के लिए आवंटित उत्पादों की संख्या अपेक्षा से कम (ज्यादातर 6 अंक) है। एक कार्यदल का गठन इन उद्देष्यों से किया जा रहा हैः आईएसएम उत्पादों, हर्बल उत्पादों एवं औशधीय पौधों को शामिल करने के लिए एचएस नेशनल लाइनों की सिफारिश करना; चिंतन–मनन करना और जहां भी आवश्यक हो, वहां आईएसएम उत्पादों, हर्बल उत्पादों और औशधीय पौधों के लिए अनिवार्य मानकों की आवश्यकता की सिफारिश करना; और आईएसएम उत्पादों, हर्बल उत्पादों एवं औषधीय पौधों की गुणवत्ता व अनुरेखण सुनिश्चित करने के तरीकों की सिफारिश करना। कार्यदल की अंतिम रिपोर्ट आयुश मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है। रिपोर्ट में आयुश उत्पादों के लिए कुछ नए एचएस वर्गीकरण का प्रस्ताव किया गया है।

आरआईएस स्थित एफआईटीएम ने आयुश उत्पादों के लिए नए एचएस वर्गीकरण की सिफारिश की।

सार्वजनिक नीति और आर्थिक विकासः भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग की केस स्टडी

राजीव खेर, प्रोफेसर टी सी जेम्स, डॉ. दिनेश कुमार और डॉ. दीपिका चावला

केस स्टडी के तहत यह पता लगाया जाएगा कि क्या भारत फार्मास्युटिकल क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान से जुड़ा सुअवसर खो रहा है और, यदि ऐसा है, तो इसके क्या–क्या, कारण हैं और ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि इस सेक्टर में अत्यंत कर्मठता से हासिल बढ़त को और भी अधिक बल मिले। इसके तहत समस्त सेक्टरों से जुड़ी नीतियों, विनिर्माण एवं व्यापार में दवा उद्योग के प्रदर्शन, प्रभाव, पीएसयू, एसएंडटी और व्यापार संबंधी घटनाक्रमों, एफटीए तथा बीआईपीए और आयुश सेक्टर का भी विश्लेषण किया जाएगा। फरवरी 2021 तक पूर्ण गहराई से अध्ययन पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को सिफारिशों से युक्त एक रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसके साथ ही आरआईएस द्वारा भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग पर एक प्रकाशन भी सुनिश्चित किया जाएगा। व्यापार आंकड़ों का विश्लेषण और संबंधित सामग्री की समीक्षा अभी जारी है।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

औषधीय पौधा सेक्टर के निर्यात संवर्धन पर अध्ययनः चुनिंदा औषधीय पौधों के लिए रणनीति

प्रोफेसर टी.सी. जेम्स

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वाणिज्य मंत्रालय के एक कार्यदल द्वारा चिन्हित किए गए 25 औषधीय पौधों के व्यापार संवर्धन को बढ़ावा देने की उपयुक्त व्यवस्थाओं की पहचान करना है। भौगोलिक फैलाव और संग्रह एवं खेती की व्यापकता से जुड़ी जटिलताओं और मूल्य श्रृंखला के साथ–साथ वस्तुओं की आवाजाही पर डेटा या अनुरेखण के मौजूदा अभाव को ध्यान में रखते हुए 25 औषधीय पौधों के गहन अध्ययन के लिए काफी समय और संसाधन लगाने होंगे। अतः कार्यदल द्वारा चिन्हित किए गए पांच सर्वाधिक महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के साथ इस दिशा में शुरुआत करने का प्रस्ताव है, जिनमें से प्रत्येक औषधीय पौधे की मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाएगा और इसके साथ ही एक या एक से अधिक पड़ाव पर ठोस उपाय करने की आवश्यकता पर फोकस किया जाएगा। अध्ययन के लिए अनुसंधान टीम का चयन पहले ही किया जा चुका है। क्षेत्र–अध्ययन (फील्ड स्टडी) बाकायदा पूरे हो चुके हैं और रिपोर्ट अभी मसौदा (ड्राफ्ट) चरण में है।

डाइनामिक्स ऑफ इब्सा डेवलपमेंट कोओपरेशन

उत्तर–एएफसीएफटीए अफ्रीकाः एक मूल्यांकन

डॉ. प्रियदर्शी दास और सुश्री सोनल गर्ग

भारत अफ्रीका आर्थिक संबंधों के क्षेत्र बदल रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका समूचे महाद्वीप में मुक्त व्यापार समझौते द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एएफसीएफटीए) को प्रारम्भ कर दिया है। सामान्य अर्थों में, अफ्रीका व्यापार एवं निवेश, औद्योगिकीकरण, आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी, सेवाएं एवं डिजिटल इकोनामी तथा इसी तरह के मामलों में मौन रूपांतरण के दौर से गुजर रहा है। विगत कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ऐसी धारणा बलवती होने लगी है कि राजनीतिक स्थिरता एवं भविष्य की व्यापक आर्थिक नीतियों के साथ अफ्रीका जल्द ही एक शानदार आर्थिक बदलाव का गवाह बन सकता है। कई विद्वानों को लगता है कि एएफसीएफटीए इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अध्ययन इस क्षेत्र में अखंड व्यापार की मौजूदा दशा–दिशा तथा अफ्रीका के लोगों से एएफसीएफटीए (एएफसीएफटीए)के वादों का आकलन करता है। वर्णनात्मक और अर्थमिति –विधि को मिलाते हुए यह आलेख वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार में दिखी शैलीगत पद्धति का अध्ययन करता है। एएफसीएफटीए (एएफसीएफटीए) का उत्तरार्ध युग भारत और अफ्रीकी देशों के बीच गहरे संबंध बनाने के लिए एक रोड मैप को सामने रखता है।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

ब्रिक्स और इब्सा

आरआईएस ने एक बहु–ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए आर्थिक सहयोग से जुड़ी पहलों की अगुवाई की

भारत ब्रिक्स एवं इब्सा के सहभागी देशों के साथ आर्थिक सहयोग कायम करने के लिए सक्रिय रूप से सन्नद्ध है। विकासशील देशों से जुड़े होने के कारण दोनों समूहों की पहलें भारत के आर्थिक राजनय के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो गई हैं। आरआईएस पिछले कई सालों से ब्रिक्स और इब्सा मसलों पर 'व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय अखंडता' स्तंभ के अपने हिस्से के रूप में काम करता रहा है। ब्रिक्स और इब्सा पर वर्क प्रोग्राम मैं विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग पर अनुसंधान अध्ययन, सदस्य देशों के युवा अद्येता के लिए फैलोशिप और भारत से अग्रणी संस्था के अकादमिक फोरम के कान्फ्रेंसों और सेमिनारों के आयोजन को समाविष्ट किया गया है। विगत में, आरआईएस द्वारा इब्सा और ब्रिक्स अकादमी फोरम का आयोजन किया जाता रहा है, जिसे विभिन्न प्रकाशनों में व्यापक रूप से समेटा गया है।

क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण पर इब्सा फंड के प्रभाव का आकलन एसडीजी की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है

स्वास्थ्य सेवा में नियामकीय व्यवस्था के बारे में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों के संकल्पों एवं प्रस्तावों का मिलान और विश्लेषण करना

प्रो. टी सी जेम्स

यह भी एक अध्ययन है जो चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच पर डब्ल्यूएचओ विश्व सम्मेलन के आयोजन के लिए डब्ल्यूएचओ के साथ आरआईएस की ज्ञान साझेदारी के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इस अध्ययन के अंतर्गत ब्रिक्स फोरम में पेश किए गए स्वास्थ्य नीति संबंधी प्रस्तावों का विश्लेषण किया जाएगा।

आईबीएसए फंड का अवलोकन

डॉ. बीना पांडे

वर्ष 2004 में अपनी स्थापना के बाद आईबीएसए फंड वर्ष 2006 में चालू हो गया जो स्थानीय सरकारों, राष्ट्रीय संस्थानों और कार्यान्वयन साझेदारों के साथ भागीदारी के माध्यम से मांग के आधार पर परियोजनाओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। अब तक 37.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी योगदान के साथ फंड ने 21 विकासशील देशों के साथ साझेदारी की है और 33 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है। आईबीएसए का प्रत्येक सदस्य देश हर साल फंड में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है जिसका उपयोग विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के लिए किया जाना है। आईबीएसए फंड का आकलन करने के लिए यह पेपर अल्प विकसित देशों में इस फंड से जुड़ी विभिन्न मौजूदा एवं पूरी हो चुकी परियोजनाओं के साथ–साथ गरीबों के क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण पर इनके सकारात्मक परिणामों के बारे में भी विस्तार से बताएगा। इन परियोजनाओं को अब सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति से जोड़ दिया गया है।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

आरआईएस में आईबीएसए फेलोशिप

आरआईएस लंबे समय से आईबीएसए से संबंधित मुद्दों पर काम करता रहा है। इस कार्यकलाप कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2017 में विदेश मंत्रालय में आईबीएसए फेलोशिप की शुरुआत की गई थी। ब्राजील के दो रिसर्च फेलो, दक्षिण अफ्रीका के एक और भारत के दो रिसर्च फेलो ने भाग लिया। उनके द्वारा तैयार शोध–पत्रों (पेपर) के आधार पर एक पुस्तक शीघ्र ही प्रस्तुत की गई। आईबीएसए फेलोशिप का दूसरा संस्करण फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत के रिसर्च फेलो ने भाग लिया था। उनके शोध–पत्रों (पेपर) के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर दरअसल जन–अनुकूल दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग को बढ़ावा देता है

भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन

भारत–अफ्रीका साझेदारी और अफ्रीका के महत्वाकांक्षी आर्थिक सहयोग एजेंडे के साथ सहभागिता: आरआईएस का अनुसंधान एवं नीतिगत मार्गदर्शन

भारत और कई अफ्रीकी देशों के बीच कूटनीतिक एवं आर्थिक जुड़ाव के तेजी से प्रगाढ़ होने की बदौलत हाल के वर्षों में भारत–अफ्रीका संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014–2018 के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के स्तर पर अफ्रीका की 23 यात्राएं और वर्श 2018–2021 की अवधि में अफ्रीका में 18 नए भारतीय मिशन खोलने की प्रतिबद्धता नए सिरे से हो रहे इस फोकस को प्रतिबिंबित करती है। जुलाई 2018 में युगांडा की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका के साथ गहन और प्रगाढ़ जुड़ाव के लिए 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित किया था जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच भावी व्यापार एवं निवेश संबंधों के लिए ठोस आधार बन सकते हैं। इसके अलावा, अफ्रीकी देशों के लिए भारत के विकास सहयोग संबंधी प्रयासों में विगत वर्षों में काफी विविधता आई है, जिनमें कई लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी), तकनीकी सहायता, मानव संसाधन का साझाकरण और परियोजना सहायता (प्रोजेक्ट सपोर्ट) के अन्य स्व रूप शामिल हैं। भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) दरअसल भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए एक संस्थागत प्रक्रिया की भूमिका निभाता रहा है।

बिम्सटेक क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा और वित्तीय प्रौद्योगिकियों का उपयोग

डॉ. प्रियदर्शी दाश

विनिमय दर में तेज उतार–चढ़ाव से निर्यात एवं आयात के मूल्य में अनिष्चितता रहती है और यह हेजिंग की लागत की दृष्टि से व्यापारियों के लिए काफी महंगा साबित होता है। इस पहलू पर वित्तीय सहयोग के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई है, जो विभिन्न देषों के बीच मुद्रा अदला–बदली की व्यवस्थाओं के अभ्युदय में अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, अकेले चीन ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार की सुविधा के लिए 31 मुद्रा अदला–बदली व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह जापान ने भी अपने एशियाई और अन्य व्यापार साझेदारों के साथ कई मुद्रा अदला–बदली व्यवस्थाएं की हैं। कई मुद्रा अदला–बदली व्यवस्थाओं के अलावा भारत ने अतीत में नेपाल, ईरान और रूस के साथ रुपये में व्यापार व्यवस्थाएं लागू की हैं। इस पृष्ठभूमि में बिम्सटेक देष भी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की संभावनाएं तलाश सकते हैं, ताकि विनिमय दर में बेतरतीब ढंग से होने वाले उतार–चढ़ाव से उत्पन्न वित्तीय जोखिम को कम किया जा सके। ब्लॉकचेन, आर्टिफिषियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती वित्तीय तकनीकों ने न केवल वित्तीय सेक्टरों को बदल कर रख दिया है, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों और समाज को सफतापूर्वक सशक्त भी बनाया है।

इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विषयों जैसे कि (ए) बिम्सटेक और अन्य क्षेत्रों में डिजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों के आकलन, (ख) स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय एवं बिम्सटेक क्षेत्रीय भुगतान व्यवस्थाओं की अवधारणा एवं स्वरूप, और (ग) वित्तीय प्रौद्योगिकियों को साझा करने में सहयोग के विषिश्ट तौर–तरीकों का गहराई से अध्ययन बिम्सटेक देषों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में किया जा सकता है। आरआईएस ने बीएनपीटीटी समूह के सदस्यों और अन्य निकायों के साथ कुछ अध्ययनों में योगदान करने का प्रस्ताव किया है। 'स्थानीय मुद्रा में व्यापार: नेपाल, ईरान और रूस के साथ भारत के रुपया व्यापार का चित्रण' विषय पर एक परिचर्चा पत्र पहले ही प्रकाशित हो चुका है।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

वित्तीय वैश्वीकरण और डिजिटल तकनीकों में उभार के साथ तालमेल बिठाने के उपक्रम में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय सहयोग की प्रकृति और क्षेत्र में बदलाव हुआ है। इसके अलावा, सन 1990 एवं 2000 के दशकों में छाये वित्तीय संकट जैसे हालात से बचने के लिए विदेशी मुद्रा को रिजर्व रखने के साथ इन देशों ने करंसी स्वैप अरेंजमेंट, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के प्रावधान पर लागत में कमी लाने के लिए इंटरनेट और डिजिटल बैंकिंग कारोबार को लोकप्रिय बनाने तथा त्वरित प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के रूप में वित्तीय सहयोग के कई उपकरणों की संभावनाएं तलाशी हैं। खुदरा एवं थोक बैंकिंग और व्यावसायिक लेन–देन के लिए फिनटेक को व्यापक रूप से बेहतर हल माना जाने लगा है। विकासशील देश होने के नाते भारत वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षमता से लैस मानव श्रम और प्रौद्योगिकियों के साथ फिनटेक एवं उभरते वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक संभावनाशील अगुवा हो सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक बड़ा और आकर्षक पड़ाव होने के रूप में भारत न केवल फिनटेक सेक्टर में नवाचार से लाभान्वित हो सकता है बल्कि वह बिम्सटेक तथा अन्य फोरम में भी क्षेत्रीय वित्तीय सहयोग में अपना योगदान दे सकता है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसीज केंद्रीय बैंकों और निजी कंपनियों द्वारा जारी की गई नवीन मुद्रा के समान उपकरण हैं। भारत में और इसके साथ अन्य विकासशील देशों में भी वित्तीय क्षेत्रों में लागू मौजूदा नियामक ढांचा अपर्याप्त एवं अपूर्ण माने जाते हैं। आरआईएस ने ऊपर लिखित सभी क्षेत्रों में बिम्सटेक तथा विकासशील देशों के संदर्भ में कुछ अध्ययन किए हैं।

डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो–करेंसी

प्रोफेसर बिश्वजीत बनर्जी और डॉ. प्रियदर्शी दाश

डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो–करेंसी दरअसल भुगतान एवं निपटान (सेटलमेंट) की दुनिया में नए प्रचलित या लोकप्रिय शब्द हैं। कई लोगों ने कैशलेस लेन–देन की बढ़ती प्राथमिकता के साथ–साथ उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान में आसानी को तरजीह दिए जाने को वैध या आधिकारिक मुद्रा के लिए खतरा मानना शुरू कर दिया है। वैसे तो डिजिटल मुद्राओं और संबंधित तकनीकी एवं नियामकीय मानकों को अपनाने पर समान वैश्विक रुख अब भी विकसित होने के चरण में ही है, लेकिन कई केंद्रीय बैंकों (या नीति–निर्माताओं) ने या तो इसे अपनाने के लिए नीतिगत उपाय कर लिए हैं या वे वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा, हिफाजत और विश्वसनीयता के लिए इस तरह के प्रपत्रों के निहितार्थों का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो–करेंसी के उपयोग में नियामकीय खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन वैध मुद्रा आधारित भुगतान और निपटान प्रणालियों को ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक, उपयोगकर्ता–अनुकूल और सस्ता बनाना बुद्धिमानी भरा कदम होगा जिन्हें वैध मुद्रा के बजाय डिजिटल मुद्रा को अपनाने की ओर अग्रसर होने वाले लोगों के लिए अक्सर व्यापक आकर्षण माना जाता है। चूंकि डिजिटल प्रौद्योगिकियां और ई–कॉमर्स व्यापक ताकतें हैं जिन्हें इतनी आसानी से पलटा नहीं जा सकता है, इसलिए केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता को विकृत करने वाली समानांतर प्रणाली को कार्य करने की अनुमति देने के बजाय डिजिटल मुद्राओं की ओर अग्रसर होने पर विचार कर सकते हैं। यद्यपि भारत ने डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो–करेंसी के मुद्दे पर क्रमिक रूप से धीरे–धीरे आगे बढ़ने का विकल्प चुना है, लेकिन इस संबंध में व्यापक होमवर्क या अध्ययन करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि देश में ई–कॉमर्स और भुगतान के डिजिटल तरीकों या साधनों के कैप्टिव उपयोगकर्ताओं (यूजर) की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है।

स्थानीय मुद्रा का उपयोग, फिनटेक और डिजिटल एवं क्रिप्टो–करेंसी निश्चित तौर पर बैंकिंग और गैर–बैंकिंग सेक्टरों में व्यापक बदलाव ला रही हैं, रोजगारों का सृजन करती हैं, और दक्षिण एशिया एवं बिम्सटेक क्षेत्रों में वित्तीय समावेश में अहम योगदान करती हैं।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

भारत और अन्य विकासशील देशों में फिनटेक सेक्टर – उभरते अवसर और नीतिगत चुनौतियां

फिनटेक का वादा और प्रौद्योगिकी गवर्नेंस की चुनौतियां: आरआईएस के लिए एक नया अनुसंधान एजेंडा

डॉ. प्रियदर्शी दाश

वित्तीय प्रौद्योगिकियां (फिनटेक) दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही हैं जो फिनटेक फर्मों के निवेश और भागीदारी में तेज रफ्तार से हो रही वृद्धि में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। वित्तीय सेक्टर में उदारीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार की बदौलत उभरते बाजारों और ब्रिक्स सहित विकासशील देशों ने बैंकिंग एवं गैर–बैंकिंग सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि और विविधीकरण दर्ज किया है। रूपांतरणकारी बदलाव लाने में सक्षम डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इत्यादि की मदद से निजी बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों ने वित्तीय सेवा उद्योग में नई तरह के व्यवसायों का पता लगाया है जिससे भारत, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं दक्षिण अफ्रीका जैसी प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संयोजन के साथ–साथ एकल–स्टॉप वाले यूनिवर्सल बैंकों का उद्भव भी हुआ है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में फिनटेक और इंश्योरटेक व्यवसायों की पैठ बढ़ाने की विशाल अप्रयुक्त संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विदेषी निवेशक और वेंचर कैपिटल फंड वित्तीय सेवा उद्योग के इस नवीन क्षेत्र में निवेश तलाशने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां एक ओर आईटी शिक्षा और डिजिटल साक्षरता के प्रसार से फिनटेक एवं इंश्योरटेक में रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और विकासशील देशों में वित्तीय समावेश सुनिश्चित होगा, वहीं दूसरी ओर सुदृढ़ नियामकीय एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अभाव में साइबर सुरक्षा और भगोड़े आर्थिक अपराधियों सहित विभिन्न अपराधों का खतरा पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है।

ग. व्यापार में सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण

भौतिक कनेक्टिविटी और व्यापार में सुविधा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के उत्प्रेरक हैं। विकास केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग एवं घरेलू बाजारों का एकीकरण संभव हो पाता है। इसी तरह सीमा पर बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, कस्टम संबंधी सुधार, निर्यात एवं आयात प्रक्रियाओं के लिए आईटी का उपयोग, प्रलेखन या दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करना, इत्यादि व्यापार में सुविधा से संबंधित सुधारों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आसियान देशों के अनुभव फिर से इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि आर्थिक कॉरिडोर या विकास कॉरिडोर से संबंधित दृष्टिकोण निश्चित तौर पर प्रभावकारी हैं। स्थानीय संसाधनों का संयोजन कर, स्थानीय औद्योगीकरण को सुविधाजनक बनाकर और निर्यात को बढ़ावा देकर विकास कॉरिडोर प्रतिभागी देशों के लिए सकारात्मक स्थितियां बनाते हैं। इस सामंजस्य का विश्लेषण करने के लिए आरआईएस दो महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रमों यथा एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी) और बिम्सटेक के तहत कई तरह के अध्ययन कर रहा है। जहां एक ओर एएजीसी पूर्ण सेक्टर को अध्ययनों के रूप में कवर करता है, वहीं दूसरी ओर बिम्सटेक क्षेत्रीय सहयोग के आशाजनक सेक्टरों के रूप में व्यापार, कनेक्टिविटी, फिनटेक इत्यादि का मोटे तौर पर जिक्र करता है।

जन–केंद्रित विकास के लिए महाद्वीपीय आर्थिक कॉरिडोर – आकांक्षाओं को ध्यान में रखना और संप्रभुता का सम्मान करना: साझेदारियों और अनुसंधान के जरिए समूचे परिदृश्य को उचित स्वरूप देने में आरआईएस की भूमिका

एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी)

क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, विशेष आर्थिक जोन, इत्यादि सहित कई स्थानिक विकास मॉडलों के माध्यम से दूर किया गया है। इनमें से विकास त्रिकोण, आर्थिक कॉरिडोर और विकास कॉरिडोर से जुड़ी अवधारणाएं अपेक्षित सामाजिक–आर्थिक प्रभाव प्राप्त करने में कहीं अधिक प्रभावकारी पाई जाती हैं। 'विकास कॉरिडोर' दरअसल 'ग्रोथ पोल' सिद्धांत के पूर्वानुमानों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है। इसमें विकास कॉरिडोर के विकास के क्रमिक पथ की परिकल्पना की गई है जो एक परिवहन कॉरिडोर से शुरू होकर एक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर तक, एक आर्थिक कॉरिडोर तक, और फिर एक विकास कॉरिडोर तक जाता है। इस अवधारणा के अनुसार, बेहतर कनेक्टिविटी से आंतरिक इलाकों में प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के प्रभावकारी उपयोग में सुविधा होगी और विकास केंद्रों में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण में तेजी आएगी। एशिया–अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी) दरअसल एसएससी के सिद्धांतों के अनुरूप विकास संविदा (डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट) अवधारणा की व्यापक स्वीकृति की एक अभिव्यक्ति है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एएजीसी में विकास कॉरिडोर का आइडिया दरअसल विकास की एक समग्र अवधारणा है जो किसी देश के प्रमुख क्षेत्रों को/किसी क्षेत्र को देश/क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों से स्थानिक संदर्भ में जोड़ता है। एएजीसी में जन–केंद्रित सतत विकास रणनीति की परिकल्पना की गई है जिसे इन चार खंभों पर मूर्त रूप दिया जाएगा (1) क्षमता एवं कौषल बढ़ाना, (2) गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना एवं संस्थागत कनेक्टिविटी, (3) विकास एवं सहयोग परियोजनाएं, और (4) लोगों के बीच पारस्परिक साझेदारी। भारत, जापान और एशिया एवं अफ्रीका के साझेदार देश उपर्युक्त चार स्तंभों में से प्रत्येक स्तंभ के तहत कई विकास परियोजनाएं शुरू करेंगे। एएजीसी के विभिन्न सेक्टरों पर प्रकाशित शोध पत्रों और सम्मेलनों एवं विविध परामर्श का ही यह परिणाम है कि 'एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोरः डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इन इंडो–पैसिफिक' शीर्षक से स्प्रिंगर की एक पुस्तक का प्रकाषन संभव हुआ है।

एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर दरअसल जन–अनुकूल दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

ग. व्यापार में सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण

पड़ोसी पहले और बिम्सटेक को मजबूत करनाः क्षेत्रीय प्रक्रियाओं में एक प्रारंभिक साझेदार के रूप में आरआईएस

दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए 'बिम्सटेक' की अनूठी क्षमता को ध्यान में रखते हुए आरआईएस मौजूदा समय में बिम्सटेक पर अपने शोध कार्य को सुदृढ़ कर रहा है। आरआईएस की वेबसाइट पर बिम्सटेक के लिए एक अलग वेबपेज विकसित किया जा रहा है। व्यापार, वित्त और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर तीन संपादित पुस्तकों की योजना बनाई गई है।

बिम्सटेक में और उससे परे आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना

बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) दरअसल दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा उप–क्षेत्रीय समूह है। व्यापार एवं निवेश, प्रौद्योगिकी, परिवहन व संचार, कृषि, पर्यटन, मत्स्य पालन, ऊर्जा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण व आपदा जोखिम प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन, और आतंकवाद एवं अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने जैसे सहयोग के 14 विविध क्षेत्रों के साथ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड सहित बिम्सटेक के सात सदस्य देशों ने पिछले दो दषकों में क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग को मजबूत करने के एक व्यापक अधिदेश को संजोया है। वर्ष 2017 में बिम्सटेक ने अपने अस्तित्व के 20 साल पूरे कर लिए। विभिन्न सेक्टरों से अपने 20 वर्षों के जुड़ाव के तहत समूह ने विशेषकर मतभेदों को कम करने और सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मतैक्य सुनिष्चित करने में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं जो निष्चित तौर पर सराहनीय है।

सहयोग और उम्मीदों का बिम्सटेक एजेंडा पिछले कुछ वर्शों में काफी अधिक विकसित हुआ है, जो सहयोग के नए एवं उभरते क्षेत्रों में व्यापक जुड़ाव के लिए सातों देशों के और भी अधिक इच्छुक होने की ओर संकेत करता है। वर्ष 2018 में काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के साथ–साथ प्राथमिकता वाले नए क्षेत्रों के रूप में नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) और पहाड़ के विशेष महत्व को रेखांकित किया गया। जहां तक भारत का सवाल है, बिम्सटेक भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के परिप्रेक्ष्य से एक जीवंत समूह है।

बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक–टैंक (बीएनपीटीटी) पर आगामी पांचवीं बैठक के मद्देनजर आरआईएस का कार्यकलाप कार्यक्रम इन महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस करेगाः हिंद–प्रशांत का अभ्युदय और बिम्सटेक के बीच साझेदारियों के लिए अवसर; समुद्री सुरक्षा एवं सामरिक सहयोग; व्यापार, वित्त एवं कनेक्टिविटी; सतत विकास लक्ष्य; नई प्रौद्योगिकियां एवं स्थानीय औद्योगीकरण; और स्वास्थ्य।

बिम्सटेक क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण के तहत सामंजस्यपूर्ण प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापार, स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा स्तंभों पर फोकस करने की आवश्यकता है।

ग. व्यापार में सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण

बिम्सटेक में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग

प्रोफेसर टी.सी. जेम्स

भारत की 'लुक ईस्ट., एक्ट ईस्ट' रणनीति के तहत भारत और अन्य बिम्सटेक देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास सहयोग पर एक अध्ययन करने की योजना है। इस अध्ययन के तहत यह भी पता लगाया जाएगा कि सीमावर्ती जिलों का विकास और पड़ोसी देशों के साथ भारत का सहयोग किस तरह से परस्पर जुड़ेगा। इसके एक हिस्से के रूप में 'त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवा के सार्वभौमीकरण की स्थिति का तथ्यात्मक विश्लेषण' तैयार किया गया है और नीति आयोग के साथ साझा किया गया है। भूटान में स्वास्थ्य सेवा पर एक तथ्यात्मक स्थिति–पत्र तैयार किया गया है और उसके आधार पर पॉलिसी थिंक टैंक के बिम्सटेक नेटवर्क में बिम्सटेक में स्वास्थ्य क्षेत्र के वित्त पोषण के तुलनात्मक विश्लेषण पर अध्ययन के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था जिसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। अध्ययन में इन मुद्दों पर गौर किया जाएगाः (i) स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सार्वजनिक व्यय प्रदान करने में क्या–क्या सार्वजनिक नीतिगत चुनौतियां हैं?, (ii) क्या समान वित्त पोषण स्वरूप (पैटर्न) हो सकते हैं?, (iii) वर्ष 2030 तक यूएचसी की प्राप्ति हेतु किफायती व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या–क्या नीतिगत और रणनीतिक उपाय किए जा सकते हैं?, (iv) स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी कौन–कौन सी सर्वोत्तम प्रथाएं या तौर–तरीके हैं जिन्हें विभिन्न देषों के बीच साझा किया जा सकता है?, और (v) स्वास्थ्य क्षेत्र के वित्तपोषण में बाह्य सहायता को उस राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंडे के लिए कैसे बेहतर रूप से इस्तेमाल में लाया जा सकता है जिसे आरआईएस ने इस अध्ययन के हिस्से के रूप में आजमाने का प्रस्ताव किया है। बिम्सटेक में स्वास्थ्य क्षेत्र के वित्तपोषण के तुलनात्मक विश्लेषण के वित्तपोषण पर एक प्रारंभिक प्रपत्र अभी मसौदा चरण में है।

बिम्सटेक क्षेत्र में एक संभावित उच्च शिक्षा हब के रूप में भारत का उभरना

डॉ. बीना पांडे

यह अध्ययन दक्षिण एशियाई और अन्य विकासशील देशों, विशेषकर बिम्सटेक के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए भारत की विकास सहायता पर केंद्रित है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में ही उच्च शिक्षण संस्थानों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। दरअसल, भारत ने स्वयं को उच्च शिक्षा के एक संभावित गंतव्य के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है जहां किफायती उच्च गुणवत्तापूर्ण या बेहतरीन शिक्षा सेवाएं प्रदान की जाती हैं और जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे आकर्शक विशेषता बन गई है।

इस पृश्ठभूमि में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित एसडीजी 4 को प्राप्त करने की पहली शर्त के रूप में गुणवत्ता, पहुंच, समानता और समावेश को बढ़ावा देने में भारत द्वारा अहम भूमिका निभाने की व्यापक गुंजाइश है। इसके अलावा, चूंकि सार्क ने अपनी चमक खो दी है, इसलिए अपनी पहल 'भारत में अध्ययन' के तहत भारत शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता में बिम्सटेक देशों के लिए एक सक्रिय भागीदार हो सकता है।

दक्षिण और बिम्सटेक क्षेत्र में एक संभावित शैक्षणिक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति का आकलन करने के लिए पहले खंड में उच्च शिक्षा प्रदान करने में अन्य देशों को भारत से मिली सहायता का ऐतिहासिक अवलोकन प्रस्तुत किया जाएगा। अगले खंड में देश के शैक्षणिक सहायता कार्यक्रमों और आपसी डिग्री की मान्यता में विकासषील देशों को शैक्षणिक सहयोग देने के तरीकों पर प्रकाश डाला जाएगा। तीसरा खंड भारत में विदेशी विद्यार्थियों की ताजा स्थिति पर प्रकाश डालेगा। अंतिम खंड में विदेशी विद्यार्थियों को आकर्शित करने में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में भारत की अंतर्निहित क्षमताओं एवं नीतिगत पहलों पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद भविष्य की कार्ययोजना हेतु सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह का उल्लेख किया जाएगा।

ग. व्यापार में सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण

बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक (बीएनपीटीटी) बैठक

ट्रैक टू प्रक्रिया का बीएनपीटीटी एक विशेष कारक है, जो क्षेत्रीय अकादमिक संस्थाओं द्वारा बिम्सटेक के सहयोग के एजेंडे के प्रति उनके योगदान को सुगम करने का काम करता है। इसके अलावा, बीएनपीटीटी का संस्थापक सदस्य होने के नाते आईआरएस बिम्सटेक सचिवालय एवं बिम्सटेक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अन्य देशों के सहयोगी संस्थाओं के साथ क्षेत्रीय सहयोग के विभिन्न मसलों, जिनमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, तकनीक और वित्त आदि शामिल है, के मुद्दे पर काम करता है। आरआईएस जनवरी 2021 में बीएनपीटीटी की 5 वीं बैठक का आयोजन करेगा जिसमें कोविड–19 के दुष्प्रभाव से निकलने की योजना पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही, इसके अगले साल होने वाले लीडर समिट में संभावित सहयोग के क्षेत्र पर भी विचार किया जाएगा।

भारत–यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारीः संभावनाएं और चुनौतियां

भविष्य के लिए साझेदारी – भारत–यूरोपीय संघ आर्थिक सहभागिता के नए परिदृश्य में भू–आर्थिक, भू–राजनीतिक और भू–रणनीतिक साधनों से लाभ उठाया जा रहा हैः आरआईएस में कार्य प्रगति पर

भारत एवं यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच पारस्परिक संबंध लंबे समय से कायम हैं और निरंतर मजबूत हो रहे हैं। इन संबंधों को द्विपक्षीय 'भौतिक, डिजिटल और पारस्परिक जन' कनेक्टिविटी को बढ़ाकर प्रगाढ़ बनाया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के मार्गदर्षन में आरआईएस ने राश्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य से भारत–यूरोपीय संघ की कनेक्टिविटी के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए हाल ही में एक अध्ययन किया है। इसके तहत इस तथ्य पर फोकस रहा है कि लोकतांत्रिक होने के नाते भारत एवं यूरोपीय संघ अपने आपसी लाभ के लिए 'पहुंच, समानता और समावेष' के सिद्धांतों पर आधारित व्यापक साझेदारी के जरिए कनेक्टिविटी के प्रति अपने साझा दृश्टिकोण को मजबूत कर सकते हैं और दुनिया भर में सतत विकास संबंधी प्रयासों में आवष्यक सहयोग दे सकते हैं। यह इतना अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कनेक्टिविटी संबंधी उपाय बड़ी तेजी से भू–आर्थिक, भू–राजनीतिक और भू–रणनीतिक साधन बनते जा रहे हैं। यह अध्ययन भारत–यूरोपीय संघ षिखर सम्मेलन के संदर्भ में किया गया है जो मार्च, 2020 में आयोजित होने वाला था। हालांकि, कोविड–19 के कारण षिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था।

आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाओं के बावजूद भारत–यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी अब भी एक ऐसा अहम क्षेत्र है जहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

घ. नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

इसके अंतर्गत दो कार्यक्रम यथा 'विज्ञान नीति कार्यक्रम' और 'विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम' हैं। दोनों ही कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक हैं। इन कार्यक्रमों से जुड़े संकाय अन्य कार्यक्रमों और प्रषिक्षण पाठ्यक्रमों में भी योगदान करते हैं। प्रथम कार्यक्रम में ये षामिल हैंः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति से संबंधित मुद्दे व थीम; नई प्रौद्योगिकियों के प्रभाव एवं निहितार्थ; जीनोम एडिटिंग एवं सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी उभरती तकनीकों का गवर्नेंस; आर्टिफिषियल इंटेलिजेंस के प्रभाव एवं निहितार्थ; डिजिटलीकरण एवं सतत विकास; और उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार (आरआरआई), जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति में एक नई अवधारणा एवं पद्धति या चलन है। आरआईएस इस कार्यकलाप कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में विदेष मंत्रालय के नेस्ट (नई एवं उभरती रणनीतिक प्रौद्योगिकियां) प्रभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्त पोशित विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम– यह भारत में विज्ञान कूटनीति से जुड़ा एकमात्र कार्यक्रम है जो डीएसटी द्वारा वित्त पोशित और समर्थित कार्यक्रम है। यह क्षमता निर्माण, नेटवर्कों को विकसित करने और विज्ञान कूटनीति में रणनीतिक चिंतन कार्य में संलग्न है। इस कार्यक्रम के तहत व्यापक गतिविधियां की जाती हैं, जिनमें प्रषिक्षण और केस स्टडीज सहित प्रकाषन, न्यूज अलर्ट षामिल हैं। इसके अलावा, विज्ञान कूटनीति पर एक पत्रिका प्रकाषित की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत विदेष स्थित भारतीय मिषनों, विषेशकर विज्ञान अताषे और इसके साथ ही नई दिल्ली स्थित विभिन्न देषों के दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों के विज्ञान परामर्षदाताओं की सेवाएं भी ली जा रही हैं।

पहुंच, समानता एवं समावेश और विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार नीतिः नीति और व्यवहार में लाने के लिए आरआईएस में वैश्विक निहितार्थों वाला एक अग्रणी अनुसंधान कार्यक्रम

विज्ञान नीति कार्यक्रम

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के साथ डॉ. कृष्ण रवि श्रीनिवास, डॉ. अमित कुमार, डॉ. निमिता पांडे और डॉ. कपिल पाटिल

यह कार्यक्रम अन्य बातों के अलावा विज्ञान नीति, प्रौद्योगिकियों, विषेशकर उभरती प्रौद्योगिकियों के नियमन और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से जुड़े मुद्दों व विशयों पर है। इस कार्यक्रम का दायरा व्यापक है और इस टीम के सदस्य अन्य बातों के अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं नवाचार और, प्रौद्योगिकी के आकलन पर भी काम करते हैं। मौजूदा समय में जारी परियोजनाओं और अनुसंधान कार्यक्रमों की थीम निम्नलिखित हैंः

1) प्रॉडिजीज (सतत विकास के लिए उभरती षक्तियों और यूरोप में डिजिटलीकरण पर अनुसंधान को बढ़ावा देना)

पहुंच, समानता एवं समावेश और विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार नीतिः नीति और व्यवहार में लाने के लिए आरआईएस में वैश्विक निहितार्थों वाला एक अग्रणी अनुसंधान कार्यक्रम

परियोजना का उद्देष्य सतत विकास और इसके विभिन्न आयामों जैसे कि सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय आयामों और इसके गवर्नेंस में डिजिटलीकरण के प्रभाव की व्यापक समझ विकसित करना है। इस परियोजना के तहत डिजिटलीकरण के सकारात्मक प्रभावों को साकार या प्राप्त करने की स्थितियों के साथ–साथ इस बारे में भी अध्ययन किया जाएगा कि आखिरकार कैसे संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। डिजिटलीकरण का लाभ समाज के सभी तबकों, विषेशकर गरीबों इत्यादि को मिले, यह सुनिष्चित करने हेतु भारत ने डिजिटलीकरण एवं विकास के लिए कई पहलें षुरू की हैं, और इसके साथ ही भारत में राश्ट्रीय स्तर पर प्रगति के लिए कई सेक्टरों में डिजिटलीकरण का उपयोग किया जा रहा है,

घ. नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए आरआईएस डिजिटलीकरण के प्रभावों को समझने के साथ–साथ यह जानने के लिए भी इस परियोजना का उपयोग कर सकता है कि डिजिटलीकरण आखिरकार कैसे सतत विकास में सकारात्मक योगदान दे सकता है और कैसे संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। यह परियोजना यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोशित की जा रही है और जर्मन विकास संस्थान द्वारा समन्वित की जा रही है।

2) न्यूहोराइजन उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार (आरआरआई) पर एक परियोजना है।

इस परियोजना यानी 'न्यूहोराइजन' का प्राथमिक उद्देष्य राश्ट्रीय एवं अंतर्राश्ट्रीय स्तरों पर अनुसंधान व नवाचार प्रणालियों में उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार (आरआरआई) को एकीकृत करने में सक्षम बनाना है। भारत के मामले में आरआईएस दरअसल डीएसटी की एसएसआर (वैज्ञानिक सामाजिक दायित्व) रूपरेखा और आरआरआई के तुलनात्मक अध्ययन पर काम कर रहा है। आरआईएस ने इस परियोजना के हिस्से के रूप में मार्च 2020 में कार्यषालाएं आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोविड के कारण इसे रद्द कर दिया गया था।

3) भारत में उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार को प्रासंगिक बनाने पर अध्ययनः डीएसटी द्वारा दो वर्शीय अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी गई है।

4) आर्टिफिषियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्सः यह दो वर्शीय कार्यकलाप कार्यक्रम अन्य बातों के अलावा रोबोटिक्स, चौथी औद्योगिक क्रांति और संबंधित थीम को कवर करता है। विदेष मंत्रालय के 'नेस्ट' के परामर्ष से रोबोटिक्स पर कार्यकलाप कार्यक्रम को संषोधित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार मानवाधिकारों, समावेष, विविधता, नवाचार एवं आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए उत्तरदायित्वपूर्ण विकास और एआई के उपयोग के लिए 'आर्टिफिषियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (जीपीएआई)' में षामिल हो गई है जो एक बहु–देष, बहु–हितधारक पहल है। इस प्रकार उत्तरदायी एआई के साथ–साथ एआई का उत्तरदायित्वपूर्ण विकास नए प्रचलित या लोकप्रिय षब्द बन गए हैं। ये इसके साथ ही नीतिगत चर्चाओं का हिस्सा हो गए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आरआईएस एक विषिश्ट स्थान सृजित करेगा और वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ मुख्यतः भारत पर फोकस करते हुए नीतिगत प्रासंगिक अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा। उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार (आरआरआई) पर आरआईएस के विषिश्ट कार्यों को देखते हुए एआई पर एक आरआरआई परिप्रेक्ष्य को पेष करने के साथ–साथ यह भी पता लगाया जाएगा कि आरआरआई को भारत में एआई से संबंधित नीति और अमल में कैसे प्रासंगिक बनाया जा सकता है। इसी तरह आरआईएस द्वारा विकसित एईआई (पहुंच, समानता और समावेष) रूपरेखा को यहां लागू किया जाएगा।

उभरती प्रौद्योगिकियांः विभिन्न परियोजनाओं के तहत आरआईएस उभरती प्रौद्योगिकियों पर निरंतर काम करता रहा है। हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर संस्थान सिंथेटिक बायोलॉजी, जीनोम एडिटिंग और, डिजिटल सीक्वेन्स इन्फॉर्मेषन (डीएसआई) पर काम कर रहा है। आरआईएस ने इससे पहले सिंथेटिक बायोलॉजी पर उस समय काम किया था जब यह भारत में अपने प्रारंभिक चरण में था। जीनोम एडिटिंग और डिजिटल सीक्वेन्स इन्फॉर्मेषन (डीएसआई) प्रमुख थीम के रूप में उभर रहे हैं। जीनोम एडिटिंग का अभ्युदय विभिन्न फसलों, पषुओं और इंसानों में एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में हो रहा है। सिंथेटिक बायोलॉजी पर आरआईएस के कार्यों में अन्य बातों के अलावा भारत और पूरी दुनिया में सिंथेटिक बायोलॉजी के विकास, सिंथेटिक बायोलॉजी के गवर्नेंस और इसके व्यापक प्रभावों को कवर किया जाएगा।

उभरती प्रौद्योगिकियों पर आरआईएस के व्यापक कार्यकलाप एआई, रोबोटिक्स, जैव विज्ञान में उभरती प्रौद्योगिकियों को कवर करते हैं और इसके तहत राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तरों पर नीतिगत मुद्दों पर बारीकी से गौर किया जाता है।

जीनोम एडिटिंग के व्यापक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए इसे कैसे अमल में लाएं और इसका नियमन करते हुए कैसे अधिकतम लाभ प्राप्त करें, यह वैश्विक चिंता का विशय बन गया है। आरआईएस इस संबंध में आईसीएमआर और डीबीटी में संलग्न नीति निर्माताओं की सेवाएं लेकर नीतिगत और गवर्नेंस से संबंधित पहलुओं पर गौर करेगा।

घ. नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

विज्ञान कूटनीति पर परियोजना

आरआईएस दो भिन्न एवं अनूठे दृष्टिकोण से एनआरआई / पीआईओ वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट का डेटाबेस बना रहा है

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के साथ डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, डॉ. कृष्ण रवि श्रीनिवास, डॉ. अमित कुमार, डॉ. निमिता पांडे, डॉ. कपिल पाटिल और स्नेहा सिन्हा

वर्श 2018 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने आरआईएस एवं राश्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (एनआईएएस), बेंगलुरू के लिए विज्ञान कूटनीति से जुड़ी एक परियोजना को मंजूरी दी। विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम अपनी विभिन्न गतिविधियों के जरिए क्षमता निर्माण, नेटवर्को को विकसित करने और रणनीतिक चिंतन में संलग्न है। 'साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू (एसडीआर)' का प्रकाषन पूरे साल में तीन बार होता है और इसका उद्देष्य इसे विज्ञान कूटनीति पर अंतरराश्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रिका बनाना है। एसडीआर का पिछला अंक मार्च 2020 में प्रकाषित किया गया था। पाक्षिक 'विज्ञान कूटनीति समाचार अलर्ट' नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं। इसे बड़ी संख्या में हितधारकों को ईमेल द्वारा भेजा जा रहा है।

आरआईएस ने एनआरआई/पीआईओ वैज्ञानिकों और एसटीईएम सेक्टरों के विदेषी प्रवासी प्रोफेषनलों के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म विकसित किया है। डेटाबेस के तहत अब तक दुनिया भर से एसएंडटी से जुड़े अनेक विशयों और सीमांत प्रौद्योगिकियों (फ्रंटियर टेक्नोलॉजी) में षोध करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों एवं टेक्नोक्रेट से 400 से भी अधिक प्रविश्टियां प्राप्त हुई हैं।

डेटाबेस के लिए अब तक भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट से 400 से भी अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं।

विज्ञान कूटनीति में संलग्न विभिन्न संस्थानों की निर्देषिका (डायरेक्टरी) इस परियोजना से संबंधित एक और प्रदेय है एवं इसे नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। वर्तमान में, इसमें विज्ञान कूटनीति संबंधी गतिविधियों/पाठ्यक्रमों में संलग्न दुनिया भर के 81 संस्थान षामिल हैं। आरआईएस ने कंप्यूटर विज्ञान, नैनो तकनीक, जीनोमिक्स सहित कई विशयों/क्षेत्रों और बुनियादी विज्ञान से जुड़े अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, इत्यादि से एकत्र की गई जानकारियों के आधार पर एनआरआई/पीआईओ वैज्ञानिकों/टेक्नोक्रेट्स का एक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में 400 प्रविश्टियां हैं और यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इत्यादि के संस्थानों को कवर करता है।

आरआईएस ने पूरे साल विभिन्न देषों के विज्ञान परामर्षदाताओं के साथ निरंतर बातचीत की। कोविड के कारण आने वाले महीनों में हम ऑनलाइन सलाह–मषविरा करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय दूतावासों एवं विदेष स्थित वाणिज्य दूतावासों की सेवाएं भी ली जा रही हैं और टीम के सदस्य जब विदेष जाते हैं तो वे राजदूतों और विज्ञान अताषे या सहचारी से मिलते हैं और कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। इन मुलाकातों के दौरान वे विज्ञान कूटनीति के जानकारों से भी बातचीत करते हैं।

सदर्न पर्सपैक्टिव ऑन साइंस डिपलोमेसी

घ. नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम)

आयुश मंत्रालय द्वारा आरआईएस में स्थापित एफआईटीएम का उद्देष्य पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) के क्षेत्र में व्यावहारिक नीति बनाने की दिषा में योगदान करना है। फोरम ने कई पहल की हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

पारंपरिक ज्ञान, आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षण

प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर

इस अध्ययन का उद्देष्य डिजिटल दुनिया सहित भारत में टीके, जीआर एवं संबधित पारंपरिक ज्ञान और टीसीई के संरक्षण के लिए वर्तमान में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की पर्याप्तता की जांच करना और मसौदा प्रपत्रों पर महत्वपूर्ण अवलोकनों को विपो आईजीसी के समक्ष प्रस्तुत करना था। यह जैव–चोरी की रोकथाम के लिए उनकी पर्याप्तता का आकलन करता है और मौजूदा कानूनों में आवष्यक परिवर्तन/परिवर्धन, यदि कोई हो, को प्रस्तावित करता है। अध्ययन के निम्नलिखित घटकों पर तीन विशय–क्षेत्र संबंधी दस्तावेज (स्कोपिंग पेपर) पहले ही प्रकाषित हो चुके हैं:

- पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण पर गहराई से अध्ययन पर स्कोपिंग पेपर
- पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण पर गहराई से अध्ययन पर स्कोपिंग पेपर
- 'आनुवांषिक संसाधनों के संरक्षण पर गहराई से अध्ययन' पर स्कोपिंग पेपर

अध्ययन के निश्कर्श पर अंतिम रिपोर्ट एफआईटीएम के सलाहकार बोर्ड को सर्कुलेट या प्रसारित की जा रही है, ताकि उनकी टिप्पणियां प्राप्त हो सकें।

टीसीएम के राष्ट्रीय और वैश्विक संवर्धन के लिए चीन की नीतिगत पहल

प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर

इस अध्ययन में अपनी सार्वजनिक/सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणाली में पारंपरिक चीनी चिकित्सा (टीसीएम) को मुख्यधारा में लाने और विश्व स्तर पर टीसीएम को बढ़ावा देने में चीन की पहलों का अन्वेशण किया गया। इसमें चीन के मुकाबले भारत की ताकत और कमजोरियों का तुलनात्मक आकलन किया गया जिससे प्राप्त सबकों को भारतीय चिकित्सा प्रणालियों (आईएसएम) को बढ़ावा देने के लिए षामिल/अनुकूलित किया जाना है।

टीसीएम के राश्ट्रीय और वैश्विक संवर्धन के लिए चीन की नीतिगत पहलों पर एक विशय–क्षेत्र संबंधी दस्तावेज (स्कोपिंग पेपर) वर्श 2019 में प्रकाषित किया गया था। फील्ड अध्ययनों और आगे के अनुसंधान पर आधारित अंतिम रिपोर्ट आयुश मंत्रालय को सौंप दी गई है।

एफआईटीएम कार्यक्रम के तहत अनुसंधान फेलोशिप

प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर

फेलोषिप का उद्देष्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा (आईटीएम) से संबंधित विशयों और चुनौतियों एवं संभावनाओं पर गहन अन्वेशण और अनुसंधान करना है। इस अन्वेशण के परिणामस्वरूप पुस्तकों सहित प्रकाषनों का उद्देष्य आईटीएम को बढ़ावा देने के लिए नीति संबंधी अनुसंधान जानकारियां प्रदान करना है। आईटीएम से संबंधित विभिन्न विशयों पर क्षेत्र विषेश के विषेशज्ञों द्वारा आमंत्रित व्याख्यान भी इस परियोजना का एक हिस्सा हैं। आरआईएस विभिन्न फेलोषिप और भावी प्रकाषनों की मंजूरी का प्रबंधन करता है। फेलोषिप कार्यक्रम के तहत दो अध्ययन निम्नलिखित द्वारा किए जा रहे हैं:

1. श्री प्रीत अमोल सिंह, एफआईटीएम डॉक्टरल फेलो और पीएचडी अभ्यर्थी, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, बठिंडा, पंजाब। परियोजना: पंजाब के चुनिंदा औशधीय पौधों पर कृशि–जलवायु, आर्थिक और अच्छी कृशि पद्धतियों को अपनाने संबंधी व्यवहार्यता या संभाव्यता अध्ययन।

2. सुश्री सौम्या अग्निहोत्री, एफआईटीएम डॉक्टरल फेलो और पीएचडी अभ्यर्थी, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल। परियोजना: पिथौरागढ़ जिले के कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक औशधीय पौधों का व्यापार और प्रबंधन।

दोनों ही अध्येताओं या फेलो ने अब तक तीन विस्तृत तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं और वे अप्रैल 2021 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे।

अध्याय 2

कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान आरआईएस की सक्रिय भूमिका

कोविड–19 वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और मानव सभ्यता को एक प्रकार के तीसरे विश्व युद्ध में उलझा दिया। आरआईएस इस अभूतपूर्व संकट पर निरंतर फोकस कर रहा है जो प्रत्येक गुजरते दिन के साथ गहराता हुआ नजर आ रहा था। संकाय ने मार्च 2020 में प्रकाशित आरआईएस डायरी के एक विशेष अंक में ठोस उपायों से जुड़े संभावित क्षेत्रों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। योगदानकर्ताओं में ये शामिल थेः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल, प्रोफेसर मिलिंदो चक्रवर्ती, प्रोफेसर टी. सी. जेम्स एवं उनकी टीम, डॉ. सब्यसाची साहा और डॉ. प्रियदर्शी डैश। श्री शुभोमय भट्टाचार्जी ने इस अंक को संपादित किया और प्रस्तावना अनुभाग में इस ओर ध्यान दिलाया कि दूसरे विश्व युद्ध में 150 मिलियन से भी अधिक सैनिक थे जिन्होंने छह साल तक लड़ाइयां लड़ीं; वर्तमान युद्ध के लिए डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि उसके पास विश्व भर में उपलब्ध चिकित्सा, पैरा मेडिकल और किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य कर्मियों (59 मिलियन) की कुल संख्या का एक तिहाई है।

वृहद मुद्दे

'कोविड–19: वैश्विक भागीदारी के लिए सही समय' [1] पर लेख में कोरोना वायरस के प्रकोप का मुकाबला करने हेतु सामूहिक रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्क सदस्य देशों और राजनेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने के प्रस्ताव की सराहना की गई। दवा उद्योग को रेखांकित करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि चीन अधिकतर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख व्यापार भागीदार है, ऐसे में आपूर्ति श्रृंखलाओं का तेजी से खंडित होना एक बड़ा झटका है। चीन में कोरोना वायरस की लगातार बिगड़ती स्थिति और इसके परिणामस्वरूप शटडाउन किया जाना दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल्स की संभावित कमी होने का संकेत देता है क्योंकि अकेले चीन सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) की वैश्विक मांग के लगभग 40 प्रतिशत की पूर्ति करता है।

अंतर–राज्य प्रवासियों पर लेख [2] में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि राज्य सरकारों को निजी कॉरपोरेट सेक्टर और कामगारों के संगठन सहित गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर अवश्य काम करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रोजगार का कोई व्यापक नुकसान न हो।

'वृहद आर्थिक प्रभाव' [3] शीर्षक वाले लेख में इस बारे में चर्चा की गई है कि कोविड–19 लॉकडाउन के संकट काल में आपूर्ति श्रृंखला को आखिरकार कैसे बरकरार रखा जा सकता है। उन्होंने इस अनिश्चित काल में रिजर्व बैंक की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और यह भी उल्लेख किया कि मौद्रिक नीति का उपयोग निर्दिष्ट महंगाई दर को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि पर्याप्त तरलता या नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए।

वैश्विक महामारी बीमा कोष

'वैश्विक महामारी बीमा कोष के लिए दलील' [4] शीर्षक वाले लेख में कहा गया है कि एसडीजी 3 में सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशहाली का आह्वान किया गया है और इस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सर्वसुलभ सेवा वाला स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक वैश्विक महामारी बीमा कोष एसडीजी 3 को प्राप्त करने का सच्चा अग्रदूत होगा जो यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवाएं अंततः सही मायनों में वैश्विक सार्वजनिक वस्तु प्रतीत हों।

फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए चुनौतियां

'कोविड–19 और भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग' [5] पर लेख में इस निराशाजनक परिदृश्य में अवसर देखने की कोशिश की गई और यह टिप्पणी की गई कि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों के तहत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इस संकट काल को एमएसएमई

कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान आरआईएस की सक्रिय भूमिका

के लिए एक अवसर में बदला जा सकता है। उन्हें चिकित्सा एवं सैनिटरी उपकरणों में किफायती प्रौद्योगिकी वस्तुओं जैसे कि मास्क, दस्ताने, कॉटन, इत्यादि के उत्पादन के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इससे निष्क्रिय या सुस्त पड़े सेक्टर में नई जान आएगी।

'कोविड काल के बाद के विश्व में औद्योगीकरणः भारत के लिए विकल्प' [6] विषय पर लेख में यह टिप्पणी की गई है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नई वास्तविकताओं से तालमेल बिठाना होगा। उनके लेखांकन तरीकों को सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागतों और जोखिमों तक फैलाना होगा। अतः अकेले उत्पादन के कारकों के संदर्भ में परिभाषित प्रतिस्पर्धी क्षमता पर्याप्त नहीं हो सकती है।

'कोविड–19ः भारतीय वित्तीय सेक्टर में अनिश्चितता को बनाए रख सकता है' [7] पर लेख में आगाह करते हुए कहा गया है कि कोविड–19 की दिशा में प्रयासों को जारी रखने के लिए भारतीय वित्तीय सेक्टर को आने वाले दिनों में कठिन समय के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

कोविड–19 और व्यापार, बहुपक्षवाद, डब्ल्यूएचओ एवं खाद्य सुरक्षा

आरआईएस कोविड–19 स्थिति पर आगे चर्चा करने के लिए आरआईएस डायरी के दो और विशेष संस्करण लाएगा। दूसरा अंक इन मुद्दों पर केंद्रित होगाः विश्व एवं भारत पर कोविड–19 के संबंधित प्रभाव और रोकथाम की रणनीतियों का क्रम, [8] ; कोविड–19 प्रकोप में डब्ल्यूएचओ की भूमिका को मजबूत करना, [9]; कोविड–19 काल में खाद्य और पोषण सुरक्षा, [10]; कोविड–19 एवं वैश्विक बहुपक्षवाद के लिए एक नई आशा [11] ; और सुधार पैकेज एवं कोविड–19,[12]

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और विष्व अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का प्रभाव

कोविड–19 से लड़ने के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर बहस फिर से शुरू गई है जिसने पूरे विश्व को एक अप्रत्याशित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संकट में डाल दिया है और जो दिन–प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया में समस्त आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां थम गई हैं। इन्हीं संदर्भों में आरआईएस डायरी के तीसरे विशेष संस्करण में इन विषयों पर लेख होंगेः कोविड–19 से निपटने के लिए भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना, [13] ; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार – कोविड–19 के प्रकोप से लड़ना, [14]; विज्ञान कूटनीतिः कोविड और उससे परे, [15] *द्वारा* बालाकृष्ण पिसुपति; प्रौद्योगिकी का वैश्विक गवर्नेंस, संस्थागत संरचना और कोविड–19 से निपटने के लिए भारतीय उपाय, [16]; भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और नवाचारः कोविड–19 महामारी के संदर्भ में एक अन्वेषण, [17]; विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार और महामारी की चुनौती, [18]; विश्व अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का प्रभाव, [19]; वैश्विक संस्थान और कोविड–19, [20]

आईपीआर

विश्लेषणात्मक अनुसंधान संबंधी जानकारियां प्रदान करने के अपने प्रयासों के तहत आरआईएस डॉ. कृष्ण रवि श्रीनिवास द्वारा लिखित 'कोरोना महामारी के काल में बौद्धिक संपदा अधिकार और नवाचार' [21] पर नीतिगत सारपत्र भी प्रस्तुत करेगा। इसमें यह चर्चा की जाएगी कि एचआईवी/एड्स संकट ने यह दिखा दिया है कि पारंपरिक बौद्धिक संपदा (आईपी) नियम और नवाचार के मॉडल लोगों तक किफायती पहुंच का आश्वासन नहीं देते हैं। इसके परिणामस्वरूप आईपी नियमों में कुछ बदलाव हुए और यह बात स्वीकार की गई कि आईपी एवं व्यापार नियमों को लोगों तक किफायती पहुंच में प्रमुख अवरोध नहीं बनने चाहिए। कोविड–19 के वर्तमान संकट ने पिछले संकट पर नए सिरे से गौर करने और उससे सबक लेने का अवसर प्रदान किया। अतः आईपी की भूमिका और एक प्रोत्साहन के रूप में इसके उपयोग पर नए सिरे से गौर करने की आवश्यकता होगी। 'चलता है' रवैया अब काम नहीं करेगा। वर्तमान संकट को समीक्षा एवं नए सिरे से गौर करने और नए प्रतिमान एवं दृष्टिकोण देने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। समय के साथ हम आईपी और नवाचार पर क्या कदम उठाएंगे, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। सवाल यह था कि सरकारें, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और अन्य हितधारक इसके लिए किस हद तक तैयार हैं।

कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान आरआईएस की सक्रिय भूमिका

स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार

'कोविड–19 महामारी और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी: सुधार के रास्ते', [22] पर नीतिगत सारपत्र में यह चर्चा होगी कि जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूएचओ, इत्यादि के गठन सहित विश्व व्यवस्था में बड़े बदलाव लाए थे, ठीक उसी तरह से महामारी के खिलाफ जल्द से जल्द एक महासंघ का गठन करना सभी राष्ट्रों के हित में होगा। चूंकि बेहद कम वायरस से बचाव के प्रभावकारी टीके उपलब्ध हैं, इसलिए निरंतर चौकस रहना पहले से ही सबसे अच्छा उपाय था। चौकस रहना, टीके (वैक्सीन) और एंटी–वायरल इस दिशा में आगे की राह हैं।

'कोविड–19 से सबक – रूपांतरणकारी जीपीडीपी के लिए उपयुक्त समय', [23] पर एक अन्य नीतिगत सारपत्र में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर चर्चा की जाएगी जो वर्तमान फोकस का विस्तार करने के लिए आशा की किरण हो सकती है, क्योंकि एक नए परिदृश्य को अनुकूल करने, 'न्यू इंडिया' के विजन को साकार करने, लॉकडाउन को धीरे–धीरे अनलॉक करने के बीच अंतर्निहित संभावनाओं को उन्मुक्त करने में ग्राम पंचायतें (जीपी) सक्षम साबित हो सकती हैं।

पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का महत्व

आरआईएस स्थित भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम) भी 'आयुष प्रणालियां और कोविड–19 महामारी', [24] पर नीतिगत सारपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि भारत की स्वास्थ्य सेवा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें बीमारी से जुड़ा भारी–भरकम बोझ, पर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना एवं कर्मियों का अभाव शामिल हैं।

इस तरह के परिदृश्य में आयुष 'आसानी से इस्तेमाल या दोहन योग्य संसाधन' है जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग एवं सोवा–रिग्पा की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां और होम्योपैथी की आधुनिक प्रणाली शामिल हैं।

एफआईटीएम का दूसरा नीतिगत सारपत्र वायरल रोगों में आरएंडडी, [25] का आकलन करता है और इस बात को सामने रखता है कि एलोपैथी में इस वायरल संक्रमण से बचाव की कोई विशिष्ट दवा न होने के मद्देनजर अब पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में भी इसका सही उपचार खोजने के अवसर उपलब्ध हो गए हैं। दरअसल, इन प्रणालियों में दो सहस्राब्दियों से भी अधिक समय तक वायरल महामारी का उपचार करने का लंबा अनुभव रहा है।

एसडीजी–3 और कोविड–19 पर तीसरा एफआईटीएम नीतिगत सारपत्र पारंपरिक चिकित्सा, [26] को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करते हुए इस बात पर प्रकाश डालेगा कि पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) प्रणालियां पूरी दुनिया को एसडीजी यथा 'सभी का अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली' की प्राप्ति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अब समय आ गया है कि टीएम सेक्टर को आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र के बराबर विकसित किया जाए।

महामारी और भारत–अफ्रीका संबंध

'डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू' का एक विशेष अंक भी प्रकाशित किया जाएगा जिसमें इन मुद्दों को कवर किया जाएगा: कोविड–19: महामारी एवं अफ्रीका [27]; अफ्रीका में कोविड–19 एवं विकास गतिशीलता [28] ; कोविड –19: अफ्रीका के लिए अप्रत्याशित चुनौती [29] ; कोविड–19 और विकसित होती भू–राजनीति [30] *द्वारा* ; वर्तमान संकट के दौरान एवं उससे परे भारत–अफ्रीका संबंध [31] *द्वारा* ; और कोविड–19 एवं अफ्रीका के समक्ष मौजूद चुनौतियां [32]

बिम्सटेक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग

चूंकि बिम्सटेक क्षेत्र के देश कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण कठिन समय से गुजर रहे थे, इसलिए इन देशों के लिए चुनौतियां सामान्य रूप से केवल स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के मोर्चों पर ही नहीं थीं, बल्कि महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने और इससे बाहर निकलने की रणनीतियों के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में सुचारू रिकवरी या आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की भी थीं। इस परिदृश्य की पृष्ठभूमि में आरआईएस 'कोविड–19 के बाद बिम्सटेक में आर्थिक सहयोग पर नए सिरे से गौर करने' विषय पर एक वेबिनार आयोजित करने की योजना बना रहा था जिसमें बिम्सटेक क्षेत्र के थिंक–टैंकों के विशेषज्ञों की भागीदारी होती। आरआईएस श्री वी. मुरलीधरन, विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार से वेबिनार में उद्घाटन भाषण देने के लिए संपर्क करेगा और माननीय श्री एम.शाहिदुल इस्लाम, महासचिव, बिम्सटेक सचिवालय, बांग्लादेश अपने विचारों को साझा करने के लिए उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे।

कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान आरआईएस की सक्रिय भूमिका

कोविड–19 के विभिन्न पहलुओं पर ई–कार्यशालाएं

आरआईएस स्थित वैश्विक विकास केंद्र अपनी ओर से पहल करते हुए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन के सहयोग से कोविड–19 के विभिन्न पहलुओं पर चार ई–कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।

ई–कार्यशालाओं का समग्र उद्देश्य कोविड–19 की रोकथाम एवं प्रबंधन में स्वास्थ्य प्रोफेशनलों के ज्ञान और जागरूकता को बढ़ाना होगा। ई–कार्यशालाओं के उद्देश्य ये होंगेः स्वास्थ्य प्रोफेशनलों को कोविड–19 महामारी पर विश्वसनीय जानकारियां प्रदान करना; विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने और कोविड–19 के विज्ञान एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देना; मरीजों के प्रभावकारी प्रबंधन और सुरक्षित ढंग से सेवाएं मुहैया कराने के लिए आवश्यक सूचना, प्रक्रिया एवं उपकरण ों से प्रतिभागियों को लैस करना; और महामारी के दौरान प्रभावकारी संचार सुनिश्चित करना एवं टीम को प्रेरित करने पर प्रतिभागियों को अनुकूल बनाना।

समाप्ति नोट्स

1 प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस
2 प्रोफेसर अमिताभ कुंडू
3 प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल
4 प्रोफेसर मिलिंदो चक्रवर्ती
5 प्रोफेसर टी. सी. जेम्स, नम्रता पाठक, अपूर्व भटनागर
6 डॉ. सब्यसाची साहा
7 डॉ. प्रियदर्शी डैश
8 प्रोफेसर एस के मोहंती
9 डॉ. भास्कर बालाकृष्णन
10 डॉ. पी. के. आनंद और श्री कृष्ण कुमार
11 श्री ऑगस्टीन पीटर
12 श्री सुभोमय भट्टाचार्जी
13 श्री अरबिंद मित्रा
14 श्री भास्कर बालाकृष्णन
15 श्री बालाकृष्ण पिसुपति
16 प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
17 प्रोफेसर टी. सी. जेम्स और अपूर्व भटनागर
18 डॉ. कृष्ण रवि श्रीनिवास
19 श्री बिस्वजीत बनर्जी
20 श्री अतुल कौशिक
21 डॉ. कृष्ण रवि श्रीनिवास
22 श्री जयदीप सी
23 डॉ. पी. के. आनंद
24 प्रोफेसर टी. सी. जेम्स और अपूर्व भटनागर
25 प्रोफेसर टी. सी. जेम्स और नम्रता पाठक
26 प्रोफेसर टी. सी. जेम्स और अपूर्व भटनागर
27 श्री अमर सिन्हा
28 श्री जॉन पैट्रिक
29 श्री महेश सी. अरोड़ा
30 श्री प्रत्यूष शर्मा
31 श्री अभिनव झा
32 सुश्री अदिति गुप्ता

अध्याय 3

नीतिगत शोध पत्र

विदेश मंत्रालय

- कोविड–19 के खिलाफ युद्ध – अनूठा जन–केंद्रित भारतीय मॉडल' पर एक नोट पीएमओ के साथ–साथ विदेश मंत्रालय को भी प्रदान किया गया।
- एलओसी और विकास सहायता पर कोरोना संकट के प्रभाव का आकलन' पर एक संक्षिप्त विवरण डीपीए, विदेश मंत्रालय को प्रदान किया गया।
- आरआईएस में एसडीजी कार्यकलाप कार्यक्रम के लिए एसटीआई पर एक नोट विदेश मंत्रालय के नेस्ट डिवीजन को प्रदान किया गया।
- एलओसी सुधार – भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास निधि (आईआईडीएफ) पर एक नोट विदेश मंत्रालय के डीपीए प्रभाग को भेजा गया।
- ब्रेक्जिट प्रभाव– यूरोपीय संघ के समझौतों' पर एक संक्षिप्त नोट पीपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय को प्रदान किया गया।
- कोरोना वायरस के व्यापार प्रभाव' पर एक नोट एफएस कार्यालय, विदेश मंत्रालय को प्रदान किया गया।
- आरआईएस ने 'भारत–यूरोपीय संघः भारत–यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारीः संभावनाएं और चुनौतियां' पर दो शोध–पत्र; और 'भारत–यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी' पर कार्य दस्तावेज विदेश मंत्रालय के ईडब्ल्यू डिवीजन को 'प्रदान किए।
- अफ्रीका में कृषि में चीन की पहल – प्रमुख बिंदु (आरआईएस से मिशन रिपोर्ट)' पर एक नोट विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

कृषि निर्यात, वित्त आयोग पर उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह

- वर्ष 2018 में कृषि, उर्वरक, कीटनाशकों और मशीनरी में भारत के व्यापार' पर एक नोट प्रदान किया गया।
- भारत में औषधीय पौधा सेक्टर के विकास की संभावनाओं' पर एक नोट प्रदान किया गया।

वाणिज्य विभाग

- आरआईएस ने वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता, वर्ष 2022 में जी20 की अध्यक्षता और एससीओ के वरिष्ठ अधिकारी आयोग की बैठक एवं वर्ष 2020 में एससीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक पर वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक जानकारियां प्रदान कीं।

नीतिगत शोध पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

- भारत, दक्षिण एशिया एवं म्यांमार – एसएंडटी सहयोग' और 'दक्षिण एशिया में एसएंडटी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता का उपयोग करने' पर आवश्यक जानकारियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रदान की गईं।

आयुष मंत्रालय

- विदेश में आयुर्वेद उत्पादों के विपणन के लिए एक नवीन दृष्टिकोण' पर एक नोट आयुष मंत्रालय को प्रदान किया गया।

वित्त मत्रांलय

- पड़ोसी देशों (दक्षिण एशिया और बिम्सटेक) में भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने' पर एक नोट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को प्रदान किया गया।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

- जैव प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग' पर नोट।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

- हिंद–प्रशांत क्षेत्र के विशेष संदर्भ में 'तटीय अनुसंधान में प्रगति' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हेतु संचालन समिति को आवश्यक जानकारियां प्रदान कीं।

अध्याय 4

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

एसडीजी कॉन्क्लेव 2020 – पूर्वोत्तर राज्यों की साझेदारियां, सहयोग और विकास

आरआईएस को नीति आयोग ने 'पूर्वोत्तर एसडीजी कॉन्क्लेव' के लिए अपने ज्ञान साझेदार के रूप में नामित किया था जिसका आयोजन 24–26 फरवरी 2020 को असम के गुवाहाटी में किया गया था। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग लिया था। इस प्रयास से जुड़े अन्य साझेदारों में असम सरकार, टाटा ट्रस्ट्स और यूएनडीपी शामिल थे। आरआईएस को पूर्वोत्तर और एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे सितंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच के छह महीनों की अवधि में अंतिम रूप दिया गया था। पूर्वोत्तर की विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उचित परामर्श के बाद ही इस रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया था। यह व्यापक परामर्श अक्सर उच्चतम राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर किया गया। इसके साथ ही आरआईएस के संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न राज्यों की राजधानियों में किए गए क्षेत्र दौरों (फील्ड विजिट) के माध्यम से भी व्यापक परामर्श का यह कार्य पूरा किया गया। जमीनी हकीकत एवं दृष्टिकोण से अवगत होने के लिए स्थानीय संसाधन व्यक्तियों और नेत्र फाउंडेशन के साथ मिलकर एक कार्यशाला अक्टूबर 2019 में आयोजित की गई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से भी इस बारे में मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। रिपोर्ट में ये अध्याय शामिल थे: राज्यों की पहल एवं एसडीजी का स्थानीयकरण; आर्थिक समृद्धि एवं सतत आजीविका के वाहक; जलवायु अनुकूल कृषि एवं विविधीकरण; पोषण, स्वास्थ्य व खुशहाली; शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता; संचार, कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचागत विकास; और एसडीजी का वित्तपोषण।

'भारत में शहरी स्वच्छता का भविष्य' विषय पर आरआईएस–प्रिया–एनआईयूए और यूरोपीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन

सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया) ने शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईयूए) एवं विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) के साथ साझेदारी में 27–28 फरवरी, 2020 को 'द्वितीयक श्रेणी

'पूर्वोत्तर एसडीजी कॉन्क्लेव, 24–26 फरवरी 2020, गुवाहाटी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय मंत्री, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण देते हुए।

के शहरों में एसडीजी का स्थानीयकरण' पर विशेष परामर्श के साथ 'शहरी स्वच्छता के भविष्य' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय मंत्री, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण दिया।

सम्मेलन के उद्देश्य ये थेः समावेशी एवं सतत शहरी स्वच्छता सेवाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए देश भर से प्राप्त सुगम्य अभिनव समाधानों को प्रदर्शित करना; नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, और समावेशी एवं सतत शहरी स्वच्छता सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनलों को एक साथ लाकर एक शिक्षण एवं ज्ञान प्लेटफॉर्म तैयार करना; और शहरी स्वच्छता कार्यक्रमों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नीतियों एवं संस्थानों को सूचित व प्रभावित करना। सम्मेलन का उद्देश्य एसडीजी 11 पर विशेषकर फोकस करते हुए द्वितीयक श्रेणी के भारतीय शहरों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण के लिए विशिष्ट रूपरेखा, कार्य पद्धति और व्यवस्था पर आम सहमति विकसित करना था। सम्मेलन के दौरान इन विषयों पर सत्र आयोजित किए गएः समावेशी एवं सतत शहरी स्वच्छता सेवाओं के लिए व्यवहार परिवर्तन और नागरिकों की सहभागिता में तेजी लाना; समावेशी एवं सतत शहरी स्वच्छता सेवाओं के लिए स्थानीय क्षमताएं विकसित करना; स्वच्छता कर्मियों (महिला स्वच्छता कर्मियों पर विशेष फोकस करने के साथ) के लिए निरोग कार्यस्थल; भारतीय शहरों में सतत जल एवं स्वच्छता सेवाओं के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करना; और द्वितीयक श्रेणी के शहरों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण पर एक विशेष सत्र।

'उज्बेकिस्तान–भारतः रणनीतिक साझेदारी के नए क्षितिज' पर गोलमेज चर्चा

आरआईएस ने नई दिल्ली स्थित उज्बेकिस्तान दूतावास के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 10 फरवरी 2020 को उज्बेकिस्तान दूतावास में 'उज्बेकिस्तान–भारतः रणनीतिक साझेदारी के नए क्षितिज' विषय पर एक गोलमेज चर्चा आयोजित की। भारत में उज्बेकिस्तान के राजदूत माननीय श्री फरहोद आर्जीव और आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने स्वागत भाषण दिया। भारत में उज्बेकिस्तान के राजदूत माननीय श्री फरहोद आर्जीव ने उज्बेकिस्तान की विकास गतिशीलता के बारे में चर्चा की। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अपर सचिव श्री बिद्युत बिहारी स्वेन ने उज्बेकिस्तान और भारत के बीच व्यापार

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

भारत में उज्बेकिस्तान के राजदूत माननीय श्री फरहोद आर्जीव स्वागत भाषण देते हुए।

संबंधों के विस्तार के लिए नए अवसरों पर व्याख्यान दिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में जेएस (ईआरएस) श्री मनीष प्रभात ने विशेष भाषण दिया। अन्य प्रमुख वक्ता ये थेः श्री राजीव कुमार, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच आईटी सहयोग के बारे में चर्चा की। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने 'डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित आर्थिक विकास में साझेदारी' विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। डॉ. संजीव बंसल, डीन (प्रबंधन अध्ययन का संकाय), निदेशक और प्रमुख, एमिटी बिजनेस स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े अनुभवों के बारे में चर्चा की। भारतीय कारोबारी समूहों के प्रतिनिधियों ने 'उज्बेकिस्तान में कारोबार करनाः भारतीय निवेशकों के लिए नए अवसर' विषय पर विशेष भाषण दिया। उज्बेकिस्तान के दूतावास के वाणिज्यिक अनुभाग ने 'प्रथम ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय निवेश फोरम (टीआईआईएफ)' पर एक प्रस्तुति (5–6 मार्च, 2020) दी। भारत में उज्बेकिस्तान के राजदूत माननीय श्री फरहोद आर्जीव ने समापन भाषण दिया। इसके बाद डिनर का आयोजन किया गया जिस दौरान उज्बेकिस्तान के बुखारा क्षेत्र के सांस्कृतिक समूह ने लाइव प्रदर्शन प्रस्तुत किया।

भारत की सामरिक पहचान

आरआईएस ने 6 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में डॉ. अनिल काकोडकर की पुस्तक 'फायर एंड फ्यूरीः ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी' पर उनके एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, साइंस डिप्लोमेसी फेलो, आरआईएस ने सत्र की अध्यक्षता की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। डॉ. एस के मल्होत्रा, पूर्व राजा रमन्ना फेलो, डीएई और सचिव, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी ने आरंभिक भाषण दिया। डॉ. अनिल काकोडकर के व्याख्यान के बाद एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें भाग लेने वाले विशिष्टजन ये थेः डॉ. सुरेश गंगोत्रा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार एवं सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, डीएई; प्रोफेसर आर. राजारमन, सैद्धांतिक भौतिकी के एमेरिटस प्रोफेसर, जेएनयू; और श्री पल्लव बागला, विज्ञान संपादक एवं स्तंभकार, एनडीटीवी।

भारत और चीन की पारंपरिक चिकित्सा पर संगोष्ठी

सरकार आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई तरह के उपाय करती रही है। इसी कवायद के तहत आयुष मंत्रालय ने आरआईएस में 'भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम)' की स्थापना की है। यह फोरम आयुष सेक्टर के व्यापार एवं उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रम और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करता रहा है। आयुष सेक्टर ने दरअसल एमएसएमई सेक्टर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रखी है। इस सेक्टर के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत को निर्यात प्रोत्साहन के अवसरों को खोलने के साथ–साथ अन्य देशों जैसे कि चीन के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखना होगा, जिसने पारंपरिक चीनी चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार में काफी अच्छी प्रगति की है।

चीन के सिचुआन स्थित चेंगदू यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन (सीयूटीसीएम) में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. वांग जांग हाल ही में अपने अध्ययन दौरे पर भारत आए थे। उनका संस्थान ही एकमात्र ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जो चीन में आयुर्वेद पर शोध कर रहा है। प्रोफेसर वांग की यात्रा के

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

'भारत और चीन की पारंपरिक चिकित्सा' पर संगोष्ठी।

दौरान हासिल किए गए गहन ज्ञान से लाभान्वित होने के अवसर का उपयोग करने के लिए आरआईएस ने 16 जनवरी 2020 को 'भारत और चीन की पारंपरिक चिकित्सा' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के भाषण से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आयुष मंत्रालय में अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक ने उद्घाटन भाषण दिया और इसके साथ ही सत्र की अध्यक्षता भी की। चीन के सिचुआन स्थित चेंगदू यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. वांग जांग के साथ–साथ प्रोफेसर तनुजा नेसारी, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली एवं सीईओ, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली भी इस अवसर पर प्रमुख वक्ता थे। प्रोफेसर टी.सी. जेम्स, सदस्य सचिव, एफआईटीएम और विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

'भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र: नियमन, स्थानीय विनिर्माण और व्यापार' पर ब्रेकफास्ट सेमिनार

आरआईएस ने 31 जनवरी 2020 को 'भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र: नियमन, स्थानीय विनिर्माण और व्यापार' विषय पर एक ब्रेकफास्ट सेमिनार का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता डॉ. शक्तिवेल सेल्वराज, निदेशक, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, वित्त पोषण और नीति, पीएचएफआई ने की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। डॉ. आभा जायसवाल, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने प्रस्तुति दी और चर्चा में भाग लेने वाले ये थे: डॉ. (सुश्री) ललिता गोयल, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर; प्रोफेसर टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस।

'सामाजिक उद्यमों और सोशल स्टॉक एक्सचेंज – भारतीय परिदृश्य' पर गोलमेज सम्मेलन

आरआईएस ने 17 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में 'सामाजिक उद्यमों और सोशल स्टॉक एक्सचेंज – भारतीय परिदृश्य' पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। डॉ. राजेश टंडन, अध्यक्ष, प्रिया ने सत्र की अध्यक्षता की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने परिचयात्मक या आरंभिक भाषण दिया। इसके बाद डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर और श्री अरुण नायर, विजिटिंग फेलो ने प्रस्तुतियां दीं। प्रस्तुति पर चर्चा के दौरान पैनलिस्ट ये थे: श्री हर्ष जेटली, वाणी; डॉ. मिराई चटर्जी, सेवा; श्री राकेश

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

'भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्रः नियमन, स्थानीय विनिर्माण और व्यापार' विषय पर ब्रेकफास्ट सेमिनार।

मारकस, एवीपीएन; डॉ. सीमा अरोड़ा, सीआईआई; सुश्री नित्या नांगलिया, सेवा; और श्री स्वप्निल अग्रवाल, धवानी आरआईएस।

'प्रभावकारी ऊर्जा बदलाव में ऊर्जा दक्षता की भूमिका' पर विशेष व्याख्यान

आरआईएस ने 13 जनवरी 2020 को 'प्रभावकारी ऊर्जा बदलाव में ऊर्जा दक्षता की भूमिका' विषय पर भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक श्री अभय बाकरे के एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने परिचयात्मक या आरंभिक भाषण दिया। इस व्याख्यान के बाद एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई। पैनलिस्ट ये थेः श्री ऑगस्टाइन पीटर, विजिटिंग फेलो, और श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, सलाहकार, आरआईएस।

प्रोफेसर क्लाउस लारेस, रिचर्ड एम. क्रासनो, विशिष्ट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना–चैपल हिल, अमेरिका के साथ संवादात्मक सत्र

प्रोफेसर क्लाउस लारेस, रिचर्ड एम. क्रासनो, विशिष्ट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना–चैपल हिल, अमेरिका के साथ एक संवादात्मक सत्र 3 फरवरी 2020 को जी. पार्थसारथी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया।

'भारत में आर्थिक मूल्य प्राप्त करने' पर पैनल परिचर्चा

आरआईएस ने स्कॉच के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 11 जनवरी 2020 को 'भारत में आर्थिक मूल्य प्राप्त करने' पर एक पैनल परिचर्चा का आयोजन किया। आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने इसकी अध्यक्षता की। पैनलिस्ट ये थेः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; श्री प्रदीप एस मेहता, महासचिव, कट्स इंटरनेशनल; डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं प्रमुख, यूएन–एस्कैप का दक्षिण एवं दक्षिण–पश्चिम एशिया (एसएसडब्ल्यूए) कार्यालय; डॉ. अभिजीत दास, प्रमुख एवं प्रोफेसर, डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने खुली परिचर्चा में भाग लिया।

प्रोफेसर क्लाउस लारेस, रिचर्ड एम. क्रासनो, विशिष्ट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना–चैपल हिल, अमेरिका के साथ संवादात्मक सत्र।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर समापन भाषण देते हुए।

11वां दिल्ली संवादः हिंद–प्रशांत महासागर क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाना

आरआईएस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में 13–14 दिसंबर, 2019 को 'दिल्ली संवाद (डीडी)' के 11वें संस्करण का आयोजन किया। 11वें दिल्ली संवाद की थीम थी 'हिंद–प्रशांत महासागर क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाना'। श्री वी. मुरलीधरन, माननीय विदेश राज्य मंत्री, भारत; और महामहिम डॉ. नोमवूयो नोक्वे, महासचिव, आईओआरए सचिवालय ने विशेष भाषण दिए, जबकि माननीया सुश्री रेटनो एल.पी. मार्सुडी, विदेश मंत्री, इंडोनेशिया ने मंत्रिस्तरीय मुख्य सत्र में विशिष्ट भाषण दिया। भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने समापन भाषण दिया। 10वें दिल्ली संवाद की कार्यवाही का भी विमोचन 11वें दिल्ली संवाद के दौरान किया गया जिसका शीर्षक था 'भारत–आसियान समुद्री सहयोग को मजबूत बनाना'। आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने मंत्रिस्तरीय मुख्य सत्र में धन्यवाद ज्ञापन किया। दिल्ली संवाद के 11वें संस्करण में आसियान देशों के कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ–साथ वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, प्रख्यात विद्वानों, प्रोफेशनलों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, व्यवसायियों और उद्योग जगत की हस्तियों सहित लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दिल्ली संवाद का 11वां संस्करण दरअसल दो दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें पांच पूर्ण सत्रों के अलावा एक मंत्रिस्तरीय मुख्य सत्र भी शामिल था। पांच पूर्ण सत्र इन विषयों पर आयोजित किए गए (1) हिंद–प्रशांत महासागर क्षेत्र में सेतु निर्माण, (2) हिंद–प्रशांत निर्माणः उभरती संरचना, (3) हिंद–प्रशांत महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, (4) औद्योगिक–क्रांति 4.0 एवं हिंद–प्रशांत, और (5) बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का भविष्य। श्री विकास स्वरूप, सचिव (सीपीवी और ओआईए), विदेश मंत्रालय ने स्वागत समारोह की मेजबानी की और भारत के माननीय विदेश मंत्री ने 13 दिसंबर, 2019 को प्रतिभागियों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। दिल्ली संवाद का 11वां संस्करण समापन सत्र के साथ संपन्न हुआ जिस दौरान 'आगे की राह' पर फोकस किया गया।

'अंतर्राष्ट्रीय कर मामलों में दक्षिण ीय सहयोग' पर तीसरा वार्षिक विकासशील देश फोरम

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

अंतर्राष्ट्रीय कराधान मुद्दे भी उन महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौतियों में शामिल हैं जिनका सामना वर्तमान में विकासशील देशों को करना पड़ रहा है। विकासशील देशों को कर अदायगी से बचने, कर चोरी और कर आधार के क्षरण जैसे सामान्य मुद्दों के अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था, निष्कर्षण उद्योगों, बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर चोरी, आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (बीईपीएस), भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खतरे और अवैध वित्तपोषण से जुड़ी चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर किसी भी वैश्विक संगठन के अभाव में ये मामले अक्सर निर्णय लेने को जटिल बना देते हैं क्योंकि विभिन्न कर क्षेत्राधिकार भिन्न–भिन्न राष्ट्रीय नियमों, नियमनों और कानूनी रूपरेखा के अंतर्गत आते हैं। चूंकि विकासशील देश वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए घरेलू संसाधन जुटाने में दक्षता विभिन्न देशों के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन गई है। आरआईएस विकास वित्त, विशेषकर घरेलू संसाधन जुटाने में मजबूती लाने, बाह्य या विदेशी वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने एवं रकम लीकेज को कम–से–कम करने के लिए संस्थागत ढांचे का निर्माण करने और बेशकीमती संसाधनों के दुरुपयोग की रोकथाम पर फोकस करता रहा है। विशेष रूप से, घरेलू संसाधन जुटाने के लिए आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण, ट्रांसफर प्राइसिंग, भगोड़े आर्थिक अपराधियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान के निहितार्थ प्रमुख चिंता का विषय हैं। चूंकि विकास वित्त पर आरआईएस के कार्यकलाप कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य कराधान मामलों पर वार्षिक विकासशील देश फोरम की साउथ सेंटर पहल से मेल खाते हैं, इसलिए आरआईएस और साउथ सेंटर ने संयुक्त रूप से 9–10 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय कर मामलों में दक्षिणीय सहयोग' विषय पर तीसरा वार्षिक विकासशील देश फोरम आयोजित किया।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस एवं प्रो. कार्लोस कोररिया, कार्यकारी निदेशक, साउथ सेंटर ने विकासशील देशों के समक्ष मौजूद अंतर्राष्ट्रीय कराधान से जुड़े मुद्दों की व्यापक रूपरेखा पेश की और कराधान मामलों पर भविष्य के रोडमैप (खाका) की परिकल्पना करने के लिए इस फोरम की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। श्री वी. मुरलीधरन, माननीय विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण दिया और 'कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की मौजूदा संयुक्त राष्ट्र समिति' के स्थान पर 'संयुक्त राष्ट्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी कर निकाय' के गठन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस निकाय को डिजिटल कंपनियों के कराधान, गलत ट्रांसफर प्राइसिंग की चुनौतियों, मुनाफे या रॉयल्टी के निर्धारण और निष्कर्षण उद्योग में तकनीकी सेवाओं के प्रभावकारी कराधान के साथ–साथ अवैध वित्तीय प्रवाह, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण तथा चोरी की गई संपत्तियों की वसूली से संबंधित मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। मोटे तौर पर यह महसूस किया गया कि विकासशील देशों की कर नीतियों और प्रशासन से जुड़े अनुभवों एवं नवाचारों को पहचानने की आवश्यकता है, जो ओईसीडी के अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग संबंधी मानकों एवं मानदंडों में परिलक्षित नहीं होता है

माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन उद्घाटन भाषण देते हुए।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, राजदूत एस.टी. देवारे और डॉ. नागेश कुमार सत्र के दौरान उपस्थित हैं।

और जो विकसित देशों की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। श्री अखिलेश रंजन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पूर्व सदस्य ने विभिन्न वैश्विक कराधान मुद्दों जैसे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, बीईपीएस और अप्रत्यक्ष संपत्तियों पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। डॉ. प्रियदर्शी डैश, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस ने 'लाभ हस्तांतरण, भगोड़े आर्थिक अपराधियों और अवैध वित्तीय प्रवाह के सार निहितार्थों' पर प्रस्तुति दी। भारत की ओर से भागीदारी के अलावा 18 अन्य विकासशील देशों के प्रतिभागियों ने भी फोरम में भाग लिया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कर अधिकारियों, शिक्षाविदों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसायटी के हितधारकों सहित 70 से भी अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। फोरम के दौरान छह तकनीकी सत्र और दो 'मुक्त समूह परिचर्चा' सत्र आयोजित किए गए।

फोरम ने कराधान के मुख्य क्षेत्रों के साथ–साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था और सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों से संबंधित कई मुद्दों पर भी गहन विचार–विमर्श किया। प्रति वर्ष 500 अरब अमेरिकी डॉलर का भारी–भरकम राजस्व नुकसान होने के अनुमान को ध्यान में रखकर फोरम ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का व्यापक समर्थन किया। 'दक्षिणीय सहयोग या विकासशील देशों के बीच सहयोग' को संयुक्त राष्ट्र की संरचना के अंतर्गत कराधान मुद्दों को प्रभावकारी ढंग से सुलझाने के लिए सबसे व्यावहारिक प्लेटफॉर्म के रूप में देखा गया। विचार–विमर्श से उभर कर सामने आए प्रमुख सुझाव ये हैं: ट्रांसफर प्राइसिंग मानक तैयार किए जाएं, व्यापक गठजोड़ के नियम बनाए जाएं, भिन्नात्मक बंटवारे की उपयुक्तता को स्पष्ट किया जाए, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएं, विभिन्न क्षेत्राधिकारों में कर लगाने के अधिकारों पर टकराव को कम किया जाए, अप्रत्यक्ष संपत्तियों का विपणन (मार्केटिंग) किया जाए, डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान, और पूंजीगत लाभ के कराधान के लिए नियम तैयार किए जाएं। विभिन्न विपणन क्षेत्राधिकारों में सामान्य लाभ का वितरण, उपभोक्ताओं से सौदा करने वाले उद्योगों एवं मध्यवर्ती फर्मों के बीच सेवाओं के वितरण से संबंधित डेटा की अनुपलब्धता, बड़े पैमाने पर कर चोरी, आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण का बढ़ता खतरा, डिजिटल अर्थव्यवस्था का उदय और कारोबार के नए मॉडल विकासशील देशों के कर अधिकारियों के लिए प्रमुख चिंताओं के रूप में उभर कर सामने आए। विकासशील देशों में अनुचित कर नियोजन, आपूर्ति श्रृंखला का विखंडन या विभाजन, लेन–देन का विभाजन, ऋणग्रस्तता के कारण हल्का पूंजीकरण और क्षमता निर्माण ऐसी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जो निष्कर्षण उद्योगों के कराधान से संबंधित हैं। देश–दर–देश रिपोर्टिंग, संपत्ति वसूली की मजबूत व्यवस्था, कर चोरी के रूप में संसाधन लीकेज एवं अवैध वित्तीय प्रवाह की रोकथाम, भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगाम कसने, बैंकों में धोखाधड़ियों व लाभ हस्तांतरण की रोकथाम, इत्यादि से विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन बेहतर ढंग से हो सकेगा। विकासोन्मुख कर नीतियां तैयार करना, आंकड़ों की सार्वजनिक उपलब्धता को बढ़ाना, टैक्स दरों में अंतर से लाभ उठाने के अंतर्निहित अवसरों को रोकना, कर प्रोत्साहन को तर्कसंगत बनाना और गलत ट्रांसफर प्राइसिंग की घटनाओं को कम करना विकासशील देशों में कराधान के संबंध में शीर्ष नीतिगत प्राथमिकताएं हो सकती हैं। फोरम ने अन्य सुझावों के अंतर्गत एक विशेष 'कर राजनयिक कैडर' के साथ–साथ एक विशिष्ट एवं प्रभावकारी 'विकासशील देश प्लेटफॉर्म' भी बनाने की आवश्यकता पर विचार–विमर्श किया जिससे विकासशील देशों के कर अधिकारियों को अपने लिए

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

उपयुक्त 'कर सहयोग व्यवस्थाओं' पर परिचर्चा और विकसित करने में सहूलियत होगी।

'दक्षिण एशिया में सतत विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता का दोहन करने' पर क्षेत्रीय नीतिगत संवाद

आरआईएस ने संयुक्त राष्ट्र–एस्कैप के साथ मिलकर 20 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में 'दक्षिण एशिया में सतत विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता का दोहन करने' पर क्षेत्रीय नीतिगत संवाद का आयोजन किया। इसने दक्षिण एशिया में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिए उप–क्षेत्रीय और क्षेत्रीय सहयोग का अधिकतम इस्तेमाल करने हेतु प्रमुख अवसरों के साथ–साथ चुनौतियों पर भी चर्चा करने के लिए भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एवं श्रीलंका के भी थिंक–टैंकों के जाने–माने प्रमुखों को एकजुट किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. नागेश कुमार, प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र एस्कैप – दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय (यूएनएस्कैप – एसएसडब्ल्यूए) और डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के आरंभिक भाषणों के साथ हुआ। प्रख्यात वक्ताओं में ये शामिल थे: श्री नजीर कबीरी, कार्यकारी निदेशक, बिरूनी संस्थान, अफगानिस्तान; डॉ. सेलिम रेइहान, कार्यकारी निदेशक, एसएएनईएम, बांग्लादेश; श्री सोनम ताशी, प्रमुख, नीति एवं नियोजन प्रभाग, आर्थिक मामलों का मंत्रालय, भूटान; श्री दिलीप चेनॉय, महासचिव, फिक्की; डॉ. पॉश राज पांडेय, अध्यक्ष, साउथ एशिया वॉच ऑन ट्रेड इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपाल; और डॉ. दुशनी वीराकून, कार्यकारी निदेशक, श्रीलंका नीतिगत अध्ययन

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रतिभागी।

संस्थान (आईपीएस), श्रीलंका। इससे पहले प्रतिनिधियों ने संकाय के साथ एक संवादात्मक सत्र के लिए आरआईएस का भी दौरा किया।

वैश्वीकृत दुनिया में गैर–पारंपरिक आर्थिक और सुरक्षा जोखिम

आरआईएस ने 'द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी, एडवोकेसी, एंड गवर्नेंस (आईपीएजी) एशिया पैसिफिक' के साथ साझेदारी में 28 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में 'वैश्वीकृत दुनिया में गैर–पारंपरिक आर्थिक और सुरक्षा जोखिम' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन ने गैर–पारंपरिक सुरक्षा और आर्थिक परिदृश्य के विषय विशेषज्ञों को एकजुट किया, ताकि उन विभिन्न आर्थिक एवं सुरक्षा खतरों पर विचार–विमर्श किया जा सके जिनका सामना वैश्विक समुदाय को करना पड़ रहा है। सम्मेलन के दौरान इन खतरों से निपटने के लिए अनेक नीतिगत रणनीतियां और विकल्प प्रस्तुत किए गए। इस पूरे आयोजन में ये सत्र शामिल थे: पर्यावरण एवं ऊर्जा सुरक्षा; प्रवासन (माइग्रेशन); बिजनेस सत्र;

प्रोफेसर एस.के. मोहंती संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का प्रभाव और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर साइबर वर्ल्ड का वर्चस्व तथा मानव एवं आर्थिक सुरक्षा। आरआईएस की ओर से प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक; प्रो. अमिताभ कुंडू, प्रतिष्ठित फेलो; डॉ. पी. के. आनंद, विजिटिंग फेलो; श्री कृष्ण कुमार, विजिटिंग फेलो; डॉ. प्रियदर्शी डैश, सहायक प्रोफेसर और श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, सलाहकार ने विचार–विमर्श में भाग लिया। विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

हिंद–प्रशांत क्षेत्र के विशेष संदर्भ में तटीय अनुसंधान में प्रगति

राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (एनसीसीआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार और आरआईएस ने संयुक्त रूप से चेन्नई में 17–19 दिसंबर, 2019 के दौरान 'हिंद–प्रशांत क्षेत्र के विशेष संदर्भ में तटीय अनुसंधान में प्रगति' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉ. एम. राजीवन ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया। डॉ. शैलेश नायक, पूर्व सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं वर्तमान में निदेशक, एनआईएएस और प्रो. एस. के. मोहंती उद्घाटन सत्र में सम्मानित अतिथि थे।

संगोष्ठी के दौरान नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) सहित तटीय अनुसंधान के चुनौतीपूर्ण और उभरते क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चाएं हुईं। इस संगोष्ठी ने तटीय अनुसंधान के इन प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति से जुड़े वैज्ञानिक ज्ञान को साझा करने के लिए एक आम मंच या प्लेटफॉर्म प्रदान किया।

संगोष्ठी ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र के शोधकर्ताओं का व्यापक ध्यान आकर्षित किया और इसमें शैक्षणिक क्षेत्र (विश्वविद्यालय, आईआईटी), राष्ट्रीय संस्थानों (एनआईओ, एनसीईएसएस, सीएमएलआरई, आईएनसीओआईएस, एनसीएससीएम, आईसीएआर) तथा सरकारी विभागों (सीडब्ल्यूपीआरएस, एनडीएमए, डीएसटी इत्यादि) ने भागीदारी की। अन्य देशों जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्रिटेन, अमेरिका, यूक्रेन, ईरान, सऊदी अरब, घाना के प्रतिभागियों ने भी इसमें भाग लिया। प्रोफेसर एस. के. मोहंती ने भी ''भारत के लिए 'ब्लू इकोनॉमी' की प्रासंगिकताः नए विकास प्रतिमान के साथ प्रयोग'' विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

जैसा कि सर्वविदित है, नीली अर्थव्यवस्था आम तौर पर एक स्वीकार्य विकास प्रतिमान के रूप में उभर कर सामने आई है जिसने सतत विकास के साथ आर्थिक विकास को प्रभावकारी ढंग से संयोजित किया है। आरआईएस ने एक ब्लू इकोनॉमी फोरम (बीईएफ) बनाया है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर की संभावनाओं एवं नीली अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में अवधारणा को बढ़ावा देने हेतु संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म मुहैया कराना; सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के प्रोफेशनलों को नियमित रूप से आवश्यक जानकारियां प्रदान करना; और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में इसको बड़ी सहजता से अपनाने की हिमायत करने को बढ़ावा देना है। यह फोरम हिंद महासागर और अन्य क्षेत्रों के नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं कारोबारी समुदाय के बीच आपसी संवाद व जुड़ाव को सुविधाजनक बनाता है।

दक्षिण एशिया हरित ऊर्जा (सेज) शिखर सम्मेलन 2019

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर पांचवें पायदान पर पहुंचने के लिए भारत ने महज कुछ ही वर्षों में काफी लंबा सफर तय कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को दोगुना कर 450 गीगावाट कर दिया जिससे यह संकेत मिलता है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर देश का फोकस लंबी अवधि के लिए है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 में बताया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अगले एक दशक में और उसके बाद भी हर वर्ष 30 अरब डॉलर से भी अधिक का निवेश अवसर मिलने की उम्मीद है।

ऐसे में यहां चुनौती भारत की नवीकरणीय ऊर्जा गाथा में निवेशकों की पर्याप्त दिलचस्पी सुनिश्चित करने की है। देश

दक्षिण एशिया हरित ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2019 में प्रतिभागी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

में कुछ सौर और पवन ऊर्जा पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है। यही नहीं, देश में इस तरह की कई और परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किफायती वित्तपोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना कुछ ऐसा मामला है जिसके लिए भारत के दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अतः इस बात पर विचार–मंथन करना अत्यंत आवश्यक है कि हरित ऊर्जा के विकास के वित्तपोषण में मदद के लिए एक क्षेत्रीय वित्तीय संरचना आखिरकार कैसे बनाई जा सकती है।

जलवायु के क्षेत्र में भारत अपने नेतृत्व के तहत ऊर्जा की मांग, आर्थिक विकास और पर्यावरण में समुचित संतुलन स्थापित करने में जुटा है जिससे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों यथा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका को भी काफी सहूलियत होगी। ऊर्जा सुरक्षा पर कोई भी समकालीन वार्तालाप भंडारण की चर्चा किए बिना संभव नहीं है। भारत को एक भंडारण नीति की नितांत आवश्यकता है क्योंकि वह अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों पर तेजी से अमल कर रहा है।

ऐसे अनगिनत नवाचार और प्रौद्योगिकियां हैं जिन्हें भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकता है। यह निकाय न केवल अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नेतृत्व में अनुकरणीय है, बल्कि सदस्य देशों को ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैसी प्रौद्योगिकियों को साझा करने और अभिनव बनाने में सक्षम भी बनाता है जिन्हें सदस्य देशों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल बनाया जा सकता है।

प्रमुख हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उपर्युक्त मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए द एशिया फाउंडेशन (टीएएफ) और आरआईएस ने 16 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में 'दक्षिण एशिया हरित ऊर्जा (सेज) शिखर सम्मेलन 2019' का आयोजन किया।

भारत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में हरित ऊर्जा के विकास में बेहतर ढंग से सक्षम बनने हेतु कारगर समाधानों की तलाश के लिए आयोजित तकनीकी सत्रों में क्षेत्रवार विशेषज्ञों ने इन विषयों पर गहन विचार–विमर्श किया: नवीकरणीय ऊर्जा का वित्तपोषण करना; ऊर्जा में व्यापक परिवर्तन– नीतिगत चुनौतियों से पार पाना; और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी। कार्यक्रम की शुरुआत सुश्री नंदिता बरुआ, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव (भारत), द एशिया फाउंडेशन के स्वागत भाषण के साथ हुई, जबकि आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने आरंभिक भाषण दिया। डॉ. टिमोथी केंडल, आर्थिक परामर्शदाता, ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने विशेष भाषण दिया। श्री आनंद कुमार, सचिव, एमएनआरई, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण पर आयोजित पहले सत्र का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के लिए किफायती वित्तपोषण के ऐसे नए स्रोतों की पहचान करना और ऐसी क्षेत्रीय वित्तीय संरचनाओं का पता लगाना था, जो इस क्षेत्र में हरित ऊर्जा के विकास का वित्तपोषण करने में मदद कर सके। इसका संचालन श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, सलाहकार, आरआईएस द्वारा किया गया। सुश्री अनिंद्या उपाध्याय, वरिष्ठ सलाहकार (नवीकरणीय ऊर्जा), टीएएफ ने 'ऊर्जा में व्यापक परिवर्तन– नीतिगत चुनौतियों से पार पाना' विषय पर आयोजित दूसरे सत्र का संचालन किया। इस सत्र के दौरान भारत में तेजी से विकसित हो रहे नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में मौजूद नीतिगत एवं नियामकीय चुनौतियों और हरित उर्जा के सीमा पार व्यापार के लिए उपलब्ध अवसरों पर फोकस किया गया।

'एसडीजी के लिए एसटीआई के अधिकतम इस्तेमाल' पर पैनल परिचर्चा।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

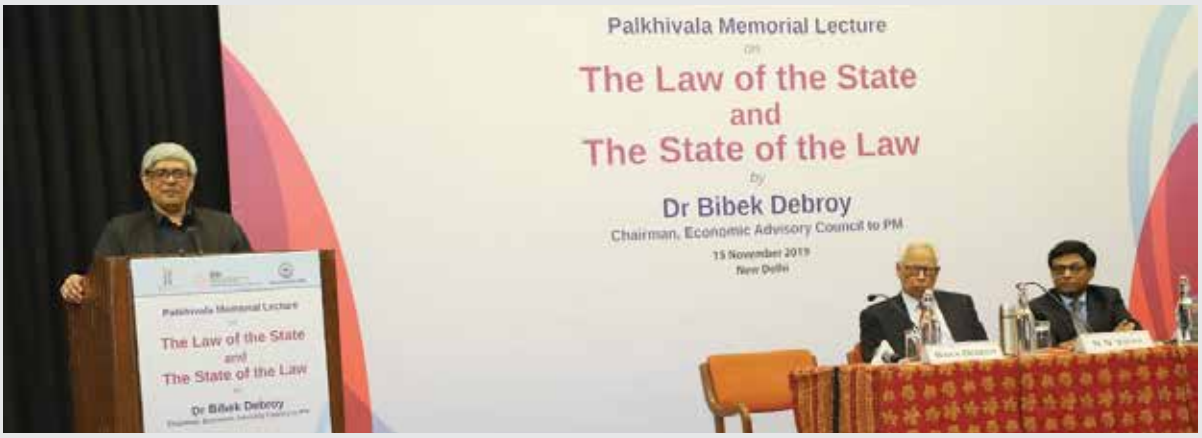

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय व्याख्यान देते हुए।

'नवाचार और प्रौद्योगिकी' पर आयोजित सत्र के दौरान ऐसी प्रौद्योगिकी पर फोकस किया गया जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि 'जीवाश्म ईंधनों के व्यापक उपयोग' के बजाय 'ज्यादा हरित बिजली मिश्रण' की ओर उन्मुख होने का क्रम निर्बाध रूप से दक्षिण एशिया में जारी रहे। इस सत्र का संचालन श्री नजरूल इस्लाम, वरिष्ठ निदेशक, टीएएफ – बांग्लादेश द्वारा किया गया। डॉ. प्रियदर्शी दाश, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस ने इस सत्र के दौरान 'दक्षिण एशिया में नवीकरण ीय ऊर्जा संबंधी नवाचारः वित्त पोषण, नीति और साझेदारियों' पर प्रस्तुति दी।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के अधिकतम इस्तेमाल' पर पैनल परिचर्चा

राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए निरंतर ठोस प्रयास करने होंगे। वैश्विक स्तर पर, एजेंडा 2030 से जुड़ी वार्ताओं के तहत भारत की एकमात्र सबसे बड़ी उपलब्धि 'प्रौद्योगिकी सुविधा व्यवस्था (टीएफएम)' का शुभारंभ है, ताकि एसडीजी की प्राप्ति के लिए विकासशील देशों को तरह–तरह के तकनीकी समाधान उपलब्ध कराए जा सकें। इस संबंध में आरआईएस भारत सरकार की विशिष्ट पहल 'भारत में एसडीजी के लिए एसटीआई की रूपरेखा तैयार करने' में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित टीएफएम विश्व स्तर पर इसके अधिदेश को पूरा करे और एसडीजी के लिए एसटीआई पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करे, आरआईएस ने ओईसीडी के साथ मिलकर 4 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में 'सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के अधिकतम इस्तेमाल' पर एक पैनल परिचर्चा का आयोजन किया।

आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने उद्घाटन भाषण दिया और डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस ने अध्यक्षता की। श्री जॉर्ज मोरीरा डा सिल्वा, निदेशक, विकास सहयोग निदेशालय, ओईसीडी ने विशेष भाषण दिया। दो विषयगत सत्र इन विषयों पर केंद्रित थेः 1) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थानों की भूमिका; 2) एसडीजी के लिए एसटीआई पर राष्ट्रीय प्राथमिकताएंः चुनौतियां और अवसर।

डॉ. नागेश कुमार, प्रमुख, एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोगः दक्षिण एवं दक्षिण–पश्चिम एशिया के लिए उप–क्षेत्रीय कार्यालय (एस्कैप–एसएसडब्ल्यूए), नई दिल्ली ने 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थानों की भूमिका' पर आयोजित पहले सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र में पैनलिस्ट ये थेः डॉ. एलेक्स बोएहमर, भारत के साथ ओईसीडी–संबंध के प्रमुख; श्री हेमांग प्रियवादन जानी, विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी; और श्री नाओटो केनहिरा, निजी क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञ (वित्त, प्रतिस्पर्धी क्षमता और नवाचार वैश्विक पद्धति), विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

'एसडीजी के लिए एसटीआई पर राष्ट्रीय प्राथमिकताएं: चुनौतियां और अवसर' पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता श्री जॉर्ज मोरीरा डा सिल्वा, निदेशक, विकास सहयोग निदेशालय, ओईसीडी ने की। इस सत्र में पैनलिस्ट ये थे: प्रो. अंबुज सागर, प्रमुख, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली; सुश्री सीमा अरोड़ा, उप महानिदेशक, सतत विकास के लिए सीआईआई–आईटीसी उत्कृष्टता केंद्र; डॉ. पी. के. आनंद, विजिटिंग फेलो, आरआईएस एवं श्री कृष्ण कुमार, विजिटिंग फेलो, आरआईएस; और डॉ. सुधांशु एस. सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ह्यूमैनिटेरियन एड इंटरनेशनल। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने खुली परिचर्चा में भाग लिया। आरआईएस के सहायक प्रोफेसर डॉ. सब्यसाची साहा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

देश का कानून और कानून का राज

आरआईएस ने नानी पालखीवाला जन्म शताब्दी समारोह संचालन समिति और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) के साथ मिलकर 15 नवंबर, 2019 को 'देश का कानून और कानून का राज' विषय पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय का पालखीवाला स्मारक व्याख्यान आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस और मेजर जनरल नीलेन्द्र कुमार (सेवानिवृत्त) मानद सचिव, नानी पालखीवाला जन्म शताब्दी समारोह संचालन समिति के भाषणों के साथ हुआ। श्री एन. एन. वोहरा, अध्यक्ष, आईआईसी ने इसकी अध्यक्षता की।

'हिंद–प्रशांत क्षेत्र में आसियान, भविष्य में आर्थिक विकास के लिए अवसर और चुनौतियां' विषय पर पूर्ण सत्र

संयुक्त राष्ट्र एस्कैप ने यूनिवर्सिटी केबांगसन मलेशिया (यूकेएम) के साथ साझेदारी में 9–10 दिसंबर, 2019 को बैंकॉक में चौथे आसियान आर्थिक एकीकरण फोरम का आयोजन किया। इस आयोजन के अंतर्गत ही आरआईएस स्थित आसियान–भारत केन्द्र (एआईसी) ने यूएनएस्कैप के साथ मिलकर 9 दिसंबर 2019 को बैंकॉक में 'हिंद–प्रशांत क्षेत्र में आसियान, भविष्य में आर्थिक विकास के लिए अवसर और चुनौतियां' विषय पर पूर्ण सत्र आयोजित किया। इस सत्र का उद्देश्य हिंद–प्रशांत क्षेत्र के आसियान आउटलुक (एओआईपी) से हिंद–प्रशांत अवधारणा की गहरी समझ उत्पन्न करना तथा आसियान, और आसियान–भारत संबंधों के लिए साझा दृष्टिकोण, नए अवसरों एवं चुनौतियों की पहचान करना था। श्री सूरत होराचाइकुल, निदेशक, भारत अध्ययन केंद्र, चुलालॉन्गकॉर्न विश्वविद्यालय, थाईलैंड ने सत्र का संचालन किया। सत्र के पैनलिस्ट ये थे: श्री नाओशी नोगुची, प्रमुख, बैंकॉक रिसर्च सेंटर, जेट्रो, थाईलैंड; श्री जॉ ओओ, कार्यकारी निदेशक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास केंद्र, म्यांमार; डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आसियान–भारत केंद्र, आरआईएस, भारत और डॉ. प्रीति श्रीसंगनाम, निदेशक, शैक्षणिक मामले, आसियान अध्ययन केंद्र, चुलालॉन्गकॉर्न विश्वविद्यालय, थाईलैंड।

यूएनएस्कैप, बैंकॉक में 'हिंद–प्रशांत क्षेत्र में आसियान, भविष्य में आर्थिक विकास के लिए अवसर और चुनौतियां' विषय पर सत्र का आयोजन।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

श्री पीयूष गोयल, माननीय रेल मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार 'पूर्ण सत्र।' में मुख्य भाषण देते हुए।

आरोग्य 2019

आरआईएस/एफआईटीएम 19 से 22 दिसंबर, 2019 तक वाराणसी में आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य 2019 कार्यक्रम' के लिए फिक्की का ज्ञान साझेदार रहा है। कार्यक्रम में आयुष सेक्टर से संबंधित विषयों पर पैनल परिचर्चाएं शामिल थीं। मोटे तौर पर, इस दौरान वैश्विक मानकों पर अमल, क्षेत्रीय सहयोग और आयुष सेक्टर के मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) एकीकरण के मुद्दों पर गहन विचार–विमर्श किया गया। 'वैश्विक व्यवस्था और आयुष उत्पादों एवं सेवाओं का मानकीकरण' विषय पर आयोजित परिचर्चा में श्री राजीव खेर, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने पैनलिस्ट के रूप में और डॉ. नम्रता पाठक, रिसर्च एसोसिएट ने पैनल समन्वयक के रूप में भाग लिया।

जलवायु परिवर्तन और विकास पथ

आरआईएस, नीतिगत अनुसंधान केंद्र (सीपीआर), और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) ने जलवायु परिवर्तन और विकास पथ के बीच जुड़ाव पर एक परिचर्चा बैठक का आयोजन किया, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2019 के साथ संलग्न होगी। श्री आर. आर. रश्मि, विशिष्ट फेलो और कार्यक्रम निदेशक, पृथ्वी विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन, (टेरी) ने सत्र की अध्यक्षता की। पैनलिस्टों में ये शामिल थे: श्री साइमन मैक्सवेल, विकास अर्थशास्त्री, एवं पूर्व निदेशक, विदेश विकास संस्थान; डॉ. पी. के. आनंद, विजिटिंग फेलो, (आरआईएस); डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, (आरआईएस); और प्रोफेसर नवरोज के. दुबाश, प्रोफेसर, नीतिगत अनुसंधान केंद्र, एवं समन्वयक, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर सीपीआर पहल, भारत।

'बीएपीए+40' के बाद नए अवसर और नई साझेदारियां

दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग पर दिल्ली प्रोसेस पांचवां सम्मेलन

आरआईएस वैश्विक विकास की रूपरेखा की बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) या विकासशील देशों के बीच सहयोग पर विचार–विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एकजुट करने में सबसे आगे रहा है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और संतुलित एवं सुविज्ञ विचार–विमर्श या परिचर्चाएं सुनिश्चित करने के लिए आरआईएस ने 'दिल्ली प्रोसेस सम्मेलनों' की शुरुआत की। वर्ष 2013 में आयोजित प्रथम सम्मेलन ने इस तरह के विचार–विमर्श के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इसके बाद वर्ष 2016, 2017 और 2018 में आयोजित सम्मेलनों में एसएससी की बहुलता एवं विविधता और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ इसके जुड़ाव पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही इन सम्मेलनों में अनुभवजन्य वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए सैद्धांतिक नजरिए से 'एसएससी' पर बड़ी बारीकी से गौर किया गया। यही नहीं,

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

ये सम्मेलन एक ऐसे निरूपण के साथ उभर कर सामने आए जिनमें एसएससी की 'विशिष्टता' को रेखांकित किया गया। 'दिल्ली प्रोसेस' के दौरान हुए व्यापक विचार–विमर्श से मार्च 2019 में आयोजित 'दक्षिणीय सहयोग पर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन (बीएपीए. 40)' में महत्वपूर्ण योगदान देने में काफी मदद मिली।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी), दक्षिणी थिंक–टैंकों के नेटवर्क (नेस्ट) और भारतीय विकास सहयोग फोरम (एफआईडीसी) के साथ भागीदारी में आरआईएस ने 'बीएपीए. 40' के बाद नए अवसरों और नई साझेदारियों को तलाशने' के लिए दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग पर दिल्ली प्रोसेस पांचवां सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन 22–23 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य भावी निहितार्थों का आकलन करना, चुनौतियों की पहचान करना और 'बीएपीए. 40' में हुई आम सहमति के अनुरूप 'एसएससी' के लिए एक रोडमैप विकसित करना था।

माननीय डॉ. नोमव्यूयो नोक्वे, महासचिव, हिंद महासागर रिम संघ, मॉरीशस ने आरंभिक भाषण दिया, जबकि आरआईएस के चेयरमैन राजदूत मोहन कुमार ने स्वागत भाषण दिया। श्री जॉर्ज चेडिएक, निदेशक, यूएनओएसएससी; प्रोफेसर अनुराधा चेनॉय, अध्यक्ष, एफआईडीसी; और प्रोफेसर ली शियाओयुन, अध्यक्ष, नेस्ट ने साझेदार संस्थानों की ओर से महत्वपूर्ण अवलोकन किए। श्री टी.एस. तिरुमूर्ति, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण के साथ सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया और 53 से भी अधिक देशों के प्रतिभागियों का स्वागत किया, जिनमें 16 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और प्रमुख एसएससी हितधारक शामिल थे।

विशेषज्ञों ने इनसे संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया: 'उद्योग 4.0' के मद्देनजर एसएससी का स्तर बढ़ाना; एसएससी की अनूठी विशेषताओं को दर्ज करने वाली प्रभाव आकलन व्यवस्था को विकसित करना; संबंधित निकायों की विविधता एवं विकासशील देशों की अपेक्षाओं को साकार करने में संस्थानों की भूमिका; और वैश्विक वित्तीय गवर्नेंस के लिए एसएससी की भूमिका। यही नहीं, विशेषज्ञों ने साथ मिलकर त्रिकोणीय सहयोग (टीआरसी) की संभावनाएं भी तलाशीं। विचार–विमर्श के दौरान आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी के साझाकरण और सह–सृजन की आवश्यकता पर भी गौर किया गया। इसके अलावा, इस परिचर्चा ने एसएससी को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की उभरती एजेंसियों को अपने अनुभवों, ज्ञान और व्यवस्थाओं को साझा करने के लिए एकजुट होने का अहम प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया।

श्री टी.एस. तिरुमूर्ति, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, उद्घाटन सत्र में साथी प्रतिष्ठित पैनलिस्टों के साथ।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

श्री पीयूष गोयल, माननीय रेल मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने वित्तीय गवर्नेंस के संदर्भ में विकासशील देशों के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने के साथ–साथ उपलब्ध अवसरों के बारे में मुख्य भाषण दिया जिसमें उन्होंने भारत के 'परिष्कृत बहुपक्षवाद' से संबंधित विजन को रेखांकित किया। डॉ. रजत कथूरिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआरआईईआर ने विकासशील देशों में रहने वाले लोगों को कुशल बनाने और इसके बाद फिर से उनका कौशल बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, ताकि वे 'औद्योगिक क्रांति 3.0' के अनुरूप अपनी काबिलियत को बनाए रखने के साथ–साथ 'औद्योगिक क्रांति 4.0' के लिए भी खुद को तैयार कर सकें।

सम्मेलन में अपरिवर्तित सिद्धांतों के सापेक्ष एसएससी का आकलन करने के साथ–साथ संचालन में संभावित बदलावों सहित विभिन्न तौर–तरीकों पर भी व्यापक सहमति जताई गई। एक–दूसरे पर निर्भर तौर–तरीकों के पूरक सेट के रूप में 'विकास सघन (कॉम्पैक्ट)' के आइडिया को प्रतिभागियों ने काफी सराहा। विशेषज्ञों ने एकजुटता की भावना से समकक्षों के साथ सकारात्मक या अन्य प्रभावों को साझा करने के लिए विकासशील देशों के साझेदारों की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया, ताकि उन्हें उन सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने में मदद मिल सके जिन्हें वे अपनी विकास आकांक्षाओं में योगदान करने के लिए आवश्यक समायोजन के साथ लागू कर सकते हैं। अतः एसएससी के आकलन का उद्देश्य आपसी समझ बढ़ाने और अनुभवों को साझा करने की इच्छा से प्रेरित होना चाहिए।

इसके अलावा, सम्मेलन ने निरंतर संवाद के लिए रास्ते खोल दिए, क्योंकि हम एजेंडा 2030 को पूरा करने के लिए विकासशील देशों की सहभागिता को मजबूत करने और त्रिकोणीय साझेदारियां शुरू करने की ओर अग्रसर हो गए हैं। यह बात सुश्री रेनाटा लोक–डेसालियन, भारत में संयुक्त राष्ट्र की समन्वयक ने अपने विशेष भाषण में और श्री किरेन रिजिजू, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कार्य एवं खेल और राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य, भारत सरकार ने अपने समापन भाषण में रेखांकित की।

दिल्ली प्रोसेस पांचवें सम्मेलन में ज्ञान संबंधी जुड़ाव को मजबूत करने के लिए बहुप्रतीक्षित कदम उठाए गए जिनके तहत एक 'थिंक टैंक्स–यूनिवर्सिटी कनेक्ट' और एक 'युवा विद्वान फोरम' की शुरुआत की गई। थिंक टैंक्स–यूनिवर्सिटी कनेक्ट से ज्ञान सृजित करने वालों के लिए एक सामूहिक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ जिसका उद्घाटन प्रोफेसर वी.के. मल्होत्रा, सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) और डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया। इस नई पहल का उद्देश्य विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण एवं अनुसंधान को और आगे बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं विकास अध्ययन जैसे विषयों को शामिल करना तथा सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया के साथ उनके जुड़ाव (इंटरफेस) को एक सामूहिक प्लेटफॉर्म का रूप प्रदान करना है।

'युवा विद्वान फोरम' सुदृढ़ एसएससी के एक और स्तंभ पर प्रकाश डालता है, क्योंकि इसने आईटीईसी प्रतिभागियों के पूर्व छात्रों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया और इस तरह से यह ज्ञान के आदान–प्रदान की प्रक्रियाओं को निरंतर जारी रख रहा है। इसका उद्देश्य एसएससी की जटिलताओं और बहुलता को स्पष्ट रूप से समझने के लिए विकासशील देशों के अनगिनत शोधकर्ताओं की सेवाएं लेना था। इस अवसर पर आरआईएस ने 27 साझेदार देशों एवं संस्थानों की भागीदारी के साथ एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की, जिसमें दक्षिणीय सहयोग को मजबूत करने में उनके बहुमूल्य योगदान को दर्शाया गया।

'दिल्ली प्रोसेस' के तहत पांचवां सम्मेलन नीति निर्माताओं, सिविल सोसायटी और अकादमिक संस्थानों का एक नेटवर्क बनाने की ओर अग्रसर हो गया, ताकि सामूहिक रूप से ठोस कदम उठाने के साथ–साथ सामूहिक विकास हेतु साझेदारियों को मजबूत करने के लिए विभिन्न हितधारकों को एकजुट किया जा सके। इस सम्मेलन से उन आइडिया और पहलों का आदान–प्रदान अत्यंत सुविधाजनक हो गया जिनके तहत सतत और समावेशी विकास के लिए वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सम्मेलन का विस्तृत एजेंडा और मुख्य अंश दरअसल तैयार संदर्भ के लिए आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जी20 ओसाका शिखर सम्मेलन' पर सवाल–जवाब सत्र

जी20 के राजनेताओं का 'शिखर सम्मेलन 28–29 जून 2019 को जापान के ओसाका में आयोजित किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया और जी20 प्रक्रिया में बड़े ही ठोस तरीके से अहम

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

श्री सुरेश प्रभु, पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

योगदान दिया। माननीय श्री सुरेश प्रभु, पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री शिखर सम्मेलन में भारत के जी20 शेरपा थे। वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मामलों में जी20 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह शिखर सम्मेलन सदस्य देशों के लिए एक बहुप्रतीक्षित आयोजन था। पिछले शिखर सम्मेलनों की तरह ही इस बार भी भारत ने ओसाका शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सदस्य देशों के समान हितों वाले वैश्विक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के रूप में अहम योगदान दिया।

भारत चूंकि वर्ष 2022 में जी20 की अध्यक्षता संभालने वाला है, इसलिए ओसाका शिखर सम्मेलन से लेकर आगे तक के रोडमैप पर सामूहिक रूप से विचार–विमर्श करना अत्यंत आवश्येक है। विचारकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, कारोबारियों और अन्य हितधारकों के बीच सुविज्ञ या समस्त जानकारियों के साथ विचार–विमर्श सुनिश्चित करने के लिए आरआईएस ने 'जी20 ओसाका शिखर सम्मेलन पर सवाल–जवाब सत्र' आयोजित किया।

माननीय श्री प्रभु, जी20 शेरपा और पूर्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने सत्र की अध्यक्षता की। सूस शेरपा श्री सुरेश रेड्डी, संयुक्त सचिव, बहुपक्षीय आर्थिक संबंध, विदेश मंत्रालय ने भी परिचर्चाओं में भाग लिया। श्री ऑगस्टीन पीटर, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। श्री सुरेश प्रभु ने अपने संबोधन में कहा चूंकि बहुत सारे ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिन पर जी20 प्लेटफॉर्म पर चर्चा करने की आवश्यकता है और किसी विशेष मुद्दे को शामिल न किए जाने की आलोचना हो सकती है, इसलिए पिछली समस्त अध्यक्षता में उठाए गए मुद्दों की निरंतरता होनी चाहिए और इसके साथ ही आगामी सभी अध्यक्षता में भी नए मुद्दों को उठाए जाने की सराहना की जानी चाहिए। भारत न केवल अपने स्वयं के हितों के लिए जी20 में भाग लेता है, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों की आकांक्षाओं को भी जी20 की परिचर्चाओं में आगे रखने की कोशिश करता है। इसके अलावा, भारत दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देशों में से एक होने के नाते वैश्विक मामलों में अपनी जवाबदेही को महसूस करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जी20 में विकासशील दुनिया के दृष्टिकोण पर बड़ी गंभीरता के साथ गौर किया जाए।

मौजूदा समय में व्यापार विशेष मायने रखता है क्योंकि बढ़ता व्यापार आर्थिक विकास की गति तेज करने में उल्लेखनीय योगदान दे सकता है। हालांकि, वैश्विक व्यापार

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार विशेष भाषण देते हुए।

तब तक नहीं बढ़ सकता है जब तक कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मजबूत और अच्छी तरह से सक्रिय न हो जाए। भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में विश्व व्यापार संगठन की केंद्रीय भूमिका हो जाए। वर्ष 2017 में अर्जेंटीना में आयोजित मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के नतीजे निराशाजनक रहने के बाद भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए 19 मार्च 2018 को एक लघु मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया कि विश्व व्यापार संगठन और भी अधिक प्रभावकारी हो जाए। 57 देशों की भागीदारी ने इस आयोजन की सफलता को अभिव्यक्त किया जिसका अर्थ यही है कि ज्यादातर सदस्य देश डब्ल्यूटीओ के कामकाज में सुधार लाए जाने के पक्षधर हैं।

बुनियादी ढांचा वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में हो रहे निवेश से कई देश लाभान्वित होते हैं। बुनियादी ढांचे में विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की क्षमता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनेक पहल की हैं, जो वास्तव में बदलते वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में अभूतपूर्व योगदान देंगी।

भारत समुद्री अर्थव्यवस्था पर जी20 के नजरिए और आर्थिक समृद्धि एवं पर्यावरण संरक्षण में महासागरों की भूमिका का पुरजोर समर्थन करता है। मध्यस्थता या पंचाट के अवसरों से लाभ उठाने और कर पनाहगाहों का पता लगाने के लिए 'आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (बीईपीएस)' की रूपरेखा को मजबूत करना होगा।

जी20 को निश्चित तौर पर सभी देशों, विशेषकर इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और मेक्सिको जैसे उभरते बाजारों को आपस में बांधने का विजन प्रदान करना चाहिए जो प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर समन्वित ढंग से उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन करने और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं को बढ़ावा देने से संबंधित वैश्विक गवर्नेंस में नए सक्रिय देश हैं।

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व राजनयिकों, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों, कारोबार जगत एवं सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम 2019

संयुक्त राष्ट्र में एसडीजी विचार–विमर्श, उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) प्रक्रिया और दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ आरआईएस की निकटता को जारी रखते हुए महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने 13–19 जुलाई 2019 के दौरान न्यूयॉर्क में एचएलपीएफ 2019 में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र में दो सदस्यीय आरआईएस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें सहायक प्रोफेसर डॉ. सब्यसाची साहा भी शामिल थे।

पिछले वर्षों की तरह ही इस बार भी आरआईएस ने एसडीजी, विशेषकर एसडीजी 17 पर जारी परिचर्चाओं, गहरी समझ और संबंधित परिदृश्य में योगदान देने के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों और एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से न्यूयॉर्क में एचएलपीएफ 2019 के दौरान अलग से दो विषयगत कार्यक्रम आयोजित किए। आरआईएस के महानिदेशक को 13 जुलाई 2019 को प्रभावकारी विकास सहयोग के लिए वैश्विक साझेदारी (जीपीईडीसी) की वरिष्ठ स्तर की बैठक (एसएलएम) के दौरान 'दक्षिणीय सहयोग में प्रभावशीलता' विषय पर आयोजित सत्र में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था। डॉ. साहा को भी एसएलएम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अपने संबोधन में प्रो. चतुर्वेदी ने दक्षता और सामंजस्य के संदर्भ में दक्षिणीय सहयोग में प्रभावशीलता से संबंधित अलग–अलग दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला।

आरआईएस ने एचएलपीएफ 2019 के दौरान अलग से दो विषयगत कार्यक्रम आयोजित किए। पहला कार्यक्रम 16 जुलाई 2019 को आरआईएस–यूएनओएसएससी–संयुक्त राष्ट्र भारत–साउथ सेंटर के साथ मिलकर 'एसडीजी के वित्तपोषण' पर आयोजित किया गया। एसडीजी से जुड़ी बढ़ती आकांक्षाओं के कारण विकासशील देशों की प्रतिबद्धताओं में कई गुना वृद्धि हो गई है। हालांकि, परिचालन स्तर पर मौजूद बड़ी चुनौतियों में ये शामिल हैं: देश में आने वाली पूंजी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना; घरेलू संसाधन जुटाना; और पूंजी पलायन की समस्या को सुलझाना। विकासशील देशों के समक्ष एक बड़ी चुनौती दीर्घकालिक विकास वित्त का अपर्याप्त होना भी है जिस वजह से सामाजिक क्षेत्र के विकास, बुनियादी ढांचे एवं औद्योगीकरण के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में कमी के लिए आवश्यक क्षमताओं का तेजी से विस्तार नहीं हो पा रहा है।

पुराने निकायों के साथ ही नए संस्थानों का उद्भव होना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके अलावा, सतत विकास के नए प्रतिमानों को विकास के वित्तपोषण के सभी स्वरूपों में मुख्यधारा में लाना होगा; और इसके साथ ही घरेलू संस्थागत क्षमताओं एवं इससे जुड़ी तैयारियों पर नए सिरे से गौर करना होगा। अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (एएएए) की पूर्ति एसडीजी 17 के कार्यान्वयन के केंद्र में होनी चाहिए। इस संदर्भ में पूंजी पलायन से जुड़ी निरंतर एवं कठिन चुनौतियों; और औद्योगीकरण, एसएमई, व्यापार में सुगमता, कौशल एवं महिला–पुरुष समानता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सतत शहरीकरण जैसे क्षेत्रों में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस दौरान अलग से आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष भाषण भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने दिया और सत्र का संचालन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, नई दिल्ली ने किया। प्रतिष्ठित पैनलिस्ट में ये शामिल थे: सुश्री रेनाटा लोक–डेसालियन, भारत में संयुक्त राष्ट्र की निवासी समन्वयक; श्री जॉर्ज चेडिएक, निदेशक एवं दक्षिणीय सहयोग पर महासचिव के दूत, दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय; डॉ. देबप्रिया भट्टाचार्य, अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित फेलो, एमडीजी अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के उपरांत विकासशील देशों की आवाज या प्रतिनिधि, नीतिगत संवाद केंद्र, बांग्लादेश; डॉ. जॉन डब्ल्यू. मैकआर्थर, सीनियर फेलो, वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं विकास कार्यक्रम, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन, वाशिंगटन डीसी और डॉ. मैनुअल एफ मोंटेस, वित्त एवं विकास पर वरिष्ठ सलाहकार, साउथ सेंटर, जिनेवा।

अपने विशेष संबोधन में डॉ. राजीव कुमार ने विकासशील देशों के लिए संसाधनों के अभिनव उपयोग, प्रौद्योगिकी के सन्निहित अनुप्रयोग और देश में ही विकसित या उभरे विकास मॉडलों पर जोर दिया।

'दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोग के जरिए एसडीजी 17 को मजबूत करने: बहुलता और बीएपीए + 40 से आगे की राह' पर दूसरा कार्यक्रम 18 जुलाई 2019 को नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट), यूएनओएसएससी, ओईसीडी और ब्रिक्स नीति केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया। विकासशील देशों में विकास के अनुभव ऐसे अनूठे परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जो उभरती वैश्विक साझेदारियों

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

को और भी अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। विकासशील देशों में विकास और संसाधन प्रबंधन पर अनुभव साझा करना दरअसल विकासशील देशों में समान विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण आइडिया है।

मौजूदा खाई को न केवल वित्तीय संसाधनों के पर्याप्त एवं समय पर प्रावधान के जरिए, बल्कि ज्ञान साझाकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सुगम्य क्षमता और तकनीकी सहायता पर मजबूत संस्थागत व्यवस्थाएं करके भी पाटा जा सकता है। अतः इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बीएपीए + 40 से उभरते रोडमैप को विकास संबंधी निकायों एवं एजेंसियों के बीच व्यापक साझेदारियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, तौर–तरीकों में सामंजस्य होना चाहिए और इसके साथ ही त्रिकोणीय सहयोग की भावना के साथ आपस में गठबंधन करना चाहिए। विचार–विमर्श के लिए प्रमुख मुद्दे ये थे: अनुभव साझा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एसएससी की स्थिति; एजेंडा 2030 को पूरा करने में एसएससी के लिए चुनौतियां; बीएपीए + 40 से आगे का रोडमैप।

इस सत्र का संचालन श्री जॉर्ज चेडिएक, निदेशक एवं दक्षिणीय सहयोग पर महासचिव के दूत, दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने किया। प्रतिष्ठित पैनलिस्ट में ये शामिल थे: राजदूत नागराज नायडू, राजदूत एवं उप स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन; सुश्री एना सियूती, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महानिदेशक, विदेश एवं उपासना मंत्रालय, अर्जेंटीना; श्री रॉबिन ओगिल्वी, संयुक्त राष्ट्र में ओईसीडी के विशेष प्रतिनिधि; डॉ. पाउलो एस्टीव्स, निदेशक, ब्रिक्स नीति केंद्र, ब्राजील; प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ; और सुश्री जियाओजुन ग्रेस वांग, कार्यक्रम एवं संचालन के लिए उप निदेशक, यूएनओएसएससी। प्रो. चतुर्वेदी ने बीएपीए + 40 से आगे बढ़ने हेतु दक्षिणीय सहयोग के लिए क्षेत्र विशेष सहयोग पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने वित्तीय समावेश के संदर्भ में किसी के भी पीछे न छूट जाने के लिए भारत द्व ारा की गई महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहलों पर भी विशेष बल दिया। प्रो. चतुर्वेदी ने एसडीजी 17 से जुड़े संकेतकों को विशिष्ट स्वरूप देने के लिए नेस्ट द्वारा किए गए प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

उपर्युक्त यात्रा के दौरान सामाजिक उद्यमों एवं निजी क्षेत्र की भूमिका और एसडीजी के लिए अभिनव वित्तपोषण पर आरआईएस की नई अनुसंधान पहल के एक हिस्से के रूप में अन्य व्यस्तताओं के साथ–साथ आउटरीच से जुड़े कार्यकलाप भी थे। आरआईएस के प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. स्टेन एच. वर्मुड, प्रबंध निदेशक, अन्ना एम. आर. लाउडर प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ एवं डीन, येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और उनके सहयोगियों के साथ बातचीत की। आरआईएस ने न्यूयॉर्क में 16 जुलाई 2019 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं एचएलपीएफ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख डॉ. राजीव कुमार के सम्मान में एक रात्रि भोज की भी मेजबानी की।

इस बैठक में उपर्युक्त विषय पर विचार–विमर्श किया गया और अमेरिका स्थित प्रमुख परोपकारी फाउंडेशनों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सामाजिक उद्यमियों तथा भारत से आए सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉ. सब्यसाची साहा ने 16 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क स्थित फोर्ड फाउंडेशन में 'निजी क्षेत्र के साथ अभिनव साझेदारियां: एसडीजी के अधिक से अधिक प्रभावों को कैसे प्राप्त करें' विषय पर अलग से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।

अमेरिका–भारत व्यापार संबंधों पर आयेजित संगोष्ठी में अमेरिका के फ्रेडरिक्सबर्ग स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मैरी वॉशिंगटन में राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय मामलों की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुरूपा गुप्ता।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

बिम्सटेक के महासचिव श्री एम. शाहिदुल इस्लाम प्रस्तुति देते हुए।

'दिल्ली प्रोसेस V – दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोगः बीएपीए + 40 के बाद नए अवसरों और नई साझेदारियों की तलाश करने' के लिए आवश्यिक तैयारी और संवाद सुनिश्चित करने के तहत आरआईएस के महानिदेशक ने 17 जुलाई 2019 को एपीसी कोलम्बिया (क्वेंटा ऑफिशियल डे ला एजेंसिया प्रेसिडेंशियल डे कोऑपरेशन – सहयोग के लिए प्रमुख एजेंसी) की महानिदेशक माननीया सुश्री एंजेला ओस्पिना से भेंट की।

महानिदेशक को इन फोरमों में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गयाः 1) मानव विकास में विषमताः 2019 मानव विकास रिपोर्ट के लिए विकासशील देशों में स्थित थिंक–टैंकों के साथ परामर्श (18 जुलाई 2019 को); 2) दक्षिणीय वैश्विक विचारक संवादः बीएपीए + 40 परिण ाम दस्तावेज पर चिंतन (17 जुलाई 2019 को); और 3) उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम 2019 में अलग से संयुक्त कार्यक्रमः प्रयासों में शामिल होनाः एसडीजी में दक्षिणीय सहयोग के योगदान का आकलन (17 जुलाई 2019 को)। मानव विकास रिपोर्ट 2019 पर परामर्श के दौरान अपने संबोधन में प्रो. चतुर्वेदी ने पहुंच एवं बुनियादी जरूरतों से संबंधित मुद्दों के महत्व; जैव विविधता के वैश्विक नुकसान पर गौर करते हुए जीवन स्तंर एवं वेलनेस से जुड़े मुद्दों; और एफडीआई एवं समावेशी मुद्दों, धन के अवैध प्रवाह, और वैश्विक कर मुद्दों के बारे में विस्तार से बताया।

आरआईएस के प्रतिनिधिमंडल ने 16 जुलाई 2019 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नीति आयोग द्वारा 'प्रतिबद्धता से उपलब्धि तकः सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में भारत का अनुभव' विषय पर अलग से आयोजित किए गए कार्यक्रम में भी भाग लिया।

अमेरिका–भारत व्यापार संबंध

भारत–अमेरिका द्विपक्षीय संबंध अब 'वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के रूप में विकसित हो गए हैं जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर आपसी हितों में बढ़ते सामंजस्य पर आधारित है। अमेरिका और भारत लंबे समय से व्यापार में भागीदार हैं। आरआईएस अमेरिका–भारत के आर्थिक संबंधों पर शोध करता रहा है। आरआईएस ने इस कार्यकलाप कार्यक्रम के तहत 25 जुलाई 2019 को अमेरिका–भारत व्यापार संबंधों पर एक संगोष्ठी का आयोजन आरआईएस में किया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरी वॉशिंगटन, फ्रेडरिक्सबर्ग में राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय मामलों की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुरूपा गुप्ता मुख्य वक्ता थीं।

अपनी प्रस्तुति में इस वक्ता ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के कई द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक नाटकीय व्यवधान देखे गए हैं। उधर, इस पृष्ठभूमि

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

एशिया–प्रशांत में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र के निदेशक डॉ. ए. सेंथिल कुमार आरआईएस में एफआईएसडी व्याख्यान देते हुए।

में भारत के साथ रणनीतिक संबंधों में मजबूती निरंतर कायम है। हालांकि, दोनों लोकतंत्रों के बीच व्यापार संबंध को मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के कई कदमों से झटका लगा है। इस्पात एवं अल्यूमीनियम पर टैरिफ लगाया जाना, भारत के लिए सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम को समाप्त करना और सर्विस सेक्टर के व्यापार में भारत के हितों के लिए खतरा पैदा होना इन कदमों में शामिल हैं। यह भी दलील दी गई कि व्यापार विवाद दरअसल व्यापार पर वैश्विक मानदंडों को लेकर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दीर्घकालिक एवं प्रामाणिक संघर्ष का एक हिस्सा है। वैसे तो व्यापार विवाद के और ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है, लेकिन समग्र रणनीतिक साझेदारी पर इसका मामूली असर ही पड़ने की संभावना है। इसके बाद आयोजित परिचर्चा में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बिम्सटेक की भावी दिशा

आरआईएस अपनी शुरुआत से ही बिम्सटेक के कार्यकलाप कार्यक्रम से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। हाल ही में बिम्सटेक के सदस्य देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

इस संदर्भ में आरआईएस ने ''बिम्सटेक की भावी दिशा' विषय पर बिम्सटेक के महासचिव माननीय श्री एम. शाहिदुल इस्लाम के व्याख्यान का आयोजन 24 जुलाई 2019 को आरआईएस में किया। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत डॉ. मोहन कुमार ने इसकी अध्यक्षता की।

माननीय श्री चुटिन्टॉर्न गोंगसाकडी, राजदूत, थाईलैंड दूतावास, नई दिल्ली और श्री शेषाद्रि चारी, सदस्य, आरआईएस की संचालन परिषद इस अवसर पर प्रतिष्ठित चर्चाकर्ता थे। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने खुली परिचर्चा में भाग लिया।

विज्ञान कूटनीति और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में क्षमता निर्माण

आरआईएस ने अपने भारतीय विज्ञान कूटनीति फोरम (एफआईएसडी) के तहत 18 सितंबर 2019 को एक मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की। डॉ. ए सेंथिल कुमार, निदेशक, एशिया–प्रशांत में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र (सीएसएसटीईएपी) (संयुक्त राष्ट्र का एक केंद्र), देहरादून ने 'विज्ञान कूटनीति और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में क्षमता निर्माण' पर व्याख्यान दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने आरंभिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने विभिन्न सामाजिक चुनौतियों से निपटने के साथ–साथ एसडीजी को प्राप्त करने में एसटीआई की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। आमंत्रित वक्ता डॉ. सेंथिल कुमार ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं अनुप्रयोगों के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। डॉ. सेंथिल ने उन नौ सामाजिक क्षेत्रों पर प्रकाश डाला, जो अंतरिक्ष डेटा से लाभान्वित होते हैं।

इन क्षेत्रों में आपदाएं, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, जलवायु, जल, मौसम, पारिस्थितिकी प्रणालियां और जैव विविधता शामिल हैं। अंतरिक्ष डेटा इसके अलावा शहर नियोजन, परिवहन और संचार नेटवर्क में भी अत्यंत उपयोगी हैं।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

'सीएसएसटीईएपी', जो वर्ष 1995 में बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र– ओएसएसए) द्वारा स्थापित किया गया एक अद्वितीय क्षेत्रीय केंद्र है, की भूमिका का उल्लेख करते हुए डॉ सेंथिल कुमार ने उन विभिन्न क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों (विदेश मंत्रालय के आईटीईसी कार्यक्रमों सहित) के बारे में विस्तार से बताया जिन्हें यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रोफेशनलों, विशेषकर एशिया–प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों के प्रोफेशनलों के लिए आयोजित करता है। अब तक एशिया–प्रशांत क्षेत्र के 36 देशों के 2217 प्रतिभागी इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से लाभान्वित हो चुके हैं। यही नहीं, भारत ने अपने स्व–शिक्षण एजुकेशन डैशबोर्ड 'स्वामी' (मौसम और आपदा प्रबंधन सूचना के लिए प्रणाली) को अपने पड़ोसी देशों जैसे कि श्रीलंका और नेपाल के साथ साझा भी किया है। डॉ. सेंथिल कुमार ने भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के छह आयामों यथा अंतरिक्ष अवसंरचना, अनुप्रयोगों, संस्थागतकरण, भूतल खंड, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में भी बताया। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में 34 देशों के साथ सहयोग से संबंधित समुचित व्यवस्थाएं की हैं। व्याख्यान के दौरान विज्ञान 'डेटा' कूटनीति की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया, ताकि आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा को प्रभावकारी आपदा प्रबंधन के लिए सही समय पर विभिन्न देशों के बीच साझा किया जा सके।

'ब्लू इकोनॉमी' पर तीसरी आसियान–भारत कार्यशाला

थाईलैंड के विदेश मंत्रालय (एमएफए) ने भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए); आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता; राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एनएमएफ), नई दिल्ली और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 12 सितंबर 2019 को बैंकॉक में 'ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था' पर तीसरी आसियान–भारत कार्यशाला का आयोजन किया।

डॉ. सुरिया चिंदावोंगसे, महानिदेशक, आसियान कार्य विभाग, थाईलैंड का विदेश मंत्रालय ने आरंभिक भाषण दिया। मुख्य भाषण माननीया सुश्री सुचित्रा दुरई, थाईलैंड में भारत की राजदूत ने दिया। कार्यशाला में आसियान के सदस्य देशों, वरिष्ठ अधिकारियों और आसियान एवं भारत के लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला को चार सत्रों में विभाजित किया गया, ताकि ब्लू इकोनॉमी पर गहन चर्चा करने के साथ–साथ उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान भी की जा सके जिनमें आसियान और भारत आपस में सहयोग एवं साथ मिलकर काम कर सकते हैं। चार सत्र इन विषयों पर आयोजित किए गए थेः (1) ब्लू इकोनॉमी

ब्लू इकोनॉमी पर तीसरी आसियान–भारत कार्यशाला में अनेक प्रतिभागी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

का विकास; (2) समुद्री संसाधनों का सतत दोहन; (3) समुद्री संपर्क या कनेक्टिविटी और (4) समुद्री सुरक्षा एवं कूटनीति।

ब्लू इकोनॉमी पर तीसरी आसियान–भारत कार्यशाला के दौरान नीली अर्थव्यवस्था पर गहन चर्चाएं की गईं जिसे अब उत्तरोत्तर समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास और प्रगति के इंजन के रूप में देखा जा रहा है।

आसियान और भारत में ब्लू इकोनॉमी की पहचान समुद्री संसाधनों के सतत दोहन के जरिए तटीय क्षेत्रों और उससे जुड़े भीतरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों के एक नए स्तंभ के रूप में की गई है। ब्लू इकोनॉमी को ज्ञान गहन क्षेत्र माना जाता है जिसमें कई संसाधनों से जुड़ी विशेषज्ञता अत्यंत आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञता के संयोजन की दृष्टि से भारत और आसियान के बीच सहयोग की आवश्यकता है। समान समुद्री डोमेन को साझा करने, महासागरों एवं समुद्रों पर समान निर्भरता रखने और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के महत्व की समान समझ रखने वाले समुद्री पड़ोसियों के रूप में आसियान और भारत ब्लू इकोनॉमी के एजेंडे को आगे ले जाने में आदर्श साझेदार हैं। इस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के विकास को बढ़ावा देने और ब्लू इकोनॉमी में आसियान–भारत सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभागियों ने कई नीतिगत सिफारिशें सुझाईं। आखिर में, थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के आसियान मामलों के विभाग के उप महानिदेशक श्री असी मामानी ने समापन राय व्यक्त की। श्री निखिलेश गिरि, संयुक्त सचिव, हिंद–प्रशांत प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत ने समापन भाषण दिया। ईआरआईए के अध्यक्ष के विशेष सहायक प्रो. यासुहिरो यामादा ने विशेष भाषण दिया। डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

चुलालॉन्गकॉर्न विश्वविद्यालय के भारतीय अध्ययन केंद्र और व्यापार एवं विकास संस्थान (आईटीडी) से प्रतिनिधिमंडल आया

थाईलैंड के चुलालॉन्गकॉर्न विश्वविद्यालय के भारतीय अध्ययन केंद्र और आईटीडी के प्रतिनिधिमंडल के लगभग 12 सदस्यों ने 15 जुलाई 2019 को आरआईएस स्थित एआईसी का दौरा किया। डॉ. सूरत होराचाइकुल, निदेशक, भारतीय अध्ययन केंद्र, राजनीति विज्ञान संकाय, चुलालॉन्गकॉर्न विश्वविद्यालय ने थाईलैंड से आए प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। प्रतिनिधिमंडल ने बिम्सटेक और बंगाल की खाड़ी संबंधी सहयोग पर भारत के दृष्टिकोण पर हमारे साथ संवाद किया। डॉ. प्रबीर डे ने 'बिम्सटेकः वर्तमान स्थिति और अवसरों' पर एक प्रस्तुति दी, जिसके बाद बिम्सटेक और अन्य वैश्विक मुद्दों पर थाईलैंड के परिप्रेक्ष्य पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ बातचीत हुई। श्री महेश अरोड़ा, निदेशक (वित्त और प्रशासन), आरआईएस ने भी परिचर्चा में भाग लिया।

चीन के युन्नान विश्वविद्यालय से आए तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 9 अगस्त, 2019 को आरआईएस स्थित एआईसी का दौरा किया। आगंतुकों ने आपसी हितों के कई द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय विषयों, विशेषकर बिम्सटेक, आसियान–भारत सहयोग और भारत–चीन सहयोग पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता युन्नान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं उपाध्यक्ष डॉ. ली चेनयांग ने की। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य ये थेः डॉ. लू गुआंगशेंग, प्रोफेसर, चीन का पड़ोसी कूटनीति अध्ययन केंद्र, युन्नान विश्वविद्यालय; डॉ. लियू पेंग, एसोसिएट प्रोफेसर, म्यांमार अध्ययन संस्थान, युन्नान विश्वविद्यालय, युन्नान प्रांत, चीन; और श्री झांग लियांग, काउंसलर, नीति नियोजन अनुभाग के प्रमुख, भारत में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दूतावास, नई दिल्ली। आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के समन्वयक प्रो. प्रबीर डे ने भारत की विदेश नीति पर एक प्रस्तुति दी और भारत एवं चीन के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।

आरआईएस ने कोच्चि में छठे इब्सा शैक्षणिक फोरम की सह–मेजबानी की

आरआईएस को केरल के कोच्चि में 3–4 मई 2019 को इब्सा शेरपा की बैठक के साथ छठे इब्सा (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) शैक्षणिक फोरम को आयोजित करने का काम सौंपा गया। फोरम ने इब्सा प्रक्रिया को अपेक्षित गति प्रदान की और इस तरह से वैश्विक गवर्नेंस एवं विकास सहयोग के लिए इस अनूठी त्रिपक्षीय साझेदारी की निरंतर प्रासंगिकता को सुदृढ़ किया। आरआईएस को इब्सा की शुरुआत से ही इससे जुड़े होने का सौभाग्य प्राप्त है।

छठे इब्सा शैक्षणिक फोरम के पहले दिन का शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण और प्रसंग चर्चा के साथ हुआ। राजदूत सुनील लाल, ब्राजील में भारत के पूर्व राजदूत, ने उद्घाटन सत्र की

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

3–4 मई 2019 को कोच्चि में आयोजित छठे इब्सा शैक्षणिक फोरम में प्रतिष्ठित प्रतिभागी।

अध्यक्षता की। श्री टी.एस. तिरुमूर्ति, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण दिया। इसके बाद 'समकालीन वैश्विक गवर्नेंस और इब्सा की भूमिका' पर एक पैनल परिचर्चा हुई जिसकी अध्यक्षता राजदूत कुमार राजीव भाटिया, पूर्व महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए), भारत ने की। पैनल के सदस्य ये थेः प्रोफेसर विलियम गुमेडे, स्कूल ऑफ गवर्नेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटर्सरैंड, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका; प्रोफेसर उलास मोरेरा लिमा, यूनिवर्सिडेड फेडरल दा बाहिया (यूएफबीए), और विजिटिंग रिसर्चर, ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट फॉर अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (आईपीईए), ब्राजील; और प्रोफेसर श्रीराम चाउलिया, डीन, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (जेएसआईए); कार्यकारी निदेशक, सेंटर फॉर ग्लोबल गवर्नेंस एंड पॉलिसी (सीजीजीपी), जेएसआईए, भारत; प्रोफेसर नार्निया बोहलर–मुलर, कार्यकारी निदेशक, मानव विज्ञान अनुसंधान परिषद (एचएसआरसी), प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका। ये प्रमुख चर्चाकर्ता थे।

इब्सा के माध्यम से दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) को मजबूत करने पर आयोजित पूर्ण सत्र 1 की अध्यक्षता श्री जोस रोमेरो परेरा जूनियर, समन्वयक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यक्रम, कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रासिलिया (यूसीबी) और शोधकर्ता, ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट फॉर अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (आईपीईए), ब्राजील ने की। इस सत्र में पैनल सदस्य ये थेः प्रोफेसर मिलिंदो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस, भारत; प्रोफेसर एलिजाबेथ सिडिरोपोलस, मुख्य कार्यकारी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के दक्षिण अफ्रीकी संस्थान (एसएआईआईए), दक्षिण अफ्रीका; और डॉ. एलेन डी पाउला ब्यूनो, साओ पाउलो विश्वविद्यालय (यूएसपी), ब्राजील। प्रोफेसर एस. के. मोहंती, आरआईएस, भारत प्रमुख चर्चाकर्ता थे।

इसके बाद 'इब्सा देशों में उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोगात्मक शैक्षणिक नेटवर्क की ओर – अवसर और संभावित लाभ' विषय पर आयोजित विशेष सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर अनुराधा चेनॉय, अध्यक्ष, फोरम फॉर इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन (एफआईडीसी) और पूर्व डीन, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारत ने की। इस सत्र में प्रोफेसर अहमद बावा, यूनिवर्सिटीज दक्षिण अफ्रीका (यूएसएफ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दक्षिण अफ्रीका; प्रोफेसर ए. सुब्रमण्यम राजू, समन्वयक, सेंटर फॉर मैरीटाइम स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड इंटरनेशनल स्टडीज, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, भारत और श्री जोस रोमेरो परेरा जूनियर, समन्वयक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यक्रम, कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रासीलिया (यूसीबी) एवं शोधकर्ता, ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट फॉर अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (आईपीईए), ब्राजील पैनलिस्ट थे। प्रो. श्रीराम चाउलिया, डीन, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (जेएसआईए); कार्यकारी निदेशक, सेंटर फॉर ग्लोबल गवर्नेंस एंड पॉलिसी (सीजीजीपी), जेएसआईए, भारत प्रमुख चर्चाकर्ता थे।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

दूसरे दिन का शुभारंभ 'व्यापार सहयोगः प्रतिस्पर्धी क्षमता और पूरकता' पर आयोजित पूर्ण सत्र 2 के साथ हुआ जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर एलिजाबेथ सिडिरोपोलस, मुख्य कार्यकारी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का दक्षिण अफ्रीकी संस्थान (एसएआईआईए), दक्षिण अफ्रीका ने की। प्रोफेसर एस. के. मोहंती, आरआईएस, भारत; प्रोफेसर रसिगन महाराजा, नवाचार पर आर्थिक अनुसंधान संस्थान के मुख्य निदेशक, त्शवाने यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका; और प्रोफेसर उल्लास मोरेरा लीमा, यूनिवर्सिडेड फेडरल दा बाहिया (यूएफबीए), और विजिटिंग रिसर्चर, ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट फॉर अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (आईपीईए), ब्राजील पैनलिस्ट थे। भारत के विकास अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर के. जे. जोसेफ प्रमुख चर्चाकर्ता थे।

श्री शेषाद्रि चारी, सदस्य, संचालन परिषद, आरआईएस, ने समापन सत्र – 'इब्सा 2030 – आगे की राह' की अध्यक्षता की। डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस और फैकल्टी समन्वयक, इब्सा फेलोशिप प्रोग्राम ने प्रतिवेदक की रिपोर्ट प्रस्तुत की। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि संस्थानों ने अपने–अपने विचार प्रस्तुत किए। इब्सा शेरपाओं के साथ एक विशेष संवाद का भी आयोजन किया गया।

इस अवसर पर 'इब्सा विकास सहयोग की गतिशीलता' शीर्षक से आरआईएस प्रकाशन का विमोचन किया गया। विगत वर्षों के इब्सा फेलो ने इस प्रकाशन में योगदान दिया है।

इब्सा शैक्षणिक फोरम के अंतिम घोषणा पत्र में आसन्न इब्सा शिखर सम्मेलन के शीघ्र आयोजन का आह्वान किया गया और इसके साथ ही बहुपक्षवाद के प्रति इब्सा की अटूट प्रतिबद्धता, संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्रीकरण, विश्व शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा सतत विकास को मुख्यधारा में लाने में इब्सा की भूमिका को रेखांकित किया गया। फोरम ने यह दोहराया कि इब्सा साझेदारी का स्वरूप दृष्टिकोणों की बहुलता एवं तौर–तरीकों में सामंजस्य के साथ दक्षिणीय सहयोग के मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ है और इसके साथ ही इसने दक्षिणीय सहयोग पर इब्सा घोषणापत्र के महत्व पर प्रकाश डाला।

शैक्षणिक फोरम ने गहन व्यापार एकीकरण और मानकों, निवेश एवं वित्तीय क्षेत्र में सहयोग करने का आह्वान किया। आखिर में, शैक्षणिक फोरम ने विकास के विषय पर दक्षिणी दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए इब्सा में मजबूत शैक्षणिक और अनुसंधान लिंकेज की अनुशंसा की। इसके अलावा फोरम ने मानव सुरक्षा,

'रिवार्ड' परियोजना के तहत किए गए अध्ययन के प्रमुख प्रस्तुतकर्ता।

नवीकरणीय ऊर्जा एवं हरित प्रौद्योगिकियां, नीली अर्थव्यवस्था और महासागर के गवर्नेंस जैसे उभरते मोर्चों का लाभ उठाने की अनुशंसा की जो इब्सा के लिए अत्यंत महत्वंपूर्ण हैं। पूरा पाठ आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

दवाओं तक बेहतर पहुंच और स्वास्थ्य में साक्ष्य आधारित नीति

आरआईएस ने मरीजों द्वारा स्वास्थ्य मानकों के पालन एवं निगरानी पर एक अध्ययन का समन्वय किया था, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को शामिल किया गया था और इसके साथ ही उनके द्वारा डेटा प्रबंधन के लिए एक मोबाइल एप का उपयोग किए जाने का भी सहारा लिया गया था। यह अध्ययन केरल के एर्नाकुलम जिले के पांच तालुकों में कराया गया था जिसमें एक लाख लोगों की आबादी को कवर किया गया था। इसके तहत कार्डियो–वैस्कुलर डिजीज (सीवीडी) से पीड़ित रोगियों की पहचान की गई थी और उनके स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संचार पर उनकी प्रतिक्रिया पर करीबी नजर रखी गई थी और फिर उसका विश्लेरषण किया गया था। इस अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वाले पिछले अध्ययन के निष्कर्षों को भी बीएमजे ओपन, *इंडियन हार्ट जर्नल* और *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी* सहित समकक्ष समीक्षा वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है।

यह अध्ययन रिवार्ड प्रोजेक्ट के तहत कराया गया था (जिसके तहत स्वास्थ्य पर साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और, दवाओं तक पहुंच तथा दवा संबंधी अनुसंधान एवं विकास में नवाचार को प्रोत्साहित करने पर फोकस किया जाता है)। इसका वित्त पोषण यूरोपीय अनुसंधान परिषद (ईआरसी) द्वारा किया

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आरआईएस में कौशल और रोजगार पर आयोजित गोलमेज विचार–मंथन सत्र की अध्यक्षता करते हुए।

गया था और कैलगरी विश्वविद्यालय, सेंट्रल लंकाशायर यूनिवर्सिटी (यूसीएलएएन) तथा आरआईएस साझेदार संस्थानों के रूप में थे।

चूंकि यह अध्ययन केरल सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों की साझेदारी में कराया गया था, इसलिए इसके निष्कर्षों को केरल में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति निर्माण के लिए प्रासंगिक माना जाता है। इसके साथ ही इन्हें निःसंदेह अन्य राज्यों के लिए भी प्रासंगिक माना जाता है। इस संबंध में आरआईएस ने 26 जून 2019 को तिरुवनंतपुरम में प्रसार कार्यशाला और 28 जून 2019 को नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक का आयोजन किया था।

इन कार्यशालाओं का विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

बाह्य क्षेत्र, कौशल और रोजगार पर विचार–मंथन सत्र

भारत सरकार उपयुक्त कौशल विकसित करके युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लक्षित करती रही है। इस संदर्भ में 17 जून 2019 को इस विषय के साथ–साथ इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं करने के लिए चुनिंदा विशेषज्ञों के एक समूह के साथ आरआईएस में एक विचार–मंथन सत्र आयोजित किया गया था।

श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस सत्र की अध्यक्षता की। चर्चा में शिरकत करने वाले अन्य प्रतिभागी ये थेः श्री शेषाद्री चारी, सदस्य, आरआईएस

एएजीसी परामर्श सेमिनार के दौरान उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ आरआईएस प्रतिनिधिमंडल।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

की संचालन परिषद; डॉ. दिलीप चेनॉय, महासचिव, फिक्की; डॉ. नागेश कुमार, यूएन–एस्कैप, नई दिल्ली; डॉ. सुनील शुक्ला, निदेशक, ईडीआई, गांधीनगर, गुजरात; प्रो. मुक्ति कांता मिश्रा, अध्यक्ष, सेंचुरियन विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर; डॉ. योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन–सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट, भुवनेश्वर; प्रोफेसर पुलक घोष, चेयर ऑफ एक्सीलेंस एवं निर्णय विज्ञान के प्रोफेसर, आईआईएम, बेंगलुरू; सुश्री श्रुति गोंजाल्विस, प्रबंध निदेशक, सेवा गृह ऋण लिमिटेड, नई दिल्ली; डॉ. गायत्री वासुदेवन, और श्री राजेश; सीईओ; लेबरनेट; बेंगलुरू; प्रो. अनूप के. सत्पथी; वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान; नोएडा; श्री रणजीत भट्टाचार्य, और; श्री अनंत मणि, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली; और श्री हर्ष सिंह, वरिष्ठ समन्वयक, यूएनडीपी। आरआईएस की ओर से प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक; डॉ. एस. के. मोहंती, प्रोफेसर; प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, प्रतिष्ठित फेलो; डॉ. प्रियदर्शी दाश, सहायक प्रोफेसर; डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर; श्री गौरव शर्मा; परियोजना प्रबंधक, जीडीआई; डॉ. दुरईराज कुमारसामी, सलाहकार; और श्री सुभोमय भट्टाचार्जी ने भाग लिया।

'एएजीसी' के जरिए अफ्रीकी महाद्वीप में दस्तक देने की तैयारी

एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) एशिया और अफ्रीका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और जापान द्वारा शुरू की गई एक बहु–देशीय विकास पहल है। एएजीसी के लिए निर्दिष्ट भारतीय थिंक टैंक आरआईएस ने अवधारणा प्रक्रिया के साथ–साथ विजन दस्तावेज तैयार करने को नेतृत्व प्रदान किया है। इस पहल में भारतीय कंपनियों एवं कारोबारियों को शामिल करने और इस पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आरआईएस और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से 17 मई, 2019 को मुंबई में 'एएजीसी के जरिए अफ्रीकी महाद्वीप में दस्तक देने की तैयारी' विषय पर एकदिवसीय सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार के दौरान अफ्रीकी देशों में भारतीय कंपनियों के लिए कारोबार के अवसरों, निजी क्षेत्र की भूमिका, निवेश की संभावनाओं एवं चुनौतियों, वित्तपोषण की व्यवस्थाओं, संस्थागत सुविधा और नीतिगत कदमों से संबंधित दिलचस्प मुद्दों को उठाया गया।

सेमिनार के दौरान एशियाई और अफ्रीकी देशों के बीच विकास साझेदारी को बढ़ावा देने के एक अभिनव मॉडल के रूप में एएजीसी के महत्व को दोहराया गया। एएजीसी का उद्देश्य दरअसल एशिया और अफ्रीका में विकास स्तंभों (ग्रोथ पोल) जैसे कि केन्या में मोम्बासा बंदरगाह, म्यांमार में दावेई और सितवे बंदरगाहों, इत्यादि को जोड़ते हुए प्रतिभागी देशों में स्थानीय औद्योगीकरण एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक त्रिपक्षीय राजमार्गों (टीएलएच) के प्रस्तावित विस्तार से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क मार्ग खुल जाएंगे। भारतीय कंपनियां विभिन्न सेक्टरों जैसे कि ऑटोमोबाइल विशेषकर यात्री परिवहन, नगरपालिका एवं एम्बुलेंस सेवाओं, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश पर फोकस कर सकती हैं। वैसे तो भारतीय कंपनियों ने अफ्रीका में अपनी व्यापक मौजूदगी दर्ज करा रखी है, लेकिन भारतीय निवेशक जोखिम को लेकर कुछ ज्यादा ही आशंकित हैं जिसे कम करने के लिए अफ्रीका स्थित भारतीय मिशनों, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया, निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), सीआईआई, फिक्की जैसे उद्योग संगठनों तथा व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने में शामिल अन्य एजेंसियों को सक्रियतापूर्वक ठोस कदम उठाने चाहिए। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को अफ्रीका में उपलब्ध निवेश अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए और ऋण रेखा (एलओसी) के साथ–साथ वित्तीय योजनाओं के बारे में भी पता लगाना चाहिए। निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) को अफ्रीका के विभिन्न देशों में भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनियां लगानी चाहिए। संभावित व्यापक जोखिम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से निजी क्षेत्र की कंपनियों का मार्गदर्शन करने पर विचार करने की जरूरत है।

केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड; लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड; महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड; टाटा कंसल्टेंसी; टाटा मोटर्स लिमिटेड; टाटा स्टील लिमिटेड; इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड; और किर्लोस्कर ब्रदर्स लि. सहित कारोबार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में विचार–विमर्श में भाग लिया।

श्री केशव चंद्र, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और श्री प्रसन्ना वी. सलियन, उप सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय ने परामर्श बैठक के दौरान अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। एक्जिम बैंक का प्रतिनिधित्व श्री डेविड रैसक्विन्हा, ईडी; श्री सैमुअल जोसेफ, सीजीएम; श्री डेविड सिनेट, सीजीएम और श्री प्रहलाथन एस. अय्यर, सीजीएम ने किया। आरआईएस की ओर प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक; श्री शेषाद्रि चारी, सदस्य, आरआईएस,

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

शासी परिषद एवं सामान्य निकाय; श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो; राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो; और श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, परामर्शदाता, ने इस परामर्श बैठक में भाग लिया।

आरआईएस–डीएसटी विज्ञान राजनय पर आरआईएस–डीएसटी–एनआईएएस संगोष्ठी

जैसा कि पहले बताया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के समर्थन से आरआईएस ने एनआईएएस, बेंगलुरू के साथ मिलकर 'विज्ञान राजनय कार्यक्रम' शुरू किया था। यह कार्यक्रम क्षमता निर्माण, नेटवर्कों के विकास और रणनीतिक सोच के माध्यम से विज्ञान राजनय की क्षमता को साकार करता है।

इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में आरआईएस–एनआईएएस ने भी विज्ञान राजनय के सिद्धांत और व्यवहार पर भारत से उभरते आख्यानों पर चर्चा करने के लिए 22 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में विज्ञान राजनय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। यही नहीं, इसका उद्देश्य विज्ञान राजनय का उपयोग करके अंतरिक्ष, परमाणु और एयरोस्पेस के क्षेत्र में भारत के सफल प्रयासों को प्रस्तुत करना भी था। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद प्रोफेसर वी. एस. राममूर्ति, पूर्व सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और प्रोफेसर एमेरिटस, एनआईएएस ने विशेष भाषण दिया। डॉ. साधना रेलिया, प्रमुख (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ने मुख्य भाषण दिया। इसके बाद डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान राजनय फेलो, आरआईएस और पूर्व भारतीय राजदूत एवं प्रोफेसर डी. सुबा चंद्रन, डीन, स्कूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, एनआईएएस तथा समन्वयक, एनआईएएस विज्ञान राजनय पहल ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

संगोष्ठी के दौरान प्रतिष्ठित वक्ताओं ने वर्तमान युग में विज्ञान राजनय की भूमिका पर प्रकाश डाला और इसके साथ ही विभिन्न उभरते मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। इस दौरान यह मुख्य बिंदु उभर कर सामने आया: औपचारिक राजनयिक साधन के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग बीसवीं सदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है। हालांकि, इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि इस तरह का सहयोग केवल वैज्ञानिक समुदाय तक ही सीमित रहा है और इसमें सरकार की बहुत कम भागीदारी रही है। अतः देश के राष्ट्रीय विकास और आर्थिक विकास के लिए विज्ञान राजनय की क्षमता का उपयोग करते हुए इससे अपेक्षित लाभ उठाने में सरकार की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की स्थापना में भारत द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका को हाल के महीनों में सफल विज्ञान राजनय प्रयास की एक उल्लेखनीय मिसाल माना जाता है।

विज्ञान राजनय पर आरआईएस–डीएसटी–एनआईएएस सेमिनार में प्रतिष्ठित पैनलिस्ट।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

आरआईएस के चेयरमैन राजदूत मोहन कुमार सेमिनार के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए।

विचार–विमर्श के दौरान यह बात भी रेखांकित की गई कि भारत को पड़ोस के अन्य विकासशील देशों के साथ और भी अधिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) साझेदारियां करने की आवश्यकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रयासों में भारत द्वारा बाकायदा साबित की जा चुकी अपनी विशिष्ट क्षमता को देखते हुए एशियाई क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों के चुनिंदा देशों में भी राजनयिक लाभ के लिए इसके उपयोग की संभावनाओं को आगे और तलाशने की आवश्यकता है। विज्ञान राजनय से जुड़े भारत के प्रयासों में तेजी लाने की खातिर पड़ोस के सभी विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 'ओपन यूनिवर्सिटी' की स्थापना करने और समूचे क्षेत्र में बड़ी आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 'टेलीमेडिसिन' को बढ़ावा देने जैसे विचार को अमल में लाया जा सकता है।

संगोष्ठी के दौरान भारत के विज्ञान राजनय प्रयासों को मजबूत करने के लिए कई मूल्यवान सुझाव दिए गए। एसएंडटी उत्पादों/सेवाओं को सही ढंग से प्रदर्शित करने के लिए एक हाई–टेक एसएंडटी अवसंरचना यूनिट और एक हाई–टेक एसएंडटी इन्क्यूबेशन (इंटरफेस) केंद्र की स्थापना करने तथा पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर इसे आसानी से अपनाना सुनिश्चित करने की संभावनाओं के बारे में भविष्य में पता लगाया जा सकता है। विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई–कॉमर्स और विश्व व्यापार संगठन पर संगोष्ठी

डिजिटल प्रौद्योगिकी ने वैश्विक व्यापार से जुड़ी वार्ताओं में अहम मुकाम हासिल कर लिया है। इसे अलग–अलग तरीकों से अभिव्यक्त किया गया है। उदाहरणस्वरूप, ब्यूनस आयर्स में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक में ई–कॉमर्स पर एक बहुपक्षीय समूह का गठन करने और इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण (ट्रांसमिशन) पर स्थायी अधिस्थगन का प्रस्ताव किया गया। हाल ही में भारत ने भी एक ई–कॉमर्स नीति का मसौदा तैयार किया है, ताकि तेजी से उभरते इस सेक्टर में एक विनियामक और विकासात्मक रूपरेखा तैयार की जा सके। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में ई–कॉमर्स पर बहुपक्षीय चर्चा में भाग न लेने का निर्णय लिया था। अतः डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर वैश्विक स्तर के नीति–निर्माताओं और विशेषज्ञों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए आरआईएस ने 5 जून 2019 को 'ई–कॉमर्स' पर एक परामर्श का आयोजन किया था। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत मोहन कुमार ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने परिचयात्मक भाषण दिया। इसके बाद वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री सुधांशु पांडेय ने उद्घाटन भाषण दिया। श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस, ने डब्ल्यूटीओ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर अधिस्थगन और ई–कॉमर्स संबंधी चर्चाओं पर आयोजित पहले कार्यचालन सत्र की अध्यक्षता की जिसमें सुश्री रश्मि बंगा, आर्थिक मामलों की वरिष्ठ अधिकारी, अंकटाड प्रमुख वक्ता थीं। राजदूत जयंत दासगुप्ता, डब्ल्यूटीओ में पूर्व भारतीय राजदूत और श्री ए. के. गर्ग, निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस अवसर पर मुख्य मध्यस्थ थे।

'डेटा संरक्षण, साझाकरण और प्रोसेसिंग का महत्वः भारत के लिए चुनौतियां एवं अवसर' पर आयोजित अगले सत्र के दौरान श्री किरण कार्णिक, पूर्व अध्यक्ष, नैस्कॉम, मुख्य वक्ता थे। श्री आनंद कृष्णन, भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद और श्री अरविंद गुप्ता, प्रमुख, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, इस अवसर पर मध्यस्थ थे। समापन सत्र 'राष्ट्रीय ई–कॉमर्स नीति के मसौदे' पर आयोजित किया गया जिसमें श्री शैलेंद्र सिंह, अपर सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग मुख्य वक्ता थे।

कृषि में भारत–अफ्रीका साझेदारी

भारत और अफ्रीका मित्रता एवं सहयोग का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं। वैसे तो उनके बीच द्विपक्षीय

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

विकास सहयोग का विस्तार हो रहा है, लेकिन दोनों ही देश विशेषकर खाद्य एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा और उत्पादकता के क्षेत्रों में कुछ आम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

भारत सरकार कृषि क्षेत्र में भारत–अफ्रीका सहयोग को मजबूत करने के लिए कई पहलों को बढ़ावा देती रही है। चूंकि आगामी भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए कई मुद्दे और अवसर उभर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आरआईएस पूरी सक्रियता के साथ कृषि क्षेत्र में भारत–अफ्रीका सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाओं को सुविधाजनक बनाता रहा है। इस प्रयास को जारी रखते हुए आरआईएस ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) के सहयोग से 7 जून 2019 को 'कृषि में भारत–अफ्रीका साझेदारी पर गोलमेज सम्मेलन' आयोजित किया था।

माननीय श्री बेन जाउबर्ट, कार्यवाहक उच्चायुक्त, दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग, नई दिल्ली ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इसका शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ. नफीस मियाह, दक्षिण एशियाई प्रतिनिधि, आईआरआरआई के स्वागत भाषणों के साथ हुआ। डॉ. अब्देलबागी एम इस्माइल, पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि, आईआरआरआई , ने स्वागत भाषण दिया। डॉ. अब्देलबागी एम इस्माइल, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि, आईआरआरआई, ने विशेष भाषण दिया। श्री संजय अग्रवाल, सचिव, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग ने उद्घाटन भाषण दिया।

'कृषि में भारत–अफ्रीका सहयोगः संभावनाएं और चुनौतियां' विषय पर आयोजित पहले सत्र की अध्यक्षता आईसीएआर–राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. सुरेश पाल ने की। डॉ. अलका भार्गव, अपर सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग ने 'कृषि अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकियों में भारत–अफ्रीका सहयोग' पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। समापन सत्र की अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के वैज्ञानिक सचिव डॉ. अरबिंद मित्रा ने की। डॉ. नीना मल्होत्रा, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, ने विशेष भाषण दिया। डॉ. नफीस मियाह, दक्षिण एशिया प्रतिनिधि, आईआरआरआई, ने चर्चाओं के दौरान प्राप्त सुझावों एवं विचारों को प्रस्तुत किया।

विचार–विमर्श के दौरान कई नए विचार सामने आए, जो एशिया और अफ्रीका से जुड़े आरआईएस के व्यापक

(बाएं से दाएं) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; श्री संजय अग्रवाल, सचिव, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग; माननीय श्री बेन जाउबर्ट, कार्यवाहक उच्चायुक्त, दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग, नई दिल्ली; डॉ. अब्देलबागी एम इस्माइल, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि, आईआरआरआई; और डॉ. नफीस मियाह, दक्षिण एशिया प्रतिनिधि, आईआरआरआई।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

कार्यकलाप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरह से प्रतिबिंबित किए जाएंगे। चूंकि भारत अगले वर्ष भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) की तैयारियों में जुटा हुआ है, इसलिए इस कार्यक्रम में क्षेत्रवार विशिष्टताओं की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

पहला बिंदु जिसे रेखांकित करने की आवश्यकता है वह अफ्रीका को आगे बढ़ने में मदद करने में एसडीजी की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके साथ ही यह जानने की जरूरत है कि आखिरकार कैसे वर्तमान मसलों को सुलझाने के लिए एसटीआई का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा बिंदु यह है कि भारत के अपने विकास अनुभवों और भारत की अपनी नीतिगत रूपरेखा को कृषि, नीली अर्थव्यवस्था, मत्स्त पालन और पशुधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत–अफ्रीका के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के संदर्भ में प्रासंगिक बनाया जा सकता है। तीसरा मुख्य बिंदु अफ्रीकी देशों में भारतीय साझेदारों द्वारा अब तक किए गए सफल उपायों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आईएलएंडएफएस द्व ारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए कॉटन–4 प्रोजेक्ट से जुड़े अनुभव का उदाहरण इस संदर्भ में दिया जा सकता है।

अंतिम मुख्य बिंदु विभिन्न संस्थानों की भूमिका के संदर्भ में है। भारतीय संस्थान अफ्रीका के साथ जुड़ते जा रहे हैं। यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय संस्थान और भारतीय संस्थान आपसी सहयोग की व्यवस्थाओं के रूप में एक साथ आ रहे हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत दरअसल अफ्रीका के साथ जुड़ाव के संदर्भ में इसी बात पर विशेष जोर देता रहा है। संस्थागतकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विभिन्न अफ्रीकी देशों में भारत द्वारा 13 अफ्रीकी उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का सफल उदाहरण आपसी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष सत्र

आरआईएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रौद्योगिकी और उसके गवर्नेंस से जुड़े उभरते वैश्विक रुझानों और विशेषकर भारत तथा सामान्य रूप से विकासशील देशों में नीति–निर्माताओं और नियामकों के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर निरंतर करीबी नजर रख रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने 23 अप्रैल 2019 को एक संक्षिप्त विचार–मंथन सत्र का आयोजन किया था जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं समाज पर हो रहे अनुसंधान का पता लगाना तथा व्यापक विषयों व चिंताओं की पहचान करना और फिर एआई तथा उसके गवर्नेंस के नैतिक, सामाजिक एवं कानूनी निहितार्थों पर आगे शोध करने के लिए एक रोडमैप विकसित करना था।

कार्यक्रम की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुई। राजदूत एस.टी. देवारे, अध्यक्ष, आरआईएस की अनुसंधान सलाहकार परिषद (आरएसी), ने सत्र की अध्यक्षता की। प्रमुख वक्ता ये थेः श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; श्री अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; प्रो. वी. कामाकोटि, कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास; सुश्री सिंधुश्री खुल्लर, सदस्य, आरआईएस की आरएसी; डॉ. वी. सिद्धार्थ, भारत के प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद के पूर्व सचिव; डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस एवं पूर्व भारतीय राजदूत; डॉ. साधना रेलिया, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग; डॉ. एस.आर. राव, सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग; सुश्री कविता भाटिया, निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; श्री मयंक, वैज्ञानिक डी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

आरआईएस की ओर से डॉ. रवि श्रीनिवास, सलाहकार; श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, सलाहकार; डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर; डॉ. अमित कुमार, रिसर्च एसोसिएट; सुश्री निमिता पांडे, रिसर्च एसोसिएट और सुश्री गीतिका खंडूजा, अनुसंधान सहायक ने भी सत्र में भाग लिया।

त्रिपक्षीय राजमार्ग और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इसके निहितार्थः तामू सीमा प्राधिकरण के साथ बैठक

आरआईएस 'त्रिपक्षीय राजमार्ग और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इसके निहितार्थ' नामक एक नया अध्ययन कराता रहा है। इस अध्ययन के संबंध में आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

के नेतृत्व में चार सदस्यीय अध्ययन दल ने तामू का दौरा किया और 9 अप्रैल 2019 को म्यांमार के तामू में तामू सीमा व्यापार अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारतीय महावाणिज्य दूत श्री नंदन सिंह भैसोरा उपस्थित थे। इसके अलावा मणिपुर विश्वविद्यालय के प्रो. प्रियरंजन सिंह भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में जिला कलक्टर, तामू; व्यापार विभाग, कस्टम; मोरे एवं तामू के व्यापार मंडलों, और भारत व म्यांमार के अन्य हितधारकों तथा व्यापार समुदाय ने भाग लिया। इस दौरान सीमा व्यापार, प्रक्रियाओं, बाधाओं, एक संयुक्त सीमा व्यापार समिति के गठन, रुपया व्यापार, कनेक्टिविटी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने, ई–वीजा, बॉर्डर पास, हवाई एवं बस कनेक्टिविटी, मोटर वाहन समझौते और विभिन्न अन्य मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

'एक्ट ईस्टः पूर्वोत्तर सीमा पर भारत के व्यापार' पर आरआईएस की संगोष्ठी

आरआईएस ने 3 जून 2019 को नई दिल्ली में 'एक्ट ईस्टः पूर्वोत्तर सीमा पर भारत के व्यापार' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। राजदूत गौतम मुखोपाध्याय ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की और आरंभिक भाषण दिया। आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने 'एक्ट ईस्टः पूर्वोत्तर भारत में व्यापार' पर एक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति में मोटे तौर पर एक्ट ईस्ट नीति (एईपी) के तहत पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों का भी आवरण किया गया।

विशेष रूप से, डॉ. डे ने पूर्वोत्तर भारत के पिछले तथा हालिया दौरे के बारे में बात की और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं विभिन्न सीमा कनेक्टिविटी परियोजनाओं तथा पहलों की संभावनाओं के दोहन के लिए कई निष्कर्षों और नीतिगत सिफारिशों को रेखांकित किया। श्री वनलालरुआता फनाई, सहायक महाप्रबंधक, अनुसंधान और विश्लेषण समूह, एक्जिम बैंक इस अवसर पर चर्चाकर्ता थे। संगोष्ठी में अनुसंधान विद्वानों, सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों और अन्य लोगों ने भाग लिया।

भारत–मध्य एशियाः पारंपरिक संबंध और विकास साझेदारी

भारत ने मध्य एशियाई देशों के साथ विकास सहयोग को मजबूत करने को सदैव काफी प्राथमिकता दी है। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने 4 अप्रैल 2019 को 'भारत–मध्य एशियाः पारंपरिक संबंध और विकास साझेदारी' पर एक सेमिनार का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, ने की। कार्यक्रम की शुरुआत

किर्गिस्तान में भारत के राजदूत श्री आलोक डिमरी अन्य साथी प्रतिभागियों के साथ संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करते हुए।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

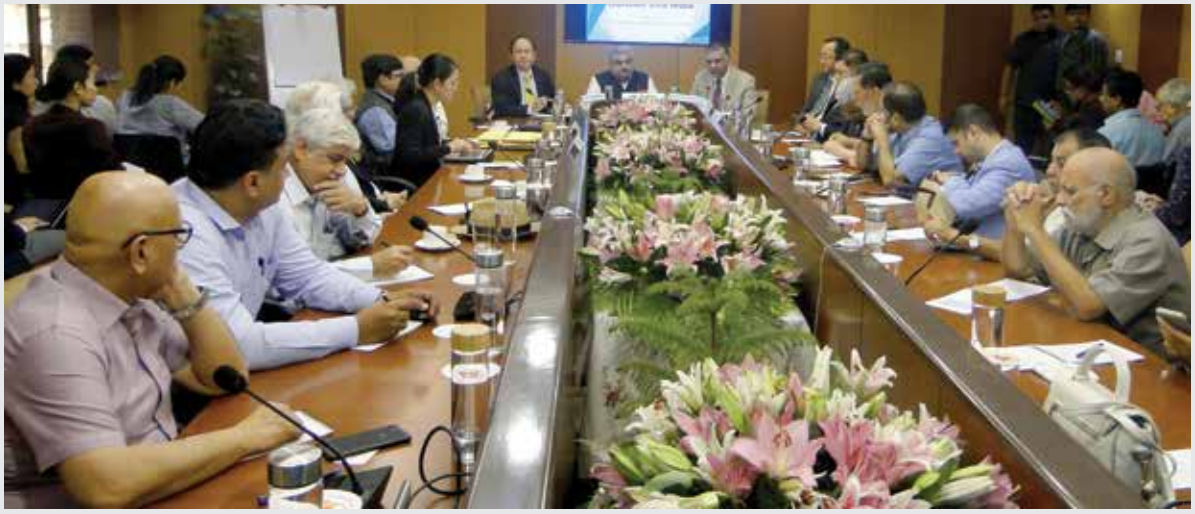

डॉ. सूर्या चिन्डावोंगसे आरआईएस ब्रेकफास्ट सेमिनार में व्याख्यान देते हुए।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुई। किर्गिस्तान में भारत के राजदूत आलोक डिमरी मुख्य वक्ता थे।

इसके बाद माननीय श्री एसेन इसेव, मिशन के राजदूत असाधारण उप प्रमुख, दूतावास एवं पूर्णाधिकारी, भारत में उज्बेकिस्तान का दूतावास और डॉ राम, किर्गिज गणराज्य; माननीय श्री उपेंद्र दास, प्रमुख एवं प्रोफेसर, शेलार गेल्डिनजारोव, राजदूत, क्षेत्रीय व्यापार केंद्र, तुर्कमेनिस्तान का भारतीय दूतावास; श्री ए'जामजॉन मानसुरोव, प्रथम सचिव, विदेश व्यापार संस्थान ने परिचर्चाओं में भाग लिया।

एफटीए और भारतीय अर्थव्यवस्था

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक परिचर्चा बैठक 9 मई 2019 को आरआईएस में आयोजित की गई। परिचर्चा में सक्रिय रूप से शामिल होने वाले जाने–माने व्यक्ति ये थेः श्री सुधांशु पांडेय, अपर सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; श्री अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच; श्री दामू रवि, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; डॉ. रथिन रॉय, निदेशक, एनआईपीएफपी; डॉ. अभिजीत दास, प्रमुख, डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र, आईआईएफटी; श्री अनिलेश महाजन; और डॉ. राम उपेंद्र दास, प्रमुख, क्षेत्रीय व्यापार केंद्र। आरआईएस की ओर से विचार–विमर्श में भाग लेने वालों में प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक; प्रो. एस.के. मोहंती; राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो; और श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो शामिल थे।

भारत–अफ्रीका आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना

आरआईएस ने अफ्रीका के साथ व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और वित्त संबंधी सहयोग पर एक प्रमुख मौलिक शोध कार्यक्रम शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रमुख प्राथमिकताओं, प्रमुख चुनौतियों और संभावित संस्थागत सहयोग एवं संबंधित कदमों की पहचान करने हेतु आगे की राह तलाशने के लिए 27 जून 2019 को परामर्श सत्र आयोजित किया गया था।

बड़ी संख्या में इन प्रतिष्ठित प्रतिभागियों ने विचार–विमर्श में भाग लियाः राजदूत सतीश मेहता; राजदूत अजीत कुमार; राजदूत दिव्याभ मनचंदा; राजदूत अजमपुर रंगिया घनश्याम; राजदूत राधिका लोकेश; श्री जी. वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय; श्री मोहित यादव, निदेशक (सीएंडडब्ल्यूए), विदेश मंत्रालय; श्री ई. बी. राजेश, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय निदेशक– अफ्रीका, सीआईआई; डॉ. मिलन शर्मा, प्रमुख–ग्लोबल इनिशिएटिव्स, आईएलएंडएफएस क्लस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिमिटेड, श्री नदीम पंजेटन, मुख्य

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

प्रो. रवि बी. ग्रोवर, एमेरिटस प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान और सदस्य, परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा बीसवीं एसटीआईपी फोरम में व्याख्यान देते हुए

महाप्रबंधक, एक्जिम बैंक; प्रो. अजय कुमार दुबे, जेएनयू; डॉ. शाहिद अहमद, पूर्व प्रोफेसर एवं प्रमुख, जामिया मिलिया इस्लामिया; प्रो. सुरेश कुमार, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय; और डॉ.रुचिता बेरी, आईडीएसए।

आरआईएस की ओर से प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ. एस. के. मोहंती; राजदूत अमर सिन्हा; राजदूत भास्कर बालाकृष्ण; डॉ. पी.के. आनंद; श्री कृष्ण कुमार; डॉ.रवि श्रीनिवास; डॉ. बीना पांडे; श्री अरुण एस. नायर; डॉ. सब्यसाची साहा; डॉ. प्रियदर्शी डैश; डॉ. अमित कुमार; डॉ. सुशील कुमार; सुश्री निमिता पांडेय; डॉ. आभा जायसवाल; श्री एम.सी. अरोड़ा; और डॉ. नम्रता पाठक ने परिचर्चा में भाग लिया।

आरआईएस ब्रेकफास्ट सेमिनार सीरीज

आसियान हिंद–प्रशांत आउटलुक और भारत

'हिंद–प्रशांत' स्वरूप हाल के वर्षों में अपनी ओर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करने में काफी सफल रहा है। भारत और आसियान दोनों की ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक हैसियत है। भारत एक ऐसे 'हिंद–प्रशांत' में विश्वास करता है जो स्वतंत्र, खुला एवं समावेशी हो और जो एक सहकारी तथा सहयोगात्मैक नियम–आधारित व्यवस्था पर स्थापित हो। इसकी गूंज न केवल इस समूचे क्षेत्र में, बल्कि पूरे विश्व में भी सुनाई पड़ती है। हिंद–प्रशांत एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई एशियाई ताकतें फिर से विशेषकर भू–आर्थिक दृष्टि से उभर रही हैं। वैसे तो आसियान की केंद्रीयता को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन आसियान और भारत निश्चित तौर पर 'हिदं–प्रशांत' को सुदृढ़ करने के लिए आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। समुद्री पड़ोसी होने के नाते आम समुद्री क्षेत्र, महासागर एवं समुद्र पर एक सामान्य निर्भरता और महासागर संसाधनों के सतत दोहन के महत्व की एक सामान्य समझ को साझा करके आसियान और भारत अवश्य ही 'हिद–प्रशांत' साझेदारी को आगे बढ़ाने में आदर्श साझेदार हो सकते हैं।

आसियान देशों ने अपनी–अपनी 'हिद–प्रशांत' गाथाएं प्रस्तुत कीं। 20 मार्च 2019 को इंडोनेशिया ने जकार्ता में एक 'उच्चस्तरीय हिंद–प्रशांत संवाद' की मेजबानी की। आसियान का अध्यक्ष होने के नाते थाईलैंड बड़ी सक्रियता के साथ 'हिद–प्रशांत' एजेंडे को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने में जुटा हुआ है। अतः थाईलैंड की 'हिदं–प्रशांत' रणनीति को समझना अत्यंत आवश्यक है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में इन मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए डॉ. सूर्या चिन्डावोंगसे, महानिदेशक, आसियान मामलों का विभाग, विदेश मंत्रालय, थाईलैंड, ने 10 अप्रैल 2019 को आरआईएस में 'आसियान हिद–प्रशांत आउटलुक ओर भारत' पर आरआईएस ब्रेकफास्ट व्याख्यान दिया। भारत में थाईलेंड के राजदूत माननीय श्री चुटिंटोर्न गोंगसकडी ने भी विचार–विमर्श में भाग लिया। सेमिनार की अध्यक्षता भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव (पूर्व) राजदूत अनिल वाधवा ने की। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने खुली परिचर्चा में भाग लिया।

जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन' का विमोचन

आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने आसियान अध्ययन केन्द्र (एएससी) और चुलालोंगकॉर्न विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केन्द्र के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 6 जून 2019 को चुलालोंगकॉर्न विश्वविद्यालय, बैंकॉक, थाईलैंड, में *जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन* के विमोचन का आयोजन किया। प्रो. सुतीपचंद चिरथिवत, कार्यकारी निदेशक, आसियान अध्ययन केंद्र (एएससी) ने आरंभिक भाषण दिया। डॉ. मिया मिकिक, निदेशक, व्यापार, निवेश एवं नवाचार, संयुक्त राष्ट्र एस्कैप, बैंकॉक ने विशेष भाषण दिया। आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) और चुलालोंगकॉर्न विश्वविद्यालय के आसियान अध्ययन केन्द्र (एएससी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित 'जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन (जेएईआई)' में एशिया से संबंधित अर्थशास्त्र के विस्तृत विषयों की विस्तृत कवरेज सुनिश्चित की जाती है जिसमें वर्तमान अनुसंधान का विवेचन, अंतरराष्ट्रीय

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

तुलना और देश संबंधी अध्ययन भी शामिल हैं। 'एशियाई एकीकरणः उभरते रुझान और चुनौतियां' विषय पर एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई जिसका संचालन डॉ. पीति श्रीसंगनाम, निदेशक, अकादमिक मामले, आसियान अध्ययन केंद्र, चुलालोंगकॉर्न विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। पैनल के सदस्य ये थेः डॉ. मिया मिकिक, डॉ. चरित तिंगसादाध, एसोसिएट प्रोफेसर एवं पूर्व निदेशक, यूरोपीय अध्ययन केंद्र, चुलालोंगकॉर्न विश्वविद्यालय; डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर एवं समन्वयक, आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी), नई दिल्ली; और डॉ. विटादा औंकुनवट्टाका, आर्थिक मामलों के अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र एस्कैप। आखिर में डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

स्टिप व्याख्यान श्रृंखला

स्टिप व्याख्यान श्रृंखला के भाग के रूप में निम्नलिखित व्याख्यानों का आयोजन किया गयाः

स्टिप व्याख्यान

- प्रोफेसर माइकल ग्रब, अनुसंधान निदेशक और ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने नई दिल्ली में 3 अक्टूबर 2019 को 'ऊर्जा क्रांति में नवाचार एवं नीतिः यूरोप से कुछ अंतर्दृष्टि' विषय पर 24वां स्टिप फोरम व्याख्यान दिया।
- प्रोफेसर कन्नन एम. मौदगल्या, एराच एंड मेहरू मेहता एडवांस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी चेयर प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–बॉम्बे ने 18 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में 'शिक्षा एवं रोजगार के लिए मौखिक शिक्षण के माध्यम से आईटी कौशल प्रशिक्षण' विषय पर 25वां स्टिप फोरम व्याख्यान दिया। डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस ने अध्यक्षता की।
- श्री जयंत सहस्रबुद्धे, राष्ट्रीय आयोजन सचिव, विजनाना भारती ने 18 दिसंबर 2019 को 26वां व्याख्यान दिया। विषय था 'पैट्रिक गेडेस का विजन और कृतियांः आज की दुनिया में इसकी प्रासंगिकता'। डॉ. नकुल पाराशर, निदेशक, विज्ञान प्रसार ने इसकी अध्यक्षता की।

'भारत को अपने गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है?', इस विषय पर डॉ. दिनेश के. असवाल, निदेशक, सीएसआईआर–राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) ने 12 जुलाई 2019 को व्याख्यान दिया। श्री गौहर रजा, अग्रणी विज्ञान संचारक (कम्युनिकेटर) और पूर्व वैज्ञानिक, सीएसआईआर ने इसकी अध्यक्षता की।

'नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक का वित्त पोषण', इस विषय पर टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री मनीष चौरसिया ने 12 अगस्त 2019 को व्याख्यान दिया। श्री आर. आर. रश्मि, प्रतिष्ठित फेलो एवं कार्यक्रम निदेशक, टेरी ने इसकी अध्यक्षता की।

- 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के लिए नवाचार', इस विषय पर डॉ. शेखर सी. मंडे, सचिव, डीएसआईआर और महानिदेशक, सीएसआईआर ने 19 सितंबर 2019 को व्याख्यान दिया। डॉ. चंद्रिमा शाहा, प्रख्यात प्रोफेसर और पूर्व निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एवं निर्वाचित अध्यक्ष, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने इसकी अध्यक्षता की।

उन्नीसवीं एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 'शहरीकरण और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में उभरते संक्रामक रोगों पर कदमः विज्ञान कहां गया?' विषय पर डॉ. ओलिवर टेलले, सीएनआरएस में शोधकर्ता, फ्रांस डी साइंसेज ह्यूमेन्स , फ्रांस का दूतावास, भारत द्वारा 22 अप्रैल 2019 को दिया गया। इसकी अध्यक्षता डॉ. दिनकर एम. सलुंके, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, नई दिल्ली, ने की।

- बीसवीं एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 'ज्ञान उत्पादन की विधियों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उद्भव के बीच संबंध' विषय पर प्रो. रवि बी. ग्रोवर, एमेरिटस प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान और सदस्य, परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 7 जून 2019 को दिया गया। प्रो. राममूर्ति राजारमण, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, जेएनयू ने इसकी अध्यक्षता की।

एफआईएसडी व्याख्यान

- श्री कियोशी कुरिहारा, भारत में जापान के दूतावास में प्रथम सचिव (एसएंडटी) ने 24 अक्टूबर 2019 को दूसरा एफआईएसडी व्याख्यान दिया। विषय था 'एसडीजी के लिए जापानी एसटीआई पहल'। इसकी अध्यक्षता डॉ. अरबिंद मित्रा, वैज्ञानिक सचिव, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, भारत सरकार ने की।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

- 2 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में राजदूत श्री जोनाथन फ्राइड, जी20 के लिए प्रधानमंत्री के निजी प्रतिनिधि एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के लिए जीएसी के समन्वयक और श्री केंट, उप उच्चायुक्त, कनाडा के दूतावास के साथ परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 9 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में राजदूत श्री जूलियन वेंचुरा वलेरो, उप विदेश मंत्री, मेक्सिको के दूतावास के साथ परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 1 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा आयोजित प्रथम भारत–जर्मनी रणनीतिक संवाद के दौरान 'भारत–जर्मनी साझेदारी: रणनीतिक और आर्थिक आयामों की तलाश करने' पर एक प्रस्तुति दी।
- 21 अक्टूबर, 2019 को न्यूयॉर्क में यूएनडीपी–ओईसीडी द्वारा संयुक्त रूप से 'सतत विकास और समावेशी वैश्वीकरण से जी20 के नीतिगत कदमों के लिए मिल रहा है दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित जी–20 कार्यशाला के दौरान 'सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' पर प्रस्तुति दी।
- 21 अक्टूबर, 2019 को न्यूयॉर्क में यूएनडीपी–ओईसीडी द्वारा संयुक्त रूप से 'सतत विकास और समावेशी वैश्वीकरण से जी20 के नीतिगत कदमों के लिए मिल रहा है दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित जी–20 कार्यशाला के दौरान 'जी20 के सहभागिता समूहों के साथ संवाद' पर आयोजित सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- 22 अक्टूबर 2019 को न्यूयॉर्क शहर में जी–20 कार्यशाला के दौरान आयोजित अनौपचारिक डीडब्ल्यूजी बैठक में भाग लिया।
- 5 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी) द्वारा 'अफ्रीका में व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने और मजबूत करने में दक्षिणीय सहयोग की भूमिका' पर आयोजित ई–परिचर्चा में भाग लिया।
- 16 नवंबर 2019 को बेंगलुरू में राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (एनआईएएस) द्वारा 'एनआईएएस रणनीतिक पूर्वानुमान 2020: समकालीन वैश्विक मामलों' पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान '2020 में, 2020 के बाद दुनिया के साथ भारत की आर्थिक सहभागिता?' पर एक प्रस्तुति दी।
- 10 नवंबर 2019 को नागपुर में श्री दत्तोपंत ठेंगडी की समिति के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लिया।
- 26 नवंबर 2019 को एनटेबे, युगांडा में 'प्रेरणा, समावेश और नवाचार: एफएओ–चीन दक्षिणीय सहयोग कार्यक्रम की दसवीं वर्षगांठ और दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोग के लिए भविष्य के दृष्टिकोण' पर आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रम में 'बेहतर पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोग' पर एक प्रस्तुति दी।
- 7 दिसंबर 2019 को पटियाला में विकास अर्थशास्त्र एवं नवाचार अध्ययन केंद्र (सीडीईआईएस), पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला, और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारतीय श्रम अर्थशास्त्र सोसायटी (आईएसएलई) के 61वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान 'एनआईएस, आर्थिक विकास और असमानता: शूमपीटर का एक दृष्टिकोण' पर विशेष व्याख्यान की अध्यक्षता की।
- 11 दिसंबर, 2019 को गुइलिन, चीन में संयुक्त राष्ट्र – विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चीन सरकार द्वारा 'सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार' विषय पर आयोजित संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यशाला के दौरान 'समावेशी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीतियों ' और 'एसडीजी के लिए एसटीआई रोडमैप – संयुक्त दिशा–निर्देश और वैश्विक पायलट कार्यक्रम ' पर प्रस्तुतियां दीं।
- 3 दिसंबर और 5 दिसंबर 2019 को सियोल, कोरिया में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा 'विकास सहयोग की वैश्विक संरचना का भविष्य – दक्षिणीय सहयोग के साझेदारों के दृष्टिकोण' पर आयोजित गोलमेज बैठक के दौरान क्रमशः 'विकास सहयोग के लिए वैश्विक संरचना का भविष्य: विशिष्ट कदम' और 'विकास प्रभावशीलता एजेंडे के लिए आउटरीच: विभिन्न दृष्टिकोण' पर पैनल परिचर्चाओं में पैनलिस्ट थे।
- 18–19 दिसंबर, 2019 को टोक्यो, जापान में विश्व बैंक द्वारा 'एसडीजी रोडमैप के लिए एसटीआई पर एक वैश्विक पायलट कार्यक्रम के लिए सहयोग' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 27 सितंबर 2019 को श्रीलंका के कोलंबो में श्रीलंका के नीतिगत अध्ययन संस्थान (आईपीएस) द्वारा आयोजित 12वें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन में 'चौथी औद्योगिक क्रांति में नवाचार और व्यापक बदलाव या कायापलट को बढ़ावा' पर एक प्रस्तुति दी।
- 16 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित सतीश देवधर की पुस्तक 'आर्थिक सूत्र: आर्थिक चिंतन के लिए प्राचीन भारतीय दृष्टांत' के विमोचन समारोह में पैनलिस्ट थे।
- 12 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित व्यापार बोर्ड (बीओटी) की उच्चस्तरीय बैठक में 'भारत की व्यापार नीति' पर एक प्रस्तुति दी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

- 8 सितंबर, 2019 को बांग्लादेश के ढाका में नीतिगत संवाद केंद्र (सीपीडी) द्वारा 'बेल्ट एंड रोड पहलः तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत बांग्लादेश की स्थिति ' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में 'बीआरआई की राजनीति ' पर अपने विचार व्यक्त किए।
- 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में सतत विकास के लिए सीआईआई–आईटीसी उत्कृष्टता केंद्र द्वारा आयोजित 14वें निरंतरता शिखर सम्मेलन में 'भविष्य के लिए एजेंडा' पर एक प्रस्तुति दी।
- 20 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) के आकलन पर आईसी समूह की बैठक' में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 13 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 17 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में सहयोग के लिए कोलंबियाई अध्यक्षीय एजेंसी (एपीसी–कोलम्बिया), दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी) और सतत विकास डेटा के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएसडीडी) द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम 2019 की बैठक के दौरान 'प्रयासों में शामिल होनाः एसडीजी में दक्षिणीय सहयोग के योगदान को मापना' विषय पर अलग से किए गए संयुक्त कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे।
- 17 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा 'दक्षिणीय वैश्विक विचारक संवाद – बीएपीए + 40 परिणाम दस्तावेज पर राय ' विषय पर अलग से आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान एक प्रस्तुति दी।
- 16 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में फोर्ड फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान 'निजी क्षेत्र के साथ अभिनव साझेदारियांः अधिक से अधिक एसडीजी को कैसे प्राप्त करें ' पर एक प्रस्तुति दी।
- 16 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एचएलपीएफ में नीति आयोग द्वारा 'प्रतिबद्धता से उपलब्धि तकः सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में भारत के अनुभव' विषय पर अलग से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।
- 15 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में येल विश्वविद्यालय द्वारा 'आर्थिक विकास में सामाजिक उद्यमों की भूमिका और सफल विकासात्मक पहलों का स्तर बढ़ाना' विषय पर आयोजित पारस्परिक संवादात्मक बैठक में भाग लिया।
- 13 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए मेक्सिकन एजेंसी (एएमईएक्ससीआईडी) द्वारा आयोजित 'प्रभावकारी विकास सहयोग के लिए वैश्विक साझेदारी ' की वरिष्ठ–स्तरीय बैठक (एसएलएम) में 'दक्षिणीय सहयोग में प्रभावशीलता ' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 6 जुलाई को नई दिल्ली में न्यूज नेशन नेटवर्क द्वारा आयोजित 'बजट पश्चात संगोष्ठी' में पैनलिस्ट थे।
- 20 जून 2019 को ब्रसेल्स में न्यूक्लियस और आरआरआई–प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स के 'परिवर्तन के रास्ते ' पर आयोजित संयुक्त सम्मेलन में 'संस्थागत परिवर्तन और आरआरआईः एक भारतीय परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 19 जून 2019 को नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित 'वैश्विक मुद्दे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' पर मॉड्यूल के दौरान 59वें एनडीसी कोर्स में 'क्षेत्रीय/वैश्विक वित्तीय विकास में नए वित्तीय संस्थानों के असर' पर एक प्रस्तुति दी।
- 18 जून 2019 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा भारत के आर्थिक विकास में तेजी लाने पर आयोजित 5वें अर्थशास्त्री सम्मेलन के दौरान एक प्रस्तुति दी।
- 15 जून 2019 को भारत के दूतावास, बिश्केक द्वारा आयोजित भारत–किर्गिस्तान बिजनेस फोरम में 'सतत और समावेशी विकास के लिए भारत–किर्गिस्तान विकास साझेदारी' पर एक प्रस्तुति दी।
- 26 मई 2019 को टोक्यो में एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) द्वारा आयोजित टी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान 'एसडीजी के लिए एसटीआई के इस्तेमाल' पर एक प्रस्तुति दी।
- 22 मई 2019 को नई दिल्ली में आईसीएआर–एनआईएपी द्वारा 'सुरक्षित एवं सतत कृषि के लिए कृषि नीतियां और कार्य योजना' पर आयोजित संवादात्मक बैठक में भाग लिया।
- 16 मई, 2019 को पुणे में योजक– सतत विकास के लिए अनुसंधान और रणनीतिक नियोजन के लिए केंद्र के सहयोग से सेवा इंटरनेशनल द्वारा आयोजित सेवा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में 'मध्य भारत के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की गतिशीलता' पर एक प्रस्तुति दी।
- 13 मई 2019 को नई दिल्ली में आईसीएसएसआर द्वारा आयोजित आईसीएसएसआर–स्वर्ण जयंती समारोह में 'विकास पर एक नई गाथा के लिए अनुसंधान प्राथमिकताओं को फिर से तय करने' पर समापन भाषण दिया।
- 1 मई 2019 को नई दिल्ली में आईसीडब्ल्यूए द्वारा 'इंडियाज ईस्टवर्ड एंगेजमेंटः फ्रॉम एंटिक्विटी टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी'

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

नामक पुस्तक पर आयोजित पैनल परिचर्चा में पैनलिस्ट थे।

- 25 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में आयोजित 'वित्तीय समावेशन पर सीएनआरआई राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 के दौरान 'प्रतिमान बदलावः नया संदर्भ, भारत की ओर से नई विकास गाथा' पर एक प्रस्तुति दी।
- 8 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विदेशी राजनयिकों के लिए 67वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) के दौरान 'एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी)' पर एक प्रस्तुति दी।
- 5 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) द्वारा आयोजित आसियान–भारत कार्यशाला में 'बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' पर एक प्रस्तुति दी।
- 2 अप्रैल 2019 को केपटाउन में आयोजित एनडीबी वार्षिक बैठक में 'टिकाऊ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण'पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. एस.के. मोहंती

- 4 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में विकास आयोग एमएसएमई द्वारा 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की निर्यात क्षमता को मुक्त करने के लिए अध्ययन' विषय पर आयोजित परामर्श बैठक में भाग लिया।
- 9 अक्टूबर 2019 को विकास आयोग एमएसएमई के कार्यालय में आयोजित परामर्श बैठक में 'भारत में एमएसएमईः निर्यात और आयात स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना' विषय पर एक प्रस्तुति दी। इसके साथ ही 'भारत में एमएसएमईः निर्यात और आयात स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना' विषय पर रिपोर्ट भी पेश की।
- 14 अक्टूबर 2019 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास आयोग के कार्यालय द्वारा आरआईएस का प्रतिनिधित्व करने हेतु एमएसएमई सेक्टर के लिए संयुक्त कार्य समूह (जेएसजी) के एक सदस्य के रूप में नामांकित किए गए।
- 21 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में विकास आयोग, एमएसएमई के कार्यालय में 'जेएजी निर्यात संवर्धन और स्वदेशीकरण' विषय पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 31 अक्टूबर 2019 को दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में 'हिंद महासागर का मानचित्रण अध्ययनः उभरते अनुसंधान एजेंडे' पर 'समुद्री दक्षिण एशिया और हिंद महासागर' की अनुसंधान कार्यशाला श्रृंखला की उद्घाटन कार्यशाला में भाग लिया और 'भारत में ब्लू इकोनॉमी पर उभरती सोचः एक नया वैश्विक विकास प्रतिमान' पर एक प्रस्तुति दी।
- 1 नवंबर 2019 को विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए), नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'प्रथम भारत–जर्मनी रणनीतिक संवाद' में भाग लिया और 'हिंद महासागरः भारत–जर्मन रणनीतिक सहयोग का एक नया क्षेत्र' विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की।
- 25–29 नवंबर, 2019 को बीजिंग, चीन में विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के महानिदेशक के नेतृत्व में चौथे भारत–चीन थिंक टैंक फोरम (आईसीटीटीएफ) 'में एक सदस्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 28 नवंबर, 2019 को 'चीन और भारत के बीच घनिष्ठ विकास साझेदारी करना' विषय पर आयोजित सत्र के दौरान 'अगले 20 वर्षों में वैश्विक परिदृश्य में अवसर और चुनौतियों' पर एक प्रस्तुति दी।
- 16 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में 'आसियान विद्यार्थियों को 1000 फेलोशिप का शुभारंभ समारोह ' विषय पर विदेश मंत्रालय के हिंद–प्रशांत प्रभाग द्वारा आयोजित और माननीय विदेश मंत्री एवं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में भाग लिया।
- 4 सितंबर 2019 को विकास आयोग एमएसएमई, निर्माण भवन, नई दिल्ली में 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की निर्यात क्षमता को उन्मुक्त करने के लिए अध्ययन ' पर आयोजित परामर्श बैठक में भाग लिया।
- 22 अगस्त 2019 को पृथ्वी भवन, नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के सचिव के साथ संचालन समिति की परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 20 अगस्त 2019 को वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली में 'प्रतिकूल वैश्विक परिदृश्य में भारत और ईरान के बीच बढ़ते आर्थिक संबंध' पर आयोजित परामर्श बैठक में भाग लिया।
- 14 अगस्त 2019 को वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली में 'ईरान में भारत की निर्यात क्षमता ' पर आयोजित परामर्श बैठक' में भाग लिया।
- 14 अगस्त 2019 को वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव को 'ईरान में भारत की निर्यात क्षमता ' विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- 13 अगस्त 2019 को वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ 'ईरान में भारत की निर्यात क्षमता ' विषय पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 9 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) द्वारा 'भारत और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन देशों के बीच संबंधों का जायजा लेना' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।
- 7 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'प्रलेखन अधिकारी के लिए कैरियर उन्नति योजना चयन समिति / स्क्रीनिंग – सह –

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

मूल्यांकन समिति ' में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की चयन समिति के एक सदस्य के रूप में भाग लिया।

- 21 जून 2019 को नई दिल्ली स्थित वाणिज्य विभाग में 'ईरान को भारत से निर्यात की संभावनाओं' पर आयोजित परामर्श बैठक में भाग लिया।
- 14 जून 2019 को नई दिल्ली में माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 'अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक 2019–20 पर आयोजित परामर्श बैठक में भाग लिया।
- 11 जून 2019 को नई दिल्ली में 'भारत–रूस आर्थिक सहयोग' पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 8 जून 2019 को कोलकाता में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद द्वारा 'पारस्परिक रूप से लाभकारी भविष्य के लिए भारत–बांग्लादेश संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने' पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया और 'भारत–बांग्लादेश व्यापार संबंधः आर्थिक सहयोग के लिए उभरती संभावनाओं' पर एक प्रस्तुति दी।
- 16 मई 2019 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित 'संचालन समिति – कार्य समूह # 1: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति' की बैठक में भाग लिया और 'नीली अर्थव्यवस्था एवं महासागर के गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय लेखांकन की रूपरेखा' पर एक प्रस्तुति दी।
- 15 मई 2019 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा 'भारत और ईरान के बीच प्रस्तावित तरजीही व्यापार समझौते के लिए वार्ता' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 10 मई 2019 को नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी भवन में आयोजित संचालन समिति की परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 6 मई 2019 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित 'एलएसी के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी – व्यापार और निवेश के लिए रणनीति' पर अध्ययन रिपोर्ट संबंधी कार्यक्रम में भाग लिया।
- 18 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय द्वारा 2017 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटी) एवं 2 भूटानी राजनयिकों के लिए आयोजित प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और 'विकास का एक नया प्रतिमानः नीली अर्थव्यवस्था' पर एक प्रस्तुति दी।
- 14–15 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा 'हितधारक परामर्श' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया और 'ईरान भारत पीटीएः वरीयता की गुंजाइश के लिए एक विश्लेषण' पर एक प्रस्तुति दी।
- 9–10 अप्रैल 2019 को मॉरीशस में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य द्वारा आयोजित 'रणनीतिक नियोजन' पर आईओआरए कार्यशाला तथा आईओआरए सचिवालय में 'संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर आगे की कार्रवाई' पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और आईओआरए में सुधारों पर प्रस्तावः आर्थिक गतिशीलता में नई जान फूंकने' पर एक प्रस्तुति दी।
- 5 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली स्थित वाणिज्य विभाग में 'एलएसी के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी : व्यापार और निवेश के लिए रणनीति' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

श्री राजीव खेर

प्रतिष्ठित फेलो

- 16 दिसंबर को दिल्ली में और 26–27 दिसंबर 2019 को चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' (आईसीएआई) की अनुशासनात्मक समिति – बेंच– प्प की बैठक में भाग लिया। 'भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समकालीन चुनौतियां' विषय पर आईसीएआई के सदस्यों के समक्ष व्याख्यान भी दिया।
- 19–22 दिसंबर 2019 को वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फिक्की के सहयोग से आयुष मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य 2019, आयुष एवं वेलनेस पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन में 'पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के लिए मानकों' पर एक सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 17 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में कट्स और वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा 'दक्षिण एशियाई एकीकरण के लिए ई–कॉमर्स को उन्मुक्त करना ' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित रिपोर्ट विमोचन बैठक में भाग लिया।
- 4 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के बोर्ड और कंपनी की ऑडिट समिति की बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया। इसके अलावा, 16 दिसंबर को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
- 13 और 14 दिसंबर को हैदराबाद में आईकेडीएचडब्ल्यूएजे के सलाहकारों के साथ 'घरेलू नीतिगत बाधाओं और भारत की निर्यात क्षमता' विषय पर एक्जिम बैंक समर्थित अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग एवं फार्मेक्ससिल के एक सर्वेक्षण और एक परामर्श बैठक में भाग लिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

- 5 दिसंबर 2019 को मुंबई में ट्रू नॉर्थ एडवाइजर्स एलएलपी की 15वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। इससे पहले 14 नवंबर, 2019 को विभिन्न निवेश प्राप्तकर्ता कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ परामर्श बैठक में भाग लिया।
- पहले 21, 22, एवं 29 नवंबर को और फिर 3 एवं 10 दिसंबर को पीठासीन पंच–निर्णायक (आर्बिट्रेटर) के रूप में एलएंडटी और सेल के बीच के एक पंचाट मामले में हुई विभिन्न सुनवाई का संचालन किया।
- 2 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में 'चीन पर सीआईआई कोर समूह' की चौथी बैठक में भाग लिया।
- 26 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में सीआईआई की अंतर्राष्ट्रीय परिषद 2019–20 की तीसरी बैठक में भाग लिया।
- 22 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आईसीआरआईईआर द्वारा 'वैश्विक मूल्य श्रृंखला और गुम कड़ी: भारतीय उद्योग जगत के मामले' विषय पर आयोजित पैनल परिचर्चा और पुस्तई विमोचन समारोह में भाग लिया।
- 16 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा 'एफटीए का अध्ययन' विषय पर आयोजित हितधारक परामर्श बैठक में भाग लिया।
- 10 नवंबर, 2019 को आईडीई–जेट्रो द्वारा आयोजित रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क मीटिंग (आरआईएनएम) की वार्षिक बैठक और 11–12 नवंबर 2019 को बैंकॉक में ईआरआईए द्वारा आयोजित 'एशिया–प्रशांत थिंक–टैंक शिखर सम्मेलन 2019' में एक चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया।
- 5 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा 'क्रिप्टोकरेंसी, लिब्रा और व्यापार एवं निवेश समझौतों' विषय पर आयोजित वार्तालाप में भाग लिया।
- अक्टूबर और नवंबर के दौरान चार अवसरों पर 'आरसीईपी' पर सीएनबीसी, ईटी नाऊ और न्यूज X द्वारा साक्षात्कार लिया गया।
- 30 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा एचएलएजी समूह की रिपोर्ट के विमोचन और उसी दिन इस समूह की सिफारिशों पर सीएनबीसी द्वारा आयोजित एक पैनल परिचर्चा में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 25 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित 'एफटीए के अध्ययन पर संचालन समिति' की बैठक में भाग लिया।
- 21 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति (बेंच II) की बैठक में भाग लिया।
- 18 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित आसियान के सदस्य देशों के राजनयिकों और एएसईएम के सदस्य देशों के राजनयिकों के लिए 'भारत एवं एफटीए (बीटीआईए और आरसीईपी के विशेष संदर्भ के साथ)' पर एक व्याख्यान दिया।
- 24 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में ईटी नाऊ द्वारा रिकॉर्ड की गई 'आरसीईपी' पर एक पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 25–27 सितंबर 2019 को इलाहाबाद में यूपी लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार बोर्ड के विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में नामित किए गए।
- 23 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के सौजन्य से आईटीईसी प्रतिभागियों को 'वैश्विक व्यापार की बदलती गतिशीलता ' विषय पर व्याख्यान दिया।
- 20 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में सीएनबीसी टीवी18 द्वारा 'आरसीईपी ' पर आयोजित एक परिचर्चा में भाग लिया।
- 19 सितंबर 2019 को मुंबई में 'ट्रू नॉर्थ एलएलपी ' की बैठक में भाग लिया।
- 17 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में 'उत्पादों का आयुष वर्गीकरण और गुणवत्ता रोडमैप ' पर गठित कार्यबल की अध्यक्षता की।
- 13 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अनुसंधान केंद्र (सीआरआईटी), विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 'द्वितीय आरसीईपी राउंडटेबल ट्रैक 1.5' में एक वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 11 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में 'न्यूज X ' पर इनका साक्षात्कार 'आरसीईपी ' पर किया गया।
- 9 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में 'प्रमुख बाजारों में नियामक चुनौतियों से निपटने के लिए फार्मा उद्योग की क्षमता का विकास ' के मुद्दे पर वाणिज्य विभाग के सचिव के साथ एक परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 9 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में डब्ल्यूटीओ के समक्ष विचाराधीन मुद्दों पर वाणिज्य विभाग द्वारा बुलाई गई एक परामर्श बैठक में भाग लिया।
- 5 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा आयोजित 6–7 वरिष्ठ चिंतकों की एक छोटी गोलमेज बैठक में भाग लिया।
- 28 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई की अंतर्राष्ट्रीय परिषद 2019–20 की दूसरी बैठक में भाग लिया।
- 23 अगस्त 2019 को बेंगलुरु में कोका–कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित भारतीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 14 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में एचएलएजी की प्रमुख सिफारिशों का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए माननीय

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ एक बैठक में भाग लिया।

- 14 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा एफटीए अध्ययन पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 13 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 'अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने ' पर आयोजित पारस्परिक संवादात्मक सत्र में भाग लिया।
- 12 अगस्त 2019 को पुणे में किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 10 अगस्त 2019 को मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति (बेंच III) की बैठक में भाग लिया।
- 8 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित 'निर्यात पर सीआईआई की राष्ट्रीय समिति ' की दूसरी बैठक को संबोधित किया।
- 7 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया द्वारा 'उभरते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भारत और अमेरिका के लिए चुनौतियां एवं अवसर ' विषय पर आयोजित परिचर्चा बैठक में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 15 जून 2019 को नई दिल्ली में आईसीआरआईईआर द्वारा 'भारत की एक्ट ईस्ट नीति को सुगम बनाना: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित लैंड कस्टम स्टेशनों पर बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में कमी के विश्लेषण' पर आयोजित कार्यशाला में एक वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 10 जून 2019 को नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा आयोजित 'चीन पर सीआईआई के कोर ग्रुप की बैठक' में भाग लिया।
- 6 जून 2019 को नई दिल्ली में विदेश व्यापार महानिदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा माननीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित व्यापार बोर्ड और व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद की संयुक्त बैठक में भाग लिया।
- आरबीआई के गवर्नर के आमंत्रण पर मुंबई में 31 मई 2019 को 'भारत की व्यापार नीति– भारतीय रिजर्व बैंक में उभरती चुनौतियों और अवसरों' पर एक व्याख्यान दिया।
- 16 मई 2019 को पुणे में आयोजित किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 9 मई 2019 को नई दिल्ली में आईसीआरआईईआर द्वारा 'विकासशील देशों के लिए वर्तमान व्यापार मुद्दों' पर आयोजित गोलमेज परिचर्चा में भाग लिया।
- 8 मई, 2019 को नई दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय में 'डब्ल्यूटीओ: संबंधित मुद्दों' विषय पर आयोजित एक संवादात्मक सत्र के दौरान व्याख्यान दिया।
- 7 मई 2019 को नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा 'भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियों: इनकार, स्वीकृति, प्रतिकूल प्रतिक्रिया' पर आयोजित परिचर्चा और पुस्तक विमोचन समारोह' में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 27 अप्रैल 2019 को ग्रेटर नोएडा में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित 'अकादमिक सलाहकार समिति' की बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 24 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) की बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 21 अप्रैल 2019 को मुंबई में कोका–कोला इंडिया द्वारा आयोजित भारत सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लिया।
- 18 अप्रैल 2019 को मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति की बैठक में भाग लिया।
- 16 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में आईसीआरआईईआर और ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा 'भारत के लिए विजन: 2030 पर संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।
- 5 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में 'विश्व व्यापार के भविष्य' पर आयोजित सीआईआई वार्षिक सत्र 2019 में एक वक्ता और पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

श्री अमर सिन्हा

प्रतिष्ठित फेलो

- 15 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में श्री रवि कपूर, सचिव (पूर्वोत्तर पर वस्त्र) , वस्त्र मंत्रालय के साथ आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 18 अक्टूबर 2019 को पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल में 'नेपाल में सिख विरासत और भारत–नेपाल संबंधों' पर आयोजित परिचर्चा में भाग लिया।
- 22 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) में 'रूसी रणनीतिक अध्ययन संस्थान (आरआईएसएस) के साथ मॉस्को में संवाद' पर एक प्रस्तुति दी।
- 23 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री नादर नादेरी के साथ परिचर्चा बैठकों में भाग लिया।
- 24 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में श्री हेनरी किसिंजर के साथ

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

आयोजित परिचर्चा बैठक में 'पड़ोस, विशेषकर अफगानिस्तान में भारत की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी।

- 24 अक्टूबर 2019 को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में श्री जेफ स्मिथ के साथ क्षेत्रीय स्थिति पर आयोजित गोलमेज बैठक में भाग लिया।
- 5 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में जनरल एस. एल. नरसिम्हन के साथ आयोजित 'चीन पर गोलमेज परिचर्चा' में भाग लिया।
- 9 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में श्री ताहिर कादिरी, प्रभारी राजदूत, अफगानिस्तान और श्री राघवेन्द्र सिंह, निदेशक, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के साथ 'अभिलेखागार एवं संग्रहालय और ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर भारत–अफगानिस्तान सहयोग' पर आयोजित परिचर्चा बैठकों में भाग लिया।
- 15 नवंबर, 2019 को विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में अफगान राजनयिकों के समक्ष 'आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने' पर एक प्रस्तुति दी।
- 26–27 नवंबर 2019 को इथियोपिया में श्री अल्बर्ट मुचुंगा, व्यापार एवं उद्योग आयुक्त और एसडीजी तथा जीडीसी पर यूएनसीईए के निदेशक के साथ परिचर्चा बैठकों में भाग लिया।
- 29 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति श्री हामिद करजई के साथ अफगानिस्तान की राजनीति/चुनाव पर आयोजित परिचर्चा बैठकों में भाग लिया।

प्रो. अमिताभ कुंडू

प्रतिष्ठित फेलो

- 2 अक्टूबर 2019 को नोएडा स्थित राष्ट्रीय श्रम संस्थान में आयोजित गांधी जयंती समारोह के दौरान 'ग्रामीण–शहरी प्रवासन और मेहनत के साथ जीवन यापन पर गांधी के विचार' विषय पर उद्घाटन भाषण दिया।
- 9 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली स्थित माता सुंदरी कॉलेज में 'पूर्वोत्तर भारत की विकास संभावना' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उद्घाटन भाषण दिया।
- 18 अक्टूबर 2019 को कोलंबो में सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में 'एशियाई देशों में शहरीकरण और प्रवासन' विषय पर एक पेपर प्रस्तुत किया।
- 24 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली स्थित बाहा इंटरनेशनल सेंटर में धर्म, विकास और शांति पर विशेष व्याख्यान दिया।
- 30 अक्टूबर 2019 को बैंकॉक में आयोजित 'असमानता पर ऑक्सफैम की क्षेत्रीय बैठक' में समापन भाषण दिया।
- 9 नवंबर 2019 को कोलकाता के सत्संग सेंटर में 'ठाकुर अनुकुलचंद्र की शिक्षाओं में धर्म, जीवन, शांति' पर विशेष व्याख्यान दिया।
- 15 नवंबर 2019 को कोलकाता में आयोजित क्षेत्रीय विज्ञान संघ सम्मेलन में विशेष व्याख्यान दिया।
- 16 नवंबर 2019 को आइला विश्वविद्यालय कोलकाता में आयोजित 'बंगाल में अल्पसंख्यक और समावेशी भारत का विजन' विषय पर उद्घाटन भाषण दिया।
- 2 नवंबर 2019 को रामा विश्वविद्यालय कानपुर में 'उद्यमिता और नवाचार' पर आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया।
- 26 नवंबर 2019 को इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 'मध्य प्रदेश के लिए विकास परिप्रेक्ष्य' पर विशेष व्याख्यान दिया।
- 1 दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद में एसडीपीआई द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में 'ऊर्जा दक्षता और निरंतरता' पर एक सत्र की अध्यक्षता की; दक्षिणीय सहयोग इस्लामाबाद पर एक प्रस्तुति भी दी; 2 दिसंबर 2019 को आयोजित एक अंतर–विश्वविद्यालय सम्मेलन में 'भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्तता' पर एक प्रस्तुति दी।
- 9 दिसंबर 2019 को शिकागो विश्वविद्यालय के दिल्ली केंद्र द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में 'किफायती आवास प्रणाली' पर एक प्रस्तुति दी।
- 18–19 दिसंबर 2019 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स द्वारा समर्थित एक परियोजना के तहत स्मार्ट शहरों के चयन के लिए एक ज्यूरी सदस्य के रूप में अपने विचार व्यक्त किए और प्रस्तुति दी।
- 21 नवंबर, 2019 को भूगोल विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय में 'भौगोलिक अध्ययन में कार्यप्रणाली' पर विशेष व्याख्यान दिया और 22 नवंबर 2019 को जम्मू–कश्मीर विज्ञान कांग्रेस में 'विज्ञान, अध्यात्म और सांख्यिकीय मिथक' पर भी विशेष व्याख्यान दिया।
- 28 दिसंबर 2019 को आकाशवाणी में 'आधार और राष्ट्रीय पहचान' पर सामयिकी पर अपने विचार व्यक्त किए।
- 20 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा 'एसडीजी का कार्यान्वयनः संभावनाएं और चुनौतियां' विषय पर आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया।
- 20 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा "एसडीजी के कार्यान्वयनः संभावनाएं और चुनौतियां" पर आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया।
- 25 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ रूरल इंडिया (सीएनआरआई) द्वारा 'वित्तीय समावेशन' पर आयोजित सम्मेलन के दौरान एक सत्र की अध्यक्षता की।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

- 25 अप्रैल, 2019 को सहभागितापूर्ण विकास पर शोध के लिए कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ रूरल इंडिया (सीएनआरआई) को लाइफ टाइम अवार्ड दिया।
- 1 मई 2019 को जम्मू विश्वविद्यालय में नीतिगत अनुसंधान एवं गवर्नेंस संस्थान द्वारा आयोजित उपभोक्ता संरक्षण कार्यशाला में 'क्षमता निर्माण और उपभोक्ता कल्याण' पर मुख्य भाषण दिया।
- नई दिल्ली में मानव विकास संस्थान द्वारा 'प्रवासन के रुझान और स्वरूप' पर आयोजित एक सेमिनार में एक आमंत्रित पेपर प्रस्तुत किया।
- 14 मई 2019 को नई दिल्ली में विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा आयोजित 'एआईआईबी– अवसंरचना वित्तपोषण की बदलती रूपरेखा' पर प्रस्तुति के बारे में टिप्पणी करने के लिए पैनलिस्ट थे।
- 17 मई 2019 को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा क्षमता निर्माण पर आयोजित कार्यशाला में उद्घाटन भाषण दिया।
- 7 जून 2019 को नई दिल्ली में ऑक्सफैम के सभी कर्मचारियों और सदस्यों के समक्ष 'राजनीति और असमानता के अर्थशास्त्र' पर एक विशेष व्याख्यान दिया।
- गुवाहाटी में 19–20 जून, 2019 के दौरान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षणिक विकास पर यूनेस्को–आरआईएस कार्यशाला का आयोजन किया।
- 25–26 जून 2019 को कोलंबो में आयोजित एक सम्मेलन में 'शहरीकरण और दक्षिण एशियाई शहरीकरण में विऔद्योगीकरण' पर एक पेपर प्रस्तुत किया।

ऑगस्टीन पीटर

विजिटिंग फेलो

- 4 अक्टूबर, 2019 को केरल के कुट्टिक्कणम में एक स्वायत्त कॉलेज 'मैरियन कॉलेज' की वार्षिक रजत जयंती व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन किया और 'भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर एक पेपर प्रस्तुत किया।
- 4 अक्टूबर, 2019 को सेंट थॉमस कॉलेज, पाला, केरल में श्री जॉर्ज थॉमस कोट्टुकप्पल्ली (पूर्व सांसद) स्मारक व्याख्यान दिया।
- 5–7 जुलाई 2019 को 'विश्लेषण में प्रगति' थीम पर रोड्स, ग्रीस में सीईएसएसई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में 'ब्रिक्स के डिजिटल बाजारों में प्रवर्तन के घटनाक्रम' पर आयोजित पैनल परिचर्चा में पैनलिस्ट थे।

प्रो. टी. सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- 1 अक्टूबर 2019 को सीएसआईआर–टीकेडीएल तकनीकी समीक्षा समिति में सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 17 अक्टूबर 2019 को आईसीएमआर आईपीआर नीतिगत समीक्षा समिति की बैठक में सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 23 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी कॉलेज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 'आईपीआर और नवाचार' विषय पर व्याख्यान दिया।
- 20 दिसंबर 2019 को इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नई दिल्ली और सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, पुणे द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 'प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों' विषय पर व्याख्यान दिया।
- 10 जुलाई, 2018 को विपो–इंडिया समर स्कूल में एमएनएलयू, नागपुर और बौद्धिक संपदा प्रबंधन के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) द्वारा 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं पेटेंट और रसगुल्ला का अनोखा मामला ' पर आयोजित सत्रों में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 18 अगस्त, 2018 को पूरक और एकीकृत स्वास्थ्य केंद्र, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, पुणे द्वारा 'आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अनुकूल माहौल बनाने ' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया और 'गवर्नेंस एवं वित्त पोषण ' के साथ–साथ 'सामाजिक विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य ' पर भी प्रस्तुतियां दीं।
- 2 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा आसियान के सदस्य देशों के लिए 'बौद्धिक संपदा अधिकारों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' पर आयोजित कार्यशाला में 'अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत आईपीआर में सीमा संबंधी उपायों' पर एक व्याख्यान दिया।
- 3–4 मई 2019 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, गुवाहाटी, असम में 'पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का प्रभावी संरक्षणः राष्ट्रीय एवं सामुदायिक अनुभव' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य भाषण दिया।
- 20 जून 2019 को नई दिल्ली स्थित इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आयोजित कार्यशाला में 'कॉपीराइट, ट्रेड मार्क और औद्योगिक डिजाइन' पर एक प्रस्तुति दी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

डॉ. पी.के. आनंद

विजिटिंग फेलो

- 3 अक्टूबर 2019 को गुड़गांव स्थित हीपा (हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान) में 'सुशासन और एसडीजी' पर एक प्रस्तुति दी।
- 26 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में 'संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, 2019' को पेश किए जाने पर एक प्रस्तुति दी।
- 28 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में 'मानव एवं आर्थिक सुरक्षाः आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए एसडीजी का उपयोग करने' पर आयोजित सत्र में 'वैश्वीकृत दुनिया में गैर–पारंपरिक आर्थिक और सुरक्षा जोखिमों' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में प्रस्तुति दी।
- 2 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली स्थित नीति आयोग में एनआईएलईआरडी की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया।
- 4 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में 'एसडीजी के लिए एसटीआई पर राष्ट्रीय प्राथमिकताएंः चुनौतियां और अवसर' पर आयोजित सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 20 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा आयोजित 'राज्यों की वित्तीय स्थिति से जुड़े मुद्दे – राज्य बजट 2019–20 के विश्लेषण पर सम्मेलन' में भाग लिया।
- 'पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एसडीजी कॉन्क्लेव रिपोर्ट और एसडीजी कॉन्क्लेव के लिए एजेंडा ' पर विचार–विमर्श करने के लिए 18 सितंबर 2019 को नीति आयोग में आयोजित बैठक में भाग लिया।
- एक ज्ञान साझेदार के रूप में आरआईएस के संदर्भ में 22 जुलाई, 2019 को पृथ्वी भवन, नई दिल्ली में वैज्ञानिक सचिव की अध्यक्षता में 'भारत के लिए एसडीजी रोडमैप हेतु एसटीआई पर यूएनईएस ग्लोबल पायलट प्रोग्राम के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति ' की बैठक में भाग लिया।
- 16 अगस्त 2019 को नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में माननीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से आईटीईसी प्रतिभागियों के साथ मिलकर विचार–विमर्श किया।
- 6 सितंबर 2019 को यूनेस्को, नई दिल्ली में संसाधनों की दक्षता पर फोकस करते हुए 'व्यवसाय में सर्कुलर अर्थव्यवस्थाः एसडीजी–12 उत्तरदायी खपत और उत्पादन की ओर कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा ' पर आईयूसीएन इंडिया लीडर्स फॉर नेचर के साथ मिलकर यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया।
- कोलंबो में श्रीलंका के नीतिगत अध्ययन संस्थान की मेजबानी में 26–27 सितंबर 2019 के दौरान 'चौथी औद्योगिक क्रांति (4आईआर) में दक्षिण एशिया के भविष्य को समुचित स्वरूप प्रदान करने' की थीम के साथ '12वें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस) XII ' में भाग लिया और एक सत्र की अध्यक्षता की।
- हैदराबाद में 24–26 अप्रैल 2019 के दौरान भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई)–जर्मन विकास संस्थान/मैनेजिंग ग्लोबल गवर्नेंस (एमजीजी) द्वारा '2030 एजेंडे के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और संवाद' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। सिविल सेवाओं की भूमिका पर फोकस करने करते हुए सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के कार्यान्वयन से जुड़े भारतीय अनुभवों पर चर्चा की और साझा किया।
- 18 जून 2019 को यांगून में म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (एमआईएसआईएस) और फ्रेडरिक–एबर्ट–स्टिफ्टंग (एफईएस) द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और 'बिम्सटेक देशों में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन' पर एक प्रस्तुति दी। आपदाओं के जोखिमों को कम करने के लिए ठोस सुझाव दिए गए।

श्री कृण कुमार

विजिटिंग फेलो

- 26 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में 'संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, 2019' पेश किए जाने के अवसर पर एक प्रस्तुति दी।
- 28 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में 'मानव एवं आर्थिक सुरक्षाः आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए एसडीजी का उपयोग करने' पर आयोजित सत्र में 'वैश्वीकृत दुनिया में गैर–पारंपरिक आर्थिक और सुरक्षा जोखिमों' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में एक प्रस्तुति दी।
- 4 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में 'एसडीजी के लिए एसटीआई पर राष्ट्रीय प्राथमिकताएंः चुनौतियां और अवसर' पर आयोजित सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 20 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा आयोजित 'राज्यों की वित्तीय स्थिति से जुड़े मुद्दे – राज्य बजट 2019–20 के विश्लेषण पर सम्मेलन' में भाग लिया।
- 23 और 24 सितंबर, 2019 को बैंकॉक में आसियान एवं पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए) और थाईलैंड की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद (एनआरसीटी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और 'सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को साकार करने के लिए दक्षता आधारित क्षेत्रीय दृष्टिकोण ' पर एक प्रस्तुति दी।
- 'पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एसडीजी दस्तावेज और एसडीजी कॉन्क्लेव के लिए एजेंडा ' पर विचार–विमर्श करने के लिए

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

18 सितंबर 2019 को नीति आयोग में आयोजित बैठक में भाग लिया।

- 22 जुलाई, 2019 को वैज्ञानिक सचिव की अध्यक्षता में 'भारत के लिए एसडीजी रोडमैप हेतु एसटीआई पर यूएनईएस ग्लोबल पायलट प्रोग्राम के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति ' की बैठक में भाग लिया।
- हैदराबाद में 24–26 अप्रैल 2019 के दौरान भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई)–जर्मन विकास संस्थान/मैनेजिंग ग्लोबल गवर्नेंस (एमजीजी) द्वारा '2030 एजेंडे के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और संवाद' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। सिविल सेवाओं की भूमिका पर फोकस करने करते हुए सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के कार्यान्वयन से जुड़े भारतीय अनुभवों पर चर्चा की और साझा किया।
- 18 जून 2019 को यांगून में म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (एमआईएसआईएस) और फ्रेडरिक–एबर्ट–स्टिफ्टंग (एफईएस) द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया

डॉ. के. रवि श्रीनिवास

विजिटिंग फेलो

- 14 अक्टूबर 2019 को वाराणसी स्थित आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में एशिया में चावल अनुसंधान पर भागीदारी के लिए परिषद (सीओआरआरए) की 23वीं वार्षिक बैठक में 'खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता के लिए दक्षिणीय सहयोग का उपयोग करने और एशिया व अफ्रीका में बेहतर लघु खेत मूल्य–श्रृंखला' पर एक प्रस्तुति दी।
- 31 अक्टूबर 2019 को यांगून, म्यांमार में आईएफपीआरआई, आरईएसएकेएसएस – एशिया और एमआईआईडी द्वारा 'एशिया में उभरती कृषि खाद्य प्रणालियों' पर आयोजित सम्मेलन में ''भारत में जैव प्रौद्योगिकी के परिदृश्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 6 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और टीकेडीएल–सीएसआईआर द्वारा 'पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टीकेडीएल): जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान पर पहले से ही ज्ञात साक्ष्य के एक साधन के रूप में विकास, प्रबंधन और इसका उपयोग' विषय पर आयोजित आसियान–भारत क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में 'स्वदेशी ज्ञान प्रणालियां, बौद्धिक संपदा व्यवस्था, और पहुंच एवं लाभ साझा करने' पर व्याख्यान दिया।
- 10 दिसंबर 2019 को आईआईटी–मद्रास, चेन्नई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'रिपब्लिक ऑफ प्लांट्स' में 'फसलों और प्राकृतिक संसाधन में होड़: आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, पौध आनुवांशिक प्राकृतिक संसाधन और मुक्त स्रोत बीज (ओपन सोर्स सीड्स)' विषय पर मुख्य भाषण दिया।
- 3 मई 2019 को ब्रिस्बेन में सीएसआईआरओ द्वारा 'व्यापक बदलाव लाने वाली प्रौद्योगिकी के प्रभावों का आकलन करना' विषय पर आयोजित कार्यशाला में 'सिंथेटिक जीव विज्ञान के गवर्नेंस में 'आरआरआई की क्या भूमिका' है?' विषय पर भाषण दिया।

डॉ. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- 5 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में ओईसीडी, पेरिस द्वारा आयोजित '2019 ओईसीडी – भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और संबंधित कार्यक्रमों' के शुभारंभ में भाग लिया; सतत विकास लक्ष्यों को लागू करना: नए तौर–तरीके और अभिनव वित्तपोषण" पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 8–9 दिसंबर, 2019 को ढाका, बांग्लादेश में यूएनएस्कैप और बांग्लादेश सरकार द्वारा आयोजित 'एसडीजी पर तीसरे दक्षिण एशिया फोरम' में भाग लिया; 'दक्षिण एशिया में एसडीजी की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए कार्यान्वयन के साधनों का उपयोग करना: वित्त, प्रौद्योगिकी, क्षमता–निर्माण और व्यापार (एसडीजी 17) ' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 10 दिसंबर 2019 को ढाका, बांग्लादेश में यूएनएस्कैप और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय एवं रणनीतिक अध्ययन संस्थान (बीआईआईएसएस) द्वारा आयोजित 'दक्षिण एशिया में सतत विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर नीतिगत संवाद' में भाग लिया; 'नए वैश्विक संदर्भ में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की संभावना और चुनौतियां' विषय पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 26–27 सितंबर 2019 को कोलंबो, श्रीलंका में 'चौथी औद्योगिक क्रांति में दक्षिण एशिया के भविष्य को समुचित स्वरूप देने ' पर आयोजित 12वें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन में '4 आईआर के दौरान दक्षिण एशिया में नवाचार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा ' पर समानांतर सत्र डी 1 में पैनलिस्ट के रूप में योगदान दिया।
- 20 सितंबर 2019 को अंबेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में 'नवाचार प्रणालियां और विकासशील देश' विषय पर व्याख्यान दिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

डॉ. प्रियदर्शी दाश

सहायक प्रोफेसर

- 16–17 अक्टूबर 2019 को कुआलालम्पुर में जापान इकोनॉमिक फाउंडेशन (जेईएफ), टोक्यो और रणनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (आईएसआईएस), कुआलालम्पुर द्वारा आयोजित एशिया–प्रशांत फोरम 2019 में 'आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए नई चुनौतियां' विषय पर आयोजित सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लेते हुए 'एशिया–प्रशांत में विकास के उत्प्रेरकः डिजिटल अर्थव्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना ' पर प्रस्तुति दी।
- 11 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में वाणी, एफआईडीसी और हेनरिक बॉल स्टिफ्टंग द्वारा 'गुणवत्ता और सतत अवसंरचना निवेश सुनिश्चित करने में भारतीय सिविल सोसायटी की भूमिका' विषय पर आयोजित गोलमेज बैठक में 'गुणवत्ता और सतत अवसंरचना निवेशः नवाचार एवं संस्थान' विषय पर प्रस्तुति दी।

डॉ. दुरइराज कुमारसामी

सलाहकार, आरआईएस स्थित आसियान-भारत केंद्र

- 14 अगस्त 2019 को चीन के बीजिंग में इंटरनेशनल एक्सचेंज सेंटर फॉर इनोवेटिव टैलेंट्स (आईईसीआईटी), बीजिंग म्यूनिसिपल यूनेस्को क्लब एसोसिएशन में 'भारत में सेवा क्षेत्र में व्यापार और निवेश के अवसरों ' पर एक प्रपत्र (पेपर) प्रस्तुत करने के लिए एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।
- एशिया–प्रशांत व्यापार और निवेश के लिए चर्चाकर्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।
- 23 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा 'भारत–वियतनाम समुद्री सहयोग' पर आयोजित आरंभिक कार्यशाला में 'भारत–वियतनाम समुद्री कनेक्टिविटीः व्यापार और निवेश के अवसर' पर एक प्रस्तुति दी।
- 25 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के दूतावास और द पॉलिसी टाइम्स द्वारा 'वियतनाम में निवेश के अवसर' पर वियतनाम के राजदूत के साथ आयोजित संवाद के दौरान 'वियतनाम में भारतीय निवेशः गुंजाइश और अवसर' पर एक प्रस्तुति दी।

अध्याय 5

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

'दक्षिणीय सहयोग से अवगत होने' पर आईटीईसी कार्यक्रम

आरआईएस ने 11–22 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में 'दक्षिणीय सहयोग से अवगत होने' पर भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 25 से भी अधिक देशों के मध्यम स्तर के सरकारी अधिकारियों/राजनयिकों, प्रोफेशनलों और विद्वानों सहित 30 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों में दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) के बारे में एकीकृत और बहुआयामी समझ विकसित करना था, ताकि वे इसकी विविधता और बहुलता से अवगत हो सकें। यह कार्यक्रम सैद्धांतिक रूपरेखा एवं वैश्विक संरचना पर केंद्रित था और इस दौरान समावेशी विकास सुनिश्चित करने के मार्ग में मौजूद अविलम्ब चुनौतियों पर विचार–विमर्श किया गया।

इस पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में किए गए प्रयासों और चुनौतियों के साथ–साथ एसएससी के लिए आकलन की एक रूपरेखा को भी कवर किया गया। आरआईएस ने प्रतिभागियों के हित में इन मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आतंरिक संकाय के अलावा प्रख्यात विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया। प्रतिभागियों ने 'दक्षिणीय सहयोग में वैश्विक मुद्दे और स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम' के शीर्षक वाली जो रिपोर्ट तैयार की थी उसे भी इस अवसर पर प्रस्तुत किया गया।

आरआईएस संकाय के साथ प्रतिभागी।

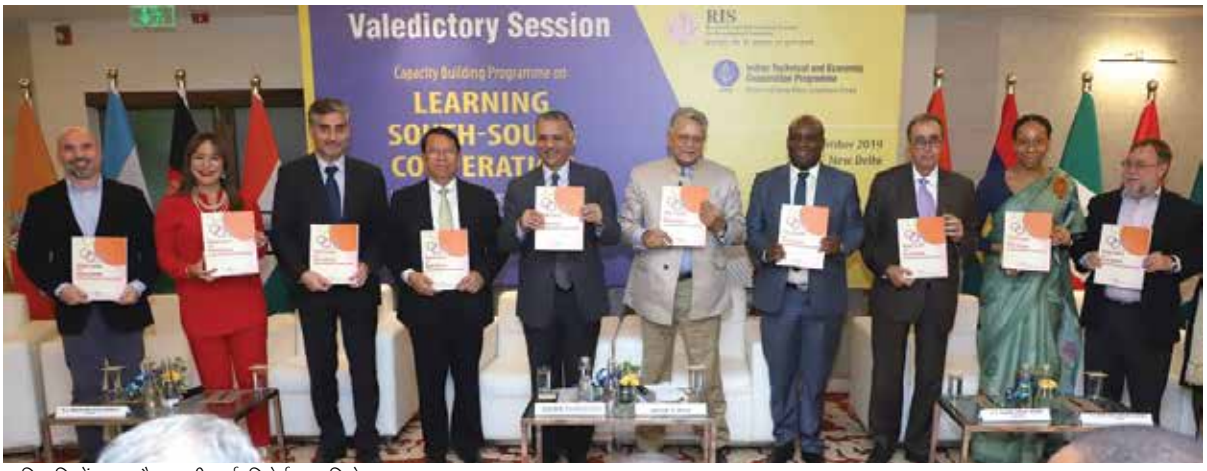

प्रतिभागियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का विमोचन।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने और जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके कार्यान्वयन की रणनीतियों को जानने के लिए आरआईएस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के 'भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम' के तहत एसडीजी पर दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा संस्करण 5–16 अगस्त 2019 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया।

इस कार्यक्रम में 24 देशों के 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस समूह को शिक्षाविदों के साथ–साथ नीति निर्माण क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ संवाद और चर्चाएं करने का अवसर मिला।

ये प्रतिभागी इसके अलावा राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एसडीजी की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाने वाले 'विश्लेषणात्मक स्थिति–प्रपत्रों' को तैयार करने के लिए समूह–परिचर्चाओं में भी जुटे रहे। ये प्रपत्र (पेपर) 'विकासशील देशों के एसडीजी परिप्रेक्ष्य का स्थानीयकरण ' शीर्षक वाली रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए थे।

विषयगत सत्रों को आयोजित करने के अलावा प्रतिभागियों के लिए अध्ययन दौरों का भी आयोजन किया गया, ताकि वे भारत की संसद और अन्य संबंधित मंत्रालयों का दौरा कर सकें। इन प्रतिभागियों को नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी (जो इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव श्री प्रवीण श्रीवास्तव के साथ पारस्परिक संवादात्मक सत्र में भाग लेने का अवसर भी मिला। उन्होंने दिल्ली और आगरा में ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध स्थलों का भी दौरा किया।

कार्यक्रम का विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आरआईएस संकाय के साथ 'एसडीजी' पर आरआईएस–आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरआईएस संकाय के साथ 'व्यापार और निरंतरता' पर आरआईएस–आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी।

व्यापार और निरंतरता

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और विद्वानों के बीच क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आरआईएस ने जुलाई 2018 में विशेष रूप से तैयार किया गया 'व्यापार और निरंतरता पर आईटीईसी कार्यक्रम' लॉन्च किया।

पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण 8 से 19 जुलाई 2019 तक आयोजित किया गया था जिसमें दक्षिण एशिया, उप–सहारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य–पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तथा कैरेबियन का प्रतिनिधित्व करने वाले 16 देशों के 29 अभ्यर्थियों ने सहभागिता की थी।

कार्यक्रम में ये चार व्यापक आधार या स्तंभ थेः जैविक विविधता संधि, नागोया प्रोटोकॉल सहित जैव विविधता और जैव–सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, इत्यादि ; पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार, गैर–टैरिफ उपाय, इत्यादि; हरित वित्त, जलवायु वित्त सहित वित्तपोषण, नियम–कायदे, कारोबार में नवाचार, इत्यादि; और एफटीए एवं आरटीए में पर्यावरणीय प्रावधान। प्रतिभागियों को अनेक व्याख्यानों में भाग लेने के साथ–साथ इन विषयों पर समूह संबंधी नियत कार्यों (ग्रुप असाइनमेंट) में संलग्न होने का अवसर मिलाः– विकासशील देशों में जैविक संसाधनों का सतत दोहनः अधिक से अधिक समृद्धि के लिए आनुवांशिक संसाधन; पर्यावरणीय वस्तुएं एवं सेवाएंः विकासशील देशों के लिए चुनौतियां और अवसर; विकासशील देशों में हरित वित्तपोषणः मंगोलिया, केन्या एवं नाइजीरिया के अनुभव; और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में पर्यावरणीय प्रावधान। इन्हें 'व्यापार और निरंतरता पर उभरते मुद्दे' शीर्षक वाली रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था।

'विज्ञान राजनय' पर आरआईएस–आईटेक कार्यक्रम

विज्ञान राजनय' पर आईटेक–आरआईएस क्षमता निर्माण कार्यक्रम 6–17 जनवरी 2020 के दौरान आयोजित किया गया। 25 देशों के 32 प्रतिभागियों ने इस पाठ्यक्रम में सक्रिय भाग लिया।

विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों को विज्ञान राजनय के सिद्धान्त एवं व्यवहार से अवगत कराया गया। यह भी सिखाया गया कि कैसे विकासशील देश विज्ञान राजनय से लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गयाः विज्ञान राजनय का परिचयः अवधारणाएं एवं रूपरेखा; विज्ञान राजनय में अनुभव साझा करना; उभरते प्रोद्योगिकी विज्ञान जैसे जीन सम्पादन और एआई; साइबर सुरक्षा; आईसीटी एवं कानून एन्फोर्समेंट; डिजिटल अर्थव्यवस्था; प्रोद्योगिकी स्थान्तरण एवं व्यापार; एवं एसडीजी एवं दक्षिण दक्षिण सहयोग।

लैक्चर और ग्रुप डिसकशन के साथ साथ प्रतिभागी इन्टरनैशनल सोलर एलायंस व आईसीजीईबी भी गये।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

विज्ञान राजनय पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरआईएस संकाय के साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति (आईईआईडीपी) पर आईटीईसी के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति पर आरआईएस–आईटेक कार्यक्रम

2001 से लेकर अबतक आईटेक और विदेष मंत्रालय के तत्वाधान में आरआईएस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति (आईईआईडीपी)' पर आईटेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

यह कार्यक्रम 10 फरवरी से 9 मार्च 2020 के दौरान आयोजित किया गया। 23 देषों के मध्यम स्तर के सरकारी अधिकारियों/राजनयिकों, नीति से जुड़े प्रोफेषनलों और विद्व ानों सहित 28 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के अन्त में एक रिपोर्ट भी निकाली गई।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और प्रथाओं पर चौथा आरआईएस–एक्जिम बैंक समर स्कूल

आरआईएस ने भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के सहयोग से 10–19 जून, 2019 को नई दिल्ली में ग्रीष्मकालीन स्कूल कार्यक्रम का चौथा संस्करण आयोजित किया। इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता कर रहे विद्यार्थियों के लिए किया जाता है।

विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यक्रम के दौरान इन मापांक (मॉड्यूल) पर विस्तृत चर्चा हुई: व्यापार सिद्धांत में हाल के घटनाक्रम; व्यापार विश्लेषण के साधन एवं प्रौद्योगिकियां; एफटीए और क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों को समझना; प्रौद्योगिकी में व्यापार के मुद्दे एवं वर्गीकरण मुद्दे; व्यापार एवं विकास: आईपीआर एवं नए मुद्दे; और समूह प्रस्तुतियां।

प्रो. दीपक नैय्यर, प्रोफेसर एमेरिटस, जेएनयू चौथे आरआईएस–एक्जिम बैंक समर स्कूल में विशेष व्याख्यान देते हुए।

कुल 49 अभ्यर्थी थे, जिसमें से 2 बिम्सटेक सचिवालय से थे और तीन बिम्सटेक देशों से थे (बांगलादेश, नेपाल एवं थाईलैंड)।

कार्यक्रम का आरम्भ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक और प्रो. एस.के. मोहंती, आरआईएस के स्वागत भाषण के साथ हुआ। श्री देबाशीष मल्लिक, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात–आयात बैंक; श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। प्रो. दीपक नय्यर, प्रोफेसर इमेरिटस, जेएनयू ने विशेष व्याख्यान दिया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में आरआईएस–जीडीसी–पीएचएफआई–जीडीसी फेलोशिप कार्यक्रम

यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन क्षेत्र में भारत के व्यापक उपक्रमों, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, और आयुष मंत्रालय द्वारा परम्परागत औषधि पद्धति का सांस्थानीकरण जैसे भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल हैं, उनके प्रदर्शन से संबद्ध है। यह कार्यक्रम डिजिटल प्रौद्योगिकियों के कारक पर भी केंद्रित है, जिसको भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का बेहतर तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एशिया और अफ्रीका के छह देशों, खास तौर पर भूटान, म्यांमार, केन्या, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के प्रतिभागियों को शामिल किया जा रहा है। ये प्रतिभागी अपने–अपने देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रक्रिया में केंद्र अथवा राज्य प्रशासन स्तर पर संबद्ध हैं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर आरआईएस–जीडीसी–सेवा फेलोशिप कार्यक्रम अहमदाबाद और दिल्ली में चलाया जा रहा है

'महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फेलोशिप कार्यक्रम' लोक स्वास्थ्य सेवा ट्रस्ट (एलएसएसटी) के साथ साझेदारी में 24 फरवरी से 7 मार्च, 2020 तक अहमदाबाद और दिल्ली में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एशिया और अफ्रीका के चार देशों यथा भूटान, रवांडा, तंजानिया, एवं इथियोपिया से आए प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया जा रहा है जो भारत में बड़ी संख्या में स्वयं–सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन

से संभव हुआ है और जिसकी बदौलत भारतीय समाज में महिलाओं की भागीदारी एवं जुड़ाव काफी बढ़ गया है। इस आयोजन के दौरान भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)' के बारे में भी बताया जा रहा है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सामुदायिक नेता बनने के रूप में सशक्त किया है और इसके साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प एवं कारीगरों को आवश्यक सहारा प्रदान किया है। इन बदलावों के लिए इस्तेमाल में लाई गई प्रणालियों जैसे कि डिजिटल तकनीकों, जो तैनात की गई थीं, और संगठनात्मक संरचनाओं, जो सृजित की गई थीं, के बारे में भी विस्तार से बताया गया, ताकि इस मॉडल की समग्र समझ विकसित हो सके।

आरआईएस में इंटर्नशिप

आरआईएस भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों और संबंधित संकायों में अध्ययन करने वाले छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान करता रहा है। विगत वर्षों में इंटर्नशिप कार्यक्रम की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके फलस्वरूप इस कार्यक्रम के विषय–वस्तु, पर्यवेक्षण और शिक्षण–उपादानों में संरचनागत मौलिक बदलाव किये गये हैं। आरआईएस वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए अपने संकाय तथा साथियों से बातचीत करके परस्पर संवादों के नवाचार तरीकों के साथ ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम लाया है। इसके साथ ही, आरआईएस के विभिन्न वेबिनारों और वेब–आधारित संवादों में इंटर्नस की भागीदारी को आसान बनाया गया है।

अध्याय 6

प्रकाशन कार्यक्रम

रिपोर्ट/पुस्तक

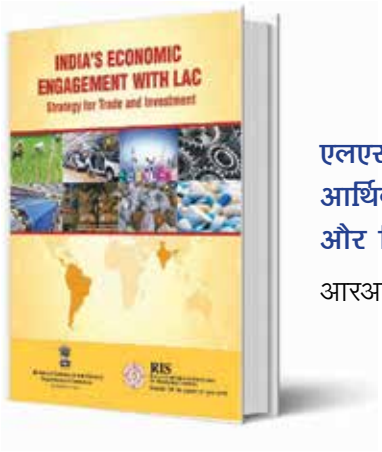

एलएसी के साथ भारत की आर्थिक साझेदारीः व्यापार और निवेश के लिए रणनीति

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और व्यवहारः समकालीन मुद्दे

आरआईएस–एक्जिम बैंक, नई दिल्ली, 2019

गैर–शुल्क उपाय (एनटीएम): आसियान–भारत व्यापार के साक्ष्य

एआईसी और आरआईएस, 2019

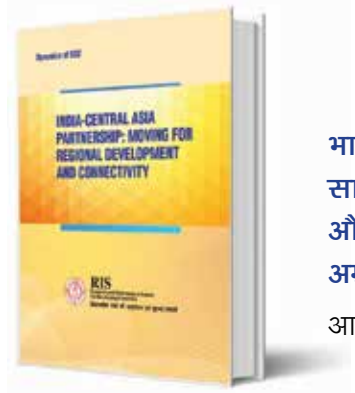

भारत–मध्य एशिया साझेदारीः क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी के लिए अग्रसर

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

डब्ल्यूटीओ चर्चा और भारत में ई–कॉमर्स के मुद्दे

आरआईएस, नई दिल्ली, 2020

प्रमुख विचारः दिल्ली प्रक्रिया दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग पर पांचवा सम्मेलन

आरआईएस, नई दिल्ली, 2020

प्रकाशन कार्यक्रम

भारत–आसियान समुद्री सहयोग को मजबूत करना, 2019

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

वैश्विक शासन और आर्थिक सहयोग: विकासशील देशों के लिए अवसर और चुनौतियां

आरआईएस, नई दिल्ली, 2020

दक्षिणीय विचार – दक्षिणीय सहयोग के प्रभाव का आकलन – परिप्रेक्ष्य में भिन्नता (2019)

आरआईएस, यूएनओएसएससी, 2020

इब्सा विकास सहयोग की गतिशीलता

आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

सुवर्णभूमि में नौकायनः सांस्कृतिक मार्ग और समुद्री परिदृश्य

हिमांशु प्रभा रे और सुसान मिश्रा, एआईसी और आरआईएस, 2019

प्रकाशन कार्यक्रम

आरआईएस के परिचर्चा प्रपत्र

#246: The 2008 Financial Crisis and Shifts in Economic Power by Manmohan Agarwal & Amrita Brahmo

#245: Economic Multilateralism in Peril by Manmohan Agarwal

#244: Surmount Challenges, Cash in New Trade Opportunities by Dammu Ravi

#243 सामाजिक उद्यमों और सामाजिक इन्क्यूबेटरों के लिए सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज: भारत के लिए एक खोजपूर्ण अध्ययन द्वारा *सचिन चतुर्वेदी, सब्यसाची साहा और अरुण एस. नायर*

#242 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आय में सामंजस्य के अनुभव: एक अनुभवजन्य विवेचन द्वारा *सुनेत्र घटक और प्रबीर डे*

#241 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की संभावनाएं
द्वारा *मनमोहन अग्रवाल और अद्रिता बनर्जी*

#240 टिकाऊ कृषि और पोषण सुरक्षा: उत्पादन के विकल्पों के साथ उभरते नीतिगत विकल्प द्वारा *पी. के. आनंद, कृष्ण कुमार और श्रुति खन्ना*

#239 महंगाई और विकास पर मौद्रिक नीति का असर
द्वारा *मनमोहन अग्रवाल और इरफान अहमद शाह*

जी20 डाईजस्ट

खंड 2 संख्या 5

खंड 1 संख्या 2 जुलाई–अगस्त 2019

खंड 1 संख्या 1 मई–जून 2019

आरआईएस डायरी

कोविड–19 पर विशेष संस्करण

खंड 15, संख्या 4, अक्टूबर 2019

खंड 15 संख्या 3, जुलाई 2019

खंड 15 , संख्या 2, अप्रैल 2019

विकास सहयोग समीक्षा

खंड 2 संख्या 9 दिसंबर 2019

खंड 2 संख्या 5 अगस्त 2019

खंड 2 संख्या 4 जुलाई 2019

खंड 2 संख्या 2 एवं 3 मई–जून 2019

खंड 2 संख्या 1, अप्रैल 2019

प्रकाशन कार्यक्रम

एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास समीक्षा

खंड 21 संख्या 3 और खंड 22, संख्या 1, नवम्बर 2019–मार्च 2020

खंड 21 संख्या 1 और 2 मार्च और जुलाई 2019

साउथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल

खंड 20, संख्या 2, अक्तूबर 2019

खंड 20, संख्या 1, मार्च 2019

स्मरणीय अंक (2000–2020) आरआईएस एवं आईपीएस

यूनिकोड यहां जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन

खंड 1, संख्या 2, नवंबर 2019

खंड 1, संख्या 1, अप्रैल 2019

आरआईएस का नीतिगत सार–पत्र

#88 **चीन में वस्त्र क्षेत्र का रोबोटाइजेशन : प्रभाव और अनिवार्यताएं** द्वारा अमित कुमार

एफआईटीएम नीतिगत सार–पत्र

#4 **वेलनेस पर्यटन के लिए विशेष वेलनेस जोनः समर्पित आईएसएम हब बनाने की संभावनाएं तलाशना** द्वारा प्रो. टी. सी. जेम्स और अपूर्वा भटनागर

#3 **गरीबी कम करने के लिए औषधीय पौधे की खेतीः संभावनाएं और चुनौतियां** द्वारा प्रो. टी.सी. जेम्स और डॉ. नम्रता पाठक

एफआईटीएम अनूठा (स्कूपिंग) पेपर

#4 **भारत में औषधीय पादप आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण**

विज्ञान राजनय समीक्षा

खंड 2 संख्या 1, मार्च 2020

खंड 1 संख्या 4, नवंबर 2019

खंड 1 संख्या 3, जुलाई 2019

विज्ञान राजनय न्यूज़ अलर्ट

अंक 22: 16–30 सितंबर 2019

अंक 21: 01–15 सितंबर 2019

अंक 20: 16–31 अगस्त 2019

अंक 19: 01–15 अगस्त 2019

अंक 18: 16–31 जुलाई 2019

अंक 17: 01–15 जुलाई 2019

अंक 16: 16–30 जून 2019, अंक 15: 01–15 जून 2019

अंक 14: 16–31 मई 2019, अंक 13: 01–15 मई 2019

अंक 12: 16–30 अप्रैल 2019, अंक 11: 01–15 अप्रैल 2019

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

शोध पत्र

आनंद, पी. के. और कृष्ण कुमार। 2019. 'भारत के 2030 एजेंडे और भारत में एसडीजी के लिए उभरती वैचारिक रूपरेखा एवं निगरानी व्यवस्था: मात्रा से गुणवत्ता की ओर बढ़ना'। स्प्रिंगर।

चतुर्वेदी, सचिन। 2019. 'परिचय: सतत विकास लक्ष्य और भारत। प्रति: सचिन चतुर्वेदी, टी. सी. जेम्स, सब्यसाची साहा, प्रतिवा शॉ (संपादक) 2030 एजेंडा और भारत: मात्रा से गुणवत्ता की ओर बढ़ना', पृष्ठ 1–13, स्प्रिंगर, सिंगापुर।

चतुर्वेदी, सचिन; टी.सी. जेम्स; सब्यसाची साहा; प्रतिवा शॉ। 2019. 'एसडीजी के लिए भारत की कवायद: निरंतर प्रतिमान परिवर्तन और सामंजस्य। प्रति: सचिन चतुर्वेदी और अन्य (संपादक) 2030 एजेंडा और भारत: मात्रा से गुणवत्ता की ओर बढ़ना'। दक्षिण एशिया आर्थिक और नीतिगत अध्ययन। स्प्रिंगर, सिंगापुर।

चतुर्वेदी, सचिन; कृष्ण रवि श्रीनिवास; अमित कुमार। 2019. ' कार्टाजेना प्रोटोकॉल, सामाजिक–आर्थिक आकलन, और भारत में सामाजिक–आर्थिक आकलन (एसईए) अध्ययनों की विस्तृत समीक्षा। प्रति: चतुर्वेदी, सचिन और श्रीनिवास के. (संपादक) आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का आकलन। स्प्रिंगर, सिंगापुर।

चतुर्वेदी सचिन और सब्यसाची साहा। 2019: वैश्विक गवर्नेंस और संस्थान–निर्माण के लिए ब्रिक्स के आर्थिक सहयोग की भूमिका: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य, रणनीतिक विश्लेषण, डीओआई: 10.1080/09700161.2019.1694643

चतुर्वेदी, सचिन; कृष्ण रवि श्रीनिवास और अमित कुमार। 2019. 'कार्टाजेना प्रोटोकॉल, सामाजिक–आर्थिक आकलन, और भारत में सामाजिक–आर्थिक आकलन (एसईए) अध्ययनों की विस्तृत समीक्षा' प्रति: सचिन चतुर्वेदी और कृष्ण रवि श्रीनिवास (संपादक), आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का आकलन – भारत की केस–स्टडी के आधार पर वैश्विक निहितार्थ। स्प्रिंगर, सिंगापुर।

चतुर्वेदी, सचिन; एस. साहा; और ए.एस. नायर। 2019. सामाजिक उद्यमों और सामाजिक इन्क्यूबेटरों के लिए सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज: भारत के लिए एक खोजपूर्ण अध्ययन। आरआईएस परिचर्चा पत्र संख्या 243

चतुर्वेदी, सचिन. 2019. *वैश्विक प्रौद्योगिकी आकलन के निर्माण में 'भारत में प्रौद्योगिकी आकलन' : ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोप, जर्मनी, भारत और रूस से अंतर्दृष्टि* , जूलिया हैन और मिल्टोस लडिकस (सं), कार्ल्सरुहर इंस्टीट्यूट फर टेक्नोलोजी (केआईटी), कार्ल्सरुहे। (सह–लेखक)

चतुर्वेदी, सचिन. 2019. 'चैंपियन क्षेत्रों को पहचानें और बढ़ावा दें ' । द *वीक*, 31 अगस्त।

चतुर्वेदी, सचिन. 2019. '*दक्षिण एशिया में कृषि व्यापारः मुद्दे, चुनौतियां और आगे की राह* ' , नागेश कुमार और जोसेफ जॉर्ज (सं.) *दक्षिण एशिया में सतत खाद्य सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय सहयोग* , टेलर और फ्रांसिस।

चतुर्वेदी, सचिन. 2019. 'परिचयः उभरते दक्षिण एशिया के समक्ष मौजूद चुनौतियां – उद्योग एवं रोजगार ' और 'निष्कर्षः दक्षिण एशिया में विनिर्माण एवं रोजगार ' सचिन चतुर्वेदी और सब्यसाची साहा (सं.) *दक्षिण एशिया में विनिर्माण और नौकरियांः सतत आर्थिक विकास के लिए रणनीति,* सिंप्रगर।

चतुर्वेदी, सचिन और प्रियदर्शी दाश। 2019 जी20 और ग्लोबल गवर्नेंस, जापान स्पॉटलाइट, मई/जून अंक।

चतुर्वेदी, सचिन 2019. दक्षिण एशिया के लिए व्यापार और आर्थिक एकीकरणः एशिया में कॉरिडोर और गतिशीलता की खोज। दीपार्घ्य मुखर्जी (सं.) एशिया में आर्थिक एकीकरणः क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के साथ महत्वपूर्ण संभावनाएं और चुनौतियां। रूटलेज, लंदन।

चतुर्वेदी, सचिन और के. रवि श्रीनिवास। 2019 भारत में प्रौद्योगिकी का आकलन। जूलिया हैन और मिल्टॉस लडिकस (सं.) एक वैश्विक प्रौद्योगिकी आकलन का निर्माण करनाः ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोप, जर्मनी, भारत और रूस से परख। केआईटी वैज्ञानिक प्रकाशन, कार्लश्रूहे।

चतुर्वेदी, सचिन (सह–लेखक)। 2019 दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग पर पारंपरिक स्वतंत्र रिपोर्ट से परे सहयोग में 'आगे और परे' , दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, न्यूयॉर्क।

चतुर्वेदी, सचिन; रहमान मुस्तफिजुर; और श्रीनिवास, कृष्णा रवि। 2019 2030 एजेंडे को लागू करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का इस्तेमाल करना। जी 20–2019, टी 20 जापान नीतिगत सार

डैश, प्रियदर्शी (2019). 'ब्रिक्स में बॉन्ड बाजार की गतिशीलता' , जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, खंड 10, संख्या 2, जुलाई–दिसंबर, पृष्ठ 3–43

डे, प्रबीर। 2019. एक्ट ईस्ट से एक्ट इंडो–पेसिफिक की ओरः भारत का बढ़ता पड़ोस, नॉलेज वर्ल्ड, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर और चार्ल्स कुनाका। 2019. ' कनेक्टिविटी का आकलनः चुनौतियां और अवसर', प्रतिः एस कथुरिया और पी माथुर (संपादक) ताकत का इस्तेमालः पूर्वोत्तर भारत को मुख्यधारा में लाने के लिए नीतिगत रूपरेखा, विश्व बैंक, वाशिंगटन, डी.सी.।

डे, प्रबीर। 2019. ' दक्षिण एशिया के लिए बीआरआई को बेहतर बनाना', ट्रेड इनसाइट, खंड 15, संख्या 3

डे, पी. 2019 "दक्षिण एशिया के लिए कनेक्टिविटी 2.0 ", *ट्रेड इनसाइट*, खंड 15, संख्या 2, अगस्त, 2019

डे, पी. 2019. "पूर्वी दक्षिण एशिया में भूमिबद्ध यानी चारों ओर भूमि से घिरे देशों के लिए व्यापार सुविधा को प्राथमिकताएं", *25वां वर्ष विशेषांक* , नेपाल फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन (एनईएफएफए), काठमांडू, सितंबर 2019

डे, प्रबीर। 2019 'एक बेहतर बेल्ट और रोड का निर्माण करना', ईस्ट एशिया फोरम, 25 अप्रैल 2019

डे, प्रबीर। 2019 'एक्ट ईस्ट से एक्ट इंडो–पेसिफिक तकः नई सरकार के लिए एजेंडा' , इकोनॉमिक टाइम्स, 1 जून।

जेम्स, टी. सी. 2019. पारंपरिक ज्ञान को परिभाषित करना – पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यः राष्ट्रीय और सामुदायिक परिप्रेक्ष्य द्वारा टोपी बसर (सं.), एनएलयूएंडजेए, असम, गुवाहाटी।

प्रकाशन कार्यक्रम

मोहंती, एस.के. 2019 'एलएसी के साथ भारत की आर्थिक साझेदारीः व्यापार और निवेश के लिए रणनीति '। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।

कुमारसामी, दुरईराज और प्रबीर डे। 2019. 'हिंद–प्रशांत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देनाः संभावनाएं और अवसर', भारत त्रैमासिक (इंडिया क्वार्टरली), खंड 75, संख्या 4 पृष्ठ 1–20

कुंडू, अमिताभ। 2019. एकीकृत विकास और टिकाऊ शहरः एक वैकल्पिक विकास प्रतिमान की आवश्यकता। 2030 एजेंडा और भारतः मात्रा से गुणवत्ता की ओर बढ़ना (पृष्ठ 97–128). स्प्रिंगर, सिंगापुर।

कुंडू, अमिताभ। 2019. 'एशियाई देशों में शहरीकरण और औद्योगीकरणः समय से पहले विऔद्योगीकरण का खतरा'। 'एशिया में शहरीकरण का प्रबंधन' पर क्षेत्रीय कार्यशाला संबंधी पुस्तिका में, एसोसिएशन ऑफ एकेडमीज एंड सोसाइटीज ऑफ साइंस इन एशिया, श्रीलंका।

कुंडू, अमिताभ। 2019. ''विकास के लक्ष्य हासिल करने के लिए नॉलेज कॉरिडोर के निर्माण में दक्षिणीय सहयोग' । सुलेरी, ए. (संपादक), एसडीपीआई खंड

कुंडू, अमिताभ। 2019. 'महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा पर फोकस करने से आबादी घटेगी, कामकाज में भागीदारी बढ़ेगी' । इंडियन एक्सप्रेस, (प्रतिनिधि)

कुंडू, अमिताभ। 2019. प्रवासन (माइग्रेशन) में विरोधाभासः जनगणना के आंकड़ों में अवधि की गलतबयानी। ज्योग्राफी एंड यू (सह–लेखक पी. सी. मोहनन, वेबपेज) अक्टूबर।

कुंडू, अमिताभ। 2019 राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली पर साक्षात्कार। मिंट। 7 मई।

कुंडू, अमिताभ। 2019 'राष्ट्रीय सांख्यिकी को अवश्य ही मजबूत किया जाना चाहिए।' हिंदुस्तान टाइम्स 26 जून।

पांडेय, बीना। 2019. 'भारत में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें: एसडीजी 4 प्राप्त करने की पहली आवश्यकता '। '2030 एजेंडा और भारतः मात्रा से गुणवत्ता की ओर बढ़ना (पृष्ठ 165–196). स्प्रिंगर, सिंगापुर।

पीटर, ऑगस्टीन। 2019. 'ऑनलाइन कार्यक्षेत्र पाबंदियां और एकाधिकार का दुरुपयोगः उभरते भारतीय परिप्रेक्ष्य' , ' वैश्विक प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तनः नए निकाय और नई चुनौतियां ' में , पाउलो बुक्किरोसी और विलियम कोवासिक, क्लूवर। (संपादक) (सुश्री नेहा सिंह के साथ सह–लेखक)।

पीटर, ऑगस्टीन। 2019. 'भारत में डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा कानून का विकास', 'कंपीटिशन पॉलिसी इंटरनेशनल' में, अक्टूंबर, 2019 (सुश्री नेहा सिंह के साथ सह–लेखक)।

साहा, एस. और प्रतिवा शॉ। (2019) . भारत में नए सिरे से औद्योगीकरण और नवाचारः एसडीजी 9 के लिए रोडमैप। '2030 एजेंडा और भारतः मात्रा से गुणवत्ता की ओर बढ़ना ' में, (पृष्ठ 41–64). स्प्रिंगर, सिंगापुर।

श्रीनिवास, के. रवि और अमित कुमार। 2019. 'सामाजिक–आर्थिक आकलन में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव'। प्रतिः चतुर्वेदी, सचिन और श्रीनिवास के. (संपादक), आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का आकलन । स्प्रिंगर, सिंगापुर।

श्रीनिवास, के. रवि। 2019. 'आगे की राहः प्रौद्योगिकी में नए रुझान और सामाजिक–आर्थिक आकलन का संदर्भ'। प्रतिः चतुर्वेदी, सचिन और श्रीनिवास के. (संपादक) , आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का आकलन। स्प्रिंगर, सिंगापुर।

अध्याय 7

आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र

आरआईएस के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ने हाल के महीनों में नवीनतम विशिष्ट प्रकाशनों, रिपोर्टों, डेटाबेस, ई–जर्नल्स एवं लेखों इत्यादि को हासिल किया है, ताकि आरआईएस की संकाय और आगंतुक विद्वानों को अद्यतन जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकें। यह कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विभिन्न प्रकाशनों या आलेखों के कार्यक्रम का आदान–प्रदान करता है और विभिन्न स्तरों पर विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर और भी अधिक प्रकाशनों या आलेखों तथा अध्ययन कार्यक्रमों को जोड़कर संसाधन आधार को निरंतर समृद्ध करता रहता है।

इस केंद्र के प्रमुख वैश्विक संस्थानों जैसे कि एफएओ, आईएलओ, ओईसीडी, यूएन, अंकटाड, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इत्यादि के साथ घनिष्ठ जुड़ाव हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य–पत्र (वर्किंग पेपर), परिचर्चा पत्र (डिस्कशन पेपर), री–प्रिंट्स, समसामयिक पत्र दरअसल प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या तो परस्पर आदान–प्रदान किए गए कार्यक्रमों के जरिए प्राप्त होते हैं या संस्थागत वेबसाइटों के माध्यम से डाउनलोड किए जाते हैं। वर्तमान केंद्र में 25,340 से भी अधिक पुस्तकें हैं जिनमें सरकारी प्रकाशन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अन्य शोध संस्थानों के दस्तावेज शामिल हैं। इनके अलावा सजिल्द पुस्तक के रूप में 1850 पत्र–पत्रिकाएं हैं। इस केंद्र ने 580 से भी अधिक प्रिंट और ऑनलाइन पत्र–पत्रिकाओं की सदस्यता भी ले रखी है जिनमें जस्टर, आईएमएफ ई–लाइब्रेरी, एल्सवियर– साइंसडायरेक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, विली इत्यादि शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस केंद्र को प्रतिष्ठित स्रोतों से सम्मानार्थ भेंट के आधार पर लगभग 50 पत्र–पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। 350 से भी अधिक सीडी रॉम और डेटाबेस हैं। एक और खास बात यह है कि 'डेलनेट' का सदस्य होने के नाते यह संसाधन–साझाकरण को बढ़ावा देता है।

इस केंद्र में आसान पहुंच के लिए इंट्रानेट के माध्यम से ऑनलाइन समृद्ध संग्रह उपलब्ध है।

अभिलेखन केंद्र/पुस्तकालय के संग्रह में ये शामिल हैं

- पुस्तकें
- सांख्यिकीय वार्षिकी
- दस्तावेज–डब्ल्यूपी–ओपी–डीपी
- जर्नल / पत्र–पत्रिकाएं (प्रिंट+ऑनलाइन+सीडी–रॉम)
- भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के समाचार पत्र
- पिछला संस्करण (बैक वॉल्यूम)
- सीडी–रॉम
- सीडी–रॉम में डेटाबेस
- आरआईएस डेटाबैंक

व्यापार, टैरिफ एवं गैर–टैरिफ उपायों, भुगतान संतुलन, वित्तीय सांख्यिकी, विकास सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी, बौद्धिक संपदा सेवाओं और कॉरपोरेट डेटा एवं सूचना पर आरआईएस का वैश्विक डेटाबेस। भारतीय आंकड़े 8– अंकीय स्तर पर व्यापार संबंधी टाइम सीरीज डेटाबेस, भारतीय कंपनियों एवं उनके वित्तीय प्रदर्शन के डेटाबेस, सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस और सीमा शुल्क टैरिफ आंकड़ों को कवर करता है।

आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र

आरआईएस का डेटा सर्वर

आरआईएस एक आधुनिक डेटा सर्वर का रख–रखाव बिल्कुल सही ढंग से कर रहा है जिसमें उसके आंकड़ो कोष की बढ़ी हुई सुरक्षा के तहत आंकड़ों को नष्ट करने वाले वाइरल या हैकिंग सहित किसी भी संभावित बाहरी हमले से बचाव की पुख्ता व्यवस्था की गई है। आरआईएस ने त्वरित संदर्भ के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टाइम सीरीज आंकड़ा हासिल किया है। इसने टैरिफ आंकड़ा कोष, भारतीय कंपनियों के डेटाबेस, व्यापार आंकड़ों की दिशा (डॉट्स), विश्व विकास संकेतकों (डब्ल्यूडीआई), इत्यादि के साथ इस पर महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ा (एचएस एंड एसआईटीसी) अपलोड किए हैं। सर्वर पर आंकड़ा कोष को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। यह संकाय के सदस्यों को तत्काल अद्यतन डेटा उपलब्ध कराता है जो उनके साक्ष्य–आधारित शोध अध्ययनों में गहराई से मदद करता है। यही नहीं, ऐसे में व्यक्तिगत आरआईएस संकाय सदस्यों के लिए महंगी बहु–वैश्विक डेटा प्रणालियों को खरीदने की जरूरत नहीं रह जाती है।

आरआईएस की वेबसाइट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर

(www.ris.org.in)

आरआईएस की वेबसाइट को प्रतिदिन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली एवं यूजर (उपयोगकर्ता) अनुकूल सामग्री के साथ नवीनीकरण किया जाता है और यह नवीनतम सुविधाओं एवं कार्यों से सुसज्जित या लैस है। इसे आरआईएस की आंतरिक टीम द्वारा वास्तविक समय पर अपडेट किया जाता है, ताकि उसके आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में वैश्विक सार्वजनिक डोमेन में गहन अनुसंधान अध्ययनों और संबंधित घटनाक्रमों को उपलब्ध कराया जा सके। यह स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त, निवेश, विकास सहयोग, वैश्विक आर्थिक मुद्दों, क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिणीय सहयोग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित आरआईएस के कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों के बारे में व्यापक अद्यतन जानकारी प्रदान करती है। यह अनुसंधान रिपोर्टों, पत्र–पत्रिकाओं, सूचना–पत्र (न्यूजलेटर) और मीडिया लेखों के रूप में आरआईएस द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकाशनों की विस्तृत श्रृंखला की मुफ्त डाउनलोड सुविधा प्रदान करती है। इसमें आरआईएस द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं का विवरण भी है। चालू वित्त वर्ष (2019–20) के दौरान तीन नए उप–कार्य क्षेत्रों (सब–डोमेन) को आंतरिक तौर पर विकसित किया गया है और फिर उन्हें आरआईएस की वेबसाइट से लिंक कर दिया गया है, ताकि उनकी स्पष्ट और व्यापक पहुंच संभव हो सके। अब आरआईएस की मुख्य वेबसाइट के अंतर्गत ग्यारह उप–कार्य क्षेत्र (सब–डोमेन) हैं। इनमें ये शामिल हैं:

एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
http://aagc.ris.org.in

आसियान भारत केंद्र
http://aic.ris.org.in

ब्लू इकोनॉमी फोरम
http://blueeconomyforum.ris.org.in

भारतीय विकास सहयोग के लिए फोरम
http://fidc.ris.org.in

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम)
http://fitm.ris.org.in

वैश्विक विकास केंद्र
http://gdc.ris.org.in

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) पहल
http://iora.ris.org.in

न्यू एशिया फोरम
http://newasiaforum.ris.org.in

सतत विकास लक्ष्यों पर आरआईएस का कार्यक्रम
http://sdg.ris.org.in

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट)
http://southernthinktanks.ris.org.in

एफआईएसडी
http://fisd.ris.org.in

इसके अलावा, वेबसाइट पर निम्नलिखित वेबसाइट पेज भी हैं :

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
http://ris.org.in/asian-infrastructure-investment-bank

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम
http://ris.org.in/science-technology-and-innovation-policy-stip-forum-and-monthly-lecture-series-0

दिल्ली प्रोसेस
http://ris.org.in/delhi-process

गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर दस्तावेज
http://ris.org.in/documents-non-aligned-movement

समर स्कूल
http://ris.org.in/summer-school-0

पेरिस शांति फोरम
http://ris.org.in/deadline-extended-extra-time-submit-your-project-paris-peace-forum

आरआईएस की देख–रेख वाली अन्य वेबसाइटें

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट)
http://southernthinktanks.org

एफआईएसडी
http://fisd.in

इब्सा
http://ibsa-trilateral.org

दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस)
http://saceps.org.in

चालू वित्त. वर्ष (2019–20) के दौरान आरआईएस की वेबसाइट ने 'हिट' की कुल संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज की है। इसने गूगल द्वारा संचालित शीर्ष अनुसंधान परिणामों में से एक का दर्जा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है जो इसकी निरंतर बढ़ती दृश्यता को रेखांकित करता है। आरआईएस नियमित रूप से अपने त्रैमासिक ई–न्यूजलेटर और मासिक ई–पत्रिका को भी प्रकाशित करता है जिन्हें प्रमुख नीति–निर्माताओं एवं आकृतिकारों, थिंक टैंकों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, प्रमुख शिक्षाविदों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रख्यात हस्तियों के बीच दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है, ताकि उन्हें विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुद्दों पर आरआईएस द्वारा किए जा रहे विश्वसनीय शोध कार्यों की विस्तृत विविधता से अवगत कराया जा सके।

सोशल मीडिया

आरआईएस ने ट्विटर, फेसबुक एवं यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचो पर अपनी उपस्थिति काफी बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में इसके अनुगामी भी हैं। आरआईएस के यूट्यूब चैनल को निरंतर अपडेट रखा जाता है। लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग वाले आयोजनों को इसकी प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराया जाता है। आरआईएस के यूट्यूब चैनल की दर्शक संख्या में अच्छी–खासी वृद्धि दर्ज की गई है तथा उसका ग्राहक आधार भी अब और ज्यादा बढ़ गया है।

आरआईएस फेसबुक और ट्विटर

4 हजार से भी अधिक अनुगामी हैं और इसके पेजों को लोगों की रायशुमारी के आधार पर 5 में से 4.3 रेटिंग दी गई है। ट्विटर हैंडल के 4 हजार से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वास्तविक समय पर लोगों की त्वरित पहुंच के लिए आरआईएस के प्रत्येक प्रमुख कार्यकलाप को इन दोनों ही प्लेटफॉर्मों पर तुरंत उपलब्ध कराया जाता है। यही नहीं,

आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र

दर्शकों की ओर से मिली प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहजनक है।

आरआईएस की इंट्रानेट सुविधा

संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट सुविधा है जो कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से जुड़ी बातों के संबंध में पासवर्ड संरक्षित जानकारियां प्रदान करती है, जिनमें अवकाश का रिकॉर्ड, वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप), चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और अन्य विवरण शामिल होते हैं। यह अपने संकाय के लिए अनुसंधान डेटाबेस भी प्रदान करती है जो सीडी प्रारूप में उपलब्ध होता है और जो अन्य बातों के अलावा व्यापार आंकड़ों की दिशा, कस्टाडा, विश्व विकास संकेतकों, सरकारी वित्तीय आंकड़ों (आईएमएफ) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों (आईएमएफ) को कवर करता है।

वित्त वर्ष 2019–20 में आरआईएस सब–डोमेन में हिट्स

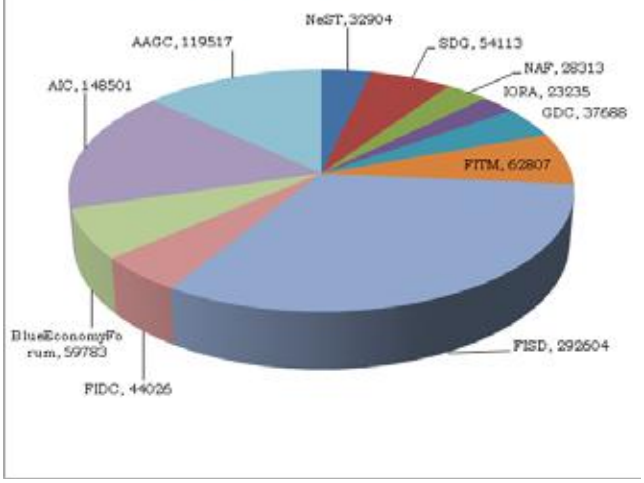

वित्त वर्ष 2019–20 में देशों द्वारा हिट्स

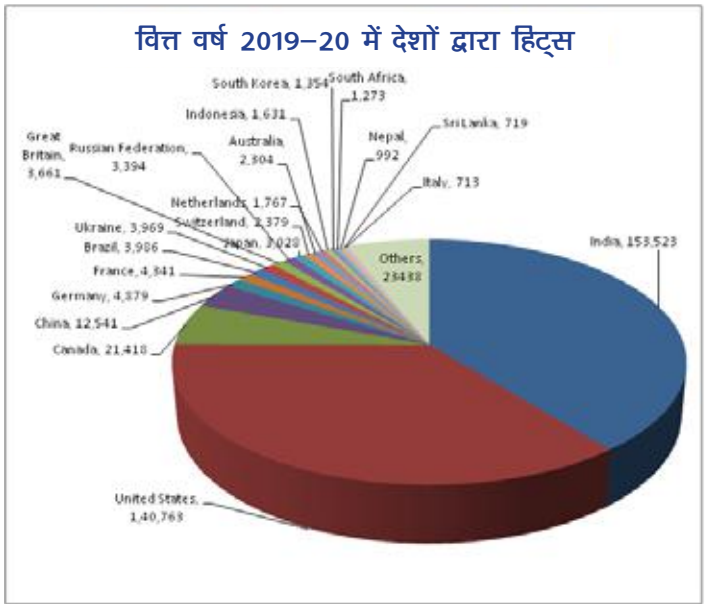

वित्त वर्ष 2019–20 में आरआईएस के सांख्यिकिय हिट्स

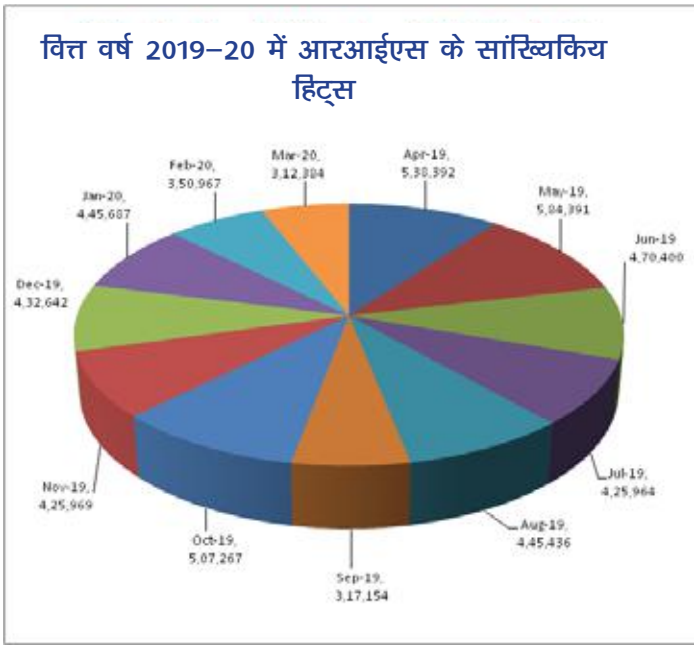

अध्याय 8

मानव संसाधन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक
विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तत तथा विकास सहयोग

संकाय

डॉ एस के मोहंती
प्रोफेसर
विशेषज्ञता : वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा विकास संबंधी आर्थिक मामले

डॉ सब्यासाची साहा
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञता : प्रोद्योगिकी एवं विकास, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, आर्थिक विकास एवं विश्व व्यापार संगठन

डॉ प्रियदर्शी दाश
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञता : अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त

डॉ बीना पाण्डेय
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता : सामाजिक क्षेत्र, जेंडर सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी मामले

विशिष्ट फैलो

श्री राजीव खेर
सलाहकार
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य

श्री अमर सिन्हा
सलाहकार
विशेषज्ञता: आर्थिक कूटनीति और दक्षिणीय सहयोग

प्रो. अमिताभ कुंडू
सलाहकार
विशेषज्ञता: सतत विकास लक्ष्य एवं क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रभाव आंकलन पद्धति

मानव संसाधन

विजिटिंग फैलो/सलाहकार/अनुसंधान एसोसिएट

श्री भास्कर बालाकृष्णन
साइंस डिपलोमेसी फैलो
विशेषज्ञता: एसटीआई सहयोग एवं विज्ञान नीति

प्रो. टी सी जेम्स
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर)

प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: सूक्ष्म–अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सहयोग और मूल्यांकन

डॉ. पी के आनन्द
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: आर्थिक विकास और विकास

श्री कृष्ण कुमार
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: आधिकारिक सांख्यिकी एवं सतत विकास लक्ष्य

डॉ. अमित कुमार
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञता: नवप्रवर्तन, दूरदर्शिता एवं नियंत्रण

सुश्री निमिता पाण्डेय
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: विज्ञान नीति

डॉ स्नेहा सिन्हा
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी अध्ययन

डॉ तन्जीम हसनत
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय एवं वित्तीय अर्थशास्त्र

डॉ. के रवि श्रीनिवास
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: बौद्धिक संपदा अधिकार एवं वैश्विक व्यापार

डॉ. सुशील कुमार
सलाहकार
विशेषज्ञता: अतंर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

श्री सुभोमॉय भट्टाचार्य
सलाहकार
विशेषज्ञता: सार्वजनिक नीति एवं ऊर्जा विशेषज्ञ

श्री अरुण सोमाचुदन नायर
सलाहकार
विशेषज्ञता: विदेशी व्यापार एवं निवेश

डॉ. ऑगस्टीन पीटर
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: व्यापार निवेश एवं प्रतिस्पर्धा नीती

डॉ. आभा जैसवाy
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और प्रबंधन

डॉ. नम्रता पाठक
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: पारंपरिक ज्ञान

डॉ दिनेश कुमार
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

डॉ दीपिका चावला
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: विकास अर्थशास्त्र एवं नवाचार अध्ययन

आसियन–भारत केंद्र

डॉ. प्रबीर डे
प्रोफेसर / समन्वयक, एआईसी
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबंधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

सुश्री श्रेया पान
अनुसंधान सहायक
विशेषज्ञताः वैश्विक व्यापार

डॉ. दूराईराज कुमारासामी
सलाहकार
विशेषज्ञताः अतंर्राष्ट्रीय व्यापार, एवं विदेश निवेश एवं व्यवहारिक अर्थमिति

वैश्विक विकास पर पहल

श्री अभिनव झा
अनुसंधान सहायक

अनुसंधान सहायक

सुश्री प्रतिवा सॉव
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री अदिति गुप्ता
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री अमीका बावा
मास्टर्स इन डिप्लोमेसी, लॉ एवं बिसनेस
(दिसम्बर 2019 तक)

श्री अंकुर जयसवाल
एम.एस.सी (इकोनोमिक्स)

श्री अपूर्व भटनागर
एम.ए. (डेवलपमेंट इकोनोमिक्स)

श्री आकांश खण्डेलवाल
एम.ए. (इकोनोमिक्स)
(जून 2019 तक)

सुश्री चांदनी डवानी
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री गीतिका खंडुजा
एम.ए. (पब्लिक पॉलिसी)
(जुलाई 2019 तक)

मानव संसाधन

अनुसंधान सहायक

सुश्री सुनन्दा महाजन
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री सोनल गर्ग
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री सभ्या राय
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री श्रेया कन्सल
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री नीहारिका
एम.एस.सी (इकोनोमिक्स)

सहायक वरिष्ठ अध्येता

प्रोफेसर अनिल सुकलाल
उप महानिदेशक, एशिया और मध्य पूर्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग, दक्षिण अफ्रीका

प्रोफेसर हरिबाबू ईजनवरजला
पूर्व कुलपति प्रभारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय

डॉ. बेनू श्नाइडर
पूर्व में संयुक्त राष्ट्र एवं अंकटाड के साथ और भारतीय रिजर्व बैंक में सलाहकार

प्रोफेसर अमृता नार्लीकर
अध्यक्ष, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (गीगा)

प्रोफेसर मुकुल जी. अशर
प्रोफेसरियल फेलो, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. बालाकृष्ण पिसुपति
चेयरपर्सन, फ्लेज और पूर्व अध्यक्ष, एनबीए, चेन्नई

डॉ. बिष्वजीत बनर्जी
मुख्य अर्थशास्त्री, वित्त मंत्रालय, स्लोवाक गणराज्य और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा

प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल
आरबीआई के पूर्व चेयर प्रोफेसर, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम

प्रोफेसर शाहिद अहमद
प्रोफेसर और प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया

प्रोफेसर श्रीविद्या राघवान
कानून के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ लॉ, नॉर्मन, अमेरिका

डॉ. रामकिशन एस. राजन
वाइस–डीन (अनुसंधान) और प्रोफेसर, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. सुमा अत्रे
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और रणनीति, ब्रुनेल बिजनेस स्कूल, यूके

डॉ. टी. पी. राजेंद्रन
पूर्व सहायक महानिदेशक, आईसीएआर और विजिटिंग फेलो, आरआईएस

प्रोफेसर केविन पी. गालाघेर
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, बोस्टन यूनिवर्सिटी; सीनियर एसोसिएट, जीडीएई, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी

स्टाफ के अन्य सदस्य

श्री महेश सी अरोड़ा
निदेशक, वित्त एवं प्रशासन

महानिदेशक कार्यालय

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रभारी, महानिदेशक कार्यालय
श्रे एन एन कृष्णन, निजी सचिव
श्रीमती रितु परनामी, निजी सचिव
सुश्री गोहर नाज, सचिवीय सहायक

प्रकाशन विभाग

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रकाशन अधिकारी
श्री संजय शर्मा, (संपादकीय) सहायक
श्री सचिन सिंघल, प्रकाशन सहायक (वेब और डिजाइन)

आंकड़ा एवं सूचना केन्द्र

श्रीमती ज्योति, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
श्रीमती सुशीला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

सूचना प्रौद्योगिकी/डॉटाबेस एकक

श्रीमती सुषमा भट्ट, उपनिदेशक, आंकड़ा प्रबंधन
श्री चन्द्र शेखर पुरी, उपनिदेशक, प्रणाली
श्रीमती पूनम मल्होत्रा, डाटा एंट्री आपॅरेटर
श्री सत्यपाल सिंह रावत, जूनियर सहायक
श्रीमती गीतिका शर्मा, डाटा एंट्री आपॅरेटर
श्री सौम्य रंजन, आईटी सहायक

वित्त एवं प्रशासन

श्री वी कृष्णामणि, उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा)
श्रीमती शीला मल्होत्रा, अनुभाग अधिकारी (लेखा)
श्री हरकेश, अनुभाग अधिकारी (सितम्बर 2019 तक)
श्रीमती अनु बिष्ट, सहायक
श्री सुरजीत, लेखाकार
श्री अनिल कुमार, सहायक
श्री पियूष वर्मा, अवर श्रेणी लिपिकं
श्रीमती शालिनी शर्मा, स्वागती

अनुसंधान सहयोग

सुश्री किरन वाघ, निजी सचिव
श्री सुरेन्द्र कुमार, निजी सहायक
श्रीमती बिन्दु गंभीर, आशुलिपिक
श्री जे. श्रीनिवास राव, सहायक
श्री बैदनाथ पाण्डेय, कार्यालय सहायक

सहायक स्टाफ

श्री सत्यवीर सिंह, स्टाफ कार चालक
श्री जे बी ठाकुरी, स्टाफ कार चालक
श्री बलवान
श्री प्रदीप
श्री राजू
श्री राज कुमार
श्री मनीष कुमार
श्री राज कुमार
श्री सुधीर राणा
श्री बिरजू
श्री प्रदीप नेगी

अध्याय 9

वित्तीय विवरण

सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटैंट्स

8, सेकेंड फ्लोर, कृष्णा मार्केट, कालका जी, नई दिल्ली–110019

टेलीफोन : 32500444, टेलीफैक्स: 40590344, ई–मेल: skacamail@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली की आम सभा के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरण के ऑडिट पर रिपोर्ट

राय

हमने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, (निकाय), के तहत पंजीकृत एक सोसायटी 'विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली' के वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है जिसमें 31 मार्च, 2020 तक की बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा–जोखा, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरण की अनुसूची शामिल हैं।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक सोसायटी की वित्तीय स्थिति, उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन और प्राप्तियों एवं भुगतान की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी 'ऑडिटिंग पर मानकों (एसए)' के अनुसार अपना ऑडिट किया। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरण के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जवाबदेही' अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार इस निकाय से बिल्कुल पृथक हैं और हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारी राय को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और बिल्कुल उपयुक्त है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और गवर्नेंस के प्रभारी की जवाबदेही

प्रबंधन पर ही इन वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी होती है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सोसायटी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन की सही व निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त या प्रासंगिक माने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण का स्वरूप निर्धारित करना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो सटीक एवं निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त होते हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन ही 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत या चालू निकाय' के रूप में अपनी कंपनी या सोसायटी की क्षमता का आकलन करने के लिए जवाबदेह होता है। प्रबंधन इसके लिए 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' से संबंधित उन तथ्यों का खुलासा करता है, जो मान्य या लागू होते हैं। प्रबंधन इसके साथ ही लेखांकन के 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' से संबंधित आधार का उपयोग करता है, बशर्ते कि प्रबंधन या तो अपने निकाय का परिसमापन करने या उसका परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या परिचालन बंद न करने के लिए उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प हो।

गवर्नेंस के प्रभारी लोग संबंधित इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर करीबी नजर रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

वित्तीय विवरण के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जवाबदेही

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त हैं। हमारा उद्देश्य एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना भी है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत या यथोचित आश्वासन दरअसल आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि 'एसए' के अनुसार किए गए ऑडिट से किसी तथ्य संबंधी गलतबयानी का सदैव पता लग ही जाएगा, बशर्ते कि वह मौजूद हो। गलतबयानी दरअसल धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उसे तथ्य संबंधी गलतबयानी तब माना जाता है जब व्यक्तिगत या समग्र रूप से वे इन वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं (यूजर) के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हों।

'एसए' के अनुसार किए जाने वाले ऑडिट के एक हिस्से के रूप में हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल संशय या तर्कवाद को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- हम धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण की तथ्य संबंधी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते हैं, इन जोखिमों को कम करने में सक्षम ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार एवं निष्पादित करते हैं, और ऐसा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं बिल्कुल उपयुक्त होता है। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी का पता नहीं लगा पाने का जोखिम दरअसल त्रुटि से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी से जुड़े जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- हम ऑडिट के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करते हैं, ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके जो विभिन्न परिस्थितियों में बिल्कुल उपयुक्त होती हैं।
- हम इस्तेमाल में लाई जा चुकी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का आकलन करते हैं।
- हम प्रबंधन द्वारा 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' से संबंधित लेखांकन आधार का उपयोग किए जाने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और यह इस प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित होता है कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित ऐसी कोई तथ्य संबंधी अनिश्चितता है जो एक 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' के रूप में अपना संचालन निरंतर जारी रखने संबंधी इस निकाय की क्षमता पर संशय प्रकट करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्य संबंधी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी ऑडिटर रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के कारण 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' के रूप में इसका संचालन थम सकता है।

हम प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री (कंटेंट) का आकलन करते हैं। हम यह भी आकलन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करना संभव हो।

हम अन्य बातों के अलावा ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश एवं सही समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो गवर्नेंस के प्रभारी हैं। इसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसकी पहचान हम अपने ऑडिट के दौरान करते हैं।

अन्य आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हम यह बताते हैं कि :

- हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं धारणा के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
- हमारी राय में, कानून के तहत आवश्यक माने जाने वाले बही–खाते को निकाय ने अब तक बिल्कुल सही ढंग से सुव्यवस्थित रखा है, जैसा कि हमारे द्वारा बही–खाते की छानबीन से प्रतीत होता है; और
- इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई बैलेंस शीट, आय एवं व्यय का विवरण और प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा–जोखा वस्तुतः बही–खाते के अनुरूप ही हैं।

के लिए, सिंह कृष्ण एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्या 008714सी

ह./–
(कृष्ण कुमार सिंह)
भागीदार
एम. संख्या 077494

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

यूडीआईएन : 20077494एएएएएएम8282

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी)

31 मार्च, 2020 तक तुलन पत्र

राशि रु. में

	अनुसूची #	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2010 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 को
देनदारियां			
अनुसंधान और विकास कोष	1	12,12,06,400.18	10,48,86,411.55
अचल परिसंपत्ति कोष (गैर – एफसीआरए)	2	2,04,70,092.00	2,05,63,226.00
अचल परिसंपत्ति कोष (एफसीआरए)		51,914.00	75,259.00
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित राशि (गैर–एफसीआरए)	3	1,17,43,716.58	97,15,074.00
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित राशि (एफसीआरए)		1,35,45,613.80	33,12,855.81
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (गैर – एफसीआरए)	4	4,35,87,287.67	5,07,83,177.67
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (एफसीआरए)		36,04,200.00	28,40,698.00
कुल		21,42,09,224.23	19,21,76,702.03
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां (गैर – एफसीआरए)	5	2,04,70,092.00	2,05,63,226.00
अचल परिसंपत्तियां (एफसीआरए)		4,53,210.00	4,76,555.00
निवेश (गैर – एफसीआरए)	6	3,03,46,419.00	3,80,32,610.00
निवेश (एफसीआरए)		8,80,50,977.33	8,57,01,574.70
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य राशि (गैर – एफसीआरए)	3	1,91,88,065.04	1,62,48,645.04
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य राशि (एफसीआरए)		14,84,068.18	54,73,025.70
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम, इत्यादि (गैर – एफसीआरए)	7	2,75,08,130.40	2,12,34,862.38
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम, इत्यादि (एफसीआरए)		2,67,08,262.28	44,46,203.21
कुल		21,42,09,224.23	19,21,76,702.03

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16

अनुसूची 1 से 16 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं

आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
कंपनी की रजिस्ट्रेशन संख्या 008714सी

ह./–	ह./–	ह./–
(कृष्ण कुमार सिंह)	महेश सी. अरोड़ा	प्रो. सचिन चतुर्वेदी
साझेदार	निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)	महानिदेशक

एम. संख्या 077494
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था)
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता राशि में

राशि रु. में

	अनुसूची #	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2020 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 को
आय			
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से अनुदान सहायता	4(ए)	11,53,67,123.00	11,69,89,000.00
प्रायोजित परियोजना अनुदान कार्यक्रमों से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए हस्तांतरित किया गया (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)	3	7,81,05,121.82	9,66,37,564.54
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर अधिशेष राशि हस्तांतरित की गई (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)		14,85,367.85	51,01,707.56
रॉयल्टी, प्रकाशन, इत्यादि से आय (गैर – एफसीआरए)		95,624.88	84,647.52
अर्जित ब्याज :			
सावधि जमा पर (एफसीआरए)		58,44,535.00	57,66,268.00
सावधि जमा पर (गैर – एफसीआरए)		10,96,315.00	10,04,714.00
बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते पर (एफसीआरए)		3,81,734.00	2,75,746.00
बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते पर (गैर – एफसीआरए)		7,17,700.00	3,88,124.00
कर्मचारियों को दिए ऋण पर (गैर – एफसीआरए)		17,751.00	30,456.00
अन्य विविध आय (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)		3,02,587.50	2,000.00
प्रायोजित परियोजनाओं से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऊपरी खर्च (ओवरहेड) के लिए रिकवरी (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)		76,58,289.68	57,51,850.18
पूर्व अवधि में आय		38,503.00	-
ठोस परिसंपत्तियों की बिक्री से आय		91,338.00	-
देय को बट्टे खाते में डाला गया		2,44,441.00	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कोष से हस्तांतरित राशि – बेची / बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों का डब्ल्यू.डी.वी. (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)	2	15,900.00	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कोष से हस्तांतरित राशि – भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता / प्रायोजित परियोजनाओं से अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)		47,33,456.00	48,40,957.00
कुल		21,61,95,787.73	23,68,73,034.80
व्यय			
कार्यक्रम व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं (गैर– एफसीआरए और एफसीआरए)	8	7,81,05,121.82	9,66,37,564.54
प्रतिष्ठान व्यय (गैर – एफसीआरए)	9	7,61,17,846.00	8,86,76,184.00
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (गैर – एफसीआरए)	10	3,93,71,705.98	3,65,42,700.89
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (एफसीआरए)	11	2,05,856.30	91,987.50
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)	5	47,33,456.00	48,40,957.00
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर घाटा राशि हस्तांतरित की गई (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)	3	11,95,243.00	34,91,628.94
पूर्व अवधि में किए गए खर्च		1,46,570.00	-
अनुसंधान और विकास कोष में हस्तांतरित अधिशेष		1,63,19,988.63	65,92,011.93
कुल		21,61,95,787.73	23,68,73,034.80

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16

अनुसूची 1 से 16 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
कंपनी की रजिस्ट्रेशन संख्या 008714C

ह./–
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार
एम. संख्या 077494
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 20/10/2020

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

ह./–
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

ह./–
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली

(सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान का लेखा–जोखा

राशि (रुपये में)

	प्राप्तियां	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2020		वर्ष समाप्त 31 मार्च 2019	
ए	प्रारंभिक शेषराशि (ओपनिंग बैलेंस)				
i)	अपने पास नकदी (गैर–एफसीआरए)	39,077.00		41,393.00	
ii)	बैंक में जमा राशि :	39,140.00		38,818.00	
	चालू खाते में– केनरा बैंक	1,49,99,045.86		76,10,981.32	
	बचत खाते / ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	43,044.21		31,70,177.46	
	बचत खाते / ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	8,57,01,574.70		7,85,53,429.70	
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	3,80,32,610.00		3,57,05,765.00	
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	2,33,293.00		1,85,222.00	
iii)	डाक टिकट– फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर – एफसीआरए)				
	कुल ए		13,90,87,784.77		12,53,05,786.48
बी	प्राप्त अनुदान				
i)	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से	12,00,00,000.00		12,00,00,000.00	
ii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से (गैर – एफसीआरए)	4,93,38,917.00		7,70,97,441.00	
iii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से (एफसीआरए)	4,58,13,716.62		93,25,520.37	
	कुल बी		21,51,52,633.62		20,64,22,961.37
सी	अर्जित ब्याज				
i)	ऋण, अग्रिम, आदि पर ब्याज (गैर – एफसीआरए)	16,471.00		30,456.00	
ii)	बचत बैंक खाता / ऑटो स्वीप पर ब्याज (एफसीआरए)	3,81,928.00		2,75,552.00	
iii)	सावधि जमा खातों पर ब्याज (गैर – एफसीआरए)	9,99,135.00		10,24,176.00	
iv)	सावधि जमा खातों पर ब्याज (एफसीआरए)	54,04,651.00		74,17,153.00	
v)	बचत बैंक खाता / ऑटो स्वीप पर ब्याज (गैर – एफसीआरए)	7,17,700.00		3,87,730.00	
vi)	बचत बैंक खाते पर ब्याज – आंध्र बैंक (गैर – एफसीआरए)	-		394.00	
	कुल सी		75,19,885.00		91,35,461.00
	कुल अग्रेनीत (कैरिड फॉरवर्ड)		36,17,60,303.39		34,08,64,208.85

	भुगतान	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2020		वर्ष समाप्त 31 मार्च 2019	₹
ए	व्यय				
i)	स्थापना व्यय – (अनुसूची – 12) (गैर – एफसीआरए)	8,47,82,161.00		7,76,37,698.00	
ii)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय – (अनुसूची–13) (गैर – एफसीआरए)	3,69,56,833.65		3,90,86,714.48	
iii)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय – (अनुसूची–14) (गैर – एफसीआरए)	2,02,425.30		90,927.50	
iv)	व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं– अनुसूची– 15 (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)	6,93,98,291.14		8,09,62,952.10	
	कुल ए		19,13,39,711.09		19,77,78,292.08
बी					
i)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (गैर – एफसीआरए)	50,62,796.00		29,49,024.00	
ii)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (एफसीआरए)	77,363.00		39,991.00	
	कुल बी		51,40,159.00		29,89,015.00
सी	अग्रिम और जमा				
i)	अग्रिम (गैर – एफसीआरए)	13,13,606.00		8,97,576.00	
ii)	अग्रिम (एफसीआरए)	1,75,375.00		2,60,626.00	
iii)	प्राप्य टीडीएस (गैर – एफसीआरए)	3,39,167.00		4,33,077.00	
iv)	प्राप्य टीडीएस (एफसीआरए)	6,24,284.00		3,61,715.00	
v)	गतावधि या पुराने चेक (एफसीआरए)	1,170.00		-	
	कुल सी		24,53,602.00		19,52,994.00
डी	अन्य				
i)	टेन्डर का रिफंड	34,46,448.86		-	
ii)	कर्मचारियों की ओर से प्राप्त राशि का रिफंड	-		1,07,096.00	
iii)	अंशदायी भविष्य निधि में भुगतान की गई राशि	24,25,266.33		-	
	कुल डी		58,71,715.19		1,07,096.00
	कुल अग्रेनीत (कैरिड फॉरवर्ड)				

	प्राप्तियां	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2020		वर्ष समाप्त 31 मार्च 2019	
	कुल अग्रनीत (कैरी फॉरवर्ड)		36,17,60,303.39		34,08,64,208.85
डी	अन्य आय				
i)	प्रकाशन बिक्री	-		1,600.00	
ii)	रॉयल्टी	85,576.52		81,384.00	
iii)	विविध आय	3,41,090.50		400.00	
	कुल डी		4,26,667.02		83,384.00
ई	अग्रिम और जमा				
i)	ऋण / अग्रिम की वसूली (गैर – एफसीआरए)	1,19,547.00		1,88,637.00	
ii)	कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली (गैर – एफसीआरए)	8,18,216.00		-	
iii)	गतावधि या पुराने चेक (गैर – एफसीआरए)	21,391.00		3,79,038.00	
iv)	गतावधि या पुराने चेक (एफसीआरए)	-		82,134.00	
v)	अग्रिम में प्राप्त राशि (गैर – एफसीआरए)	19,284.00		-	
vi)	ऋण / अग्रिम की वसूली (एफसीआरए)	2,60,626.00		9,780.00	
vii)	आरआईएस पीएफ की ओर से प्राप्त राशि	28,49,965.00		3,08,000.00	
	कुल ई		40,89,029.00		9,67,589.00
एफ	अन्य				
i	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	1,07,238.00		-	
ii)	आयकर रिफंड	38,265.00		-	
	कुल एफ		1,45,503.00		-
	योग		36,64,21,502.41		34,19,15,181.85

	भुगतान	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2020		वर्ष समाप्त 31 मार्च 2019	
	कुल अग्रनीत (कैरी फॉरवर्ड)		20,48,05,187.28		20,28,27,397.08
ई	अंतिम शेषराशि (क्लोजिंग बैलेंस)				
i)	अपने पास नकदी (गैर –एफसीआरए)	50,816.00		39,077.00	
ii)	बैंक में जमा राशि :				
	बचत खाते में – आंध्रा बैंक (गैर – एफसीआरए)	39,140.00		39,140.00	
	बचत खाते / ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	2,16,25,605.52		1,49,99,045.86	
	बचत खाते / ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	2,12,74,113.28		43,044.21	
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	8,80,50,977.33		8,57,01,574.70	
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	3,03,46,419.00		3,80,32,610.00	
iii)	डाक टिकट – फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर – एफसीआरए)	2,29,244.00		2,33,293.00	
	कुल ई		16,16,16,315.13		13,90,87,784.77
	योग		36,64,21,502.41		34,19,15,181.85

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा–जोखा (अकाउंट्स) पर टिप्पणियां (अनुसूची –16)

अनुसूची 1 से 16 तक लेखा–जोखा (अकाउंट्स) का अभिन्न हिस्सा हैं

संलग्न समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के लिए, सिंह कृष्ण एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्या 008714सी

(कृष्ण कुमार सिंह)
भागीदार
एम. संख्या 077494

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

के लिए, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली

महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त और प्रशासन)

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

आरआईएस

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीतिगत अनुसंधान संस्थान हैं जोकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर कार्य करता है। आरआईएस प्रभावशाली नीतिगत वार्ता को बढ़ावा देने एवं वैश्विक एवं क्षेत्रिय आर्थिक मामलों के संबंध में विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आरआईएस की कार्य योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय बातचीत में विकासशील देशों के साथ समन्वय करना है। आरआईएस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कई प्रयासों की अंतः सरकारी प्रक्रियाओं में कार्यरत है। आरआईएस अपने विचारकों के गहन कार्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास भागीदारी के पटल पर नीतिगत सुसंगतता को सुदृढ़ करता है।

आरआईएस एवं इसकी कार्ययोजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने क लिए कृपया इसकी वेबसाइटः wwww.ris.org.in देखें।

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाषः 91–11–24682177–80
फैक्सः 91–11–24682173–74, ई–मेलः dgoffice@ris.org.
वेबसाइटः http://www.ris.org.in